राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 135

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, बुधवार, 23 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

'भारत की लक्ष्मी' अभियान की ध्वजवाहक होंगी दीपिका और सिंधू >> 3

सरोकार

फरमानों से बेखौफ महिलाएं गढ़ रहीं नया कश्मीर

जम्मू : कश्मीर बदल रहा है। विकास की राह में बाधक बने कट्टरपंथ को खुद कश्मीरी

महिलाएं तोड़ रही हैं। 24 को राज्य में बीडीसी के चुनाव हैं। महिलाएं अलगाववाद और आतंकवाद के फरमानों को दरकिनार कर चुनाव में हिस्सा लेकर बदलाव को धार दे रही हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

इस बार 'लक्ष्मी-गणेश' का पांच ग्राम वाला सिक्का भी

आगरा : धनतेरस और दिवाली का बाजार सजने लगा है। पूजा में रखे जाने वाले

लक्ष्मी-गणेश के चांदी के सिक्कों की बात करें तो खास यह कि इस बार 10, 20 और 50 ग्राम के अलावा पांच ग्राम वजन के सिक्के भी उपलब्ध होंगे। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

नई दिल्ली : आइएनएक्स मीडिया केस में भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सशर्त जमानत दे दी। हालांकि चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लांड्रिंग केस में जेल में होने के कारण बाहर नहीं आ पाएंगे।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

शीर्ष अधिकारियों पर आरोप के बाद इन्फोसिस के शेयर धड़ाम

नई दिल्ली : आइटी कंपनी इन्फोसिस के शीर्ष अफसरों पर अनुचित व्यापार नीति अपनाने के आरोप लगने के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयरों में 17 फीसद की गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल, 2013 के बाद इन्फोसिस के शेयरों में यह सबसे बड़ी गिरावट है। बीएसई का सेंसेक्स 334 .54 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

ह्वाइट हाउस में गुरुवार को दिवाली मनाएंगे ट्रंप

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को ह्वाइट हाउस में दिवाली का जश्न मनाएंगे। वर्ष 2016 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ट्रंप तीसरी बार इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, वह दीया जलाकर जश्न की शुरुआत करेंगे। ह्वाइट हाउस में दिवाली मनाने की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 में की थी।

आजकल ▶ पृष्ठ 16

ओजोन छिद्र में इस साल रिकॉर्ड गिरावट : नासा

वाशिंगटन : अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन गैस की परत के छिद्र में इस साल रिकॉर्ड गिरावट हुई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, 1982 के बाद से पहली बार ओजोन परत का छिद्र इतना सिकुड़ा है। गत आठ सितंबर को इसका आकार 1.64 करोड़ वर्ग किलोमीटर था जो अक्टूबर में घटकर एक करोड़ वर्ग किलोमीटर रह गया।

सोशल मीडिया को आधार से जोड़ने के सभी मामले सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने संबंधी विभिन्न हाई कोर्टों में चल रहे सभी मामलों को अपने यहां ट्रांसफर कर लिया है। शीर्ष अदालत इस बात पर विचार करेगी कि क्या सरकार फेसबुक और वाट्सएप जैसी इंटरमीडियरीज को नागरिकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देने के लिए मजबूर कर सकती है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमों की अधिसूचना जारी करने संबंधी रिपोर्ट जनवरी में दाखिल करने को कहा है। इनमें संदेशों को पढ़े जाने की जिम्मेदारी इंटरमीडियरीज पर डालने संबंधी नियम भी शामिल किए जाने हैं।

सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोड़ने और संदेशों के स्रोत का पता लगाने संबंधी कई मामले देशभर में विभिन्न हाई कोर्टों में लंबित हैं। जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने फेसबुक की याचिका स्वीकार करते हुए रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह सभी मामलों को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश करे ताकि उन्हें जनवरी, 2020 के अंतिम सप्ताह में उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके।

तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 संदेशों या किसी सामग्री के डिक्रिप्शन की अनुमति देती है। इसलिए फेसबुक व वाट्सएप का यह कहना कि इन्हें डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, स्वीकार्य नहीं है। जब कंपनियों के पास अपने प्रोडक्ट का दुरुपयोग रोकने का इंतजाम ही नहीं है तो वे किसी देश में कैसे जा सकती हैं? इस पर अदालत ने कहा कि अमेरिका में इसके लिए ये बाहरी एजेंसी की मदद लेती हैं। यहां सवाल यह है कि क्या हम उन पर दबाव बना सकते हैं? पीठ ने कहा, पहली नजर में संदेशों को डिक्रिप्ट करने या डिक्रिप्शन के लिए सरकार को सामग्री मुहैया कराने की जिम्मेदारी इंटरमीडियरीज की है। वेणुगोपाल ने कहा, वे उनसे संदेशों को डिक्रिप्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि वे डिक्रिप्शन में सहायता करें।

केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह मामला निजता में दखल का नहीं है बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हितों और संप्रभुता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस दौरान वेणुगोपाल ने कहा, आतंकी निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

- फेसबुक की याचिका पर सभी हाई कोर्टों से मंगाए मामले
- सीजेआइ के सामने पेश किए जाएंगे सभी प्रकरण
- हेट स्पीच और फेक न्यूज पर अंकुश के लिहाज से अहम है सुनवाई

फेसबुक-वाट्सएप जैसे मंचों के दुरुपयोग के मामले में किसकी क्या है राय

कोर्ट का रुख

- सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाले नियमों को अधिसूचित करने के संबंध में जनवरी 2020 में रिपोर्ट दे केंद्र
- सरकार से निश्चित समय सीमा में नियम बनाने के लिए कहा गया। यह भी कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो कोर्ट खुद निर्देश देगा
- किसी व्यक्ति की तरफ से नियमों की जानकारी मांगे जाने की स्थिति को भी शामिल करने का निर्देश दिया

केंद्र सरकार का पक्ष

- जनवरी 2020 तक तैयार हो जाएंगे नियम, संशोधित मसौदे पर इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मंत्रणा जारी
- हलफनामे में कहा, कुछ वर्षों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल में काफी तेजी आई
- सोशल मीडिया में हेट स्पीच, फेक न्यूज व राष्ट्रविरोधी गतिविधियां तेजी से बढ़ी
- इंटरनेट लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के टूल के तौर पर उभरा

कंपनियों का जवाब

- फेक न्यूज, हेट स्पीच और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले संदेशों के स्रोत की जानकारी देना यूजर्स की निजता का है उल्लंघन
- नियमों के तहत इंटरमीडियरीज डिक्रिप्शन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं
- संदेशों को डिक्रिप्ट करने की तकनीक हमारे पास नहीं, अगर स्रोत बताने पर जोर दिया गया तो कठिनाई आएगी।

कमलेश तिवारी हत्याकांड में दोनों मुख्य आरोपित गिरफ्तार

कामयाबी ▶ गुजरात एटीएस ने दोनों को राजस्थान सीमा के पास पकड़ा

अशफाक और मोईनुद्दीन ने हत्या का जुर्म कुबूला, लखनऊ लाए जाएंगे दोनों

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात एटीएस ने अशफाक शेख और मोईनुद्दीन पठान नामक आरोपितों को राजस्थान सीमा पर शमलाजी के पास से गिरफ्तार किया है। दोनों ने हत्या का जुर्म कुबूल कर लिया है। एक दिन पूर्व ही डीजीपी ओपी सिंह ने दोनों पर ढाई-ढाई लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।

गुजरात एटीएस के डीआइजी हिमांशु शुक्ल ने बताया कि दोनों को मंगलवार शाम उस वक्त पकड़ा गया, जब वो गुजरात सीमा में प्रवेश करने वाले थे। 34 वर्षीय अशफाक और 27 वर्षीय मोईनुद्दीन गुजरात के सूरत के निवासी हैं। पैसे खत्म होने के बाद दोनों ने परिजनों और दोस्तों से संपर्क किया था, जिसके बाद सर्विलांस के जरिए उनकी गतिविधियों पर नजर थी।

बता दें कि लखनऊ के खुर्शेदबाग में 18 अक्टूबर को दिनदहाड़े कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद दोनों हत्यारे लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत व अन्य स्थानों पर छिपते रहे। दोनों हत्यारोपी एक दिन पूर्व नेपाल से शाहजहांपुर पहुंचे थे और जहां से वो गुजरात जा रहे थे।

दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जाएगा। मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआइटी की टीम उन्हें लाने

शामलाजी में मंगलवार को गुजरात एटीएस की गिरफ्त में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपित अशफाक शेख और मोइनुद्दीन पठान। एएनआइ

गुजरात जा रही है। डीजीपी ओपी सिंह का कहना है कि घटना के बाद से पुलिस लगातार दोनों पर दबाव बनाए थी, जिसके चलते ही उनकी गिरफ्तारी हो सकी।

इस मामले में इससे पहले चार लोग गिरफ्तार किए गए थे। गुजरात एटीएस ने ही 19 अक्टूबर को इस मामले के साजिशकर्ता राशिद पठान, मौलाना मोहसिन शेख व फैजान को पकड़ा था। वहीं, महाराष्ट्र के नागपुर में भी सैयद असीम अली को गिरफ्तार किया गया था। एसआइटी अली को मंगलवार को लखनऊ लेकर आई। (पेज-5 भी देखें)

कठुआ कांड में नया मोड़, एसआइटी पर एफआइआर दर्ज करने का निर्देश

जेएनएन , जम्मू

पूरे देश को हिला देने वाले जनवरी 2018 के बहुचर्चित कठुआ दुष्कर्म कांड में नया मोड़ आ गया है। सिटी जज जम्मू प्रेम सागर ने मामले की जांच करने वाली राज्य क्राइम ब्रांच की छह सदस्यीय स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) के खिलाफ फर्जी गवाह तैयार करने, उन्हें गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखने और मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने के आरोप में एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी जम्मू को एफआइआर दर्ज करने और सात नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया।

हमें फर्जी बयान देने के लिए मजबूर किया गया : कठुआ मामले में क्राइम ब्रांच की एसआइटी ने सचिन शर्मा, नीरज शर्मा और साहिल शर्मा को भी अपना गवाह बनाया था, लेकिन तीनों ने सिटी जज की कोर्ट में एक आवेदन दायर कर एसआइटी के सदस्य पूर्व एसएसपी क्राइम आरके जाला, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच पीरजादा नावेद, डीएसपी क्राइम ब्रांच शितांबरी शर्मा, नासिर हुसैन, उरफान वानी और केवल किशोर के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआइटी सदस्यों ने उन्हें विशाल जंगोत्रा के खिलाफ फर्जी बयान देने के लिए मजबूर किया। वहीं, उन्हें गैर-कानूनी ढंग से हिरासत में रखा और शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया। तीनों आवेदनकर्ताओं ने कहा कि उक्त जांच अधिकारियों ने साजिश के तहत विशाल को फंसाया और उसके खिलाफ फर्जी सुबूत तैयार कर उनसे सीआरपीसी की धारा-164 के तहत जबरन बयान दर्ज कराए।

- फर्जी गवाह तैयार करने और गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखने का मामला
- टीम पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप

इनके खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश

- पूर्व एसएसपी क्राइम आरके जाला 2. एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच पीरजादा नावेद
- डीएसपी क्राइम ब्रांच शितांबरी शर्मा
- नासिर हुसैन
- उरफान वानी
- केवल किशोर

पुलिस ने शिकायत पर नहीं की कार्रवाई

आवेदनकर्ताओं के वकील अंकुर शर्मा व तरुण शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सचिन, नीरज व साहिल ने 24 सितंबर 2019 को एसएचओ पक्का डंगा को शिकायत देते हुए एसआइटी के सदस्यों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की थी। अपनी शिकायत में उन्होंने यह भी कहा था कि कोर्ट ने भी विशाल को बरी कर दिया है। ऐसे में एसआइटी सदस्यों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाए। जब एसएचओ ने कार्रवाई नहीं की तो शिकायतकर्ता पांच अक्टूबर को एसएसपी जम्मू के पास भी शिकायत लेकर गए, लेकिन वहां भी उनकी बात नहीं सुनी गई है।

यह था मामला

कठुआ में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हुई थी। इस मामले में आठ आरोपित थे। पठानकोट की अदालत ने इनमें से छह को दोषी करार दिया था। एक नाबालिग होने पर उसके खिलाफ जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मामला चल रहा है, जबकि विशाल को बरी किया जा चुका है।

भारत ने घर में जीती रिकॉर्ड 11वीं सीरीज

रांची : दक्षिण अफ्रीका को रांची टेस्ट में एक पारी व 202 रन से हराकर टीम इंडिया ने न सिर्फ उनका सूपड़ा साफ किया, बल्कि लगातार 11 घरेलू सीरीज जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। मैच के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों को मेहमानों की दूसरी पारी 133 रनों पर समेटने में मात्र नौ मिनट लगे। भारत ने पहली पारी में नौ

विकेट पर 497 रन बनाकर पारी घोषित की थी, जबकि द. अफ्रीका पहली पारी में 162 रनों पर आउट हो गई थी। सीरीज में 529 रन बनाने वाले रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच रहे। यह कोहली की कप्तानी में द. अफ्रीका पर सातवीं व टेस्ट इतिहास में इस टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है। (पेज-14)

उप्र में 'अराजकता', मंदिरों के प्रबंधन के लिए क्या किया गया : सुप्रीम कोर्ट

- बुलंदशहर के प्राचीन मंदिर से संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताते हुए की तल्ख टिप्पणी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में मंदिरों और धर्मार्थ संस्थाओं के प्रबंधन के बारे में कई तीखे सवाल पूछे और टिप्पणी की कि राज्य में 'अराजकता' की स्थिति है। राज्य के बुलंदशहर में एक प्राचीन मंदिर के प्रबंधन से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की।

जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया, ''क्या आप अपने शासकीय आदेश से कुछ भी कर सकते हैं? यह तो अराजकता है।' पीठ ने सवाल किया कि क्या राज्य में कोई भी व्यक्ति मंदिर का निर्माण करके जनता से धन एकत्र कर सकता है। पीठ ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के बीच इस तथ्य से अवगत कराने का निर्देश दिया कि क्या वह मंदिरों और धर्मार्थ संस्थाओं के प्रबंधन से संबंधित मसलों के लिए कोई कानून बनाएगी? शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से सवाल किया कि उसने प्रदेश में मंदिरों और धर्मार्थ संस्थाओं के प्रबंधन के लिए अभी तक कोई कानून क्यों नहीं बनाया? कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि राज्य ने इस बारे में अभी तक केंद्रीय कानून को क्यों नहीं अंगीकार किया?

पीठ ने पिछले सप्ताह नाराजगी जताते हुए कहा था कि यद्यपि यह मामला 2010 से लंबित है लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की ओर से पेश वकील यह बताने की स्थिति में ही नहीं थे कि क्या इस बारे में कोई कानून बनाया गया है। पीठ ने 17 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था, 'इस तथ्य के मद्देनजर, हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव/संबंधित सचिव को व्यक्तिगत रूप से 22 अक्टूबर को उपस्थित होने का निर्देश देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।' शीर्ष कोर्ट बुलंदशहर में करीब 300 साल पुराने इस मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को 'पंडों' में वितरित करने का आदेश देने संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

चुनाव नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने हरियाणा में भंग किया संगठन

चंडीगढ़ : हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने संगठन के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर के कार्यकाल में हुई सभी नियुक्तियों को रद करते हुए सभी मोर्चों को भंग कर दिया गया है। 18 बागियों को पार्टी से निकाल दिया गया है। जल्द ही नए सिरे से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद संगठन में पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। (पेज-4)

भारत धार्मिक में तो पाकिस्तान 'आतंकी' पर्यटन में जुटा

नई दिल्ली : भारत ने मंगलवार को दर्जनों देशों के राजनयिकों को करतारपुर गलियारे का धार्मिक पर्यटन कराया, वहीं पाकिस्तान ने कुछ विदेशी राजनयिकों को आतंकी गढ़ों का पर्यटन कराने की व्यवस्था की। भारत के निमंत्रण पर 90 देशों के राजदूतों ने करतारपुर कॉरिडोर में ढ़ाचागत सुविधाओं का मौका मुआयना किया। वहीं पाक सेना राजनयिकों को गुलाम कश्मीर में भारतीय सैन्य कार्रवाई में आतंकियों के ध्वस्त ठिकानों को दिखाने ले गई। (पेज-5)

जयपुर में बसपा के दो राष्ट्रीय नेताओं का मुंह काला कर गधे पर बैठाया

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से किस हद तक नाराज हैं, इसका नजारा मंगलवार को जयपुर में तब देखने को मिला जब उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और प्रदेश प्रभारी से बदसुलूकी। टिकट बेचने के आरोप लगा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार सुबह दोनों नेताओं को दफ्तर के बाहर ही न केवल गधे पर बैठाया बल्कि उनका मुंह काला कर जूतों की माला भी पहनाई। इसके साथ ही उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती भड़क गईं। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।

राजस्थान के प्रभारी सीताराम मेघवाल के साथ पार्टी पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों की बैठक लेने के लिए राष्ट्रीय समन्वयक और उपाध्यक्ष रामजी गौतम लखनऊ से जयपुर पहुंचे थे। संगठन की मजबूती एवं आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार सुबह चर्चा होनी थी, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हाथों में ग्रीस और दो गधे लेकर बनीपार्क स्थित पार्टी कार्यालय पहुंच गए। वह गौतम और मेघवाल को जबरन पकड़कर दफ्तर के बाहर ले आए। पहले तो दोनों नेताओं के मुंह काले किए और फिर उन्हें जूते-चप्पलों की माला पहना दी। दोनों को जबरन दो अलग-अलग गधों पर बैठा दिया। दोनों नेता जब गधों से उतरने लगे तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें गोद में उठाकर फिर से बैठा दिया। इस दौरान रामजी गौतम एक बार सड़क पर गिर पड़े। कार्यकर्ताओं के साथ रामजी गौतम और सीताराम मेघवाल की धक्का-मुक्की भी हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रामजी गौतम और पार्टी सुप्रीमो मायावती पर टिकट बेचने के आरोप लगाए।

हंगामे के बीच रामजी गौतम उग्र कार्यकर्ताओं से खुद को गोली मारने की बात कहते हुए भी सुनाई दिए। काफी देर तक यह घटनाक्रम चलता रहा। इस दौरान पार्टी कार्यालय के अंदर से कुछ लोग दोनों नेताओं को बचाने बाहर आए थे, लेकिन उग्र कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी खदेड़ दिया। सड़क पर हंगामे की सूचना पर सिंधी कैंप थाने से पुलिसकर्मी बसपा कार्यालय तक पहुंचे, लेकिन तब तक कार्यकर्ता वहां से जा चुके थे।

- कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय समन्वयक और प्रदेश प्रभारी से की बदसुलूकी
- टिकट बेचने के आरोप लगा दोनों के खिलाफ की नारेबाजी
- कांग्रेस पर भड़कीं पार्टी सुप्रीमो मायावती, कहा-यह सब वही करा रही

जयपुर में बसपा नेता रामजी गौतम और सीताराम मेघवाल (दाएं) को गधे पर बैठाते बसपा के आक्रोशित कार्यकर्ता। वीडियो ग्रैब

कांग्रेस गलत परंपरा डाल रही : माया पेज>>3

मुलाकात

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोले नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी- भारत के बारे में प्रधानमंत्री के सोचने का तरीका अनूठा, प्रधानमंत्री ने कहा, अभिजीत की उपलब्धियों पर भारत को गर्व

पीएम ने चेताया था, मीडिया 'मोदी विरोधी' बयान के लिए उकसाएगा

नई दिल्ली, एजेंसियां : अर्थशास्त्र के लिए इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह भेंट ऐसे समय में हुई है जब बनर्जी को वाम विचारधारा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अभिजीत मीडिया से रूबरू हुए तो पत्रकारों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। जाहिर है ज्यादातर सवाल सरकार की आर्थिक नीतियों पर उनके विचार को लेकर ही थे, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद कांग्रेस की न्याय योजना को लेकर उनकी खूब चर्चा हुई थी। बनर्जी ने हंसते हुए कहा कि वह मीडिया के जाल में फंसने वाले नहीं हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया है।

बनर्जी ने कहा, पीएम ने बातचीत की शुरुआत इस मजाक से की कि अब मीडिया आपको मोदी विरोधी बातों के लिए उकसाएगा। उन्होंने यह भी कहा, 'पीएम टीवी देखते हैं, उन्हें हर बात की जानकारी रहती है। वह इस समय भी टीवी देख रहे हैं। उन्हें पता है आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो।' अभिजीत ने कहा, पीएम के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने शासन और नौकरशाही

इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अभिजीत बनर्जी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एएनआइ

बनर्जी की खास बातें

- प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात अनूठा अनुभव
- प्रधानमंत्री ने नौकरशाही में सुधार के प्रयासों के बारे में बताया
- पीएम ऐसी नौकरशाही चाहते हैं जो लोगों के विचारों पर ध्यान दे
- भारत के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना बहुत आवश्यक

बनर्जी ने आयुष्मान भारत योजना की सराहना की

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की सराहना की। उन्होंने कहा, यह ऐसी योजना है जिसकी हमें बहुत जरूरत है। हमें ऐसे रास्ते तलाशने होंगे ताकि परिवार में किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर परिवार अपनी सारी संपत्ति न खो दे। इसलिए, उनका मानना है कि इस लिहाज से यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

के कामकाज में सुधार की अपनी कोशिशों के बारे में बताया। भारत के बारे में प्रधानमंत्री के सोचने का तरीका अनूठा है। प्रधानमंत्री नौकरशाही को जमीन से जुड़ा बनाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि नौकरशाही लोगों के विचारों को समझे, उन्हें ध्यान में रखे।

बनर्जी ने अर्थव्यवस्था पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बैंकों के हालात को भयावह करार दिया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव की जरूरत है। सरकार को बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को 50 फीसद से कम कर लेनी चाहिए, ताकि सीवीसी उनको नियंत्रित नहीं करे।

प्रधानमंत्री के साथ बैठक को बनर्जी ने अनोखा अनुभव बताया और उन्हें समय देने के लिए धन्यवाद कहा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बनर्जी के साथ बैठक के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी के साथ मुलाकात उत्तम रही। मानव सशक्तीकरण के प्रति उनका जुनून साफ दिखाई देता है। हमने कई मुद्दों पर स्वस्थ और व्यापक बातचीत की। भारत को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। उन्हें भविष्य की कोशिशों के लिए शुभकामनाएं।'

1050 मामले अपराध के हुए प्रति एक लाख जनसंख्या पर दिल्ली में 2017 में। वहीं, पूरे देश में इसका औसत 238 है। यह जानकारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट में दी गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 23 अक्टूबर 2019

यूरोपीय शहरों की तरह होंगी दिल्ली की सड़कें

घोषणा ▸ सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ाई जाएगी, कम से कम पांच फुट चौड़े फुटपाथ बनाए जाएंगे : केजरीवाल

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिर से बनाई जाएंगी पीडब्ल्यूडी की नौ सड़कें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अगले एक साल में दिल्ली की नौ सड़कें यूरोप के लंदन, पेरिस, बर्लिन समेत अन्य बड़े शहरों की तरह खूबसूरत दिखेंगी। यूरोप की तरह सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ाई जाएगी, कम से कम पांच फुट चौड़े फुटपाथ बनाए जाएंगे, सड़कों पर जाम और बॉटलनेक की समस्या खत्म होगी। यह योजना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर शुरू कर दी गई है। योजना के तहत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली नौ सड़कें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिर से बनाई (रिडिजाइन) जाएंगी। इन सड़कों पर दुर्घटना की आशंका भी कम रहेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस योजना पर चार साल से जद्दोजहद चल रही थी।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत पहले चरण में 45 किलोमीटर सड़क को रिडिजाइन किया जाएगा। इस पर चार सौ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे दिल्ली की सड़कें पहली बार आधुनिक डिजाइन से विकसित हो सकेंगी। सड़कों की रिडिजाइन से बॉटलनेक की समस्या खत्म होगी। अभी कोई सड़क चार लेन से तीन लेन की हो जाती है या छह लेन से चार लेन की। इससे अचानक सड़क पर एक जगह दबाव बनता है और जाम लग जाता है। नई डिजाइन में इसे खत्म किया जाएगा। इससे जाम की समस्या दूर होगी। नए तरह के फुटपाथ बनाए जाएंगे। ये कम से कम पांच फुट और अधिकतम 10 फुट चौड़े होंगे। दिव्यांगों के हिसाब से फुटपाथों को डिजाइन किया जाएगा। सड़क एक जैसी दिखेगी और दिव्यांगों को परेशानी भी नहीं होगी। गैर मोटर चालित वाहनों के लिए जगह बनाई जाएगी।

बढ़ाई जाएगी हरियाली : अभी सड़कों के किनारे हरियाली का दायरा बहुत कम है। नई योजना में फुटपाथ पर पेड़-पौधों के लिए जगह होगी। ग्रीन बेल्ट के लिए जगह होगी। ऑटो व ई-रिक्शा के लिए जगह व स्टैंड होंगे। नालें फिर से बनाए जाएंगे। सड़क की ढलान ठीक की जाएगी, जिससे कि बारिश का पानी सीधे जमीन में पहुंचे। सड़क किनारे स्ट्रीट फर्नीचर की भी व्यवस्था की जाएगी। खाली जमीन पर घास या फिर पौधे लगाए जाएंगे।

सड़कों के विकास व सुंदरीकरण को लेकर दिल्ली सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। साथ में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन व आर्किटेक्ट अंशिता जुनेजा। ध्रुव कुमार

तीन सड़कों के लिए काम का किया आवंटन

सड़कों की रिडिजाइन योजना के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने तीन सड़कों के लिए कंपनियों को कार्य आवंटित कर दिया है। अन्य छह सड़कों के लिए काम का आवंटन 15 नवंबर तक कर दिया जाएगा। इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य एक साल में पूरा कर लिया जाएगा। रिंग रोड के एम्स से आश्रम तक के भाग का कार्य आवंटन सोमवार को, जबकि विकास मार्ग के लक्ष्मी नगर से कड़कड़ी मोड़ तक के निर्माण कार्य व मदर डेयरी से पंचमहल तक के निर्माण कार्य का आवंटन मंगलवार को किया गया।

दिल्ली देश की राजधानी है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि यह अन्य देशों की राजधानी की तरह दिखे। अगर यहां की सड़कें सुंदर व जाम मुक्त होंगी तो पूरी दुनिया में भारत की छवि अच्छी बनेगी।
-अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

इन नौ सड़कों पर होगा काम

- वजीरपुर डिपो से रिठाला मेट्रो स्टेशन
- ब्रिटानिया चौक से आउटर रिंग रोड वेस्ट एंक्लेव पीतमपुरा तक
- शिवाजी मार्ग और पटेल रोड
- विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर से कड़कड़ी मोड़
- नरवाना रोड, मदर डेरी से पंचमहल
- रिंग रोड, मायापुरी से मोतीबाग जंक्शन
- रिंग रोड, एम्स से आश्रम
- आंबेडकर नगर से डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर
- रिंग रोड, निगम बोध घाट से मैगजीन रोड क्रॉसिंग

ये सुविधाएं भी होंगी

- रिक्शा के लिए पार्किंग
- गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्थान
- ग्रीन बेल्ट
- साइकिल लेन
- पैदल यात्रियों की लेन
- डिस्प्ले बोर्ड होंगे
- सड़क के बगल में पार्क है तो ऐसे व्यवस्था की जाएगी कि उसके अंदर की हरियाली सड़क से दिखे

व्यापारियों ने दी सीपी में दिवाली उत्सव के बहिष्कार की चेतावनी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कनॉट प्लेस (सीपी) में दिल्ली सरकार के दिवाली उत्सव का वहां के व्यापारियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि यह उत्सव उनके लिए काली दिवाली साबित होगा, क्योंकि चार दिन (26 से 29 अक्टूबर तक) के आयोजन में उनका कारोबार करीब-करीब ठप रहेगा। पत्रकार वार्ता में सीपी के व्यापारियों के संगठन नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने कहा कि ऐसे में हम उत्सव का बहिष्कार करने के साथ ही चार दिनों तक दुकानें बंद रखकर विरोध जताने जैसा कदम उठा सकते हैं।

अतुल भार्गव ने कहा कि कुछ माह से कारोबार ठीक नहीं चल रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले 30 से 40 फीसद की गिरावट है। यहां के व्यापारी उम्मीद कर रहे थे कि इस दिवाली पर बिक्री कर वह इस कमी को पूरा कर लेंगे, लेकिन इस आयोजन से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। उन्होंने एक बार फिर सरकार से आग्रह किया कि वह आयोजन कहीं और कर ले। चाहें तो सेंट्रल पार्क के भीतर आयोजन कर लें, लेकिन सीपी के इनर सर्कल में वाहनों के प्रवेश व पार्किंग पर प्रतिबंध न लगाया जाए। भार्गव ने कहा कि योग दिवस जैसे कुछ घंटे के आयोजनों व वाहन फ्री ट्रायल तक का उन लोगों का अनुभव बुरा था। उस दिन कारोबार में 80 से 90 फीसद तक की गिरावट आ गई थी।

एनडीटीए के उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता ने कहा कि सीपी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नहीं, बल्कि पूरी तरह से व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है। यहां 1800 से अधिक दुकानों के साथ ही 300 रेस्तरां भी हैं। बैंक व कार्यालय भी हैं। पत्रकार वार्ता में एनडीटीए के सचिव विक्रम बधवार व कोषाध्यक्ष विनय बहल समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोकथाम के लिए दिल्ली वालों के साथ सीपी में पटाखा रहित दिवाली मनाने का फैसला किया है। इसके लिए छोटी दिवाली (26 अक्टूबर) से दिवाली (27 अक्टूबर) के दो दिन बाद 29 अक्टूबर तक लेजर शो समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। फूड कोर्ट में लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया जा सकेगा। सरकार ने आग्रह किया है कि इस कार्यक्रम में दिल्ली के सभी लोग शिरकत करें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने परिवार के साथ इसमें शामिल होंगे।

पोस्टर लगाकर कर रहे हैं विरोध : कनॉट प्लेस के व्यापारी अपनी दुकानों पर पोस्टर लगाकर आयोजन का विरोध कर रहे हैं। पोस्टरों में लिखा है कि पटाखों को बैन करें न कि कार, क्या रात में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होगी, यह लेजर शो है या वोट बैंक मेला, चाट-पकौड़े के लिए पार्किंग का स्थान कैसे बंद कर सकते हैं।

न्यूज गैलरी

भाजपा ने बस टिकट पर सीएम की तस्वीर का किया विरोध

नई दिल्ली : दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए टिकट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाने के फैसले के विरोध में भाजपा विधायक मंगलवार को राजनिवास पहुंचे। उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल से इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने इसकी शिकायत लोकायुक्त से भी की है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों व पूर्व विधायकों का प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उपराज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में विधायक ओपी शर्मा व जगदीश प्रधान तथा पूर्व विधायक कपिल मिश्रा व अनिल वाजपेयी शामिल थे। भाजपा विधायकों का कहना है कि उपराज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यानपूर्वक सुनने के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। (जासं)

टिस ने पेश की दिल्ली के शेल्टर होम की सोशल ऑडिट रिपोर्ट

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टिस) के द्वारा पेश की गई सोशल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली में शेल्टर होम के संबंध में अधिकारियों को सात दिन में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। टिस की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में चलाए जा रहे 83 शेल्टर होम का दौरा किया जिनमें सिर्फ 47 फीसद शेल्टर होम उचित लाइसेंस के साथ चल रहे हैं। 25 फीसद ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है मगर अभी तक उन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा आश्रय घरों में कर्मचारियों की नियुक्ति कम थी और कई पद खाली थे। (जासं)

ई-कचरा निस्तारण की अवैध इकाइयों पर मांगा जवाब

नई दिल्ली : राजधानी और साथ लगते क्षेत्रों में चल रही ई-कचरा निस्तारण की अवैध इकाइयों पर एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी से जवाब मांगा है। एनजीटी ने एक गैर सरकारी द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर संज्ञान लिया है। सर्वेक्षण में सामने आया है कि राजधानी क्षेत्र में करीब पांच हजार अवैध इकाइयां चल रही हैं, जो नियमों को ताक पर रख ई-कचरे का निपटान कर रही हैं। एनजीटी ने पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिला के अधिकारियों के अलावा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी कहा है ऐसी इकाइयों की पहचान पर कार्रवाई रिपोर्ट एक माह में दाखिल करें। सर्वेक्षण में सामने आया है कि दिल्ली के सीलमपुर, मुस्तफाबाद के अलावा उप्र के गाजियाबाद में ई-कचरा निस्तारण की अवैध इकाइयां चल रही हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। (जासं)

हवा की तेज गति ने प्रदूषण से दी कुछ राहत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : पराली के धुएं का फीसद बढ़ने के बाद तेज हवा ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत दी है। हवा की गति बढ़ते ही मंगलवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 42 प्वाइंट नीचे आ गया।

सोमवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 249 रिकॉर्ड किया गया था। मंगलवार को यह गिरकर 207 के अंक पर पहुंच गया। हालांकि इस स्तर की हवा को भी खराब श्रेणी में रखा जाता है। ग्रेटर नोएडा का 228 और नोएडा का एयर इंडेक्स 210 दर्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों की तुलना में इसे थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है। फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 161, गाजियाबाद का 129 व गुरुग्राम का 174 दर्ज किया गया। इस स्तर की हवा को सामान्य कहा जाता है।

मौसम विभाग के मुताबिक पिछले दो दिनों से दिल्ली-एनसीआर 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। इसके चलते हवा में प्रदूषक कण ठहर नहीं पा रहे हैं। हालांकि सफर का अनुमान है कि बुधवार से हवा की रफ्तार धीमी हो जाएगी। इससे हवा प्रदूषण की मात्रा में थोड़ा इजाफा होगा। दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सीमावर्ती हिस्सों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी आई है। सफर के ही मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। मंगलवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 14 फीसद के करीब रही। बुधवार को इसके 19 फीसद हो जाने का अनुमान है।

ग्रीन पटाखे बेचने के लिए 53 कारोबारियों को मिला लाइसेंस

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

दिवाली पर ग्रीन पटाखा बेचने के लिए अब 53 कारोबारियों को अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया है। पहले केवल 11 कारोबारियों को ही तय मानदंड पर खरा उतरने के बाद लाइसेंस दिया गया था। मंगलवार को मुख्यालय में पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक की अध्यक्षता में हुई लाइसेंसिंग विभाग के अधिकारियों व अन्य आला अधिकारियों की बैठक में 42 और कारोबारियों को लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया गया। माना जा रहा है कि नियमों को थोड़ा लचीला कर इन्हें लाइसेंस दिया गया है। कुछ अन्य को भी लाइसेंस देने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में 14 कारोबारियों को पहले से ही साल भर ग्रीन पटाखा बेचने के लिए स्थायी लाइसेंस दिया जा चुका है।

बैठक में लाइसेंसिंग विभाग के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुभाशीष चौधरी समेत सभी छह रेंज के संयुक्त आयुक्त व 15 जिले के डीसीपी मौजूद थे। इसमें निर्णय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन कर सामान्य पटाखा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की नजर इलाके में पटाखा बेचने वालों पर तो रहेगी ही साथ ही ऑनलाइन वेबसाइटों पर भी रहेगी। ऑनलाइन किसी भी तरह का पटाखा बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

ग्रीन पटाखा बेचने का लाइसेंस लेने के लिए 27 सितंबर से 30 सितंबर तक आवेदन करने को कहा गया था। इसमें

बाजारों में बिकते ग्रीन पटाखे। जागरण

उक्त तिथि तक पूरी दिल्ली से 97 कारोबारियों ने अपने-अपने जिले में अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इसमें 86 कारोबारियों के आवेदन को मानदंड पूरा न कर पाने पर रद कर दिया गया था। केवल 11 कारोबारियों को ही अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया था। जिनकी दुकानें पक्की हैं उन्हें 24 दिनों व अस्थायी शेड वाले को 15 दिनों तक ग्रीन पटाखा बेचने की अनुमति दी गई थी। इससे पटाखा कारोबारियों में मायूसी थी, वहीं दिल्ली में सभी जिलों में लोगों को ग्रीन पटाखा मुहैया कराए जाने की समस्या भी खड़ी हो गई थी। इसके चलते अब नियमों में ढील देकर अन्य कारोबारियों को लाइसेंस दिया गया है।

प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई : प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए पटाखों की बिक्री पर दिल्ली पुलिस सख्त रुख अपनाएगी। कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली में दिवाली की रात पटाखे केवल दो घंटे चला सकेंगे। इस बार भी पिछले साल की तरह दिल्ली में पटाखा छोड़ने के लिए 2500 स्थानों को ही चिह्नित किया गया है। बैठक में सभी जिलों के डीसीपी से कहा गया है कि वे अपने-अपने जिले के सभी थानों के बीट अफसरों को स्थानीय लागों को जागरूक करने को कहें। नियमों का उल्लंघन न हो इसके लिए यह लोग अपने क्षेत्र के लोगों को भी जागरूक करें। वहीं जो लोग प्रतिबंधित पटाखे बेचते हुए मिलें उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए।

पिछले साल 60 से अधिक लोगों को प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बेचने के पर गिरफ्तार किया गया था। ऐसे पटाखे खरीदने व छोड़ने वालों पर भी धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

30 फीसद तक वायु प्रदूषण कम करेंगे ये पटाखे

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

इस दिवाली ग्रीन पटाखे तो मिलेंगे, लेकिन आकाश में रंग-बिरंगी रोशनी छोड़ने वाला कोई पटाखा नहीं होगा। बाजार में केवल सात प्रकार के पटाखे मिलेंगे और वह भी सीमित मात्रा में। सभी पटाखे बच्चों के उमंग उत्साह को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। रोमांच पूर्ण ग्रीन पटाखों के लिए अगली दिवाली तक का इंतजार करना होगा। जो ग्रीन पटाखे तैयार किए गए हैं, इनसे प्रदूषण में 30 फीसद तक की कमी आएगी। दिल्ली में 28 पटाखा निर्माताओं को इन्हें तैयार करने की अनुमति दी गई है। हालांकि अगली दिवाली तक ऐसे पटाखे तैयार करने पर काम चल रहा है, जिनसे 60 से 70 फीसद तक प्रदूषण में कमी लाई जा सके। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) ने करीब साल भर की मशक्कत के बाद केवल सात प्रकार के ग्रीन पटाखे तैयार किए हैं। सभी पटाखे शुरुआती स्तर वाले हैं। रॉकेट, स्काई शॉट, अनार बम एवं लड़ी बम जैसे पटाखे अभी तैयार नहीं किए जा सके हैं।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सहयोग से सीएसआइआर- नीरी ने जो सात प्रकार के पटाखे तैयार किए हैं उनमें सुतली बम, लक्ष्मी बम, अनार, फुलझड़ी, हंटर, पेंसिल और चकरी शामिल हैं। इसके अलावा ग्रीन पटाखों की सूची में अभी और कुछ नहीं है।

इस साल ग्रीन पटाखों की शुरुआत की गई है। इसीलिए इनकी वेरायटी भी कम हैं और इन्हें तैयार करने वाले पटाखा निर्माता भी। शायद इसीलिए इनकी उपलब्धता भी बहुतायत में नहीं है। लेकिन अगली दिवाली तक स्थिति और बेहतर हो जाएगी।
-डॉ. राकेश कुमार, निदेशक, सीएसआइआर-नीरी

खासियत : ग्रीन पटाखों का केमिकल फार्मूला ऐसा है जिससे पानी की बूंदें निकलती हैं। इससे प्रदूषण कम होता है और धूलकणों को यह कुछ हद तक नीचे ही दबा देती हैं। इनमें प्रदूषक तत्व नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड भी 30 से 35 फीसद तक कम होते हैं। ये पटाखे सेफ वाटर रिलीजर, सेफ मिनिमम एल्युमिनियम और सेफ थर्माइट क्रेकर की अवधारणा पर बनाए गए हैं। इन पटाखों से हानिकारक धूल और धुएं की जगह भाप और हवा निकलती है। पर्यावरण अनुकूल होने के बावजूद इन पटाखों के फूटने पर धमाका सामान्य पटाखों जैसा ही होता है जो 105 से 110 डेसिबल का होता है। मुख्य तौर पर यह ग्रीन पटाखे लाइट एंड साउंड शो के जैसे हैं।

डीयू को हरित व सुरक्षित बनाने पर काम करेगी कैंपस विकास समिति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कैंपस विकास समिति विश्वविद्यालय को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित बनाने जैसे मुद्दों पर काम करेगी। इसके अधीन एक टास्क फोर्स बनाई गई है। समिति के मीडिया कोआर्डिनेटर डॉ. रसाल सिंह ने बताया कि सोमवार को टास्क फोर्स की हुई पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी है। उसने अपना कार्यक्षेत्र भी तय कर लिया है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में अवैध पार्किंग, अवैध निर्माण, अतिक्रमण, जलभराव जैसी समस्याएं हैं। टास्क फोर्स इस दिशा में काम करते हुए परिसर के वातावरण को पठन-पाठन के लिए अनुकूल, शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाएगा। इसके लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों से सहयोग लिया जाएगा। महिलाओं और दिव्यांगों की सुरक्षा, निजता और सुविधा के लिए भी काम किया जाएगा।

डॉ. रसाल सिंह ने बताया कि टास्क फोर्स के सभी सदस्यों ने परिसर में 39 मंजिला इमारत बनने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह डीयू की पठन-पाठन संस्कृति पर सीधा हमला है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद विश्वविद्यालय में लगभग दोगुने छात्र-छात्राएं प्रवेश ले रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में कक्षाएं और छात्रावास नहीं बन सके हैं। टास्क फोर्स के सदस्यों ने सरकार से इस भूमि को प्राइवेट बिल्डर से वापस लेकर विश्वविद्यालय को सौंपने का आग्रह किया, जिससे कि इसका उपयोग पूर्वोत्तर के छात्र-छात्राओं, एससी/एसटी और दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने के लिए किया जा सके। उनका कहना है कि इस इमारत के बगल में डीआरडीओ भवन है, जहां रक्षा उपकरणों पर काम होता है। इससे उसकी सुरक्षा और गोपनीयता भी प्रभावित होगी। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर को सुरक्षित बनाने के लिए बाहरी वाहनों और लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने की जरूरत पर भी बल दिया। परिसर को सुरक्षित बनाने की कार्ययोजना पर भी बैठक में सहमति बनी। बैठक में प्रो. हंसराज सुमन, डॉ. गीता भट्ट, डॉ. संजय कुमार, सैकत घोष, डॉ. सुधांशू कुमार, डॉ. जसविंदर सिंह ने विचार व्यक्त किए। गौरतलब है कि समिति में 20 सदस्यों की टास्क फोर्स बनाई गई है, जो डीयू में सुरक्षा व्यवस्था, छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेगी।

293 करोड़ की वसूली के लिए सुपरटेक को आरसी जारी

जागरण संवाददाता, नोएडा

आम्रपाली और यूनिटेक के बाद अब देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक ग्रुप पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। करीब तीन सौ करोड़ रुपये की बकाया रकम वसूलने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को सुपरटेक के सेक्टर-74 स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या-01 पर आरसी जारी कर दी है। भूखंड पर वसूली भू-राजस्व विभाग की तर्ज पर की जाएगी। इस परियोजना में 80 फीसद निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, ऐसे 10 हजार फ्लैट का निर्माण शामिल है, जिसमें करीब 40 हजार लोग का सीधा प्रभावित होना तय माना जा रहा है।

बार-बार नोटिस के बावजूद नहीं किया बकाया जमा : नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-74 में सुपरटेक को जीएच-01 के रूप में 177960.50 वर्गमीटर जमीन का आवंटन किया गया है। इस पर एनसीआर की सबसे बड़ी हाउसिंग परियोजना का निर्माण चल रहा है, जिसके अंदर आवासीय-वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शामिल है। इस ग्रुप हाउसिंग भूखंड पर 22 से 24 मंजिला 40 टावर केपटाउन सोसायटी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसमें से 35 टावर का निर्माण पूरा कर चार हजार लोगों को पजेशन दिया जा चुका है। बाकी पांच टावरों में फिनिसिंग का काम पूरा किया जा रहा है, जिसमें अगले तीन माह में पजेशन देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी परियोजना के अंदर नॉर्थ आइ के रूप में 66 मंजिला टावर खड़ा किया जा रहा है, जिसका पजेशन 2021 में दिया जाना है। इसमें 2500 फ्लैट एलीट क्लास के लिए दो, तीन, चार बीएचके के साथ-साथ स्टूडियो अपार्टमेंट भी तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि टावर में 52 मंजिला इमारतों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा ओ, आर, बी ब्लॉक है, इसमें तीन से चार टॉवरों का निर्माण किया जाना है, जिसमें 2000 फ्लैट शामिल हैं। इसके अलावा परियोजना में सोसायटी के अंदर नर्सिंग होम, स्कूल के साथ-साथ बड़े-बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का निर्माण शामिल है, कुछ का संचालन भी शुरू हो चुका है। वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहा नोएडा प्राधिकरण अब अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए बड़े-बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटा है। अब डिफाल्टर बकायेदारों पर सीधा शिकंजा कस रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को सुपरटेक के खिलाफ आरसी जारी की गई है।

नोएडा के सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन। जागरण आर्काइव

▸ सेक्टर-74 में आवंटित किया गया था 177960.50 वर्गमीटर का ग्रुप हाउसिंग भूखंड

▸ 80 फीसद निर्माण हो चुका पूरा, 10 हजार फ्लैट के साथ यहां पर 40 हजार लोग करेंगे निवास

सुपरटेक को सेक्टर-74 में जीएच-1 177960 .50 वर्ग मीटर जमीन आवंटित किया गया। बकाया जमा नहीं करने पर बिल्डर व प्रमोटर्स को कई बार नोटिस जारी किया गया। बकाया नहीं जमा करने पर यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 की धारा-40 की उक्त भूखंड पर किस्तों के रूप में 253 करोड़ 24 लाख 65 हजार 84 रुपये का बकाया हो गया। यही नहीं 31 अक्टूबर 2019 तक समय बढ़ोतरी के एवज में 39 करोड़ 90 लाख 55 हजार 66 रुपये हो जाएगा। ऐसे में कुल 2 अरब 93 करोड़ 15 लाख 20 हजार 150 रुपये वसूलने के लिए आरसी जारी की गई। अब यह बकाया सुपरटेक की संपत्ति जब्त कर वसूल की जा सकती है।
-रितु माहेश्वरी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण

एनजीटी के कारण केपटाउन का निर्माण दो साल तक रुका रहा। उस समय प्राधिकरण और सरकार ने कहा था कि दो वर्ष का ब्याज वापस हो जाएगा, लेकिन किया नहीं गया। पिछले तीन वर्ष से दोनों से अपील कर रहे हैं, लेकिन वहां से केवल आश्वासन मिल रहा है। हमलोग इसके लिए फिर से अपील करेंगे।
-आरके अरोड़ा, चेयरमैन, सुपरटेक

योजना

दिल्ली-एनसीआर में लास्ट माइल कनेक्टिविटी बनाने के लिए डीएमआरसी ने उबर से किया करार, इसके तहत 210 मेट्रो स्टेशनों पर लगेंगे कियोस्क

मेट्रो स्टेशन पहुंचने का बेहतर विकल्प होगी कैब : मंगू सिंह

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली एनसीआर में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने कैब संचालक कंपनी उबर से करार किया है। कैब संचालक कंपनी व डीएमआरसी ने मेट्रो स्टेशनों से कैब सुविधा शुरू करने की मंगलवार को घोषणा कर दी है। इसके लिए 210 मेट्रो स्टेशनों पर कियोस्क लगाए जाएंगे।

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह ने आयोजित कार्यक्रम में बताया कि पहले चरण में चार स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 47 स्टेशनों पर जल्द ही यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने प्रदूषण व ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए लोगों को आवागमन के लिए कैब का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए मौजूदा समय में करीब 25 फीसद यात्री कैब का इस्तेमाल करते हैं।

उन्होंने कहा कि मेट्रो दिल्ली एनसीआर में प्रतिदिन पांच हजार फेरे लगाती है और करीब 60 लाख लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके बावजूद लाखों लोग परिवहन के अन्य साधनों से आवागमन करते हैं। अनेक लोग निजी कार से मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पार्किंग में पूरे दिन के लिए कार खड़ी कर आगे का सफर मेट्रो से करते हैं। हर रोज ऐसा करना व पार्किंग उपलब्ध कराना टिकाऊ व्यवस्था नहीं है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर छह-सात सालों से मंथन चल रहा था। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात निकलकर आई कि मांग के आधार (ऑन डिमांड) लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर विकल्प है।

स्टेशनों पर होगा कैब स्टैंड : मंगू सिंह ने कहा कि मेट्रो स्टेशनों से कैब की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टेंडर किया गया था। इसके तहत उबर को टेंडर आवंटित किया गया है। फिलहाल कंपनी को स्टेशनों पर कियोस्क लगाने की जगह देने की बात कही गई है। इसके अलावा उन स्टेशनों पर कैब स्टैंड होगा, जहां सीधे जाकर यात्री कैब ले सकेंगे।

मल्टी मॉडल इंटिग्रेशन का मॉडल किया गया पेश

कार्यक्रम में उबर के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) दारा खोसरोशाही व कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस कैब संचालक कंपनी के मोबाइल एप में 'पब्लिक ट्रांसपोर्ट' का विकल्प जोड़ा जाएगा।

मेट्रो के यात्री इस विकल्प का चयन कर कैब बुक कर सकते हैं। इससे कम समय में सुविधा उपलब्ध होगी और यात्री जल्द अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों ने मेट्रो स्टेशनों पर मल्टी मॉडल इंटिग्रेशन (एमएमई) का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि मेट्रो स्टेशनों पर किस तरह कैब, ऑटो, ई-स्कूटर, ई-रिक्शा के लिए अलग-अलग स्टैंड बनाकर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम को एक साथ जोड़ा जा सकता है। वहीं भविष्य में कैब कंपनी के एप से मेट्रो किराए का भुगतान करने की सुविधा भी दी जा सकती है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है लेकिन डीएमआरसी के अधिकारियों ने इस मॉडल को सराहा है।

'समानता के अधिकार का उल्लंघन है ऑड-इवेन'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : ऑड-इवेन में महिलाओं को छूट दिए जाने को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष याचिका आई तो उन्होंने इसे 1 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

अधिवक्ता शाश्वत भारद्वाज ने याचिका दायर कर कहा कि सरकार इस योजना को लिंग के आधार पर लागू करने जा रही है जोकि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसे रद किया जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली सरकार को इस संबंध में वरिष्ठ नौकरशाहों और बार के सदस्यों की समिति गठित करने के निर्देश देने की भी मांग की। समिति इस योजना की व्यावहारिकता पर अध्ययन करे कि क्या ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है जिससे किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन न हो। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को छूट दिए जाने के लिए दिया गया तर्क अस्पष्ट और गलत है। यह योजना केवल राजनीतिक लाभ के लिए लागू की जा रही है।

समेकित योजना के साथ किया जाए द्वारका उप नगरी का विकास : बैजल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया है कि द्वारका उपनगरी की सभी विकास परियोजनाओं को एक समेकित योजना के तहत लाया जाए। उन्होंने विकास परियोजनाओं के लिए रणनीति तैयार करने, इको सिस्टम के अनुरूप विकास योजना बनाने एवं खाली पड़ी भूमि के बेहतर उपयोग के लिए संबंधित एजेंसियों के विशेषज्ञ अधिकारियों की समिति बनाने का सुझाव भी दिया है।

मंगलवार को उपराज्यपाल ने बताया कि द्वारका एशिया की सबसे बड़ी उपनगरी है। मिश्रित भू उपयोग की नीति के द्वारा उपनगरी को इस प्रकार तैयार किया गया था कि यहां सभी नागरिक सुविधाएं रिहायशी कॉलोनियों के निकट उपलब्ध हों तथा पर्यावरण के अनुरूप वातावरण भी उपलब्ध हो सके।

1980 के करीब द्वारका उपनगरी को बसाने का कार्य आरंभ किया गया था, लेकिन इस सब-सिटी का महत्व संचार और परिवहन के उत्तम और सुगम साधनों की उपलब्धता की वजह से काफी बढ़ गया है। उपराज्यपाल ने आगे बताया कि द्वारका उपनगरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 90 फीसद निर्दिष्ट रिहायशी भूमि को विकसित कर लिया है, जबकि 50 फीसद व्यावसायिक भूमि का ही अभी तक विकास हो पाया है। द्वारका उपनगरी के लिए कुल 1100 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है, जिसमें मेट्रो रेल नेटवर्क, बस डिपो के साथ-साथ अन्य विकास परियोजनाओं और आधारभूत संरचना के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

इस संदर्भ में उपराज्यपाल ने पत्र के माध्यम से निर्देश दिए कि द्वारका उपनगरी में उपलब्ध सड़क और मेट्रो नेटवर्क तथा हरियाली यहां बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने डीडीए को द्वारका का ट्रांजिट ओरियंटेड डेवलपमेंट, नालों का पुनर्विकास, सड़कों का नवीनीकरण, पैदल पथ यात्रियों के लिए समेकित सड़क डिजाइनिंग का काम तेजी से करने को भी कहा।

31 अक्टूबर को सरकार 'इंद्रधनुष 2.0' नाम से नया टीकाकरण अभियान लांच करेगी। इसके तहत कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2.6 करोड़ बच्चे हर साल देश में पैदा होते हैं। इनमें से करीब 31 लाख बच्चे पहले वर्ष में लगने वाले टीके का चरण पूरा नहीं कर पाते हैं।

आइएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

दिक्कतें बरकरार ▶ मनी लांड्रिंग केस में भी जेल में होने के कारण नहीं आ पाएंगे बाहर

पूर्व केंद्रीय मंत्री को विशेष अदालत में पासपोर्ट जमा कराने का भी दिया आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पी. चिदंबरम फाइल फोटो

आइएनएक्स मीडिया केस में भ्रष्टाचार करने के आरोपी पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सशर्त जमानत दे दी। हालांकि चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लांड्रिंग केस में जेल में होने के कारण बाहर नहीं आ पाएंगे। आइएनएक्स मीडिया केस में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआइ ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और वह तभी से जेल में हैं।

जस्टिस आर. भानुमति, एस. बोपन्ना और ऋषिकेश राय की पीठ ने चिदंबरम की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी राशि के दो जमानती विशेष जज की संतुष्टि के पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अगर चिदंबरम किसी और केस में जेल में नहीं हैं तो उपरोक्त शर्तों पर उन्हें रिहा कर दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम ने अगर अपना पासपोर्ट जमा नहीं किया है तो वह विशेष अदालत में पासपोर्ट जमा कराएंगे और कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में जमानत देते हुए की गई टिप्पणियों का अन्य मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

आइएनएक्स मीडिया केस में सीबीआइ चिदंबरम, उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने 2007 में वित्त मंत्री रहते हुए आइएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ की फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआइपीबी) अनुमति दिलाई थी। सीबीआइ ने इस मामले में उनके खिलाफ आइपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है।

मामले व गवाहों को प्रभावित करने की आशंका नकारी : हाई कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर जमानत मांगी थी। सीबीआइ ने कोर्ट में चिदंबरम की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि अगर वह बाहर आए तो मामले और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने सीबीआइ की ये दलीलें खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं आई है, ऐसे में उनके द्वारा मामले को प्रभावित करने की आशंका जमानत नकारने का आधार नहीं हो सकती।

फ्लाइट रिस्क की दलील भी खारिज : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की चिदंबरम को फ्लाइट रिस्क बताने की दलील भी खारिज कर दी और कहा कि वह फ्लाइट रिस्क नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम और सहयोगी अभियुक्तों के खिलाफ 18 अक्टूबर को आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। चिदंबरम 21 अगस्त से जेल मे हैं, उन्हें करीब दो महीने जेल में हो गए हैं। वह 74 वर्ष के हैं और उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य की दिक्कतें भी हैं। कोर्ट ने कहा कि इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए चिदंबरम जमानत पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 30 सितंबर का हाई कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया जिसमें चिदंबरम को जमानत देने से हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया था।

हाई कोर्ट ने 63 मून्स कंपनी मामले में जवाब तलब

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने मंगलवार को 63 मून्स टेक्नालॉजी द्वारा दायर 10 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई के दावे वाले एक मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और दो वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा है। जस्टिस एके मेनन ने चिदंबरम और दो अधिकारियों केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक को आठ सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कंपनी, 63 मून्स टेक्नालाजीज को इससे पहले फाइनेंसियल टेक्नालाजीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। कंपनी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम तथा दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 12 जून को मामला दायर किया था। कंपनी ने इनके खिलाफ 'दुर्भावनापूर्ण और बदनीयती' से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। कंपनी ने कहा है कि चिंदबरम के वित्त मंत्री रहते 5,600 करोड़ रुपये के एनएसइएल घोटाले में उसके खिलाफ बदनीयती से कार्रवाई की गई। जिस समय का यह मामला है तब केपी कृष्णन कौशल विकास मंत्रालय में सचिव के पद पर थे तो रमेश अभिषेक वायदा बाजार आयोग के चेयरमैन थे। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा है कि उसकी एक इकाई नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसइएल) में सोची समझी रणनीति के तहत भुगतान संकट खड़ा किया गया और उसके बाद से उसके खिलाफ उसे लक्ष्य बनाकर लगातार दुर्भावनापूर्ण ढंग से कार्रवाई की गई। दायर मामले में कहा गया है कि विभिन्न जांच एजेंसियों की जांच में एनएसइएल, 63 मून्स और कंपनी के संस्थापक जिग्नेश शाह द्वारा धन के हेरफेर का कोई मामला साबित नहीं हो पाया। लेकिन चिदंबरम, कृष्णन और अभिषेक द्वारा रची गई साजिश के तहत समूह को लगातार निशाना बनाया गया। कंपनी ने अपनी याचिका में इन लोगों से 10,000 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई की मांग की है।

कंपनी ने 10 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई का दावा दायर किया है

मेहुल चोकसी के खिलाफ सीबीआइ मामले में दो नई अर्जी दाखिल

मेहुल चोकसी फाइल फोटो

मुंबई, एएनआइ : मुंबई में विशेष सीबीआइ अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला के संबंध में दाखिल कराई गई दो नई अर्जियों पर सीबीआइ को नोटिस जारी किया है। पीएनबी घोटाला मामले में मेहुल चोकसी मुख्य आरोपित है।

गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी 13500 करोड़ के पीएनबी जालसाजी मामले में आरोपित हैं। एक साल पहले ही चोकसी देश से भाग निकला और 15 जनवरी 2018 में उसने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली। सीबीआइ ने इससे पहले कोर्ट से चोकसी को भगोड़ा घोषित करने और उसकी संपत्ति जब्त करने का आग्रह किया था।

पहली अर्जी वकील विजय अग्रवाल और अंशुल अग्रवाल ने दायर की है। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके मुवक्किल मेहुल चोकसी का पक्ष सुने बगैर इस तरह की घोषणा प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा। दोनों वकीलों ने चोकसी के खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट निरस्त करने की मांग भी की है। यह वारंट अभी लंबित है। दोनों वकीलों ने कहा है कि जबतक उनका पक्ष नहीं सुना जाता और निस्तारण हो जाता है तबतक उन्हें भगोड़ा घोषित नहीं किया जाए। दूसरी अर्जी एएस नायर ने दाखिल की की है। उन्होंने सीबीआइ द्वारा जब्त गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के सर्वर में स्टोर डाटा की प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की है। अर्जी में कहा गया है कि जब्त की गई सामग्री को रिकार्ड पर पेश करना सीबीआइ की जवाबदेही है। इसका कारण यह है कि बचाव के लिए मामला तैयार करने में यह महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर तय की है।

मनी लांड्रिंग केस में इकबाल मिर्ची का साथी हुमायूं मर्चेंट और महिला गिरफ्तार

मुंबई, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची के साथी हुमायूं मर्चेंट और एक महिला को गिरफ्तार किया है। मिर्ची के रियल एस्टेट कारोबार को मर्चेंट ही संभालता था। मिर्ची के परिवार की जमीन से जुड़े इसी मामले में ईडी ने राकांपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ की थी।

अधिकारियों ने बताया कि हुमायूं को मनी लांड्रिंग मामले में सोमवार रात गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को विशेष अदालत ने मर्चेंट को 24 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। वहीं, बेंगलुरु की रहने वाली 45 वर्षीय रिंकू देशपांडे को जांच में सहयोग नहीं करने पर मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। रिंकू ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए इकबाल मिर्ची की एक प्रॉपर्टी में खुद को किराएदार दिखाया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि मर्चेंट ने मुंबई के वर्ली इलाके में सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट की तीन इमारतों सी व्यू, मरियम लॉज और राबिया मैंशन को हड़पने के लिए फर्जी किराएदारों को पैदा किया। ईडी प्रफुल्ल पटेल द्वारा प्रमोटेड कंपनी सनब्लिंक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मर्चेंट के संबंधों की भी जांच कर रही है।

ईडी के मुताबिक मर्चेंट ने लंदन में इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची और स्थानीय रियल एस्टेट कंपनी जॉय होम क्रीएशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर के बीच मीटिंग कराई थी। इस बैठक में इन तीनों इमारतों की जगह पर नई बिल्डिंग बनाने और कुछ समय के लिए इनके किराएदारी अधिकार को जॉय होम के नाम ट्रांसफर करने का फैसला हुआ। बताया जा रहा है कि इस सौदे में हुमायूं मर्चेंट को 170 करोड़ रुपये मिले थे। ईडी के मुताबिक यह धन अवैध था और इसे मनी लांड्रिंग के जरिए बाहर भेज दिया गया। इसी मामले में ईडी ने इस महीने के शुरू में मिर्ची के अन्य सहयोगियों हारून युसूफ और रंजीत सिंह बिंद्रा को गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर सौदा कराने में सहयोग देने का आरोप है।

हुमायूं ने दाऊद के साथी की तीन इमारतों का कराया था सौदा

प्रफुल्ल पटेल की कंपनी के साथ संबंधों की भी जांच जारी

प्रतीकात्मक

खास बातें

- मिर्ची की इमारतों के लिए फर्जी किराएदार पैदा किए
- स्थानीय रियल एस्टेट कंपनी के मालिक और मिर्ची की मीटिंग कराई
- इसी मामले में ईडी ने पिछले हफ्ते राकांपा नेता पटेल से की थी पूछताछ
- मिर्ची के दो अन्य सहयोगी को भी ईडी ने किया है गिरफ्तार

पंकज कुमार होंगे यूआइडीएआइ के नए प्रमुख

नई दिल्ली, आइएएनएस: एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में केंद्र ने मंगलवार को 10 आइएएस अधिकारियों को स्थानांतरित और पदोन्नत किया है। 13 अन्य अधिकारियों को विशेष सचिव के पद पर अपग्रेड किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा दी गई मंजूरी के मुताबिक ब्रजराज शर्मा को जहां कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) का चेयरमैन बनाया गया है वहीं पंकज कुमार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग में बतौर सचिव के तौर पर काम कर रहे 1984 बैच के जम्मू-कश्मीर कैडर के आइएएस अधिकारी ब्रजराज शर्मा को एसएससी का चेयरमैन बनाया गया है। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार यूआइडीएआइ के सीईओ बनाए गए हैं। कुमार को अस्थायी तौर पर इस पद पर अपग्रेड किया गया है। उनका पद और वेतन सचिव के बराबर होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के चेयरमैन और 1987 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी नागेंद्र नाथ सिन्हा को गृह मंत्रालय के तहत आने वाले सीमा प्रबंधन विभाग के सचिव का प्रभार दिया गया है। अंतर-राज्य परिषद सचिवालय में विशेष सचिव और 1985 बैच के आइएएस अधिकारी संजीव गुप्ता को सचिव सचिवालय के पद पर पदोन्नत किया गया है।

संजीव नंदन सहाय होंगे नए ऊर्जा सचिव : वरिष्ठ आइएएस अधिकारी संजीव नंदन सहाय को मंगलवार को सुभाष चंद्र गर्ग की जगह नया ऊर्जा सचिव नियुक्त किया गया। सहाय इसी मंत्रालय में विशेष सचिव हैं। बता दें कि वित्त सचिव के पद से हटाए जाने के बाद गर्ग ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी। इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले गर्ग फिलहाल तीन महीने की नोटिस अवधि पर चल रहे हैं।

अशोक मलिक विदेश मंत्रालय में बने सलाहकार : राष्ट्रपति के पूर्व प्रेस सचिव अशोक मलिक को विदेश मंत्रालय में नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनके वेतन और भत्ते अतिरिक्त सचिव रैंक के बराबर होंगे। उनका कार्यकाल दो साल का होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रतिष्ठित फेलो मलिक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मलिक दो सालों तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रेस सचिव रहे थे। उनका कार्यकाल इसी साल शुरुआत में समाप्त हुआ थ।

ब्रजराज शर्मा होंगे एसएससी के नए चेयरमैन, केंद्र ने 10 आइएएस अफसरों को स्थानांतरित और पदोन्नत किया

पंकज कुमार फाइल फोटो

कांग्रेस गलत परंपरा डाल रही : मायावती

प्रथम पृष्ठ से आगे

वरिष्ठ नेताओं से बदसुलूकी पर बसपा सुप्रीमो मायावती कांग्रेस पर भड़क गईं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस ने पहले राजस्थान में बसपा विधायकों को तोड़ा और अब आंबेडकरवादी मूवमेंट को आघात पहुंचाने के लिए वरिष्ठ लोगों पर हमले करा रही है। उन्होंने घटना को अति निंदनीय और शर्मनाक बताते हुए कहा कि कांग्रेस गलत परंपरा डाल रही है, जिसका लोग जैसे को तैसा जवाब दे सकते हैं।

पिछले माह ही हुई थी पदाधिकारियों की पिटाई : पिछले माह बसपा के छह विधायक राजेंद्र गुढ़ा, जोगेंद्र सिंह अवाना, वाजिब अली, संदीप यादव, दीपचंद खेरिया और लाखन सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद हुई बसपा की बैठक में भी रामजी गौतम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा, आदि के साथ मारपीट की गई थी। बाद में भगवान सिंह बाबा ने आठ पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि मंगलवार को दूसरी घटना हो गई।

निर्वाणी अखाड़ा को मिली वैकल्पिक राहत का नोट दाखिल करने की अनुमति

नई दिल्ली, प्रेट्र : अयोध्या राम जन्मभूमि मामले के हिंदू पक्षकारों में से एक निर्वाणी अखाड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ यानी वैकल्पिक राहत का लिखित नोट दाखिल करने की अनुमति दे दी ताकि वह सेवायत के तौर पर भगवान की पूजा का प्रबंधन करने के अधिकार की मांग कर सके।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एसए नजीर की पीठ के समक्ष निर्वाणी अखाड़ा के वकील जयदीप गुप्ता ने मामले का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर लिखित नोट दाखिल करने के लिए दिए गए तीन दिन के समय की गलत गणना कर ली थी। लिहाजा अब वह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में उसे दाखिल करने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं। इस पर पीठ ने उन्हें मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर लिखित नोट दाखिल करने की अनुमति प्रदान कर दी। बता दें कि निर्मोही अखाड़ा और उसके प्रतिद्वंद्वी निर्वाणी अखाड़ा दोनों भगवान राम के जन्मस्थान पर पूजा का प्रबंधन करने के अधिकार की मांग कर रहे हैं।

निर्मोही अखाड़ा ने सेवायत के अधिकार की मांग करते हुए 1959 में मुकदमा दायर किया था। जबकि निर्वाणी अखाड़ा को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और भगवान राम लला द्वारा देवकी नंदन अग्रवाल के जरिये क्रमशः 1961 और 1989 में दायर दो अलग-अलग मुकदमों में पक्षकार (प्रतिवादी) बनाया गया है। लिखित नोट में कहा गया है, 'उपरोक्त मुकदमों में किसी भी पक्षकार (हिंदुओं में से) ने सेवायत के अधिकार के लिए दावा नहीं किया है। या तो उन्होंने स्वामित्व का दावा किया है या भगवान के मित्र के तौर पर विवादित ढांचे के स्थान पर मंदिर बनाने की मांग की है। इसलिए वर्तमान प्रतिवादी (निर्वाणी अखाड़ा) के पुजारी और/अथवा सेवायत के अधिकार को कोई चुनौती नहीं है।' सुनवाई के दौरान भी निर्वाणी अखाड़ा का कहना था कि उसके महंत अभिराम दास (अब दिवंगत) 1949 में विवादित स्थल के पुजारी थे। इसके अलावा 22-23 दिसंबर, 1949 की रात को विवादित स्थल की केंद्रीय गुंबद के नीचे मूर्तियां रखने के लिए दर्ज कराई गई एफआइआर में भी उन्हें एक आरोपित बनाया गया था। अब उनके चेला धरम दास पुजारी हैं।

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने दी रजिस्ट्री में दाखिल करने की इजाजत

160 किमी की गति से ट्रेन चलाने को 18000 करोड़ की परियोजना

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता व्यस्त रूट पर ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने के लिए रेलवे 18000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू करेगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने मंगलवार को कहा कि बुनियादी ढांचा को अपग्रेड किया जाएगा।

परियोजना शुरू होने के बाद इसके पूरा होने में कम से कम चार वर्ष लगेंगे। यादव ने इंटरनेशनल रेल कांफ्रेंस-2019 और 13वीं अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद यह कहा। एयरोसिटी में सीआइआइ ने रेलवे के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।

दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता रूटों पर रेलवे का लक्ष्य दो श्रेणियों की हाई स्पीड ट्रेन चलाना है। इसके अलावा मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक से ट्रेन चलाना है। वर्तमान में विभिन्न रूटों पर ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 99 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाल ही में शुरू की गई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली-कानपुर के बीच औसत 104 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचती है।

रेल मंत्रालय के मुताबिक, 160 किलोमीटर प्रति घंटा पर ट्रेन चलाने के लिए उन्नत बुनियादी ढांचा में तारबंदी, ट्रैक उन्नत करना और सिंगनलिंग और मानव रहित क्रासिंग खत्म करना शामिल है। यादव ने कहा कि रेलवे बदलाव के मोड में है और यह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है। उन्होंने आगे कहा कि इसके तहत अगले तीन वर्षों में 68000 किलोमीटर ब्राड-गेज ट्रैक नेटवर्क को विद्युतीकृत किया जाएगा। वर्तमान में 28000 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है और अगले साल के लिए 7000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है।

मोदी के 'भारत की लक्ष्मी' अभियान की ध्वजवाहक होंगी दीपिका और पीवी सिंधू

मुंबई, प्रेट्र : फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'भारत की लक्ष्मी' अभियान का प्रतिनिधित्व करेंगी। दीपिका और सिंधू ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो को भी शेयर किया है। वीडियो में इन दोनों आइकन को इस पहल के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि इस अभियान का उद्देश्य देशभर में महिलाओं द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को प्रकाश में लाना है।

महिला सशक्तीकरण के कारणों को रेखांकित करते हुए नए अभियान पर एक वीडियो साझा करने के साथ ही पीएम ने ट्विटर पर लिखा कि भारत की नारी शक्ति प्रतिभा और तप, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। 'हमारे लोकाचार ने हमें हमेशा महिला सशक्तीकरण के लिए प्रयास करना सिखाया है।' 'इस वीडियो के माध्यम से सिंधू और दीपिका ने 'भारत की लक्ष्मी' का जश्न मनाने का संदेश दिया है।' दीपिका और सिंधू ने ट्विटर पर अभियान के लिए समर्थन जाहिर किया। दीपिका ने वीडियो को साझा करते हुए लिखा, 'इस दिवाली हम अपने देश की महिलाओं के योगदान और उपलब्धियों का जश्न मनाएं।' वहीं सिंधू ने कहा, कोई भी समाज तब बढ़ता है जब महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है और उनकी उपलब्धियों से गर्व की अनुभूति होती है। 'मैं पीएम के 'भारत की लक्ष्मी' अभियान का समर्थन करती हूं। यह भारत की असाधारण महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाता है। आइए इस दिवाली नारीत्व का जश्न मनाएं।'

पीएम ने ट्विटर पर लिखा, भारत की नारी शक्ति प्रतिभा, तप, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रतीक

दीपिका पादुकोण

पीवी सिंधु (फाइल फोटो)

मेघना गुलजार की 'छपाक' में दिखाई देंगी दीपिका

दीपिका जल्द ही मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म 'छपाक' में दिखाई देंगी। यह फिल्म एसिड अटैक की शिकार हुई लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है। लक्ष्मी स्वयं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं। वह अपने पति रणवीर सिंह के साथ कबीर खान द्वारा बनाई गई फिल्म '83' में भी दिखाई देंगी। 1983 के क्रिकेट विश्वकप पर आधारित इस फिल्म में रणवीर ने कपिल देव की भूमिका निभाई है। दीपिका ने कपिल की पत्नी रोमी की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्माण रिलायंस एंटरटेनमेंट, फैंटम फिल्म्स और नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा किया जा रहा है।

केंद्र ने कर्मचारियों के लिए तोहफा नीति में दी छूट, राशि सीमा बढ़ाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए तोहफा नीति में छूट की घोषणा की है। उसने तोहफा स्वीकार किए जाने की राशि को तीन गुना बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को संशोधित नियमों का हवाला देते हुए बताया कि समूह 'अ' और 'ब' के अधिकारी बिना सरकार की मंजूरी के 5,000 रुपये से अधिक का तोहफा स्वीकार नहीं करेंगे। पहले अधिकतम सीमा 1,500 रुपये थी। इसी तरह समूह 'स' के कर्मचारी 2,000 रुपये तक के उपहार स्वीकार कर सकते हैं, जो पहले यह सीमा 500 रुपये थी। समूह 'अ' में वरिष्ठ अधिकारी, जबकि समूह 'ब' में राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी आते हैं। समूह 'स' में ज्यादातर क्लर्क व बहुदेश्यीय कर्मचारी आते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि उपहार स्वीकार करने की सीमा में यह संशोधन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय डाक सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए तय सीमा में एकरूपता की दृष्टि से किया गया है। उपहार में मुफ्त परिवहन, बोर्डिंग, लॉजिंग व अन्य लाभ शामिल हैं। ये करीबी रिश्तेदार या निजी दोस्त के अलावा किसी अन्य की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं। सामान्य भोजन, लिफ्ट या सामाजिक आतिथ्य उपहार की श्रेणी में नहीं आएंगे। सरकार ने विदेशी अतिथियों से उपहार स्वीकार करने व रखने की 1000 रुपये की सीमा को भी खत्म कर दिया है।

कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 'विदेश अंशदान (उपहार को स्वीकार करना या रखना या दान) नियम-2012 के प्रावधान में समय-समय पर हुए संशोधनों के मुताबिक एक सरकारी सेवक जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य है या अन्य, विदेशी विशिष्ट लोगों से उपहार स्वीकार कर और रख सकता है।'

तोहफा स्वीकार करने की सीमा में की गई तीन गुना बढ़ोतरी

बेरुखी

नशे के खिलाफ निर्णायक जंग को लेकर केंद्र सरकार बहुत उत्साहित है, लेकिन उसे राज्य सरकारों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है, राष्ट्रीय कार्ययोजना के साथ ही राज्यों को तुरंत काम शुरू करने के लिए दिए जा चुके हैं पैसे

नशा विरोधी मुहिम में राज्यों का ढुलमुल रवैया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

186 जिलों में कराया गया था सर्वे, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे

28 करोड़ से ज्यादा लोग सर्वेक्षण में किसी न किसी तरह से नशे में लिप्त पाए गए

57 करोड़ रुपये दिए हैं केंद्र ने राज्यों को अभियान चलाने के लिए

प्रतीकात्मक फोटो

नशे के खिलाफ निर्णायक जंग को लेकर केंद्र भले ही उत्साहित है, लेकिन राज्यों का रवैया अब भी ढुलमुल बना हुआ है। यह स्थिति तब है, जब राज्यों को पैसे और प्लान दोनों दिए जा चुके हैं। तमिलनाडु को छोड़ दें तो किसी भी राज्य ने अब तक नशे के खिलाफ मुहिम में कुछ भी नहीं किया है। बिहार, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे कुछ राज्यों ने तो अब तक प्रस्ताव ही तैयार नहीं किए हैं। केंद्र ने राज्यों के इस रवैये को लेकर भारी नाखुशी जताई है।

हाल ही में राज्यों के साथ मिलकर नशे के खिलाफ छिड़ी मुहिम की समीक्षा की गई। इस दौरान एक-एक राज्य से जानकारी ली गई, तो पता चला कि किसी भी राज्य ने अब तक कुछ किया ही नहीं है। उनका यह रवैया तब है, जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ज्यादातर राज्यों को मौजूदा वित्तीय वर्ष में दो-दो किस्तें जारी कर चुका है। इसके तहत अब तक करीब 57 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। हालांकि, सूत्रों की मानें तो राज्यों की प्राथमिकता में अभी तक यह मुहिम शामिल ही नहीं हो पाई है।

एम्स के सर्वे में आए थे चौंकाने वाले नतीजे : केंद्र ने नशे के खिलाफ अपनी इस मुहिम को तेज करने का फैसला दिसंबर 2018 में तब लिया था, जब देश के 186 जिलों में कराए गए सैंपल सर्वे के बाद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। इस सैंपल सर्वे में 28 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से नशे में लिप्त पाए गए। छह करोड़ लोग तो ऐसे थे जो गंभीर रूप से नशे की गिरफ्त में पाए गए। ऐसे लोगों की संख्या अकेले उत्तर प्रदेश में 1.60 करोड़ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की मदद से कराए गए इस सर्वे में नशे के खिलाफ तुरंत जरूरी कदम उठाने की सिफारिश की गई है। इनमें जागरूकता के साथ-साथ नशे की गिरफ्त में गंभीर रूप से फंसे लोगों का तुरंत इलाज कराना शामिल है।

पंजाब और हरियाणा को दी गई सबसे ज्यादा मदद

नशे के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम में केंद्र का सबसे ज्यादा ध्यान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के राज्यों पर है। इन राज्यों को तुरंत ही काम शुरू करने के लिए कहा गया था। इसके लिए राज्यों को जारी 57 करोड़ रुपये की मदद में सबसे ज्यादा करीब 11 करोड़ रुपये अकेले पंजाब को दिए गए हैं। करीब साढ़े छह करोड़ रुपये हरियाणा और सवा दो करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। बिहार के लिए भी सवा दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन प्रस्ताव न मिलने के चलते उसे सिर्फ 1.12 करोड़ रुपये की पहली किस्त ही दी गई है।

विमानन सुरक्षा नियामक एक सप्ताह में जारी करेगा ड्रोन रोधी नियम

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में किसी भी अवांछित ड्रोन से निपटने के लिए विमानन सुरक्षा नियामक बीसीएएस एक सप्ताह में ड्रोन रोधी नियम जारी करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) में उप महानिदेशक महेश्वर दयाल ने कहा, 'ड्रोन निरोध के लिए हम हफ्तेभर से भी कम वक्त में दिशा-निर्देश जारी करेंगे। यह अंतिम चरणों में है। मेरे विचार से यह सुरक्षित आकाश की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।' महेश्वर दयाल उद्योग संगठन फिक्की और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी थेल्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'स्मार्ट सेफ सिक्योर स्काइज' को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि एक अगस्त को बीसीएएस के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने कहा था कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में संभावित ड्रोन हमलों के खिलाफ नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के लिए नीति बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

2009 में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्रमश : 59.6 और 72.3 फीसद मतदान हुआ था, जबकि 2014 में क्रमश : 63.3 और 76.6 फीसद मत पड़े थे। इस बार हरियाणा में 69 तो महाराष्ट्र में 60.46 फीसद लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 23 अक्टूबर 2019

चुनाव नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने हरियाणा में भंग किया संगठन

बड़ा कदम ▶ सैलजा ने तंवर के कार्यकाल में गठित सभी प्रकोष्ठ रद किए

कई पदाधिकारियों की छुट्टी 18 बागी भी पार्टी से निकाले

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने संगठन के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर के कार्यकाल में हुई सभी नियुक्तियों को रद करते हुए सभी मोर्चों को भंग कर दिया गया है। 18 बागियों को पार्टी से निकाल दिया गया है। जल्द ही नए सिरे से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद संगठन में पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

चंडीगढ़ में मंगलवार को पत्रकारों से रूबरू हुईं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य कुमारी सैलजा ने कहा कि अब केवल वही नियुक्तियां मान्य हैं, जो चुनाव के दौरान आपात स्थिति में उन्होंने की थीं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चलने वाले 18 नेताओं को छह साल के लिए बाहर किया जा चुका है।

हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा (सबसे दाएं) चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करती हुईं। जागरण

अशोक तंवर के इस्तीफे पर हाईकमान द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने संबंधी सवालों को कुमारी सैलजा ने टाल दिया। गौरतलब है कि अशोक तंवर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जननायक जनता पार्टी के साथ मंच साझा करते रहे। इसके बावजूद पार्टी ने यह साफ नहीं किया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जा चुका है अथवा नहीं। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई और कालका प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने भी अपनी बात रखी।

पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा, ईवीएम पर उठाए सवाल

सैलजा ने सभी एग्जिट पोल को खारिज करते हुए अपने दम पर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया है। गठबंधन की संभावना को खारिज करते हुए उन्होंने ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान धारा 370 और पुलवामा जैसे राष्ट्रीय मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया है। दरअसल, प्रदेश भाजपा को पिछले पांच वर्ष के दौरान कराए गए कार्यों तथा हरियाणा की जनता पर भरोसा नहीं था। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में लेकर रखी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रचार के दौरान हरियाणा के मुद्दों को उठाया। भाजपा के एक भी नेता ने इन मुद्दों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने 45 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतने का दावा किया।

दिग्गजों की सीटों पर फंसा पेच चौंकाने वाले हो सकते हैं नतीजे

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

इस बार हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव बड़े मुद्दों के बिना लड़ा गया। भाजपा ने जहां राष्ट्रीयता के मुद्दे पर जनसमर्थन हासिल करने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस ने भाजपा की पांच साल की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। करीब 11 माह पहले अस्तित्व में आई जननायक जनता पार्टी ने भाजपा अथवा कांग्रेस को छेड़ने के बजाय अपनी खुद की पार्टी के एजेंडे पर चुनाव लड़ा। इस बार दिग्गजों की सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिसके चलते नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं।

प्रदेश के 1169 उम्मीदवारों की किस्मत अब इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में बंद हो गई। 24 अक्टूबर को सभी की किस्मत का फैसला हो जाएगा, लेकिन विभिन्न सर्वे और एक्जिट पोल भाजपा की एकतरफा सरकार बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। भाजपा इससे काफी हद तक सहमत है, जबकि कांग्रेस, इनेलो और जजपा ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। एक्जिट पोल के नतीजों को यदि नजर अंदाज भी कर दिया जाए तो विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले होंगी। हरियाणा के चुनावी रण में भाजपा ने 75 से अधिक विधानसभा सीटें जीतने का

69 प्रतिशत तक पहुंचे मतदान ने हरियाणा में बढ़ाया नेताओं का हौसला

लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। भाजपा भले ही इस लक्ष्य को हासिल न कर पाए, लेकिन इसके आसपास रहकर बिना किसी बाहरी सहयोग के सरकार बनाने की स्थिति में है। अलबत्ता, भाजपा के कई दिग्गजों की सीटें फंसी हुई नजर आ रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की टोहाना में सीट फंसी हुई मानी जा रही है। बादली में कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ और नारनौंद में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, आदमपुर में सोनाली फौगाट, महेंद्रगढ़ में शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा, शाहबाद में राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और इसराना में परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार की सीट पर कांटे का मुकाबला है। मतदान प्रतिशत बढ़ने के बाद इनमें से कुछ सीटों पर स्थिति भाजपा के पक्ष में बदली हुई नजर आ सकती है और कुछ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि, जिस तरह से मतदान का प्रतिशत 61 से बढ़कर 69 तक पहुंच गया, उसके मद्देनजर भाजपा की फंसी हुई सीटों के निकलने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

कांग्रेस दिग्गजों की मुश्किलें भी कम नहीं : कांग्रेस में कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला, रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव और तोशाम में किरण चौधरी का चुनाव फंसा हुआ है। यहां चुनाव नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। थानेसर में इनेलो छोड़कर कांग्रेस में आए अशोक अरोड़ा व भाजपा के सुभाष सुधा के बीच कांटे की टक्कर है। गन्नौर में कांग्रेस के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा चुनावी आकलन बदल सकते हैं।

जजपा कई सीटों पर दे रही है टक्कर : उचाना में जजपा संयोजक दुष्यंत सिंह चौटाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता की भाजपा के उम्मीदवार से टक्कर है। इस सीट का नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। करीब दो दर्जन सीटें ऐसी हैं, जहां दुष्यंत चौटाला की पार्टी के उम्मीदवार कड़े मुकाबले में हैं। जजपा इस बार के चुनाव में खुद को स्थापित करने में कामयाब रहने वाली है।

क्षेत्रीय दलों के दिग्गजों पर भी नजर : इनेलो विधायक दल के नेता रहे अभय सिंह चौटाला की ऐलनाबाद में भाजपा के पवन बैनीवाल से टक्कर है। यहां का रिजल्ट काफी चौंकाने वाला हो सकता है। सिरसा में हलोपा अध्यक्ष गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि गोहाना में पूर्व सांसद राजकुमार सैनी अपनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं।

मतगणना से पहले नड्डा ने भाजपा महासचिवों के साथ बैठक की

नई दिल्ली, एएनआइ : हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू होने से पहले भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की। बैठक में दोनों राज्यों की राजनीतिक स्थिति पर विचार किया गया। मंगलवार को हुई बैठक में राम माधव, भूपेंद्र यादव, सरोज पांडे, अनिल जैन और अरुण सिंह एवं अन्य मौजूद थे।

हरियाणा में भाजपा की सत्ता में वापसी और हरियाणा में भाजपा की अगुआई में राजग सरकार के बनने की संभावनाओं के बीच यह बैठक हुई है। नड्डा ने पार्टी के कार्यक्रमों और सांगठनिक चुनावों पर भी निगाह डाली। अभी तक इस बैठक के बारे में पार्टी की ओर से कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है।

दिल्ली में ताल ठोकने की तैयारी में जदयू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अगले साल होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में जदयू भी अपना दावा ठोकने की तैयारी में जुट गया है। बुधवार को दिल्ली के बदरपुर में सदस्य प्रशिक्षण शिविर में जदयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका संकेत देंगे। बैठक में बिहार के जल संसाधन मंत्री और दिल्ली के प्रभारी संजय झा भी मौजूद होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की ओर से स्पष्ट किया गया था कि बिहार विधानसभा में नीतीश ही राजग का चेहरा होंगे। उसके साथ ही वहां अटकलों को विराम लग गया है, लेकिन जदयू खुद के विस्तार के लिए भी प्रयासरत है। दिल्ली में जदयू को कुछ संभावनाएं दिखती हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यहां बिहार के लोग हैं। यह अड़चन जरूर है कि दिल्ली में राजग नहीं है और अगर ऐसे में जदयू दावेदारी ठोकता है तो भाजपा के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल जदयू अपनी शक्ति परखेगी और उसी के आधार पर विधानसभा में भाजपा से तालमेल बिठाने की कोशिश हो सकती है। बहरहाल, माना जा रहा है कि बुधवार को होने वाले प्रशिक्षण शिविर में नीतीश सरकार में विकास और बिहारी अस्मिता का उदाहरण देकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला जाएगा। खासकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान को निशाना बनाया जाएगा, जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों के पांच सौ रुपये लेकर आने और पांच लाख का इलाज कराकर वापस जाने की बात कही थी।

हरियाणा में पांच बूथों पर आज दोबारा मतदान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

शाहबाद में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को बदलने के मामले में आयोग ने स्पष्ट की स्थिति

हरियाणा में पांच विधानसभा क्षेत्रों के पांच बूथों पर बुधवार को दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह सात बजे से शुरू होकर शाम छह बजे तक चलेगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि जींद जिले में उचाना कलां विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर- 71 पर दोबारा मतदान होगा। यहां कल विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। झज्जर में बेरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर- 161, जिला नारनौल में नारनौल विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर- 28, जिला रेवाड़ी में कोसली विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर-18 और जिला फरीदाबाद में पृथला विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर-113 पर बुधवार को पुनर्मतदान होगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है।

दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शाहबाद में वायरल एक वीडियो के बारे में स्थिति साफ की है। इस वीडियो में जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों ने शाहबाद के सहायक रिटर्निंग अधिकारी और अन्य स्टाफ पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को बदलने का आरोप लगाए थे।

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने मौके पर अन्य पदाधिकारियों को जाकर मामले को शांत करवाने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उपयोग में नहीं लाई गई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक अलग स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और शाहबाद के एआरओ उन्हीं खराब ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को अलग स्ट्रांग रूम में रखने जा रहे थे। रास्ते में जेजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने एआरओ की अधिकारिक गाड़ी को रोका और मशीनों को बदलने का आरोप लगाने लगे। बाद में मामले को शांत करवाया गया और उन्हें आयोग के निर्देशों के बारे में विस्तार से समझाया गया। बाद में इस मामले में जेजेपी प्रत्याशी ने स्वयं बयान दिया है कि उनके कार्यकर्ताओं व समथर्कों को गलतफहमी हो गई थी।

गांधी की हत्या के षड्यंत्रकारी थे सावरकर : बघेल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, भारत रत्न देना है तो गणेश शंकर विद्यार्थी को दिया जाए

जागरण संवाददाता, कानपुर

वीर सावरकर को भारत रत्न देने की तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भारत रत्न देना है तो आजादी के लिए लड़ने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी को दिया जाए। मंगलवार को कानपुर में आयोजित गणेश शंकर विद्यार्थी जयंती समारोह में बघेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे सावरकर से प्रभावित थे। सावरकर गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल थे। साक्ष्य के अभाव में बरी होने से वह निरपराध नहीं हो गए। उन्होंने भाजपा के गांधी प्रेम और राष्ट्रवाद पर भी सवाल उठाया। कहा, भाजपा गांधी को मानती है तो गोडसे की निंदा करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी का भारत अहिंसा का भारत है। हमारे पारंपरिक राष्ट्रवाद में असहमति को पूरा स्थान मिलता था। गणेश शंकर विद्यार्थी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे थे, जबकि क्रांतिकारी भगत सिंह वामपंथी थे। बावजूद इसके उन्होंने भगत सिंह को दो महीने अपने घर पर रखा। यह असहमति का सम्मान है जो फिलहाल खत्म हो गया है।

किदवईनगर में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के समारोह में बघेल ने कहा कि देश में चुनाव भावनात्मक व आर्थिक रूप से होता है। जो मालदार हैं उनके आगे-पीछे लोग घूमते हैं। राजनीति आपके घर के चूल्हे व रहन-सहन तक पर असर डालती है। यह तक तय करती है कि आपके घर पर कौन सी सब्जी बनेगी। भावनाओं में बहने के बजाय मुद्दों पर जनप्रतिनिधि का चुनाव करना होगा। अपने संबोधन में बघेल ने कहा कि देश में मंदी के हालात हैं लेकिन छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जहां विकास दर तेजी से बढ़ रही है। ऑटो मोबाइल सेक्टर में गिरावट है लेकिन उनके राज्य में 13 फीसद बढ़ोतरी हुई है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के जयंती समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जागरण

सेना के नाम पर हो रही राजनीति

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले गुलाम कश्मीर में सैन्य कार्रवाई किए जाने को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सेना के नाम पर राजनीति कर रही है। सेना का काम देश को सुरक्षा देना है। उसी कारण से हम सब सुरक्षित हैं। किसी भी तरह सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह बयान मंगलवार को झारखंड और उत्तर प्रदेश दौरे पर रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर दिया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सेना ने गुलाम कश्मीर में आतंकी लांचिंग पैड पर गोले दागे थे। इसमें 35 से अधिक आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे।

प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन उनके मंत्री नहीं

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा पर प्रहार करने से नही चूके। कहा, प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन क्या उनके मंत्री व अधिकारी पिछड़े समाज के हैं। जो संपन्न होकर अपने समाज का ख्याल रखे, उसी व्यक्ति का साथ दें।

बड़े भाई दिग्विजय के बंगले पर लक्ष्मण का धरना

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने बड़े भाई और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के श्यामला हिल्स स्थित बंगले पर धरना दिया। वह चाचौड़ा तहसील मुख्यालय को जिला बनाने की मांग लेकर समर्थकों के साथ यहां कई घंटे तक बैठे रहे।

दरअसल लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा से विधायक हैं। उन्होंने इस प्रदर्शन से एक बार फिर दिग्विजय सिंह को दुविधा में डाल दिया। लक्ष्मण सिंह जब प्रदर्शन कर रहे थे, तब दिग्विजय एक होटल में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने चले गए थे। लक्ष्मण सिंह ने धरने के दौरान मीडिया से कहा कि चाचौड़ा को जिला बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री कमलनाथ आश्वासन दे चुके हैं। जब दो तहसील वाला निवाड़ी जिला बन सकता है तो तीन तहसील का चाचौड़ा जिला क्यों नहीं बन सकता। दोपहर में कई घंटे वह वहां अपनी मांग सुनाने के लिए बैठे रहे और उन्हें जब तक मांग पर विचार करने का आश्वासन नहीं मिल गया, वह धरना देते रहे। घटना पर चुटकी लेते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, जो भाई को भाई के बंगले पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। यह कांग्रेस सरकार के प्रति आक्रोश की चरम अभिव्यक्ति है।

चाचौड़ा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर भोपाल में दिग्विजय सिंह के बंगले पर ग्रामीणों से साथ बैठे विधायक लक्ष्मण सिंह। नईदुनिया

सोशल मीडिया अफवाहों से धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरा : उधर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया अफवाहों को फैलाने वाला 'सबसे बड़ा मंच' बन गया है। अफवाहों का प्रसार, देश के लिए खतरा है। यही नहीं, सोशल मीडिया देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने पर खतरा बन गया है। यह धर्मनिरपेक्ष सद्भाव के लिए खतरा है। सोशल और डिजिटल मीडिया के संचालन के लिए रेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है। इन्हें अफवाहों का मंच बनने से रोकने के लिए नियम होने चाहिए। दिग्विजय मंगलवार को भोपाल में 'डिजिटल मीडिया और बदलता मध्य प्रदेश' विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

राजद उपाध्यक्ष ने राजनीति से लिया ब्रेक, लिखेंगे संस्मरण

राज्य ब्यूरो, पटना : राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी कुछ महीनों के लिए राजनीतिक गतिविधियों से अवकाश लेंगे। इस समय का उपयोग भ्रमण, अध्ययन और लेखन में करेंगे। उन्होंने कहा, 'मैं कुछ रचनात्मक कार्यों के लिए राजनीतिक गतिविधियों से अवकाश ले रहा हूं। यह मेरा राजनीति से संन्यास नहीं है। राजद में अभी जो मेरी भूमिका है, मैं उससे दूर रहूंगा।' अपनों के बीच बाबा के नाम से मशहूर शिवानंद तिवारी उन गिने-चुने राजनेताओं में से हैं, जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है। वह समाजवादी नेता रामानंद तिवारी के पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि वह 1952 से राजनीति को देख रहे हैं। अब समय आ गया है कि अपने अनुभव को लिख दूं। समय-समय पर उनके आलेख प्रकाशित भी होते रहे हैं।

थकान का अनुभव कर रहा हूं : उन्होंने मंगलवार को फेसबुक पर लिखा-थकान अनुभव कर रहा हूं। शरीर से ज्यादा मन की थकान है। संस्मरण लिखना चाहता था। वह भी नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए जो कर रहा हूं, उससे छुट्टी पाना चाहता हूं। संस्मरण लिखने का प्रयास करूंगा। लिख ही दूंगा, ऐसा भरोसा भी नहीं है, लेकिन प्रयास करूंगा। इसलिए राजद की ओर से जिस भूमिका का निर्वहन अब तक मैं कर रहा था उससे छुट्टी ले रहा हूं।

मैं कांग्रेस छोड़ चुकी हूं, समाजसेविका बनकर काम करूंगी : नवजोत कौर

लखविंदर सिंह, अमृतसर

कहा, नवजोत सिंह सिद्धू दिल के साफ, उनके खिलाफ कैप्टन के भरे गए कान

पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने मंगलवार को साफ कहा कि वह कांग्रेस छोड़ चुकी हैं और अब किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं हैं। वह मंगलवार को वेरका में एक कार्यक्रम में पहुंची थीं।

उन्होंने कहा, 'मुझे अपने हलके के सिवाय किसी से कुछ लेना-देना नहीं। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती। सब कुछ छोड़ दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इसी नाते लोगों के बीच जाऊंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू दिल के साफ हैं। सच बोलते हैं। उन्हें चालाकी नहीं आती। सिद्धू के मन में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कभी कोई बात नहीं थी। वह उन्हें पिता की संज्ञा देते थे। उन्होंने कहा

नवजोत कौर सिद्धू। फाइल

था कि आप मुझे अपना बच्चा बनाकर रखो। मुझे पंजाब से प्यार है। मैं सारा काम छोड़कर आया हूं। पता नहीं किसने सिद्धू के खिलाफ उनके कान भरे हैं।'

विकास के लिए पैसा न मिला तो धरना देंगे सिद्धू

नवजोत कौर ने कहा कि जब किसी इंसान की बात न सुनी जाए तो वह विश्वास खो देता है। बटाला ब्लास्ट के बाद नवजोत सिंह सिद्धू वहां इसलिए नहीं गए, क्योंकि वह जानते थे कि वहां जाकर अगर वह सीएम से कुछ मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब उनका फोकस अपने हलके के विकास पर है। हलके की एक-एक सड़क बनवाएंगे। इसके लिए सिद्धू बैठकें कर रहे हैं। अगर हलके के विकास के लिए पैसा नहीं दिया गया, तो वे सरकार के खिलाफ धरना भी लगाएंगे। सिद्धू ने कई प्रोजेक्ट पास करवाए, लेकिन जब उन्होंने मंत्रालय छोड़ा तो ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए।

भरा जोश

कांग्रेस महासचिव की आगुआई में तीन दिवसीय कार्यशाला शुरू, प्रशिक्षण शिविर में रोजाना होंगे दो सत्र

पूजा-अर्चना, स्वागत-सत्कार... फिर गेस्ट हाउस में डटीं प्रियंका

रसिक द्विवेदी, रायबरेली

उत्तर प्रदेश में पार्टी को तेवर में लाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की आगुआई में तीन दिवसीय कार्यशाला मंगलवार को रायबरेली स्थित भुएमऊ गेस्ट हाउस में शुरू हो गई। पहले दिन संगठन की रीति-नीति के साथ सरकार के जनविरोधी कार्यों के विरोध करने के तौर तरीके समझाए-पढ़ाए गए। हालांकि, पार्टी ने इस कार्यशाला को अत्यंत गोपनीय बनाए रखा। उप्र कांग्रेस कमेटी के 45 सदस्यों के अलावा स्थानीय व जिला स्तरीय कोई भी नेता, पदाधिकारी प्रशिक्षण में शामिल नहीं किया गया। उधर, गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले जगह-जगह प्रियंका का स्वागत किया गया। रायबरेली की सीमा पर चुरुवा में उन्होंने हनुमान जी को शीष नवाया।

शहर से करीब छह किलोमीटर दूर भुएमऊ गेस्ट हाउस में सुबह से ही पार्टी के नेताओं का आगमन शुरू हो गया था। प्रशिक्षण के लिए सूचीबद्ध किए गए 45 नेता-पदाधिकारी बैग और अटैची लेकर पहुंचे। करीब 2.30 बजे प्रियंका बछरावां पहुंचीं। उसके पूर्व उन्होंने टोल प्लाजा के पास स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। प्रियंका जब गेस्ट हाउस पहुंचीं तो कार्यशाला में सरगर्मी बढ़ गई। पार्टी के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने मीडिया से बताया कि प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली से पदाधिकारी आए हैं। प्रशिक्षण में भाजपा के झूठे वादे और झूठी बयानबाजी का तार्किक तरीके से जवाब देना सिखाया जाएगा। जन विरोधी कार्यों की मुखालफत करने के तौर तरीके भी कार्यशाला में सिखाए जाएंगे।

मोबाइल बाहर, नेता अंदर : कार्यशाला के लिए चयनित नेताओं-कार्यकर्ताओं को शिविर में बिना मोबाइल के ही बैठना पड़ा। कोई फोटो, कोई सूचना लीक न होने पाए, इसका खास ध्यान रखा गया। यहां तक की स्थानीय नेताओं को हर छोटी-मोटी चीजों से भी मुखातिब नहीं होने दिया गया।

तीन दिन, छह सत्र : यूं तो प्रशिक्षण शिविर को शुरू से ही तीन दिवसीय कहा जा रहा है लेकिन प्रियंका वाड्रा के बारे में जानकारी मिली है कि वह बुधवार शाम तक ही इसमें शिरकत करेंगी, जबकि प्रशिक्षण छह सत्रों में पूर्ण होगा। प्रतिदिन दो सत्र होने हैं। बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा दोनों सत्रों में मौजूद रहेंगे। वह संवाद के तौर तरीके सिखाएंगे और बताएंगे।

सत्ता है काम करें, बहानेबाजी नहीं : प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बढ़ते आपराधिक मामलों पर प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया। कहा कि भाजपा के पास सत्ता है, काम करे बहानेबाजी नहीं। लखनऊ से रायबरेली आते वक्त प्रियंका हरचंदपुर के कठवारा में रुकीं। वहां मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगलराज कायम है। योगी सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है।

आज कुछ नए चेहरे थामेंगे कांग्रेसी झंडा : रायबरेली की सदर विधायक अदिति सिंह इन दिनों पार्टी लाइन से हटकर भाजपा के करीब दिख रही हैं। ऐसे में प्रियंका उनकी भरपाई के लिए अदिति के ही घर में सेंध लगाते हुए उनके चचेरे भाई मनीष सिंह को बुधवार को कांग्रेस में शामिल कर सकती हैं। मनीष सिंह पूर्व सांसद अशोक सिंह के बेटे हैं।

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ-प्रयागराज राजमार्ग पर बछरावां क्षेत्र के चुरुवा मंदिर में बजरंग बली के किए। जागरण

महाराष्ट्र में ग्रामीणों का दावा, हर वोट भाजपा के हक में गया

पुणे, प्रेट्र : महाराष्ट्र के एक गांव नावलेवाड़ी में रहने वालों को दावा है कि सोमवार को लोकसभा सीट सतारा के लिए हुए उपचुनाव में किसी भी प्रत्याशी को दिया जाने वाला वोट भाजपा उम्मीदवार के हक में जा रहा था। निर्वाचन अधिकारियों ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया है।

रिटर्निंग ऑफिसर कीर्ति नालावाडे ने कहा कि ईवीएम को बदला गया था, लेकिन इसका ग्रामीणों के दावे से कोई संबंध नहीं है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वे लोग एनसीपी उम्मीदवार श्रीनिवास पाटिल को वोट देना चाहते थे, लेकिन उनके वोट भाजपा प्रत्याशी उदयनराजे भोसले के खाते में गए। एनसीपी नेता शशिकांत शिंदे ने भी दावा किया कि जब वह गांव के एक बूथ का दौरा करने गए तो उन्होंने भी यह गड़बड़ी देखी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। सतारा संसदीय सीट के लिए उपचुनाव 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के साथ हुआ।

400 उन छात्राओं ने एक साथ मध्य प्रदेश में राज्य ओपन स्कूल परीक्षा में शामिल होने के लिए यह परीक्षा (मिड टर्म टेस्ट) दी है, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। शिक्षा विभाग का दावा है कि यह विश्व रिकॉर्ड है।

पाक की हरकतों को रोकने के लिए बनेगा संयुक्त काउंटर ऑपरेशन सेंटर

नई दिल्ली, आइएएनएस : पंजाब में दोबारा आतंकवाद को उभारने की कोशिशों में जुटे पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत ने संयुक्त काउंटर ऑपरेशन सेंटर बनाने का फैसला किया है। इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), खुफिया ब्यूरो (आइबी), गृह मंत्रालय के साथ ही पंजाब पुलिस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह सेंटर संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने का काम करेगा।

सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पाकिस्तान में जमे आतंकी संगठनों द्वारा ड्रोन से पंजाब में हथियार गिराने और उसके बाद लगातार सीमावर्ती राज्य में ड्रोन देखने जाने के बाद नई दिल्ली में हुई सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया गया था। यह सेंटर आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों को अंजाम देने के साथ ही पंजाब में आतंकियों को जड़े जमाने से रोकेगा।

इस फैसले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने पंजाब के डीजीपी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों से इस दिशा में समयबद्ध तरीके से जल्द से जल्द काम करने और कार्रवाई के बारे में जानकारी देने को कहा है। करतारपुर कॉरिडोर के खुलने और आइएसआइ द्वारा पंजाब में आतंकवाद को हवा देने की खुफिया सूचनाओं के बीच गठित होने वाला यह सेंटर सुरक्षा एजेंसियों के लिए नोडल एजेंसी का काम करेगा। खुफिया एजेंसियों ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान की मंशा करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करने का है। सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) जैसे कट्टरपंथी संगठनों के जरिए पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को पूरा करना चाहता है। पाकिस्तान में खालिस्तान के समर्थन में अभियान चलाने के लिए कई गुरुद्वारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भड़काऊ पर्चे बांटे जा रहे हैं। पंजाब पुलिस के साथ ही एनआइए ने भी एसएफजे के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं।

खास बातें

- पाकिस्तान पंजाब में दोबारा आतंकवाद को उभारने की कोशिशों में जुटा है
- करतारपुर कॉरिडोर के जरिए भी वह आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है
- पाक में बैठे आतंकियों ने ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार गिराए थे
- खालिस्तान समर्थक अभियान में कई गुरुद्वारों का कर रहा इस्तेमाल

भारत धार्मिक तो पाक 'आतंक' पर्यटन में जुटा

कूटनीति ▶ भारत के आमंत्रण पर 85 देशों के राजनयिकों ने मंगलवार को किया करतारपुर कॉरिडोर का दौरा

पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर में राजनयिकों को ध्वस्त 'आतंकी शिविर' दिखाए

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

भारत और पाकिस्तान कूटनीति को कितना अलग दृष्टिकोण से देखते हैं इसका एक बड़ा उदाहरण मंगलवार को देखने को मिला। एक तरफ भारत ने जहां दर्जनों राजनयिकों को करतारपुर गलियारे का धार्मिक पर्यटन कराया वहीं पाकिस्तान ने कुछ विदेशी राजनयिकों को आतंकी गढ़ों का पर्यटन कराने की व्यवस्था की।

सिखों के दो पवित्र गुरुद्वारों को जोड़ने वाले करतारपुर कॉरिडोर को अगले महीने खोला जाने वाला है। वहां जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सरकार ने जबरदस्त ढ़ाचागत सुविधाएं तैयार की हैं। भारत सरकार के निमंत्रण पर दुनिया भर के 90 देशों के राजदूतों ने इन सुविधाओं का मौका मुआयना किया।

दूसरी तरफ पाकिस्तान सेना राजनयिकों को गुलाम कश्मीर में भारतीय सैन्य कार्रवाई में आर्तकियों के ध्वस्त ठिकानों को दिखाने ले गई। भारत ने दो दिन पहले जोरा और शाहकोट बॉर्डर पर चार आतंकी लांच पैड को नष्ट किया था। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की कार्रवाई में आम जान-माल का नुकसान हुआ है और उसे दिखाने के लिए ही विदेशी राजनयिकों को

श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के तहत 84 देशों के राजदूत मंगलवार को अमृतसर पहुंचे। इस शिष्टमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया, जबकि श्री दरबार साहिब में पहुंचने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने उनका स्वागत किया। जागरण

आमंत्रित किया गया था। भारतीय उप उच्चायुक्त को भी आमंत्रित किया गया था। वैसे पाकिस्तानी दावों के अनुसार बोस्निया, ईरान, बेल्जियम समेत डेढ़ दर्जन देशों के राजनयिक वहां गए थे।

पाकिस्तान अभी भी यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि भारतीय सेना की कार्रवाई में उसे भारी क्षति उठानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान का यह पुराना रवैया है। वर्ष 2016 में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक और हाल में बालाकोट में की गई कार्रवाई को भी वह नहीं मानता है। बालाकोट में उसने सिर्फ कुछ पेड़ों को नुकसान पहुंचने की बात कही थी। लेकिन बाद में कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों ने वहां दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की।

भारतीय एजेंसियों का कहना है कि मंगलवार को विदेशी राजनयिकों को नियंत्रण रेखा पर ले जा कर पाकिस्तान घरेलू स्तर पर खोई प्रतिष्ठा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैजल भी राजनयिकों के साथ थे।

सीमा पर शांति की अपील कर पाक ने की फायरिंग

नई दिल्ली, एएनआइ : पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जबकि, सोमवार को उसने भारत से सीमा पर शांति बनाए रखने का अनुरोध किया था, ताकि वह गुलाम कश्मीर में राजनयिकों और विदेशी पत्रकारों की यात्रा करा सके। सैन्य सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने मेंढर के बालाकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद भारत को संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के लिए उकसाना था, ताकि राजनयिकों और पत्रकारों को दिखा सके। लेकिन भारत ने शांति बनाए रखा।

करतारपुर पर 24 अक्टूबर को समझौता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : करतारपुर कॉरिडोर के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच अब गुरुवार यानी 24 अक्टूबर को समझौता होगा। पहले यह समझौता एक दिन पहले बुधवार को होने वाला था। प्रत्येक भारतीय तीर्थयात्री से 20 डॉलर (लगभग 1400 रुपये) सेवा शुल्क लेने को लेकर पाकिस्तान अभी भी अड़ा हुआ है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे पर आगे भी बात होती रहेगी। भारत की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जाएगा कि यह धार्मिक उद्देश्य से सेवा शुरू की जा रही है और इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होना चाहिए।

'श्री करतारपुर साहिब जाने वाली संगत की फीस अदा करे केंद्र'

जेएनएन, चंडीगढ़ : कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी ने मंगलवार को कहा कि श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं से पाकिस्तान 20 डॉलर जजिया टैक्स वसूलने की हठ लगाए बैठा है। ऐसे में भारत सरकार को आगे आना चाहिए और इस फीस की अदायगी करनी चाहिए। सिख संगत की ओर से अदायगी करना खुले दर्शनों की भावना के खिलाफ है।

तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि भारत और पाकिस्तान 23 अक्टूबर को समझौते पर दस्तख्त करने जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान 20 डॉलर फीस लेने पर अड़ता है, तो भारत सरकार को समझौते में यह बात शामिल करनी चाहिए कि संगत के दर्शनों की लागत वह वहन करेगी।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में रह गए गुरुद्वारों के लिए रोज की जाने वाली अरदास का जिक्र किया और लिखा, 'जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां, गुर धामां दी जिहना तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो।' श्री करतारपुर साहिब तक बिना शुल्क पहुंच करने की सहायता में सरकार का यह एक बहुत बड़ा कदम होगा, जो हर सिख का सपना है, इसके लिए वह हर रोज अरदास करता है।

ब्रह्मोस मिसाइल ने 300 किमी दूर भी लगाया सटीक निशाना

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय सेना ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफल परीक्षण किया है। 21 और 22 अक्टूबर को दागी गईं ब्रह्मोस मिसाइलों ने 300 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना लगाया और उसे ध्वस्त कर दिया।

वायुसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ट्राक द्वीप से इन मिसाइलों को दो दिनों के भीतर फायर किया। रूटीन ऑपरेशनल ट्रेनिंग के लिए फायर की गईं इन मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को एकदम सटीक तौर पर ध्वस्त किया। बता दें कि ब्रह्मोस मध्यम दूरी की एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे किसी एयरक्राफ्ट, शिप या छोटे प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। 21 और 22 अक्टूबर को दागी गईं 2.5 टन वजनी इन मिसाइलों का लक्ष्य लगभग 300 किलोमीटर दूर था। दोनों ही मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को सीधे-सीधे हिट किया। इस परीक्षण के बाद भारतीय वायुसेना छोटे प्लेटफॉर्म से मिसाइल दागकर लक्ष्य पर सीधा हमला करने के मामले में और सशक्त हुई है और उसकी क्षमता बढ़ गई है।

राजनाथ ने कहा- युद्ध हुआ तो देंगे मुंहतोड़ जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- देश को दिलाया भरोसा-समुद्री सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित
- अब फिर नहीं होगा 26/11 जैसा आतंकी हमला

खास बातें

- रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत कभी आक्रामक देश नहीं रहा
- भारत ने किसी देश की एक इंच जमीन नहीं हथियाई है
- पाक के मंत्री ने परमाणु युद्ध की धमकी दी है

पाकिस्तान से लगातार मिल रही परमाणु हमले की धमकियों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है। उन्होने दो टूक कहा है कि अगर दुश्मन ने हमारी तरफ बुरी नजर से देखा तो भारत की सशस्त्र सेनाएं मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगी। रक्षा मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश की समुद्री सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और अब दोबारा 26/11 जैसा आतंकी हमला नहीं होगा।

गुलाम कश्मीर में आतंकी लांच पैड पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद मंगलवार को राजनाथ सिंह नौसेना के कमांडरों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी आक्रमक देश नहीं रहा, न ही किसी देश की एक इंच जमीन पर कब्जा किया। अगर किसी ने भारत की तरफ बुरी नजर से देखा तो भारत में इतनी ताकत है कि वो किसी भी हमले का जवाब दे सके।

राजनाथ सिंह का यह बयान पाकिस्तान के मंत्री की उस धमकी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब तोप और टैंकों से पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि परमाणु युद्ध होगा। वहीं इससे कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी धमकी दी थी कि अब अगर भारत के साथ युद्ध छिड़ा तो वह वो परमाणु-युद्ध तक जाएगा। दरअसल, पाकिस्तान की इस बौखलाहट के पीछे भारतीय सेना द्वारा एलओसी पर हाल ही में की गई कारवाई है। पाकिस्तान के युद्धविराम उल्लंघन का कड़ा जवाब देते हुए सेना ने गुलाम कश्मीर में पाक सेना की कई चौकियों और आतंकी लांच-पैड्स को तबाह कर दिया था। इसके बाद मंगलवार को पाकिस्तानी सेना विदेशी राजनयिकों को नीलम घाटी लेकर गई, जिसका मकसद यह साबित करना था कि गुलाम कश्मीर में कोई आतंकी कैंप नहीं हैं और ना ही भारतीय सेना ने किसी आतंकी कैंप या फिर लांच पैड को तबाह किया है।

नई दिल्ली में मंगलवार को नौसेना के कमांडरों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान सैन्य अधिकारियों से मिलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र

नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में शिरकत करने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि देश की समुद्री-सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है और भारतीय नौसेना फिर से 26/11 जैसा आतंकी हमला देश पर नहीं होने देगी।

आइएफएफआइ ने की 'ओपन एयर स्क्रीनिंग' के लिए फिल्मों की घोषणा

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव (आइएफएफआइ) ने मंगलवार को घोषणा की कि हास्य फिल्में 'पड़ोसन' एवं 'अंदाज अपना-अपना' और ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गली ब्वॉय' और 'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक' 'ओपन एयर स्क्रीनिंग' का हिस्सा होंगी। यह फिल्मोत्सव गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा।

'द जॉय ऑफ सिनेमा' विषय के तहत आयोजित होने वाले 50वें आइएफएफआइ के दो परिसरों अल्तिन्हो में जॉगर्स पार्क और मीरामार बीच पर 14 फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म जगत के प्रेमियों को शानदार सिनेमाई अनुभव मुहैया कराने के लिए हर साल 'ओपन एयर स्क्रीनिंग' का आयोजन किया जाता है। इस स्क्रीनिंग में कोई भी शामिल हो सकता है और इसके लिए किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। प्रवेश मुफ्त होगा। जॉगर्स पार्क में 'चलती का नाम गाड़ी', 'हेराफेरी', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'बधाई हो' और 'टोटल धमाल' जैसी फिल्में भी दिखाई जाएंगी। इस उत्सव में विभिन्न देशों की करीब 250 फिल्में दिखाई जाएंगी।

बरेली के मौलाना को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- मौलाना कैफी अली ने हत्यारोपितों के इलाज में उनकी मदद की थी।
- कर्नाटक में भी पकड़ा गया एक संदिग्ध, इनोवा चालक व मालिक से भी सवाल-जवाब

कमलेश तिवारी की हत्या के आरोपित मोईनुद्दीन व अशफाक की मदद के संदेह में पुलिस ने बरेली के प्रेमनगर निवासी मौलाना कैफी अली को हिरासत में लिया है। आरोप है कि दोनों हत्यारोपितों ने घटना के बाद मौलाना कैफी अली से संपर्क किया था और बरेली जाकर मुलाकात भी की थी। मौलाना कैफी अली ने हत्यारोपितों के इलाज में उनकी मदद की थी। पुलिस की एक टीम ने सोमवार रात बरेली निवासी मौलाना कैफी अली को उनके आवास से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और लखनऊ लेकर आई है। पुलिस उनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी से इनोवा चालक तौहीद अहमद व मालिक राजकुमार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

कमलेश हत्याकांड के तार गुजरात व महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक से भी जुड़ रहे हैं। कर्नाटक पुलिस हत्याकांड के साजिशकर्ताओं से जुड़े होने के संदेह में एक युवक से पूछताछ कर रही है। उप्र एटीएस ने कर्नाटक पुलिस से संपर्क कर युवक से पूछताछ में सामने आये तथ्यों की जानकारी मांगी है। उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक तक साजिशकर्ताओं का नेटवर्क खंगाला जा रहा है। अब तक जिस तरह एक के बाद एक साजिश की परतें खुलती जा रही हैं, उससे हत्याकांड के पीछे किसी आतंकी संगठन की भूमिका का संदेह और गहराता जा रहा है। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच का हवाला देकर किसी संगठन की भूमिका को लेकर अभी मौन साधे हैं।

लखनऊ लाया गया एक और साजिशकर्ता : महाराष्ट्र एटीएस ने नागपुर में कमलेश हत्याकांड की साजिश से जुड़े जिस आरोपित सैयद आसिम अली (29) को गिरफ्तार किया था, उसे उप्र एटीएस ट्रांजिट रिमांड पर मंगलवार शाम लखनऊ लेकर आई। आसिम अली से गहनता से पूछताछ की जा रही है। हत्याकांड में उसकी भूमिका व साजिश से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।

हत्यारे अशफाक को हिंदू समाज पार्टी में शामिल करने पर घिरे जैमिन बापू

जागरण संवाददाता, लखनऊ

- तीन जून को बनाया था पार्टी का सूरत का आइटी सेल प्रभारी

कमलेश तिवारी के हत्यारे अशफाक को उनकी हिंदू समाज पार्टी से जोड़ने के लिए गुजरात प्रभारी जैमिन दवे बापू घिर गए हैं। दो दिन पहले जहां एटीएस ने जैमिन बापू से पूछताछ की, वहीं अब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अशफाक को पार्टी से जोड़ने को लेकर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर जैमिन बापू ने अशफाक को दिया गया नियुक्ति पत्र और उसका आधार कार्ड सार्वजनिक कर दिया है।

दरअसल, हिंदू समाज पार्टी से जुड़ने से पहले अशफाक ने रोहित सोलंकी के नाम से न केवल फेसबुक अकाउंट बनाया बल्कि पार्टी और हिंदुत्व के बारे में कई पोस्ट की। पार्टी से जुड़ने के बाद हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैमिन ने तीन जून को अशफाक (कागजों पर रोहित कुमार सोलंकी) को सूरत का आईटी सेल का प्रभारी बनाया था। जिसका नियुक्ति पत्र कमलेश तिवारी और जैमिन बापू की ओर से जारी किया गया था। आइटी सेल प्रभारी बनकर ही अशफाक ने हिंदुओं के 50 नकली नामों से फेसबुक अकाउंट बनवाए। उनको हिंदू समाज पार्टी से भी जोड़ा। पार्टी के फेसबुक अकाउंट से उसने देशभर से हिंदुत्व विचारधारा के चार हजार लोगों को जोड़ लिया था। इसे देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष जैमिन बापू का वह कुछ ही दिन में खास बन गया। पार्टी की जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की बधाई की होर्डिंग में जैमिन बापू के साथ अशफाक यानी रोहित सोलंकी की फोटो लगाई जाने लगी।

राशिद के हाथ था फेसबुक अकाउंट : दुबई में कम्प्यूटर का काम कर चुका राशिद पठान ही अशफाक के साथ हिंदू समाज पार्टी के फेसबुक अकाउंट को चलाता था। फेसबुक पर होने वाली हर गतिविधि पर उसकी नजर बनी रहती थी। पार्टी से जुड़ने के बाद अशफाक ने जैमिन बापू को 50 हजार रुपये देने की बात कही थी जिस पर जैमिन ने मना कर दिया था।

किया था नियम का पालन

जैमिन बापू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि उन्होंने नियम के तहत पार्टी में रोहित सोलंकी को शामिल किया था। उसके नाम से आधार कार्ड और उसकी फोटो ली गई थी। रोहित सोलंकी के नाम से जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो उसमें पहले से ही हिंदू समाज पार्टी के कई कार्यकर्ता उसकी लिस्ट में शामिल थे।

पीड़ित परिजनों से मिले करणी सेना के अध्यक्ष

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मंगलवार को सीतापुर के महमूदाबाद में योगी सरकार और प्रशासन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अब पांच सौ लोग यहां लगा रखे हैं, दो-चार दिन पहले अगर लगा दिए होते तो ये घटना नहीं होती। वह कमलेश के परिवार से मिलने पहुंचे थे।

कुसुमा देवी ने कहा, हमें झूठी सांत्वना दे रहे

कमलेश तिवारी के घर पहुंचने के बाद करणी सेना के सामने कमलेश की मां ने बोलना शुरू किया तो एसडीएम ने वीडियो बनाने से मना कर दिया। इस पर मां कुसुम तिवारी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप जड़ने शुरू कर दिए। कहा कि प्रशासन ने मीडिया को बैन कर रखा है। 24 घंटे का समय दिया गया था। 48 घंटे हो गए लेकिन कोई सूचना नहीं है। सिर्फ आश्वासन और सांत्वना दी जा रही है। मुझको इंसाफ चाहिए।'

साजिशकर्ताओं ने कहा था, तुम कत्ल करो, जमानत हम कराएंगे

ज्ञान बिहारी मिश्र, लखनऊ

- हत्यारों को साजिशकर्ताओं ने दिया था आश्वासन
- यू-ट्यूब पर वीडियो डालकर सैयद आसिम ने भड़काया था

कमलेश तिवारी के हत्यारों की मदद करने में एक के बाद एक नए नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि हत्या में कितने लोगों की भूमिका है, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। हत्यारे अशफाक और मोइनुद्दीन, नागपुर में गिरफ्तार किए गए सैयद आसिम अली से सोशल मीडिया के जरिये ही संपर्क में आए थे। पूछताछ में पता चला है कि सभी साजिशकर्ताओं ने हत्यारोपितों के पकड़े जाने पर जमानत कराने की जिम्मेदारी ली थी।

गुजरात से गिरफ्तार किए गए मौलाना शेख सलीम, फैजान और राशिद अहमद पठान लगातार सैयद कासिम के संपर्क में थे। हत्यारों ने सूरत में आरोपितों को फोन कर कमलेश की हत्या करने की जानकारी दी थी। इसके बाद आसिम को इसके बारे में बताया गया था। पूर्व में हुई बातचीत के दौरान आसिम ने इस बात की गारंटी ली थी कि वह न केवल उनकी जमानत कराएगा बल्कि सारे खर्चे भी उठाएगा। सूरत से आसिम को हत्या की जानकारी दी गई थी। इस पर आसिम ने उन्हें आगे की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था। छानबीन में पता चला है कि आरोपित आसिम यू-ट्यूब पर वीडियो अपलोड करता था। आसिम के वीडियो देखकर ही अशफाक और मोइनुद्दीन उससे प्रभावित हुए थे। इसके बाद उनकी आसिम से सोशल मीडिया और फोन पर बात होने लगी थी। आसिम ने आरोपितों को खुद के कई भड़काऊ वीडियो भी भेजे थे।

मुलाकात की पुष्टि नहीं : पूछताछ में अब तक आसिम से अन्य आरोपितों की मुलाकात की बात स्पष्ट नहीं हो सकी है। यही नहीं एटीएस और एसटीएफ ने जिन मददगारों को पकड़ा है, उनसे भी हत्यारों की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए वे लगातार संपर्क में थे। आरोपित आसिम ने पूछताछ में बताया है कि उसे कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश की जानकारी थी और यह भी पता था कि शुक्रवार को अशफाक और मोइनुद्दीन कत्ल की वारदात को अंजाम देंगे।

बरेली से मिला था वकील का नंबर : हत्यारों ने ठाकुरगंज निवासी जिस अधिवक्ता को फोन किया था, उनका नंबर बरेली में उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बरेली के मददगारों ने आरोपितों के मांगने पर अधिवक्ता का नाम और नंबर उन्हें दिया था। इसके बाद दोनों ने अधिवक्ता को फोन कर सरेंडर करने की बात कही थी।

भाईचारा

सबसे बड़े विवाद के पटाक्षेप की प्रतीक्षा में मौजू हो उठी है यह विरासत

हाशिम-परमहंस से रोशन है सौहार्द की विरासत

रघुवरशरण, अयोध्या

जिस विवाद के पटाक्षेप की प्रतीक्षा करते हुए हाशिम सवा दो वर्ष पूर्व चिरनिद्रा में लीन हो गए और परमहंस डेढ़ दशक पूर्व। अब उस मंदिर-मस्जिद विवाद का पटाक्षेप होने को है। परमहंस मंदिर आंदोलन के पर्याय ही नहीं पहुंचे संत भी थे। वह बिहार के छपरा जिले के एक कुलीन परिवार से थे। देश के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करते हुए वह अयोध्या आ पहुंचे। उन्होंने धूनी तो रमाई विरक्त आचार्य के संरक्षण में पर उनका रोम-रोम समाज के प्रति अनुरक्त था।

समाज के प्रति इसी राग के चलते यह किशोर वैरागी युवा होते-होते किसी परिचय का मोहताज नहीं रह गया। कोई भूखा हो, बीमार पड़ा हो या जोर-जुल्म का शिकार हो, रामचंद्रदास हर किसी की मदद में खड़े मिलते थे। वह सामाजिक विषयों के प्रति सजग संवेदनशील सेवाभावी के साथ शास्त्रज्ञ, प्रखर वक्ता और साधना में रमे खांटी साधु भी थे। यह संतुलन उन्हें बेजोड़ बना रहा था। इसी के चलते उन्हें परमहंस की उपाधि से नवाजा गया। वह भगवान राम के अनन्य उपासक थे तो उनकी जन्मभूमि के लिए भी पूरी ताकत से खड़े हुए। राममंदिर के लिए वह आजादी के पूर्व से ही संघर्षरत रहे और 1949 में रामलला के प्राकट्य प्रसंग के दौरान तो वह केंद्रीय भूमिका में सामने आए। रामलला के लिए संघर्ष उनकी आस्था का सवाल था तो आस्था की इसी परिधि में हाशिम अंसारी भी शामिल रहे, जो वर्षों तक बाबरी मस्जिद के पर्याय बने रहे।

मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई के दौरान फैजाबाद की विशेष अदालत से बाहर निकलते परमहंसदास व हाशिम अंसारी (फाइल फोटो)

परमहंस और हाशिम एक ही इक्के से सिविल कोर्ट जाया करते थे। यह मेल-जोल दोस्ती में बदल गई। हाशिम यदा-कदा परमहंस के आश्रम दिगंबर अखाड़ा भी जाते थे और उनके बीच काफी आत्मीयता भी रहती थी। 1984 से 1992 तक मंदिर आंदोलन निरंतर तीव्र होता गया।

इसी के साथ ही परमहंस का कद भी बढ़ता गया पर उनके पांव कभी जमीन से नहीं डिगे। मंदिर आंदोलन जिन दिनों व्यापक तनाव का सबब बना था। उन दिनों भी वह यह याद दिलाना नहीं भूलते थे कि मंदिर बने पर इस शर्त पर कि हिंदू या मुस्लिम में से किसी का एक बूंद खून न गिरे। वह चांदबीबी, रहीम, रसखान एवं कारू मियां जैसे समरसता के प्रतीकों का भी मंचों से जिक्र कर अपनी भावनाओं का एहसास कराते थे।

31 जुलाई 2003 को परमहंस के साकेतवास के बाद हाशिम अंसारी उनके जिक्र मात्र से विभोर हो जाया करते थे। परमहंस से जुड़ी स्मृति की गठरी खोल दिया करते थे। इस दौरान उनकी आंखें भी नम हो जाया करती थीं। परमहंस से दोस्ती और उनकी स्मृतियों से ही संभवतः प्रेरित होकर हाशिम अंसारी स्वयं को रोक नहीं सके। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट से निर्णय आने की बेला में हाशिम विवाद छोड़कर संवाद से मसले के हल के प्रयास में लगे।

अयोध्या राम मंदिर में स्थापित होगी महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति : विहिप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अयोध्या मंदिर में राम व हनुमान के साथ महर्षि वाल्मीकि की भी मूर्ति स्थापित की जाएगी। उन्होंने ही जगत को रामायण दी है। रामकथा बताई है। वह असाधारण तपस्वी थे। जब तप में लीन हुए तो उनके शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया था। आलोक कुमार ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति मंदिर के मुख्य परिसर में ही स्थापित की जाएगी। आलोक कुमार दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में भारतीय बौद्ध संघ द्वारा आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर आयोजित समरसता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन की अध्यक्षता राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया ने की। अन्य विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वाल्जी भाई झाला और सुलभ इंटरनेशनल के बिंदेश्वरी पाठक शामिल थे।

आलोक कुमार ने कहा, विश्वास है कि राममंदिर पर फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि हमारे तर्क मजबूत हैं। मंदिर के पक्ष में ढेरों सबूत रखे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक समरसता अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि देश में समरसता का प्रभाव बढ़ रहा है। दिल्ली की सभी रामलीलाओं में महर्षि वाल्मीकि के चित्र भी दिखाई देते हैं। इसी तरह अनुसूचित समाज के लोगों को पूजा के लिए बुलाया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि राम के बेटों लव और कुश का लालन पालन भी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ, तभी उनमें इतना तेज आया कि उन्होंने राम की सेना को भी परास्त कर दिया। दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास के मंदिर के पुर्ननिर्माण की लड़ाई सुग्रीम कोर्ट से जीतने को कुछ लोगों द्वारा एक समाज विशेष की जीत बताए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वाल्मीकि, रविदास के साथ ही गुरुनानक देव जैसे महापुरुष भारत के संत थे।

अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली कोशिश थी श्रीरामजानकी यात्रा

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या : विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में राम मंदिर आंदोलन का पहला समन्वित प्रयास 1984 की श्रीरामजानकी रथयात्रा रही। इस दौरान हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए अस्पृश्यता पर पहला प्रहार हुआ। उस समय तक समाज जाति एवं वर्ग आधारित छुआछूत के बंधन में जकड़ा था। रथ यात्रा के दौरान किया जाने वाला भोजन पड़ाव के आसपास के गांवों के विभिन्न जाति-वर्ग के लोगों की रसोई से जुटाया गया। भोजन में रोटी एवं पूड़ी के साथ अचार और गुड़ सभी वर्गों के घरों से लाया गया। वंचित व उपेक्षित वर्ग के लोगों को सहसा विश्वास नहीं हो रहा था कि यात्रा में शामिल नामी एवं प्रतिष्ठित साधु-संत उनके घर की रसोई में बना भोजन करेंगे। लोग स्वयं भोजन का पैकेट लेकर पड़ाव तक पहुंचे। पहले पड़ाव की जिम्मेदारी संभालने वाले रामनगर धौरहरा निवासी आलोक प्रकाश सिंह बताते हैं कि ऐसे उत्सुक लोगों को परोसने के लिए कहा गया तो लगा कि जीवन धन्य हो गया।

40 हजार सेब की पेटियों की खरीदारी हो चुकी है शोपियां से अब तक। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नैफेड) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर स्थानीय व्यापारियों व सेब उत्पादकों से उनकी फसल खरीदने के लिए मंडियां बनाई हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 23 अक्टूबर 2019

जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के कर्मियों को दिवाली के बाद मिलेगा तोहफा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 अक्टूबर को फिर दिवाली होने वाली है। इस दिन से केंद्र शासित प्रदेश बनते ही दोनों प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह सातवें वेतन आयोग की अनुसंशा के अनुरूप भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसपर अपनी मुहर लगा दी है। सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भत्ता देने से कुल 4800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

गृह मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल सातवें वेतन आयोग की अनुसंशा के अनुरूप भत्ता नहीं मिल रहा था। इन कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा, उनके हॉस्टल के खर्च, यात्रा, मेडिकल और अन्य भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों से बहुत कम थे। केंद्रीय कर्मचारियों के समान भत्ता मिलने की स्थिति में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा के लिए 607 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही बच्चों के हॉस्टल के खर्च के रूप में 1823 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। यात्रा भत्ता के रूप में 1200 करोड़ रुपये, एलटीसी के रूप में 1000 करोड़ रुपये, स्थायी मेडिकल भत्ता के रूप में 108 करोड़ रुपये और अन्य भत्ता के रूप में 62 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। जाहिर है दोनों प्रदेशों के 4.5 लाख कर्मचारियों के लिए दिवाली के बाद का बड़ा तोहफा होगा।

गौरतलब है कि सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर का विभाजन कर लद्दाख को अलग कर दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटने का फैसला लिया। इनमें लद्दाख बिना विधानसभा के, जबकि जम्मू-कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। संसद के दोनों सदनों ने दो-तिहाई बहुमत से सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद से जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों की स्थिति के बारे में अटकलें लगाई जा रही थी। अब गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी अब केंद्रीय कर्मचारी कर्मचारी माने जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर में इतिहास बन जाएंगे छह आयोग

नया जम्मू कश्मीर

31 अक्टूबर को दो केंद्र शासित राज्यों में बंट जाएगा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

▸ सिर्फ तीन आयोग अस्तित्व में बने रहेंगे, अध्यक्ष और सदस्य नए सिरे से लेंगे शपथ

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

राज्य एहतिसाब आयोग और जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग समेत जम्मू-कश्मीर में लागू छह आयोग 31 अक्टूबर को इतिहास बन जाएंगे। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर दो केंद्र शासित राज्यों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का रूप ले लेगा।

पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पास किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और निशान भी समाप्त हो गया है। वहीं, राज्य संविधान के तहत गठित छह आयोग भी अब समाप्त हो जाएंगे। जम्मू-कश्मीर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी समाप्त हो जाएगा। यह आयोग जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के तहत बना था। जम्मू-कश्मीर महिला एवं बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम और इसी साल जम्मू-कश्मीर लॉ कमीशन भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अब सिर्फ तीन आयोग ही बने रहेंगे और उनके अध्यक्षों व सदस्यों को भी नए सिरे से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।

सिर्फ ये तीन आयोग बने रहेंगे

राज्य के पुनर्गठन के बाद यहां सिर्फ तीन अन्य आयोग बने रहेंगे, जिनमें जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग भी शामिल है। यह आयोग सिर्फ केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में ही प्रभावी रहेगा। लद्दाख इसके दायरे से बाहर रहेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य सतर्कता आयोग और जम्मू कश्मीर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना रहेगा।

संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर अकाउंटबिलिटी कमीशन जिसे एहतिसाब आयोग कहते हैं, 31 अक्तूबर को समाप्त हो जाएगा। वर्ष 2002 में सत्ता में आई पीडीपी-कांग्रेस गठबंधन सरकार ने राजनीतिक और वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और संबंधित संस्थाओं को जिम्मेदार बनाने के लिए इसे गठित किया था। एहतिसाब आयोग मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्यों, विधायकों और एमएलसी के खिलाफ शिकायतों की जांच करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। हालांकि यह आयोग तीन-चार साल बाद ही लगभग निष्क्रिय हो गया था। फिलहाल, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज बशीर अहमद खान इसके अध्यक्ष हैं। अधिकारियों ने बताया कि एहतिसाब आयोग के समाप्त होने के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में केंद्रीय कानून के तहत अन्य केंद्र शासित राज्यों की तरह लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी।

एहतिसाब आयोग की तरह जम्मू कश्मीर राज्य सूचना आयोग भी अब पूरी तरह अस्तित्वहीन हो जाएगा। यह आयोग भी जून 2018 से लगभग निष्क्रिय पड़ा हुआ है। आयोग के तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त खुर्शीद अहमद गनई को पिछले साल जून में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। उनके स्थान पर एडीजीपी मुनीर अहमद खान को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था। इसके अलावा वर्ष 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कांफ्रेंस सरकार द्वारा गठित जम्मू कश्मीर राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग भी अब समाप्त हो जाएगा।

आइजी बोले-पाक की हरकतों पर बीएसएफ की कड़ी नजर

राज्य ब्यूरो, जयपुर: सीमा पार पाकिस्तान की गतिविधियों पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की कड़ी नजर है और वह किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बीएसएफ के आइजी राजस्थान फ्रंटियर अमित लोढ़ा ने जैसलमेर स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा के दो दिवसीय दौरे के बाद मीडिया से बातचीत में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि बीएसएफ को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसएफ पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सीमा के पास के इलाके में अक्सर ड्रोन नजर आने की बात पर उन्होंने कहा कि बीएसएफ को सभी गतिविधियों की जानकारी है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ सीमा के निकट रहने वाले लोगों के लिए बेहतर स्थितियां बनाने का प्रयास करता है। उन्होंने बताया कि हाल में हमने 'घर आंगन' नाम से एक योजना भी शुरू की है, जिसके जरिये ग्रामीणों के साथ अच्छा तालमेल बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं।

सिक्किम के मुख्यमंत्री की अयोग्यता पर फैसले को चुनौती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की छह साल की अयोग्यता अवधि कम करने के संबंध में निर्वाचन आयोग के पैनल द्वारा किए गए फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। प्रेम सिंह तमांग को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार देते हुए 13 महीने की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सरकार व तमांग की प्रतिक्रिया मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी।

तमांग की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने इस साल अप्रैल में राज्य विधानसभा चुनाव जीता था और उन्होंने 27 मई को मुख्यमंत्री का पद संभाला। हालांकि, अयोग्यता के कारण वह चुनाव नहीं लड़ सके थे। उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए छह महीने के भीतर विधानसभा चुनाव लड़ना आवश्यक था। तमांग को 26 दिसंबर 2016 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी और 10 अगस्त 2018 को एक वर्ष की सजा पूरी की थी। तमांग पर 1996-97 में गायों की खरीद में 9.5 लाख रुपये का दुरुपयोग करने का मामला है। उस समय वह पशुपालन मंत्री थे। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के महासचिव डीके बहादुर कटवाल द्वारा दायर याचिका के अनुसार जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 11 असंवैधानिक है, क्योंकि यह अयोग्यता अवधि को हटाने के लिए चुनाव आयोग को अनियंत्रित शक्ति प्रदान करता है।

त्राल में मुठभेड़, जैश के तीन आतंकी ढेर

आतंक पर अंकुश ▸ आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद भी बरामद

पांच अगस्त के बाद से अब तक मारे गए 12 आतंकी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर में सुरक्षाबलों ने ग्रामीणों और पंच-सरपंचों को डरा-धमका रहे आतंकियों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए मंगलवार को त्राल में जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में दो विदेशी और एक स्थानीय बताया जा रहा है। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद भी बरामद किया है।

जानकारी के अनुसार, पुलिस को मंगलवार दोपहर को सूचना मिली कि जैश के तीन आतंकी त्राल के राजपोरा में काजीनाग आए हुए हैं। राज्य पुलिस के विशेष अभियान दल के जवानों ने उसी समय सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर इन आतंकियों के खिलाफ एक अभियान चलाया। दोपहर तीन बजे यह अभियान शुरू हुआ और सुरक्षाबलों ने आतंकियों के ठिकाने का अनुमान लगाते हुए घेराबंदी शुरू कर दी। करीब दो घंटे बाद जब जवान तलाशी लेते हुए आगे बढ़ रहे थे तो मकान में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और मौके से भागने का प्रयास किया। जवानों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायर किया। इसके बाद दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों की तरफ से अंतिम गोली करीब पौने आठ बजे चली। लगभग 15 मिनट तक जब आतंकियों की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई तो जवानों ने सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते हुए आतंकी ठिकाना बने मकान की तलाशी ली। इस दौरान उन्हें वहां तीन आतंकियों के शव व उनके हथियार मिले। मारे गए आतंकियों के पास से आतंकी संगठन से जुड़े कई दस्तावेज, दो अत्याधुनिक वायरलेस और एक जीपीएस भी मिला है। पांच अगस्त के बाद घाटी में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच यह छठी और दक्षिण कश्मीर में तीसरी मुठभेड़ है। इससे पूर्व 16 अक्टूबर को पुलवामा में तीन आतंकी मारे गए थे। आठ अक्टूबर को अवंतीपोर के कावनी इलाके में सुरक्षाबलों ने लश्कर के दो स्थानीय आतंकियों उफैद और अब्बास को मार गिराया था। अन्य तीन मुठभेड़ों में एक जिला गांदरबल में और दो उत्तरी कश्मीर के बारामुला व सोपोर में हुई हैं।

गुज्जर समुदाय के दो लोगों की हत्या में थे शामिल

राज्य पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने जैश के तीन आतंकियों की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि ये आतंकी गत अगस्त में त्राल के ऊपरी क्षेत्र में गुज्जर समुदाय के दो लोगों को अगवा कर मौत के घाट उतारने की वारदात में शामिल थे। फिलहाल, इन आतंकियों के अन्य साथी जो त्राल के आस-पास ही कहीं छिपे हैं, उनकी तलाश की जा रही है।

एलओसी पर आतंकी हमले में नायब सूबेदार शहीद

जागरण संवाददाता, राजौरी

▸ सीमा में आधा किमी अंदर घुसे आतंकियों ने चौकी को बनाया निशाना

जिले में नौशहरा के कलाल सेक्टर में एलओसी पर आतंकियों के एक समूह ने भारतीय क्षेत्र में घुसकर सेना की चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले में सेना का नायब सूबेदार शहीद हो गया। हमले के बाद सेना ने क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

कलाल सेक्टर में मंगलवार दोपहर बाद आतंकवादियों का एक दल भारतीय क्षेत्र में 500 मीटर अंदर घुस आया और सेना की चौकी पर करीब से गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में महाराष्ट्र निवासी नायब सूबेदार सुनील राव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पास के सैन्य अस्पताल में लाया गया, जहां वह शहीद हो गए। वहीं, सुंदरबनी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सैन्य चौकियों और रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर गोलाबारी की।

उल्लेखनीय है कि रविवार को कश्मीर के टंगडार सेक्टर में पाक सेना की गोलाबारी में सेना के दो जवान शहीद हो गए और एक स्थानीय व्यक्ति भी मारा गया था। जवाबी कार्रवाई में आतंकियों के चार लांचिंग पैड ध्वस्त कर दिए थे। इसमें दस पाकिस्तानी सैनिक और 20 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए थे।

पाक सेना की गोलाबारी की आड़ में घुस आए थे आतंकी

सूत्रों की मानें तो पाक सेना ने पहले गोलाबारी शुरू की। इसी गोलाबारी की आड़ में आतंकियों का दल भारतीय क्षेत्र में पांच सौ मीटर अंदर घुस आया और चौकी पर हमला कर दिया। हमले के बाद आतंकियों की तलाश में सेना ने एलओसी के पास बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान को शुरू कर दिया जो देर रात तक जारी था।

सत्यपाल मलिक ही हो सकते हैं जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

31 अक्टूबर को लेह और श्रीनगर में होना है शपथ ग्रहण समारोह

सत्यपाल मलिक। फाइल

जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है और 31 अक्टूबर का दिन नजदीक आ रहा है। बावजूद इसके केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर (उप राज्यपाल) को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्यपाल सत्यपाल मलिक को ही दोनों नए केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख का लेफ्टिनेंट गर्वनर बनाए रखने की पक्ष में है। हालांकि, मलिक ने इस पर अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है। अगर सब सही रहता है तो वह 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहले उप राज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह अलग-अलग होगा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गर्वनर को 31 अक्टूबर की सुबह लेह में शपथ दिलाई जाएगी जबकि जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दोपहर में श्रीनगर में शपथ दिलायी जाएगी। अगर राज्यपाल मलिक दोनों केंद्र शासित राज्यों की कमान संभालने को सहमत होते हैं तो वह पहले लेह में शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद श्रीनगर में।

हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगी शपथ : उपराज्यपाल को भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ही शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और हाई कोर्ट के जज भी मौजूद रहेंगे।

सलाहकारों पर भी नहीं हुआ अभी निर्णय : राज्यपाल के मौजूदा पांच सलाहकारों की सेवाओं को बहाल रखने या समाप्त करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस संदर्भ में अंतिम फैसला सत्यपाल मलिक के साथ विचार-विमर्श के बाद ही होगा। अलबत्ता, लद्दाख में उप राज्यपाल का कोई सलाहकार नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल चाहेंगे तो वह मौजूदा सलाहकारों में से एक-दो की सेवाओं को ले सकते हैं।

पाकिस्तान ने रिहायशी क्षेत्रों पर बरसाए गोले, महिला घायल

जेएनएन, जम्मू

▸ भारत का करारा जवाब, सीमा पार भी भारी नुकसान की सूचना

▸ अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी) पर भी पाक ने की गोली बारी

गुलाम कश्मीर में भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान हताश और डरा हुआ है। इसलिए अब भारत के रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। मंगलवार को पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा (एसओसी) पर पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर कई गांवों में भारी गोलाबारी की, जिसमें एक स्थानीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है।

सीमा पार भी भारी नुकसान की सूचना है। वहीं, शाम को पाकिस्तान ने जम्मू के केरी बट्टल सेक्टर में भी गोलाबारी शुरू कर दी। एक मोर्टार मकान के ऊपर गिरा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में कई गांवों को निशाना बनाया। सोमवार रात शुरू हुआ मोर्टार दागने का सिलसिला मंगलवार तड़के चार बजे तक चला। इसके बाद मंगलवार रात पाक रेंजर्स ने फिर गोलाबारी शुरू कर दी। बीएसएफ ने भी पाक रेंजर्स को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं।

पाकिस्तानी सेना ने दोपहर करीब 12 बजे बालाकोट में डेरी डब्बसी, गोलद, बालाकोट, पंजानी, ब्रूटा आदि गांवों पर अचानक मोर्टार दागने शुरू कर दिए। इस दौरान एक मोर्टार गोलद गांव के एक घर के ऊपर गिरा। इससे फूल जहान पत्नी काला खान घायल हो गई। महिला को उप जिला अस्पताल मेंढर में लाया गया, जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज राजौरी रेफर कर दिया गया।

आइबी के आसपास सुरक्षा बढ़ाई, तलाशी अभियान : हीरानगर सेक्टर में आइबी पर पाक गोलाबारी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी हैं। एसएसपी श्रीधर पाटिल के निर्देश पर एसडीपीओ चड़वाल रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने हरिपुर पंचायत के बठल चक क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। सुबह छह से आठ बजे तक चले अभियान में तरना नाले के साथ लगते नाले को खंगाला गया, लेकिन कुछ नहीं मिला।

सेना ने तीन मोर्टार किए निष्क्रिय

भारतीय सेना सीमा पर दुश्मन से लड़ने के साथ सीमावर्ती लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। मंगलवार को सेना ने पुंछ में पाकिस्तान की ओर से चंद रोज पहले दागे गए 120 एमएम के तीन मोर्टार निष्क्रिय किए। ये मोर्टार खेतों में पड़े हुए थे। इससे लोगों में डर का माहौल था और वह खेतों में काम करने नहीं जा रहे थे। एएनआइ

पंजाब सीमा के गांवों में दिखे ड्रोन, गिराने के लिए की फायरिंग

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर : पंजाब के सरहदी जिले के बॉर्डर एरिया में सोमवार रात लगभग 10:30 बजे तीन ड्रोन देखे जाने से गांव हजारा सिंह वाला में दहशत फैल गई है। बीएसएफ जवानों व पुलिस ने इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर ड्रोनों पर फायर कर उन्हें गिराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद मंगलवार सुबह बीएसएफ के जवानों ने चौकसी बढ़ाते हुए छानबीन की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उधर, फिरोजपुर के सरहदी क्षेत्र में ही हेरोइन मिलने, ड्रोन दिखने, अज्ञात कार बरामद होने और दो पाकिस्तानी नागरिक काबू आने की घटनाओं ने इलाके में सनसनी फैला दी है।

गांव हजारा सिंह वाला में बीएसएफ के जवानों द्वारा ड्रोन देखे जाने पर उसे गिराने के लिए 50 से ज्यादा फायर किए, लेकिन गोली की रेंज कम होने से ड्रोन गिरे नहीं। इस संदर्भ में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। उधर, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ड्रोन दिखने या फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई हैं। मगर, ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही बीएसएफ द्वारा फायरिंग की गई, तो गांव में दहशत का माहौल बन गया। इससे पहले 7, 8, 9 और 10 व 14 अक्टूबर को ड्रोन देखने के मामले सामने आते रहे हैं।

भ्रष्ट नेताओं और ताकतवर लोगों ने बर्बाद किए युवाओं के सपने : सत्यपाल मलिक

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि भ्रष्ट नेताओं और ताकतवर लोगों ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के सपनों को बर्बाद कर दिया। राज्यपाल ने एक तरफ मुख्यधारा वाली पार्टियों के नेताओं और हुर्रियत को लताड़ा तो दूसरी तरफ उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक में भ्रष्टाचार की परतों को खोला। वह श्रीमाता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटड़ा के सातवें दीक्षा समारोह को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि अगर नेताओं, नौकरशाहों ने दिल्ली से आए पैसे का सही इस्तेमाल किया होता तो लोगों के घरों की छत भी सोने की होती। हालत यह है कि जब मैं बाबा अमरनाथ यात्रा गया तो देखा कि पिठ्ठू वालों के पास स्वेटर भी नहीं था। यहां के नेताओं का एक घर कश्मीर में, एक दिल्ली में, एक दुबई में और एक लंदन में है। स्वयं लाखों-करोड़ों कमाते हैं पर बच्चों को एक नौकरी भी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि राजभवन में युवा आए और मुझे बताया कि हमने जम्मू-कश्मीर बैंक लिखित परीक्षा पास की, इंटरव्यू पास किया, मेरिट में आए लेकिन नियुक्तियां दूसरे लोगों को दे दी गई। मुख्यमंत्री, एमएलए के नजदीकी लोगों को लगा दिया गया। कहा- चेयरमैन से पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि दवाब में यह काम किया था। मुझे बताया गया कि यह 25 नहीं है बल्कि 582 लोगों को हक से वंचित कर दिया गया। जब मैं सही फैसला करके निकला तो बाहर 200 बच्चे खड़े थे। एक बच्ची के हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। उसने कहा कि आपको अल्लाह ने हमारे लिए भेजा था।

मैं दो जन्नत देने का वादा करता हूं : उन्होंने कहा कि यहां के नेता दूसरों के बच्चें के सपने तोड़ उन्हें गुमराह करते हुए कहते हैं कि जन्नत मिलेगी। मैं आपको दो जन्नत देने को तैयार हूं। पहली जन्नत तो यह कश्मीर है। इसे संभालो, यह सिरमौर है। वहीं, जब आप एक अच्छे मुसलमान की तरह रहोगे तो दूसरी जन्नत मिलेगी।

अब झारखंड के सभी जिलों में दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को पीड़ित महिलाओं और बच्चियों के अधिकारों की रक्षा और मजबूती से करने के लिए दो अहम फैसले किए। पहला फैसला दुष्कर्म पीड़ित वर्ग के लिए लिया गया, जिसके तहत तय किया गया है कि सभी जिलों में अब दुष्कर्म और पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस) एक्ट के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुने जाएंगे। अब तक राज्य में ऐसे दो ही कोर्ट थे। अब 22 और कोर्ट के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार राज्य के सभी जिलों में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट उपलब्ध होंगे।

दूसरा अहम फैसला आया है एसिड अटैक पीड़ितों के लिए। इनके इलाज में अब पारिवारिक आमदनी की शर्त समाप्त कर दी गई है। साथ ही, पूर्व में पांच लाख रुपये तक खर्च की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है। अब इलाज में जितनी भी राशि खर्च होगी, सरकार भुगतान करेगी। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने 24 फैसलों पर अपनी स्वीकृति दी।

टेरर फंडिग में पीएलएफआइ सुप्रीमो सहित 11 के खिलाफ आरोपपत्र दायर

राज्य ब्यूरो, रांची

नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआइ) को टेरर फंडिंग के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने नक्सली संगठन पीएलएफआइ सुप्रीमो दिनेश गोप सहित 11 आरोपितों पर चार्जशीट दाखिल की है। इनमें दिनेश गोप को छोड़ शेष 10 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

रांची स्थित एनआइए की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में एनआइए ने बताया है कि 10 नवंबर 2016 को एक केस दर्ज हुआ था। उक्त केस नोटबंदी के वक्त 25.38 लाख के 500 व 1000 के पुराने नोट के साथ पेट्रोल पंप कर्मियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। तब बात सामने आई थी कि ये रुपये पीएलएफआइ सुप्रीमो दिनेश गोप के थे, जो लेवी-रंगदारी से जुटाए गए थे। इस मामले में रांची पुलिस ने 9 जनवरी 2017 को पहला आरोपपत्र दाखिल किया था। एनआइए ने टेरर फंडिंग के इस केस को टेकओवर करते हुए 19 जनवरी 2018 को नया केस पंजीकृत किया और अनुसंधान शुरू किया। एनआइए ने अदालत से दिनेश गोप को स्थायी भगोड़ा घोषित कर दिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एनआइए लगातार कोशिश कर रही है।

अनुसंधान के क्रम में एनआइए दिनेश गोप व उसके सहयोगियों के कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इनमें झारखंड, बंगाल व नई दिल्ली के ठिकाने शामिल हैं, जहां से अब तक 42.79 लाख रुपये नकदी, लैपटॉप, मोबाइल और लेवी-रंगदारी के रुपयों के निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए थे। इस केस में एनआइए ने करीब 70 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति भी जब्त की है।

तथ्य सामने आए : एनआइए की जांच यह बात सामने आई कि आरोपित विनोद कुमार, चंद्रशेखर कुमार, नंद किशोर महतो और मोहन कुमार पीएलएफआइ सुप्रीमो दिनेश गोप के खास आदमी हैं। इन्होंने आपराधिक साजिश के तहत पीएलएफआइ के लेवी-रंगदारी के रुपयों को जुटाने में मदद की।

यह बात भी सामने आई कि सुमंत कुमार, नंदलाल स्वर्णकार, चंद्रशेखर सिंह, अरुण गोप, जितेंद्र कुमार व नवीन भाई जयंती भाई पटेल तथा दिनेश गोप ने मिलकर लेवी-रंगदारी के रुपयों को शेल कंपनियों (मुखौटा) में खपाया। ये रुपये ठेकेदार, व्यवसायी व विकास परियोजनाओं से लेवी के रूप में उठाए गए थे।

शेल कंपनियों में निवेश

लेवी के रुपये जिन शेल कंपनियों में निवेश किए गए थे, उनमें मेसर्स शिव आदि शक्ति, मेसर्स शिव शक्ति समृद्धि इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स भव्य इंजीकॉन आदि शामिल हैं। ये कंपनियां दिनेश गोप के परिवार के सदस्यों के साथ पार्टनरशिप में संचालित हैं।

आचार्य बालकृष्ण और आयुर्वेद विवि के रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस

जागरण संवाददाता, नैनीताल

▸ छात्रों की याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट ने तीन सप्ताह में मांगा जवाब

▸ शासनादेश रद होने के बाद भी बढ़ी हुई फीस नहीं लौटाने का मामला

हाई कोर्ट ने आयुर्वेद कॉलेजों में बढ़ी हुई फीस का शासनादेश रद होने के बाद भी छात्रों को फीस नहीं लौटाने को गंभीरता से लिया है। इसके बाद भारतीय आयुर्वेद एवं अनुसंधान संस्थान, पतंजलि योगपीठ के निदेशक आचार्य बालकृष्ण, प्रधानाचार्य डीएन शर्मा, उत्तराखंड आयुर्वेद विवि की रजिस्ट्रार माधवी गोस्वामी को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

पिथौरागढ़ के शुभम पंत समेत दो दर्जन छात्रों ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पिछले साल नौ जुलाई को हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2015 को जारी शासनादेश रद कर दिया था। इस आधार पर आयुर्वेद कॉलेज के करीब 50 छात्रों ने याचिका दायर कर कहा कि उनसे बढ़ी हुई फीस न ली जाए। कोर्ट ने पुराने आदेश का हवाला देकर याचिका स्वीकार करते हुए संस्थान को बढ़ी हुई फीस न वसूलने और वसूली गई फीस का पैसा वापस करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फीस निर्धारण का अधिकार सिर्फ रेगुलेटरी कमेटी को है। इसके बाद भी संस्थान द्वारा फीस नहीं लौटाई जा रही है। याचिकाकर्ता के वकील विनोद तिवारी ने कोर्ट को बताया कि अदालत के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद आचार्य बालकृष्ण समेत अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। यहां बता दें कि आयुर्वेद कॉलेजों में 80 हजार सालाना फीस को बढ़ाकर दो लाख 15 हजार कर दिया था। मगर कोर्ट ने बढ़ी हुई फीस वाला शासनादेश रद कर दिया था।

बजरंग दल नेता की हत्या के 20 दोषियों को 10-10 साल की सजा

नईदुनिया, विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा में करीब तीन साल पहले हुई बजरंग दल नेता की हत्या के मामले में कोर्ट ने 20 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला लोक अभियोजक कालूराम मैना के मुताबिक, 12 नवंबर 2016 को कोतवाली थाना अंतर्गत गुठान क्षेत्र में बजरंग दल के तत्कालीन नगर संयोजक दीपक कुशवाह की हत्या कर दी गई थी। दीपक के भाई राकेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया था। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आत्माराम टांक ने मंगलवार को सद्दाम, अफजल, किश्वर, टीपू उर्फ मोहम्मद शादाब, कल्लू उर्फ मोहम्मद रफीक, नदीम खान, इकबाल, शालू उर्फ जुबेर, मोहम्मद आबिद, जावेद खां, मोहम्मद हनीफ, नवेद उर्फ छोटू, अजय राजपूत, नवेश उर्फ नवेद, गुड्डा उर्फ सोहेल, हसीफ खां, उवेश उर्फ इमरान खां, शानू खां, भय्यू पठान और इमरान उर्फ भज्जू को सजा सुनाई।

2000 के पार हो गई है बिहार की राजधानी पटना के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) में डेंगू मरीजों की संख्या। इस मौसम में पीएमसीएच में अब तक 2025 मरीज मिले हैं। पीएमसीएच में अब तक पिछले वर्ष की तुलना में 500 अधिक मरीज आए हैं।

न्यूज गैलरी

डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर फैसला आज

नई दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगा। डीके शिवकुमार ने चिकित्सकीय कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की अपील की है। शिवकुमार की जमानत याचिका को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि शिवकुमार एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जांच के दौरान उन्हें जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित व सुबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। (जासं)

मोदी-शाह के रहते आरक्षण पर खतरा नहीं : सुशील मोदी

पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह दुष्प्रचार किया जाता है कि भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, हकीकत है कि जब तक समाज में भेदभाव है आरक्षण जारी रहेगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार के रहते आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता है। पटना में रविदास कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मोदी सरकार ने एससी-एसटी एक्ट में 23 और नई धाराओं को जोड़ कर उसे और मजबूत तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिथिल की गई कुछ धाराओं को संसद में बिल पारित कर पुनर्स्थापित किया जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध माना। उन्होंने कहा कि भाजपा क्रीमी लेयर के विरोध में है। (राब्यू)

बंगाल में राज्यपाल की बैठक में नहीं पहुंचे ममता के अफसर

बढ़ी दूरियां ▶ राज्यपाल ने सरकार के व्यवहार को बताया 'असंवैधानिक'

कहा, ऐसा लग रहा कि बंगाल में है किसी तरह की सेंसरशिप

जागरण संवाददाता, कोलकाता

उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी के बाद मंगलवार को उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिलों में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से बुलाई गई बैठक में भी न तो आला प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और न ही वहां से निर्वाचित जनप्रतिनिधि। इससे क्षुब्ध राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार का व्यवहार 'असंवैधानिक' है। ऐसा लग रहा है, मानों बंगाल में किसी तरह की सेंसरशिप है। दरअसल, उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन ने सोमवार शाम ही राजभवन को पत्र भेजकर सूचित कर दिया था कि जिलाधिकारियों, सांसदों और विधायकों को बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजना राज्य सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। पत्र में यह भी कहा गया था कि सभी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उत्तर बंगाल में होने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशासनिक समीक्षा बैठकों के लिए 21 से 23 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों ने दावा किया कि उन्हें बैठक के लिए निमंत्रण ही नहीं मिला।

जगदीप धनखड़। फाइल

राज्यपाल ने इस पर कहा- 'मैं जिलाधिकारियों के पत्र देखकर हैरान हूं। उन्होंने बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। वह भी तब, जब उन्हें चार दिन पहले इस बाबत सूचना दे दी गई थी। क्या यह प्रतिष्ठा की लड़ाई है। ऐसा लगता है कि बंगाल में किसी तरह की सेंसरशिप है। राज्यपाल के साथ बैठक अथवा बातचीत के लिए भला अनुमति क्यों लेनी पड़गी। मुख्यमंत्री अथवा मंत्रियों के आने पर वे हाजिर होते हैं।' राज्यपाल ने आगे कहा- 'सबको पता है कि रेड रोड पर हुए पूजा कानिर्वल के दौरान चार घंटे किसकी पब्लिसिटी हुई थी।

सरकार छुट्टी पर गई है क्या: ममता सरकार पर तंज कसते हुए राज्यपाल ने कहा, 'क्या सरकार छुट्टी पर चली गई है। मुख्यमंत्री तो छुट्टी ले सकती हैं लेकिन कोई सरकार कैसे छुट्टी लेगी। क्या राज्यपाल राज्य के अधीन हैं। फिर प्रशासनिक अधिकारियों को मुझसे बात करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है।' राज्यपाल ने मंत्रियों द्वारा उन्हें लेकर दिए गए हालिया बयान पर कहा कि मुझे जवाब देने के लिए राज्य सरकार को अलग से एक मंत्री रखना चाहिए।

'बंगाल में चलता है ममता का संविधान': राज्यपाल के जिला दौरे में प्रशासनिक अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में देश का नहीं बल्कि ममता बनर्जी का संविधान चलता है। यही वजह है कि एक संवैधानिक प्रधान के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है।

'प्रशासनिक प्रधान देंगी राज्यपाल का जवाब': इस पूरे प्रकरण पर राज्य के शिक्षा मंत्री व तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा- 'मैं राज्यपाल की प्रत्येक बात का जवाब देना उचित नहीं समझता। निश्चित तौर पर प्रशासनिक प्रधान होने के नाते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमाम घटनाक्रमों पर नजर रखे हुई हैं और वह ही राज्यपाल की बातों का जवाब देंगी। राज्यपाल क्या बोल रहे हैं, ये उनकी मर्जी है।

'बांग्लादेशी घुसपैठियों ने 66 लाख बिहारियों को किया बेरोजगार'

जागरण संवाददाता, पटना

- बोले आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार
- कहा, भारत से पाकिस्तान गए 60 हजार से अधिक मुस्लिमों को आज तक नहीं मिली नागरिकता

'भारत में रहने वाले कुल बांग्लादेशी घुसपैठियों में से 80 फीसद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा असम में रहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने सिर्फ बिहार में ही 66 लाख लोगों के रोजगार पर कब्जा कर लिया है। वोट बैंक के कारण नेताओं ने घुसपैठिए और शरणार्थी के बीच के अंतर पर पर्दा डालने का काम किया है। भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) इससे पर्दा उठाने का माध्यम है।' ये बातें मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक सह राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के पटना चैप्टर ने एनआइसी, पीओके और बाल्टीस्तान की मुक्ति, बढ़ती जनसंख्या विकास के लिए चुनौती, जल व जलवायु संरक्षण तथा बढ़ता प्रदूषण विषय पर व्याख्यान आयोजित किया।

इंद्रेश ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थी हैं। वहां उन्हें धर्म के कारण परेशान किया गया। बहनों और बेटियों से दुष्कर्म किया गया। मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसी स्थिति में देश छोड़ने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, लेकिन बांग्लादेश से आए मुसलमान के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी। वह भारत में संसाधनों पर कब्जे के लिए आए। भारत से पाकिस्तान गए 60 हजार से अधिक मुस्लिमों को अभी तक नागरिकता नहीं मिली है।

एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं : उन्होंने कहा कि एनआरसी से डरने की

एएन सिन्हा इस्टीट्यूट में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के संगोष्ठी को संबोधित करते आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इन्द्रेश कुमार। जागरण

जरूरत नहीं है। रजिस्टर में नाम दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे देश के नागरिकों को जबरदस्ती बाहर कर दिया जाएगा। कई विकसित व इस्लामिक देशों में एनआरसी लागू है। इसे पूरे देश में लागू कर यह तय कर लिया जाए कि कितने भारतीय हैं, कितने शरणार्थी और कितने घुसपैठिए। इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सीपी ठाकुर ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है। विश्व की 16.5 फीसद आबादी भारत में रहती है। जबकि विश्व के कुल संसाधन का 3.5 फीसद ही भारत के पास है।

नाबालिग की याचिका पर एनजीटी ने सीपीसीबी से एक माह में रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली, प्रेट्र: ई-कामर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाने का निर्देश जारी करने संबंधी एक नाबालिग की याचिका पर एनजीटी ने मंगलवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने शीर्ष प्रदूषण निगरानी निकाय को एक महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

दरअसल, यह याचिका 16 वर्षीय एक छात्र आदित्य दुबे ने अपने अभिभावकों के माध्यम से दायर की है। इसमें कहा गया है कि उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट कार्डबोर्ड डिब्बे, कई परतों वाली प्लास्टिक शीट और प्लास्टिक बब्बल का इस्तेमाल करती हैं। इनवॉयस तक अलग प्लास्टिक में रखी होती है। यह प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग है। कंपनियां इस मसले पर अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रही हैं। याचिका में छात्र ने ई-कामर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाने का निर्देश जारी करने की मांग की है।

मीनेश दुबे और दिव्य प्रकाश पांडे के माध्यम से दायर की याचिका में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत आती हैं, लेकिन निगरानी और क्रियान्वयन एजेंसियों की कमी के चलते ये कंपनियां सामान वितरण के दौरान अत्यधिक प्लास्टिक का प्रयोग करती हैं।

बिहार में सेना में भर्ती के नाम पर ठगी, दो जवान गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटना

- एक अभ्यर्थी से लेते थे तीन से साढ़े तीन लाख रुपये, सेना कर रही दोनों से पूछताछ

बिहार में दानापुर छावनी में सेना बहाली में ठगी के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जालसाज सेना में भर्ती के नाम पर एक अभ्यर्थी से तीन से साढ़े तीन लाख रुपये वसूलते थे। इसके लिए पूरा गैंग काम कर रहा था। जेसीओ की सूझबूझ से ठगी के खेल का पर्दाफाश हुआ। एक जवान सुनील को पकड़ लिया गया है। सुनील मनेर का रहने वाला है। दूसरे जवान का नाम सेना नहीं बता रही है। उससे अभी पूछताछ की जा रही है।

आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट ने जवान सुनील से पूछताछ की है। हालांकि बाद में उसे बीआरसी (बिहार रेजीमेंट सेंटर)को सौंप दिया गया। मामले में पूर्व सैनिकों की संलिप्तता की बात भी सामने आई है। आरोपित से मिले कागजात की पड़ताल की जा रही है। इससे पूर्व बहाली के नाम पर ठगी के एक अन्य मामले में भोजपुर के सिपाही की भी जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार सिपाही सुनील बंगाल और दूसरा सिपाही पूर्वोत्तर के किसी राज्य में तैनात है। ये दोनों छुट्टी में घर आते थे और नौकरी के नाम पर युवाओं को जाल में फंसाते थे। सेना में नौकरी के नाम पर एक युवक से साढ़े तीन लाख तक की वसूली की जाती थी।

इस तरह पकड़ा गया : बीते शनिवार (19 नवंबर) को बीआरसी के पास सुनील कुमार को पकड़ा गया। वह कुछ युवकों से बहाली को लेकर बात कर रहा था। इसी क्रम में एक जेसीओ (जूनियर कमिशंड ऑफिसर) ने उससे पूछताछ की तो वह बाइक छोड़कर भाग निकला। आरोपित ने भागने के दौरान हेलमेट से जेसीओ के सिर पर वार करना चाहा। मगर ड्यूटी पर तैनात सेना के जवान और आर्मी इंटेलिजेंस ने सुनील को धर-दबोचा। पूछताछ में एससी-एसटी के प्रमाण पत्र में नाम बदल सेना में बहाली की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार मार्च में भी सुनील को संदिग्ध युवकों से बात करते हुए पकड़ा गया था, बाद में छोड़ दिया गया था। उस पर आर्मी इंटेलिजेंस नजर रख रही थी। करीब पांच साल पूर्व सेना में जाने के बाद सुनील बहाली के दौरान छुट्टी लेकर घर आता था।

तलाक लेकर पेड़ से करो शादी फिर दोबारा से मुझसे रचाओ ब्याह

नईदुनिया, भोपाल

- भोपाल में मांगलिक पति के सामने पत्नी ने रखी अनूठी शर्त
- पत्नी का आरोप-मांगलिक होने की बात छुपाकर की शादी
- मंगल दोष के कारण उसको महसूस हो रहा जान का खतरा

भोपाल में महिला थाने के परिवार परामर्श केंद्र में घरेलू विवाद का एक अनूठा मामला पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ अधिकारी की पत्नी ने शिकायत की थी कि पति ने धोखे में रखकर शादी की और अपने मांगलिक होने की बात छुपाई। दोनों की दोबारा काउंसिलिंग की गई तो पत्नी ने कहा कि मंगल दोष के कारण उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। इस दौरान पत्नी ने शर्त रखी कि पति पहले उसे तलाक दे, फिर पेड़ से शादी करे और इसके बाद फिर उससे ब्याह रचाये। पति ने इस शर्त को मानने से इन्कार कर दिया है। मामला रचना नगर में रहने वाले परिवार का है। परामर्श केंद्र में दंपती को 20 दिन का समय दिया गया है, जिससे वह विवाद को सुलझा सकें।

दंपती की शादी को चार साल हुए हैं और उनकी डेढ़ साल की बेटी है। बताया जाता है कि दो माह पहले स्टोर रूम की सफाई के दौरान पत्नी को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें पति के जन्म की तारीख और समय दर्ज था। शादी के समय दी गई कुंडली में जन्म की तारीख और समय कुछ और था। जब पत्नी ने डायरी से मिले जन्म की तारीख व समय से कुंडली बनवाई तो पंडित ने पति को मांगलिक बताया। इसके बाद से विवाद शुरू हो गया।

> दोनों पक्षों को समझाकर साथ रहने के लिए भेजा गया है, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं है। उसने शर्त रखी है कि तलाक लेने के बाद पहले पेड़ से शादी को फिर वह उससे शादी कर लेगी। पति इसे पत्नी का अंधविश्वास मान रहा है और वह इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है।
>
> **- मोहिब अहमद, काउंसलर, परिवार परामर्श केंद्र**

एक ही घर में बेगानों की तरह रह रहे : पति ने काउंसलर को बताया कि पत्नी का अंधविश्वास खत्म नहीं हो रहा है। दोनों एक ही घर में बेगानों की तरह रह रहे हैं। पत्नी कई ज्योतिषियों और लोगों से मिलकर मंगल दोष का तोड़ पूछ रही है। इसी के चलते उसने शर्त रखी है कि हम दोनों को अभी तलाक ले लेना चाहिए। इससे यदि मंगल दोष का थोड़ा भी प्रभाव मेरे ऊपर हुआ होगा तो उससे मैं मुक्त हो जाऊंगी। इसके बाद तुम पेड़ या घड़े से शादी कर लो, इससे तुम्हारा मंगल दोष निवारण हो जाएगा। फिर साल भर बाद हम दोबारा शादी कर लेंगे। पति का कहना है कि इन सभी बातों को वह नहीं मानता और इतना सब नहीं कर सकता है।

मंगल दोष का निवारण करना होगा : उधर, पत्नी का कहना है कि जब से उसे इस बात का पता चला है, तब से वह मानसिक रूप से बहुत परेशान है। अब भी लोग मांगलिक दोष के निवारण के लिए कुछ न कुछ करते हैं। कई लोग मंगल दोष के निवारण के लिए पेड़ से शादी करते हैं, जिससे निवारण होता है। ज्योतिषी भी ऐसा ही करने की सलाह दे रहे हैं।

तेजपाल पर यौन शोषण मामले में पीड़िता से लगातार दूसरे दिन जिरह

- बचाव पक्ष बुधवार को भी जारी रखेगा जिरह

पणजी, प्रेट्र : तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराने वाली महिला से गोवा की अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन जिरह की। महिला पहली बार सोमवार को सुनवाई के लिए अदालत में पेश हुई थी। मामले की सुनवाई बंद कमरे में हो रही है।

तेजपाल के खिलाफ उसकी पूर्व सहकर्मी द्वारा दर्ज कराए गए इस मामले की उत्तरी गोवा के मापुसा कस्बे में जिला जज शमा जोशी सुनवाई कर रही हैं। मंगलवार को जिरह के दौरान तरुण तेजपाल भी अदालत में मौजूद थे। बाद में तेजपाल के वकील राजीव गोम्स ने बताया कि महिला से जिरह बुधवार को भी जारी रहेगी।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में गोवा कोर्ट को छह महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए कहा था। साथ ही तरुण तेजपाल की उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद करने संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। तेजपाल ने कथित तौर पर 2013 में पीड़िता का गोवा के एक पंच सितारा होटल के ऐलीवेटर में यौन शोषण किया था। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इन्कार किया है। अदालत

तरुण तेजपाल। फाइल

से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अपराध शाखा ने तेजपाल को 30 नवंबर, 2013 को गिरफ्तार कर लिया था।

वह मई, 2014 से जमानत पर हैं। पिछले साल सितंबर में जिला अदालत ने तेजपाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। इससे पहले उन्होंने आरोप तय किए जाने पर रोक के लिए बांबे हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

मप्र में मैंथा प्लांट के टैंक में दम घुटने से दो चचेरे भाइयों की मौत

नईदुनिया, छतरपुर (ईशानगर): मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ईशानगर थाना क्षेत्र के ग्राम कटारे का पुरवा में मैंथा प्लांट में दम घुटने से चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाइयों को बचाने गए दो अन्य ग्रामीण भी जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गए। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, ईशानगर से लगभग चार किमी दूर स्थित ग्राम कटारे का पुरवा में हरि पटेल के खेत में पिपरमेंट (मैंथा) का प्लांट लगा है। यह प्लांट कुछ समय से बंद था, जिसे फिर से शुरू करने के लिए सोमवार शाम करीब सात बजे हरि पटेल का 25 वर्षीय पुत्र शिवम टैंकनुमा प्लांट में लगे जाले साफ करने उतरा। कुछ देर में वह बेहोश हो गया। काफी देर तक उसकी आहट नहीं मिली तो उसका चचेरा भाई चरण सिंह मौके पर पहुंचा। चरण सिंह भी प्लांट के अंदर कूद गया और उसे निकाल पाता, इससे पहले वह भी बेहोश हो गया। खेत पर काम कर रही शिवम की मां की सूचना पर ग्रामीण पहुंचे। दोनों को निकालने के लिए दो युवक मंगल पटेल और रवि पटेल उतरे। जहरीली गैस से वे भी बेहोश हो गए। ग्रामीण कसी तरह चारों को निकालकर अस्पताल ले गए। जहां शिवम और चरण को मृत घोषित कर दिया गया।

चिन्मयानंद प्रकरण में एसआइटी ने हाई कोर्ट में पेश की प्रगति रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- आवाज की जांच रिपोर्ट न मिलने पर 28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
- पीड़िता की अर्जी पर कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर एलएलएम छात्रा से दुष्कर्म व पीड़िता के खिलाफ लगे ब्लैकमेल के आरोपों की जांच कर रही एसआइटी ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की। कोर्ट को बताया कि स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये मांगने के लिए किए गए फोन कॉल (आवाज) की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 नवंबर तय करते हुए जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र व न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दायर जनहित याचिका की निगरानी हाई कोर्ट की खंडपीठ कर रही है।

पीड़िता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रविकिरण जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने पीड़िता की एक अर्जी पर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया। इसमें चिन्मयानंद के खिलाफ पीड़िता की ओर से बहुत पहले नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई गई है। उस मामले की अलग से जांच की मांग की। बताया गया कि एसआइटी उस मामले की भी जांच कर रही है। वहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार से इस अर्जी पर भी जवाब मांगा है।

> **जमानत पर छह नवंबर को होगी सुनवाई**
>
> स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने की आरोपित दुष्कर्म पीड़िता की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार व चिन्मयानंद के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। इस मामले में सुनवाई छह नवंबर को होगी। इस अर्जी की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने की। अर्जी में झूठा फंसाने का आरोप लगाते हुए जमानत पर छोड़ने की मांग की गई है।

पीएफ के सहायक आयुक्त की तीन करोड़ की संपत्ति जब्त

जागरण संवाददाता, कोलकाता : रिश्वत लेने के आरोपों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भविष्य निधि (पीएफ) के सहायक आयुक्त की करीब तीन करोड़ की चल-अचल संपत्ति को जब्त किया है।

आय के स्रोतों के बाबत ईडी शीघ्र ही उनसे पूछताछ भी करेगी। सूत्रों के अनुसार, कोलकाता स्थित पार्क स्ट्रीट के पीएफ कार्यालय में तैनाती के दौरान सहायक आयुक्त रमेश सिंह पर विभिन्न माध्यमों से 6-7 करोड़ रुपये घूस लेने का आरोप लगा था। जांच में जुटे ईडी अधिकारियों को उनके घर की तलाशी में महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। दस्तावेजों की जांच के बाद मंगलवार को ईडी ने सहायक आयुक्त के मकान, गाड़ी सहित करीब तीन करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली। ईडी सूत्रों के अनुसार, रुपये लेने के बदले सहायक आयुक्त ने कई गैर कानूनी कार्य किए थे। इस काम में एक गिरोह भी उनकी मदद करता था। गलत तरीके से कमाए गए करोड़ों की रकम से उन्होंने कोलकाता में मकान सहित अन्य संपत्तियां खरीद ली थीं। सूत्रों के अनुसार सहायक आयुक्त से गलत कार्यों में शामिल अन्य लोगों के बारे में शीघ्र ही पूछताछ की जाएगी।

आध्यात्मिक गुरु कल्कि की पत्नी व पुत्र से आयकर विभाग ने की पूछताछ

- छापेमारी में 500 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्तियों का हुआ है पर्दाफाश
- छापे के दौरान विदेश में अघोषित निवेश के साक्ष्य भी हाथ लगे थे
- चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चित्तूर व कुप्पम के 40 ठिकानों पर की गई थी छापेमारी

चेन्नई, एएनआइ: आध्यात्मिक गुरु कल्कि भगवान की पत्नी पद्मावती व बेटा कृष्णा मंगलवार को यहां आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों ने उनसे संपत्तियों के संबंध में पूछताछ की। आयकर विभाग ने गत दिनों उनके ठिकानों पर छापेमारी करते हुए करीब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित संपत्तियों का पता लगाया था।

कृष्णा की कंपनी ह्वाइट लोटस के चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चित्तूर व कुप्पम स्थित परिसरों में छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने 44 करोड़ रुपये नकद, 90 किलो सोने के गहने व 20 करोड़ रुपये मूल्य के अमेरिकी डॉलर आदि जब्त किए थे। कुल जब्ती 105 करोड़ रुपये के मूल्य की थी। इसके अलावा आयकर विभाग ने 409 करोड़ रुपये की बेहिसाब प्राप्ति रसीद (कैश रिसिप्ट), 115 करोड़ रुपये के अघोषित बैंक खाते व 85 करोड़ रुपये का हवाला के जरिये विदेश में निवेश का पता लगाया था।

छापे के दौरान विदेश में अघोषित निवेश के साक्ष्य भी हाथ लगे थे। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चित्तूर व कुप्पम के 40 ठिकानों पर की गई छापेमारी में 300 अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे।

> **'देश छोड़कर नहीं भाग रहा'**
>
> आइएएनएस के अनुसार, आध्यात्मिक गुरु कल्कि ने देश छोड़कर भागने की अफवाहों का खंडन किया। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, 'सरकार या आयकर विभाग ने कहा है कि हम देश छोड़ चुके हैं। यह गलत है। मैं अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तमिलनाडु के नेमम में हूं। हम दोनों देश नहीं छोड़ेंगे। वास्तव में हम अब ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। आश्रमों की गतिविधियां पहले की तरह चलती रहेंगी।'

पुरी को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए खर्च होंगे 3,208 करोड़

जागरण संवददाता, भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार समुद्र तट के किनारे स्थित धार्मिक नगरी पुरी को विश्व स्तरीय शहर बनाएगी। इसके लिए आगामी तीन सालों में इस शहर के विकास पर 3,208 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुरी में 2019-20 और 2021-22 के बीच तीन वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, विरासत और वास्तुकला के विकास (एबीएडीएचए) के तहत 3,208 करोड़ रुपया खर्च करने का निर्णय लिया गया है। पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है। यहां देश-विदेश से लोग दर्शन के लिए आते हैं। पुरी में रथयात्रा भी निकाली जाती है। मान्यता है कि रथ खींचने से मोक्ष मिलता है। इस कारण रथयात्रा के दौरान पुरी में भक्तों की काफी भीड़ जुटती है।

उसी तरह से पुरी गोवर्द्धन पीठ के संचालन का अधिकार जगतगुरू शंकराचार्य के पास होगा। इसका संचालन अब हिंदू देवोत्तर अधिनियम के अनुसार नहीं किया जाएगा। अब यह मठ सरकारी नियंत्रण में नहीं होगा।

कवायद

..ताकि नेपाल की नदियां न मचा सकें तबाही

पूर्वांचल व बिहार में बाढ़ से बचाव के उपाय सुझाएगी गंडक की हाईपावर कमेटी, चार दिन में संवेदनशील 12 तटबंधों का निरीक्षण, मंथन करेगी विशेषज्ञों की टीम

राजेश्वर शुक्ला, गोरखपुर

नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार में बाढ़ से हुई तबाही का आकलन करने के साथ 2020 में इसकी पुनरावृत्ति टालने की कवायद तेज हो गई है। गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन के चेयरमैन समेत उत्तर प्रदेश, बिहार के प्रमुख अभियंताओं वाली गंडक की उच्च स्तरीय स्थाई समिति चार दिन कुशीनगर में रहकर गंडक नदी पर नेपाल के वाल्मीकि बैराज से लेकर उत्तर प्रदेश के आखिरी गांव अहिरौली तक 12 संवेदनशील, अतिसंवेदनशील तटबंधों का निरीक्षण करेगी। नेपाल की कई नदियां मिलकर वाल्मीकि बैराज के पास गंडक नदी का रूप धारण करती हैं।

गंडक नदी नेपाल के नवलपरासी से लेकर महराजगंज, कुशीनगर व बिहार में तबाही मचाती है। इसे रोकने के लिए उच्च स्तरीय समिति कटान निरोधक कार्यों को अनुमोदित करती है, जिस पर उत्तर प्रदेश व बिहार सरकार काम करती है। गंडक की यह हाईपावर कमेटी 23 अक्टूबर को कुशीनगर आ रही है। पहले दिन अहिरौली-पिपराघाट (एपी) तटबंध, दूसरे दिन अमवाखास, नरवाजोत, छितौनी व बिहार के तटबंध पर हुए नुकसान की पड़ताल

प्रतीकात्मक

करेगी। 25 अक्टूबर को महराजगंज के नारायणी, नेपाल के ए तथा बी गैप, लिंक व अन्य तटबंध का निरीक्षण होगा। 26 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्यों पर मुहर लगेगी।

कमेटी में सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे के निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान पटना के मुख्य अभियंता (रिसर्च), उत्तराखंड रुड़की के सिंचाई अनुसंधान संस्थान के निदेशक, प्लानिंग, प्रोग्राम व कोआर्डिनेशन खंड नेपाल सरकार के उपनिदेशक तथा मुख्य अभियंता, पश्चिमी कैनाल, नवलपरासी, नेपाल भी शामिल रहेंगे।

> **भारत करता है नेपाल के चार बंधों का रख-रखाव**
>
> इंडो-नेपाल संधि के तहत नेपाल के चार तटबंधों और मुख्य कैनाल गंडक का रखरखाव भारत सरकार करती है। यह बांध नवलपरासी में गंडक बैराज से लेकर महराजगंज की सीमा तक नेपाल के ए, बी गैप, लिंक व नेपाल तटबंध नाम से हैं। यहां बाढ़ निरोधक कार्यों को करने की अनुमति हाईपावर कमेटी देती है।

> गंडक की हाईपावर कमेटी में नेपाल के भी प्रतिनिधि हैं। इस दौरे में नेपाल के निचले हिस्से में जल भराव की समस्या को दूर करने के उपायों पर भी मंथन होगा। महराजगंज व कुशीनगर के तटबंधों को सुरक्षित करने के साथ नेपाल के धोबा ड्रेन पर चार जगह पुल बनाए जाएंगे।'
>
> **-एके सिंह, प्रमुख अभियंता, सिंचाई व जल संसाधन विभाग**

कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई आज

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 बागी विधायकों की तरफ से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टाल दी। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। कांग्रेस-जदएस के बागी विधायकों ने दलबल कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने के मामले को चुनौती दी है।

मामले की सुनवाई जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ कर रही है। बागी विधायकों ने कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर दिसंबर में होने वाले चुनाव में शामिल होने की अंतरिम अनुमति दिए जाने की मांग भी की है।

कर्नाटक के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने इन बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। इसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी और विधानसभा सीटें खाली हो गई थीं। पहले इन सीटों पर 21 अक्टूबर को ही चुनाव होने थे, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने तिथियों में बदलाव करते हुए इसे पांच दिसंबर कर दिया था।

जेल में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह की जान को खतरा बता मांगी सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- डेरा सच्चा सौदा अस्पताल के डॉक्टर ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका
- याची ने शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देने का लगाया आरोप

डेरा सच्चा सौदा अस्पताल के डॉक्टर मोहित गुप्ता ने हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सुनारिया जेल में बंद डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह की जान को खतरा है। याचिका में गुरमीत सिंह को कोर्ट में पेश करने की मांग करते हुए उनकी सुरक्षा की मांग की गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि जेल प्रशासन राम रहीम से उनको मिलने भी नहीं दे रहा है। जेल नियमों के तहत उनको फोन करने की सुविधा भी नहीं दी जा रही। इस बाबत उन्होने सूचना के अधिकार के तहत जेल नियमों की जानकारी मांगी थी कि एक कैदी के क्या अधिकार हैं, लेकिन उनको यह जानकारी भी नहीं दी गई।

याचिका में जेल अधीक्षक के वाहन चालक के पिता, जो जेल के बाहर चाय की दुकान संचालित करते हैं, का हवाला देकर बताया गया कि जेल में गुरमीत सिंह को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। यह जेल कहने को तो सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन पिछले एक साल में इस जेल में दर्जनों गैंगवार और फोन मिलने की घटनाएं हो चुकी हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि जेल में यहां बड़े अपराधियों को रखा जा रहा है, जो डेरा प्रमुख के लिए किसी खतरे से कम नहीं हैं। साथ ही याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि लोकसभा चुनाव में एक नेता ने उन पर अपनी पार्टी को समर्थन देने का दबाव भी बनाया था। मंगलवार को याची ने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि वह इस याचिका पर तुरंत सुनवाई के आदेश दें ताकि डेरा प्रमुख की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

दैनिक जागरण

सात्विक भोजन मन को शुद्ध करता है

सोशल मीडिया पर लगाम

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया। अब इन सभी याचिकाओं की सुनवाई वह स्वयं करेगा। इन याचिकाओं के संदर्भ में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसकी ओर से अगले तीन माह में सोशल मीडिया संबंधी नियम तैयार कर लिए जाएंगे। इन नियमों के बारे में अभी कुछ कहना कठिन है, लेकिन ऐसे सवाल उठ खड़े होना स्वाभाविक है कि आखिर सरकार को ऐसे कोई नियम क्यों तैयार करने चाहिए? यह अंदेशा भी प्रकट किया जा रहा है कि कहीं नियम बनाकर सरकार सोशल मीडिया की निगरानी तो नहीं करने लगेगी? ऐसे सवाल और संदेह के बीच इस सच की अनदेखी नहीं की जा सकती कि पूरी दुनिया के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या बना गया है। यह समस्या इसलिए और विकट हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए कोई कारगर व्यवस्था नहीं कर रही हैं। जब उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित करने का शोर मचने लगता है। यह शोर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सोशल मीडिया के नियमन की कोई जरूरत नहीं। सच तो यह है कि इसकी जरूरत कहीं अधिक बढ़ गई है। इसका कारण यही है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग सभ्य समाज के समक्ष गंभीर संकट पैदा कर रहा है।

सरकारों के साथ उसकी एजेंसियों के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकना कठिन हो रहा है। सरकारी एजेंसियों की ओर से सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल को रोकने के जो थोड़े-बहुत उपाय किए गए हैं वे इसलिए बेअसर साबित हो रहे हैं, क्योंकि फर्जी एवं अधकचरी खबरों के जरिये दुष्प्रचार अभियान चलाने और सामाजिक ताने-बाने को क्षति पहुंचाने अथवा किसी को बदनाम करने वाला एक संगठित उद्योग खड़ा हो चुका है। यह एक ऐसा उद्योग है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा बन रहा है। आखिर कौन भूल सकता है कैंब्रिज एनालिटिका नामक कंपनी की उस कारस्तानी को जिसने फेसबुक का डाटा चोरी कर कई देशों के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की थी? ऐसे व्यापक छल-कपट को देखते हुए यह आशा करना व्यर्थ है कि सरकारें सोशल मीडिया का नियमन करने के कोई उपाय न करें। नियमन की जरूरत इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियां अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं। इसकी गिनती करना कठिन है कि फेसबुक सरीखी नामी कंपनी ने डाटा चोरी के मामले में कितनी बार मिथ्या जानकारी देकर लोगों को भरमाने की कोशिश की है।

हिमाचल की सेहत

स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। यदि रुपया-पैसा हाथ से निकल जाए तो उसे फिर हासिल किया जा सकता है, लेकिन एक बार स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे पुरानी स्थिति में लाना बहुत कठिन होता है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन के समस्त सुखों का आधार है। बदलते समय के साथ लोग स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं। वे लोग, जो तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं, वे जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन अब भी बड़ा वर्ग ऐसा है, जो स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है। हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। नीति आयोग के मानकों के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन पर जारी की गई रैंकिंग इसे साबित भी करती है। चिंताजनक है कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी जिला 100 में से 50 फीसद अंक भी हासिल नहीं कर सका है। बिलासपुर जिला प्रदेश में 47.78 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर, जबकि लाहुल स्पीति 27.25 अंकों के साथ अंतिम स्थान पर है। कुल्लू एवं शिमला जिलों की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है। दोनों जिलों ने रैंकिंग में क्रमशः नौवां और दसवां स्थान पाया है। नीति आयोग द्वारा जारी की गई सभी राज्यों की रैंकिंग में भी हिमाचल एक पायदान नीचे चला गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन में जनजातीय जिले चंबा में बहुत अधिक कमियां पाई गई हैं। वहां पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ऑनलाइन डाटा तैयार नहीं किया जा रहा है और चिकित्सकों की कमी के साथ अन्य सुविधाओं का भी अभाव है। लाहुल स्पीति में घरों के बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण और उपकरणों के साथ अन्य सुविधाओं की कमी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के लिए यह रैंकिंग चेतावनी है, जिससे सबक लेकर भविष्य में स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर अधिक गंभीर होने की जरूरत है। मामला लोगों की सेहत से जुड़ा है, इसलिए इसमें लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। जिन कारणों से प्रदेश के प्रदर्शन में गिरावट आई है, उन्हें दूर करने के लिए अभी से प्रयास करने की जरूरत है, ताकि अगली बार ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।

नीति आयोग की रैंकिंग स्वास्थ्य विभाग को आईना दिखाने वाली है। सबक लेकर बेहतर नियोजन कर खामियां दूर की जानी चाहिए

तथ्यों की कसौटी पर लिखा जाए इतिहास

ए. सूर्यप्रकाश

उन लोगों के चेहरे बेनकाब होने ही चाहिए जिन्होंने हमारे स्वर्णिम अतीत को स्याह बनाने की हरसंभव कोशिश की है

अवधेश राजपूत

आजादी के बाद छह दशकों तक देश में 'लुटियन समूह' का बोलबाला रहा। इसमें नेहरूवादी-मार्क्सवादी और छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों का जमावड़ा रहा जो कुछ असहमतियों के बावजूद वैचारिक सहोदर हैं। उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर लोक नीतियों और इतिहास लेखन तक को प्रभावित किया। अपने इस प्रभाव से वे ऐसा झूठा विमर्श खड़ा करने में सफल रहे जिसने भारतीय सभ्यता पर प्रहार करते हुए उसे लगातार कमजोर किया ताकि वह समय के साथ विस्मृत होती जाए। इससे वे स्वतंत्रता के बाद जन्मीं भारत की तीन पीढ़ियों को उनकी स्वर्णिम विरासत से दूर रखने में सफल रहे। उन्होंने भारतीयों के मन में अपने अतीत को लेकर हीनता और शर्म का भाव भी भर दिया। इस मोर्चे पर सबसे ज्यादा नुकसान वामपंथी नेताओं, नौकरशाहों और अकादमिक तबके ने किया। उन्होंने स्कूली किताबों से लेकर इतिहास के उच्च अध्ययन पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु को विकृत किया। साथ ही ऐसे विधायी कदम उठाए और सरकारी नीतियां बनाईं जिससे आम जनमानस अपनी खुद की संस्कृति और परंपराओं से परहेज करने लगे।

सदियों से भारत की सभ्यतागत पहचान हिंदुत्व से जुड़ी थी तो इस तबके की व्यापक योजना हिंदू विरोध ही बन गई। उसने हिंदुत्व से जुड़ी चीजों के प्रति नकारात्मकता और हिंदू विरोधी बातों को प्रोत्साहन देने का काम किया। नफरत और विरोध की इस आग का दायरा कई क्षेत्रों तक फैलता गया जिसमें वेदों, रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों का उपहास उड़ाना, योग और आयुर्वेद को खारिज करना और सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत की लानत-मलानत करना शामिल था। दुनिया में अन्यत्र ऐसी कोई मिसाल मिलना मुश्किल है जहां कुछ लोगों का समूह देश की बड़ी आबादी को उनकी सभ्यता एवं संस्कृति से दूर करने में सफल रहा हो। यह वर्ग 67 वर्षों तक अपनी इस मुहिम में कामयाब रहा। इसमें 1998 से 2004 के बीच राजग सरकार के छह वर्षों का कार्यकाल भी शामिल है। सत्ता की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में आने के बाद ही वे अपनी नियति को प्राप्त हुए, जब 2014 में भारतीय जनता उनसे त्रस्त आ गई और उसने नेहरूवादी-मार्क्सवादी ब्रिगेड को उनके अड्डों से बेदखल करने का फैसला किया। 2019 के आम चुनाव में जनता ने अपने उसी जनादेश को दोहराया। इससे विमर्श बदलने की प्रक्रिया में निरंतरता का भाव आया और विश्व में प्राचीन भारतीय सभ्यता के अद्भुत योगदान को स्वीकारने, सराहने का सिलसिला शुरू हुआ।

भारतीय जनता ने छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी तबके को जब हाशिये पर पहुंचा दिया है तब राष्ट्रीय गौरव की पुनर्स्थापना प्रक्रिया भी अवश्य आरंभ की जानी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा इतिहास के पुनर्लेखन के आह्वान को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। शाह ने तमाम उदाहरण गिनाए, मगर उन्होंने वीर सावरकर का विशेष उल्लेख किया जिन्होंने 1857 को स्वतंत्रता के पहले संग्राम की संज्ञा दी थी जबकि इतिहासकारों ने उसे अंग्रेजों के खिलाफ महज एक बगावत माना था। शाह ने सही कहा कि हमें ऐसा इतिहास लिखना चाहिए जो तथ्यों से न्याय करे। जैसे औरंगजेब की ही मिसाल लें। वर्ष 1669 में उसने अपने सेनापतियों को हिंदू मंदिरों के विध्वंस का आदेश दिया। इनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और मथुरा के बेहद पवित्र मंदिर शामिल थे। उसने मथुरा में मंदिर ध्वस्त कर एक विशाल मस्जिद बनवाई और भगवान कृष्ण की मूर्ति को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन करा दिया ताकि मुस्लिम श्रेष्ठता कायम हो सके।

औरंगजेब हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम अपनाने वालों को सरकारी नौकरियां देता था। सजा में छूट भी एक लुभावनी पेशकश हुआ करती थी। हिंदुओं द्वारा मंगाई जानी वस्तुओं पर उसने कर बढ़ाया और जजिया कर भी थोप दिया। उसने सिख गुरुद्वारों को भी नहीं बख्शा। गुरु तेगबहादुर को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया और इस्लाम अपनाने से इन्कार करने पर उनका सिर कलम करवा दिया। गुरु गोविंद सिंह के दौर में भी सिखों पर उसके जुल्म जारी रहे और उसने उनके बेटों की हत्या करा दी। ये औरंगजेब की कुछ करतूतें हैं। फिर भी तमाम इतिहासकारों ने तथ्यों की अनदेखी कर उसे एक 'सेक्युलर' व्यक्ति बताया। अगर विकृत इतिहास लेखन के लिए कोई पुरस्कार होता तो ऐसा इतिहास लिखने पर वह शर्तिया मिल जाता। क्या छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी दिल्ली के दिल में एक प्रमुख सड़क का नामकरण ऐसे आततायी के नाम पर करने के पीछे का तर्क बता पाएंगे?

भारत के छोटे-बड़े शहरों में तमाम सड़कों का नामकरण इस अपराधी शासक के नाम पर हुआ। यह इसलिए संभव हुआ, क्योंकि हिंदुत्व से नफरत करने वाले ही विमर्श गढ़ने की दिशा नियंत्रित कर रहे थे। इसी तर्ज पर बाबर, हुमायूं और जहांगीर जैसे बर्बर जुल्म ढाने वालों को भी राजधानी सहित देश के अन्य इलाकों में बहुत सम्मान दिया गया। ऐसे अपराधियों से जुड़े प्रतीकों को कायम रखकर भारत कब तक सेक्युलर एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र बना रह सकता है? यदि हमें संविधान की रक्षा करनी है और हम अपनी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक परंपराओं को सहेजना चाहते हैं तो इतिहास की पुस्तकों में इस सच को शामिल करना होगा। हमारी लोक नीतियां भी संविधान के बुनियादी मूल्यों के आधार पर बननी चाहिए। इसका अर्थ यही होगा कि ऐसी भयावह स्मृतियों के अवशेषों को हमेशा के लिए दफन करना होगा। सौभाग्य से दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब उसे बेहद सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया है। औरंगजेब की श्रेणी में आने वाले दूसरे नामों के साथ भी यही सुलूक किया जाए। उनके साम्राज्य से जुड़े कड़वे सच और कट्टरता के किस्से पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनने चाहिए। ऐसा करके ही सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत का भविष्य ऐसी कट्टरता में नहीं, बल्कि वास्तविक लोकतंत्र में निहित है जहां समता एवं समानता का सिद्धांत ही मूलमंत्र है।

भारत को अपना बसेरा बनाने वाले फ्रांसीसी पत्रकार फ्रेंकोइस गुटेर और बेल्जियन विद्वान कोनार्ड एल्स्ट ने भारतीयों को उस धोखेबाजी को लेकर चेताया है जो वामपंथी नेता, अकादमिक एवं नौकरशाह करते आए हैं। गुटेर अर्से से भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की दुहाई दे रहे हैं। एल्स्ट ने उन मार्क्सवादी इतिहासकारों को निशाना बनाया है जिन्होंने हिंदू प्रतीकों को मिटाने की मुहिम चलाई और जिन्हें वामपंथी सोच वाले कथित सेक्युलर नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का साथ मिला। भारतीय राज्य ने भी इसमें सहयोग दिया। एल्स्ट का कहना है कि भारतीय अंग्रेजीदां अभिजात्य वर्ग के लिए भारतीय सभ्यता को तिलांजलि देना ही फैशन बन गया। गृहमंत्री की बातों का सार भी यही है। अब उन लोगों के चेहरे बेनकाब होने ही चाहिए जिन्होंने हमारे स्वर्णिम अतीत को स्याह बनाने की हरसंभव कोशिश की।

(लेखक प्रसार भारती के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

कत्ल होता कानून का शासन

राजीव सचान

सभ्य समाज के लिए इससे बुरी बात और कोई नहीं कि कोई किसी के सिर इनाम रखे और फिर भी उसका कुछ न बिगड़े

इससे इन्कार नहीं कि 2016 में गुमनाम से हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी ने पैगंबर साहब को लेकर अपने एक बेजा बयान से मुस्लिम समाज को उद्वेलित करने का काम किया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि उनका एक तरह से एलानिया कत्ल कर दिया जाता। दुर्भाग्य से ऐसा ही किया गया और वह भी तब जब उन्हें अपने उक्त बयान के कारण करीब एक साल तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में रहना पड़ा। कमलेश की गिरफ्तारी के बाद भी उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन किए गए। मालदा, पश्चिम बंगाल में हुए ऐसे ही प्रदर्शन में एक पुलिस थाने समेत कई वाहन जला दिए गए थे। इसके अलावा बिजनौर के एक मौलाना और एक मुफ्ती ने कमलेश तिवारी का सिर कलम करने वाले को डेढ़ करोड़ रुपये का इनाम देने का एलान किया था। इस पैसे के साथ सोने का एक मुकुट भी देने की पेशकश की गई थी। अगर कोई यह सोच रहा है कि इसके बाद इस मौलाना और मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया होगा तो वह गलत है। इन दोनों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन बीते दिनों तब जब कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई। इसका सीधा-सरल मतलब यही निकला कि करीब तीन साल तक किसी ने यह नहीं समझा कि इस तरह किसी के सिर इनाम रखने से कानून के शासन की हेठी होती है और उसका मजाक भी उड़ता है। कहना कठिन है कि इस मुफ्ती और मौलाना का कमलेश तिवारी की हत्या से कोई लेना-देना है या नहीं, लेकिन सभ्य समाज के लिए इससे बुरी बात और कोई नहीं कि कोई किसी का सिर काटने की जरूरत जताए और फिर भी उसका बाल बांका न हो।

यह पहली बार नहीं जब किसी ने किसी के सिर पर इस तरह इनाम रखा हो। अपने देश में इस तरह का काम होता ही रहता है और मुश्किल से ही ऐसे लोगों पर कोई कारगर कार्रवाई होती है। रह-रहकर जिस-तिस का सिर, जीभ, नाक काटने की धमकी देना इतना आम हो चला है कि इस पर भरोसा करना कठिन है कि देश में कानून का राज है। ऐसी धमकियां देने वालों के खिलाफ कभी-कभार कार्रवाई होती भी है, लेकिन आम तौर पर वह इतनी मामूली किस्म की होती है कि ऐसे लोगों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उलटे वे और चर्चित हो जाते हैं। सूरजपाल अम्मू और अकबरुद्दीन ओवैसी इसके सटीक उदाहरण हैं। कमलेश तिवारी की हत्या के बाद खुद को शिवसेना नेता बताने वाले अरुण पाठक ने उनके हत्यारों को मारने वालों को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। 2006 में बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी ने पैगंबर साहब के कार्टून बनाने वाले डेनमार्क के कार्टूनिस्ट के सिर पर 51 करोड़ रुपये का इनाम रखा था। इसके बाद इन्हीं हाजी जी ने फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली आब्दो के दफ्तर में हुए आतंकी हमले को जायज ठहराया। हाजी याकूब को कोई चाहे जिस नजर से देखे, यह जानना ज्यादा जरूरी है कि बीते लोकसभा चुनाव में हापुड़-मेरठ निर्वाचन क्षेत्र में वह दूसरे नंबर पर रहे थे और उन्हें पांच लाख से अधिक वोट मिले थे।

कमलेश तिवारी की हत्या को चाहे जैसी घटना के तौर पर व्याख्यायित किया जाए, लेकिन हिंदू समाज पार्टी के दफ्तर में उनके कत्ल और शार्ली आब्दो दफ्तर में हुए आतंकी हमले में ज्यादा अंतर नहीं। उस हमले के जरिये भी यही रेखांकित किया गया था कि पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले जिंदा नहीं बचेंगे और कमलेश तिवारी की हत्या से भी यही जाहिर किया गया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इन दिनों वह तबका खामोश है जो लिबरल-सेक्युलर के तौर पर जाना जाता है। इस तबके को इस पर उचित ही आपत्ति है कि कमलेश तिवारी की हत्या के बाद पैगंबर साहब के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणियां की गईं। ये टिप्पणियां वाकई शर्मनाक और माहौल दूषित करने वाली थीं और उनके खिलाफ आवाज उठनी ही चाहिए, लेकिन आवाज उनके खिलाफ भी तो उठनी चाहिए जो कमलेश तिवारी की हत्या का जश्न मनाने या फिर हत्या को जायज ठहराने में लगे हुए थे। यह देखना दयनीय रहा कि जश्न मनाने वालों ने पैगंबर साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों के जवाब में जब शांति का उपदेश देना शुरू किया तो कहीं दुबका पड़ा सेक्युलर-लिबरल तबका तत्काल उनके साथ आ खड़ा हुआ।

कमलेश तिवारी पहले ऐसे शख्स नहीं जिन्हें अपनी कथनी-करनी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी हो। गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी के साथ भी यही हुआ था। माना जाता है कि गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी के हिंदुत्व विरोधी विचारों से चिढ़े लोगों ने उनकी हत्या की। विडंबना यह है कि जिन लोगों के लिए गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी की हत्या गंभीर बात थी उनके लिए कमलेश तिवारी की हत्या कुछ भी नहीं। गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी की हत्या के बाद जो बुद्धिजीवी तबका असहिष्णुता के खतरे को बयान करने की होड़ में लिप्त था वह अब मौन साधे हुए है। कमलेश तिवारी की हत्या से आक्रोशित लोग इस मौन का जिक्र करते हुए यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वे अब कुछ क्यों नहीं बोलते? यह सवाल ही व्यर्थ है। आखिर जो अपने दोहरेपन के लिए कुख्यात हैं उनसे यह प्रमाण पत्र लेने की कोशिश क्यों की जा रही है कि कमलेश तिवारी की हत्या खौफ पैदा करने वाला एक जघन्य कृत्य है? इस तबके की ओर से नीर-क्षीर विवेक का परिचय देने की अपेक्षा एक तरह की मृग मरीचिका ही है। खुद के सीने पर लिबरल-सेक्लुयर होने का बिल्ला लगाए इस तबके से कोई उम्मीद नही रखी जानी चाहिए, लेकिन जिन पर कानून का शासन बनाए रखने की जिम्मेदारी है उन्हें तो यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाए। अभी ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसका पता भीड़ की हिंसा वाली घटनाओं से भी चलता है। अगर कानून हाथ में लेने वाले हर तरह के तत्वों अथवा अपने बयानों और कृत्यों से कानून को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ समय रहते कठोर कार्रवाई हो रही होती तो शायद कमलेश तिवारी की जान नहीं जाती।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परम धर्म

जीवन में प्रमुख रूप से तीन अंग माने जाते हैं- विचार, साधना और कर्म। फलस्वरूप मनुष्य विचारक, साधक एवं कर्मठ कहा जाता है। जब मनुष्य कर्मधारा को विशेष दिशा में दृढ़ता से मोड़कर उसमें एकाग्र रहकर ध्यान जमाता है, तब उसका साधक स्वरूप दिखाई देता है। साधना के क्षेत्र में मन का बड़ा महत्व है। इसके चलते विचरण करते मन को स्थिर करके ही साधना में रत हुआ जाता है। एक मनुष्य में यह तीनों स्वरूप मिल सकते हैं। कोई अधिक विचारक हो सकता है तो कोई अधिक साधक अथवा अधिक कर्मठ।

विचारक को दार्शनिक कहते हैं। शंकराचार्य का अद्वैत रूप विचारक या दार्शनिक का है। गोविंद भक्ति अथवा संन्यासरत स्वरूप साधक का है। पानी में डूबते समय माता से धर्म प्रचार की आज्ञा मांगने वाला रूप कर्मशील पुरुष का है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका में माया तथा मानस में नाम और राम का विवेचन करने वाले तुलसी जी विचारक या दार्शनिक हैं। एकाग्रमन से विनयपत्रिका लिखने वाले तुलसीदास साधक रूप हैं। दुखों से संघर्ष करने वाले, शैवों की उपेक्षा को हंसकर टालने वाले तथा मित्र टोडरमल के स्वर्ग गमन के उपरांत उसके पुत्रों को प्रबोध प्रदान करने वाले तुलसीदास कर्मठ स्वरूप ही हैं।

मनुष्य की भांति राष्ट्र, साहित्य एवं धर्म के भी तीन स्वरूप होते हैं। प्रत्येक संप्रदाय, मत, जाति और समाज में यह तीन अंग-दर्शन, साधना एवं व्यवहार रूप में देखे जा सकते हैं। कोई मत या धर्म दर्शन प्रधान हो जाता है तो कोई साधना या व्यवहार प्रधान। हिंदू धर्म दर्शन-प्रधान है। इसमें साधना भी बहुत फैली, लेकिन अब न साधना है और न व्यवहार। आचार्य गोरेलाल जी कहते हैं कि दूसरे के हित के समान विश्व में कोई धर्म ही नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान अधर्म या पाप नहीं है। धारण करने वाला गुण ही तो धर्म है। परहित से बढ़कर कौन गुण होगा जो समाज को धारण करेगा। धर्म की कसौटी है कि मनुष्य से परहित हो। जो स्वार्थी बनकर केवल अपने सुख के लिए सब कुछ करता है, वह अधर्मी ही कहा जाएगा।

श्रीमती रमन त्रिपाठी

नेत्र रोग का बढ़ता दायरा

देवेंद्रराज सुथार

यूएन स्वास्थ्य एजेंसी की रिपोर्ट दर्शाती है कि आंखों की समस्याएं जीवनशैली में आए बदलावों से भी बढ़ रही हैं

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में दो अरब से ज्यादा लोग नेत्र समस्याओं और दृष्टिबाधिता से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नेत्रों से जुड़ी समस्याओं पर अब तक की यह पहली रिपोर्ट है। रिपोर्ट में आशंका जताई है कि आगामी दशकों में जनसंख्या वृद्धि और बुढ़ापे के साथ-साथ जीवनशैली में परिवर्तन एवं शहरीकरण से नेत्र विकारों, दृष्टिबाधिता और नेत्रहीनता से पीड़ित लोगों की संख्या में नाटकीय ढंग से बढ़ोतरी हो सकती है।

इस रिपोर्ट में ऐसे तथ्य हैं जो दर्शाते हैं कि आंखों की समस्याएं जीवनशैली में आए बदलावों से भी बढ़ रही हैं। इनमें विशेष तौर पर टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से होने वाली समस्याएं भी शामिल हैं। कमजोर नजर से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि बच्चे अब ज्यादा समय घर से बाहर नहीं बिताते हैं। घर के अंदर रहने की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि आंखों के लेंस को आराम ही नहीं मिल पाता। घर के बाहर बिताए जाने वाले समय और बाद में होने वाली कमजोर दृष्टि की समस्याओं में स्पष्ट संबंध है। निःसंदेह आधुनिक युग में सभी लोग मोबाइल-लैपटॉप, कंप्यूटर पर निर्भर हो गए हैं। अब ऐसा कोई दफ्तर नहीं है जिसमें कंप्यूटर पर काम न हो। रजिस्टर, कलम का जमाना तो बहुत पीछे छूट चुका है।

हालांकि इससे काम काफी तेजी एवं पुख्ता से हो रहे हैं, लेकिन हम इस रफ्तार में अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। मसलन लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से उसकी स्क्रीन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें आंखों के विभिन्न हिस्सों जैसे रेटिना और कॉर्निया पर अपना असर डाल रही हैं। 2007 में हुए एक शोध के अनुसार कम दायरे में देखने के कारण भी आंखों की रोशनी कम होती है। यानी जब हम एक केंद्रीय बिंदु पर अधिक देर तक ध्यान लगाए रहते हैं और अन्य वस्तुओं को नहीं देखते तब भी हमारी आंखों की रोशनी कम होती है। उम्रदराज युवाओं में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते रहने से उनमें असहजता, खुजली महसूस होने लगती है। आमतौर पर आंखें एक मिनट में 12-15 बार झपकती हैं, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने वाले एक मिनट में केवल 4-5 बार ही आंखों को झपकाते हैं। आंखों को कम झपकाना और अधिक समय तक काम करते रहने से ड्राई आई सिंड्रोम, खुजली जैसी समस्याएं होती हैं। वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर पर लगातार काम करने वालों की आंखों से पानी निकलने की समस्या भी हो जाती है, क्योंकि आंखें नहीं झपकाने से पानी सही तरीके से आंखों में फैलता नहीं और उससे खुजली होती है। लगातार टीवी देखने से आंखों की रोशनी कम होने लगती है, क्योंकि टीवी से निकलने वाली घातक किरणें हमारी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं।

निःसंदेह हमें नई तकनीक से जुड़े रहकर आगे बढ़ने के साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

अव्यावहारिक सुझाव

स्कूली शिक्षा में सुधार का सही उपाय शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रो. गीता गांधी किंगडन ने वाउचर व्यवस्था को प्राथमिक शिक्षा में लागू करने पर बल दिया है, जो कि देश और परिस्थिति के विपरीत ही नहीं, बल्कि पूर्णतः अव्यावहारिक भी है। भारत की तुलना अमेरिका से करना कहां तक उचित है? भारत में लागू होने वाली कोई योजना स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बनाई जा सकती है। भारत कृषि प्रधान देश है और अधिकांश लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि प्रत्येक अभिभावक के खाते में एक निश्चित धनराशि भेज दी जाए तो वह शिक्षा के बजाय अपनी अन्य मूलभूत जरूरत को पूरा करने में खर्च कर देगा, न कि बच्चों की शिक्षा पर। यह सुझाव अपरोक्ष रूप से निजीकरण को बढ़ावा देने वाला है। वास्तव में सरकार यदि स्कूली शिक्षा को सुधारने के प्रति गंभीर हो तो उसे सर्वप्रथम विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करना चाहिए और सभी प्राथमिक विद्यालयों को बेहतर सुविधाओं और आवश्यक संसाधनों से लैस कर देना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से कुपोषण जैसी समस्या पर सफलता अर्जित की है ठीक उसी तरह से सरकार चाहे तो शिक्षा की बेहतरी के लिए ठोस कदम उठा सकती है।

सर्वजीत आर्या, कन्नौज

ताकि लोग निरोग रहें

बरसात और बाढ़ के बाद अब बीमारियों का दौर शुरू हो गया है। देश के कई बड़े शहरों में अप्रत्याशित बाढ़ और फिर फैलती बीमारियों का सामना करने में सरकारें नाकाम दिखीं हैं। कुदरत का कहर अपने हाथों में नहीं है, लेकिन कुदरत की व्यवस्था से छेड़छाड़ ही इस तबाही की मूल वजह है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जल संरक्षण का पाठ पढ़ाती सरकारें जल निकासी का रास्ता ढूंढती रही हैं। रिहायशी इलाकों में जल जमाव और उससे पैदा होती बीमारियों को लेकर दूसरों पर दोषारोपण कर जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता। हवा-पानी के रास्ते में रुकावट पैदा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन और सेना का इस्तेमाल लोगों को बचाने और नालियों की सफाई के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बैठे-बैठाए बीमारियों को न्योता देने से बेहतर है शहर-मोहल्लों के घर छोटे ही सही, मगर नालियां बड़ी बनें, ताकि शहर साफ और लोग निरोग रहें।

mkmishra75@yahoo.in

कमजोर होती कांग्रेस

हरियाणा एवं महाराष्ट्र कभी कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन अब इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की हालत काफी पतली है। इन राज्यों में चुनाव के बाद एक्जिट पोल के अनुसार अब भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां दो तिहाई बहुमत से इन दोनों राज्यों में सरकार बनाने जा रही हैं। कांग्रेस के इस पतली हालत के लिए खुद कांग्रेसी जिम्मेवार हैं। कांग्रेस में संगठन का अभाव दिखाई दे रहा है। चुनाव जीतने के लिए कोई रणनीति दिखाई नहीं दी, कांग्रेस के अंदर मोदी जैसे नेतृत्व की कमी एवं पार्टी के अंदर गुटबाजी रही। यह कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। कांग्रेस को संगठन और नेतृत्व दोनों को ठीक करने की जरूरत है। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए।

विजय तिवारी, शिक्षक, नई दिल्ली

गुलाम कश्मीर है मुद्दा

पाकिस्तान को अब कश्मीर का राग अलापना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसे भारत ने अब हल कर लिया है। अगर वह कुछ करना ही चाह रहा है तो अमन और शांति के लिए अपने घर में पल रहे आतंकियों और उनके अड्डों को शीघ्र ही काबू में करे। वैसे भी कश्मीर के बजाय असली मुद्दा तो गुलाम कश्मीर है, जिस पर उसने कब्जा कर रखा है।

mahesh_nenava@yahoo.com

सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती

हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या के पीछे बड़ी साजिश सामने आई है। यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती है। जिस तरह से हत्यारों के संपर्क विभिन्न राज्यों से मिल रहे हैं और हत्या के लिए पहनावा ही नहीं बदला, अपितु धर्म विशेष के बारे में अध्ययन भी किया। ऐसा साधारण अपराधी नहीं कर सकते हैं। अतिविशिष्ट लोगों की सुरक्षा में लगी एजेंसियों को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है।

श्रीनिवास यादव, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

99 प्रतिशत गांवों तक पहुंच गया है वर्तमान में देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज, जो चार साल पहले तक महज 38 प्रतिशत ही था।

आजकल

हमारे एजेंडे में कब आएगी स्वच्छता

पीएम नरेंद्र मोदी ने गत दिनों मामल्लपुरम में समुद्र तट पर कचरे की सफाई की। देश भर से लोगों ने उनके इस कार्य की सराहना की। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का यह कदम एक अनुकरणीय मिसाल बन जाएगा और आम जनता को साफ-सफाई की प्रेरणा देगा, लेकिन यहां एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्यों उनको बार-बार स्वच्छता के आग्रह को लेकर आह्वान करने और उदाहरण देने पड़ रहे हैं? आम आदमी के जीवन में साफ-सफाई प्रमुख मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है?

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

हाल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के वक्त तमिलनाडु के शहर मामल्लपुरम में 12 अक्टूबर, 2019 की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सैर को पहुंचे तो समुद्र तट पर यहां-वहां बिखरे कचरे को देखकर स्वच्छता के प्रति उन्हें अपना कर्तव्य एक बार फिर याद आ गया। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एंबेसडर पीएम मोदी ने इस तरह कचरे की जो सफाई की, उसका एक वीडियो मीडिया में कुछ दिनों तक छाया रहा और देश भर से लोगों ने प्रधानमंत्री के इस कार्य की सराहना की। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का यह कृत्य एक अनुकरणीय मिसाल बन जाएगा और आम जनता को साफ-सफाई की प्रेरणा देगा, लेकिन यहां एक अहम सवाल पैदा होता है कि पांच साल पहले देश में शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत अभियान' का आखिर हासिल क्या है? क्यों प्रधानमंत्री को बार-बार स्वच्छता के आग्रह को लेकर आह्वान करने और उदाहरण देने पड़ते हैं? इससे साबित होता है कि सरकार की ओर से शुरू किए गए अभियानों के बावजूद आम जनता कई मामलों में अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझती है?

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने दो अक्टूबर, 2014 को 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य देश में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज को हासिल करने के प्रयासों में तेजी लाना बताया गया। इसके लिए एक शुरुआती समयसीमा इस साल दो अक्टूबर, 2019 तय की गई थी, जिसके तहत देश को खुले में शौच से मुक्त कराना था। इसके लिए देश में 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं और वर्तमान में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज भारत के 99 प्रतिशत गांवों तक पहुंच गया है, जो चार साल पहले तक महज 38 प्रतिशत ही था।

इसमें कोई संदेह नहीं कि आबादी के बोझ से जूझते हमारे देश में हरेक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं देना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इन सुविधाओं में पीने का साफ पानी, शोधित सीवरेज, कचरे का निष्पादन, 24 घंटे बिजली आपूर्ति, सुचारु यातायात और बेहतर चिकित्सा हासिल करना जैसी चुनौतियां शामिल हैं, पर इनसे भी ज्यादा जरूरी है स्वच्छ माहौल, जो तभी मिल सकता है जब सरकार, स्थानीय प्रशासन और हर शहरी की मानसिकता साफ-सफाई को लेकर एकदम स्पष्ट हो। इसी मकसद से बीते देश में कुछ वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण कराया जा रहा है, ताकि इसका आकलन हो सके कि क्या हमारे शहरों, गांवों और कस्बों में साफ-सफाई को लेकर कोई जागरूकता आई है और क्या लोग स्वेच्छा से, सरकार और प्रशासन के अभियानों और दंडकारी उपायों के बिना अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखने में दिलचस्पी रखते हैं? ऐसे सर्वेक्षणों में देश के चुनिंदा शहरों ने मिसाल कायम की है। जैसे साफ-सफाई की तमाम कसौटियों पर मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार तीसरी बार पहले नंबर पर घोषित किया गया है। ध्यान रखना होगा कि 28 दिनों की अवधि में 64 लाख लोगों के सीधे फीडबैक से तैयार स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 में देश के जिन 4237 शहरों का सर्वेक्षण किया गया था। हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के बाहर सफाई के पुरस्कार हासिल करने वाले शहरों की संख्या कम ही दिखती है। मामल्लपुरम के सागर तट पर फैली गंदगी के हालिया प्रकरण को देखकर लगता है कि साफ-सफाई को लेकर हमारी सरकारों, प्रशासन और खुद नागरिकों में इसे लेकर कोई उलझन है जिससे स्वच्छता कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है। इसे लेकर कोई उत्सुकता भी नहीं दिख रही है कि हमारे शहर और गांव-कस्बे साफ-सफाई की पहलकदमियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और साबित करें कि स्वच्छता को लेकर उनकी मानसिकता में क्रांतिकारी बदलाव आ गया है।

सवाल है कि क्या साफ-सफाई का जिम्मा सिर्फ सरकार और प्रशासन के सिर ही होना चाहिए। दरअसल भारतीय जनमानस में सफाई को लेकर एक खास किस्म की अड़चन दिखाई देती है। हमारे देश में ज्यादातर लोगों का जोर सफाई के बजाय 'पवित्रता' पर रहा है, जो या तो ईश्वर प्रदत्त होती है या आंतरिक उपायों से हासिल की जाती है। अपने परिवेश को साफ-सुथरा रखने के बजाय इसका जोर भीड़ से अलग दिखने पर है। कहीं न कहीं हमारे अवचेतन में यह भी बैठा हुआ है कि सफाई हमारा नहीं, किसी और का यानी सरकार का काम है। इसी सोच का नतीजा है कि वर्ण व्यवस्था ने एक खास वर्ग को यह काम सौंप कर छुट्टी पा ली और बाकी समाज के लिए साफ-सफाई कोई मुद्दा ही नहीं रहा। कहने को तो आज वर्ण व्यवस्था के बंधन कुछ ढीले हुए हैं, लेकिन इस परजीवी मानसिकता से निजात आज भी नहीं मिली है कि हमारे सामने पड़ा कचरा उठाना किसी और की जिम्मेदारी है, बल्कि शहरों में तो ऐसे नजारे आम हैं जहां तमाम सोसायटियों के पीछे उस कचरे के अंबार लगे हैं जो उन्हीं सोसायटियों से निकलता है।

हालांकि इस मामले में सरकारों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं, जैसे कि नगर पालिकाओं-निगमों को एकदम बरी नहीं किया जा सकता है। यह मानने से इन्कार नहीं होना चाहिए कि अब तक सरकारें भी इस मामले में जरा ज्यादा ही लापरवाह रही हैं। वे नगर निगमों को सफाई का पैसा तो देती रहीं, लेकिन इस बारे में कोई प्रेरणा नहीं जगा पाईं कि उन्हें इस पैसे का सही इस्तेमाल भी करना है। हालांकि मौजूदा केंद्र सरकार ने स्वच्छता मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी, दोनों मोर्चों पर सफाई के अभियान शुरू किए। उसने स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत गांवों में हर घर में शौचालय बनाने और देश को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा तो स्वच्छ भारत शहरी मिशन में घरों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी शौचालय और कूड़ा-कचरा प्रबंधन पर फोकस किया। पांच साल पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से आह्वान किया था कि वे देश को साफ-सुथरा बनाने में सरकार की मदद करें। उन्होंने इसके लिए 2019 यानी मौजूदा वर्ष की डेडलाइन भी सामने रखी थी, क्योंकि यह वर्ष गांधी जी की 150वीं जयंती का है। उनका मत था कि 2019 तक सारा देश साफ-सुथरा हो जाए, क्योंकि गांधी जी को सफाई बहुत पसंद थी। इसके लिए उन्होंने यह अपील भी की थी कि देश का हर नागरिक साल में कम से कम सौ घंटे सफाई को दे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह दिवाली पर हम अपने घर को साफ करते हैं, क्यों न पूरे देश को साफ रखने का प्रयास करें। अगर देश साफ रहेगा तो बीमारियों का प्रसार घटेगा। इससे लोगों के इलाज पर आने वाला खर्चा बचेगा। भारत को सफाई के मामले में विश्व के स्तर पर पहुंचना होगा। देश के पचास पर्यटन स्थलों में सफाई की व्यवस्था विश्व स्तर की करनी होगी, तभी भारत के बारे में दुनिया के लोगों की धारणा बदलेगी और हमारा पर्यटन बढ़ेगा।

बेशक हमारी सरकार और प्रधानमंत्री के इरादे सही दिशा में हैं, पर सवाल है कि क्या उनके आह्वानों का असर हमारे शहरों, शहरवासियों से लेकर गांव-देहात में पड़ सका है? स्वच्छता सर्वेक्षण की इस साल की सूची इस मानसिकता की तस्वीर को काफी हद तक साफ करती है। उम्मीद है कि सफाई को लेकर हमारी सोच को लगे जाले इससे साफ हो सकेंगे।

बदलाव के लिए कितने तैयार हैं हम

भले ही कोई यकीन न करे, पर यह सच है कि हमारे देश में अधिकांश लोग खुद कोई मेहनत किए बगैर अपनी कल्पनाओं में खुशहाल रहना चाहते हैं। ऐसे में अगर सरकार पैसे खर्च करके कोई बड़ी योजना चलाए तो भी उसकी सौ फीसद कामयाबी इसीलिए सुनिश्चित नहीं हो पाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसमें अपनी ओर से तनिक भी सहयोग नहीं करना चाहते हैं। मदद करना तो दूर, वे अपनी उन आदतों में भी कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते भले ही इसके लिए उन पर एकाध मौकों पर जुर्माना क्यों न लगा दिया जाए। यही वजह है कि ढेर सारी कवायदों के बावजूद साफ-सफाई के प्रति हम आज भी बहुत ज्यादा संजीदा नहीं हो सके हैं। न सिर्फ हमारे घर-मोहल्ले और सड़कें, बल्कि धर्मस्थल तक बेहद गंदे हैं और हमें इसे लेकर कोई खास परेशानी भी नहीं है।

अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि प्रधानमंत्री को ही नहीं, बल्कि हमारी न्यायपालिका को भी समय-समय पर यह कहना पड़ता है कि ज्यादा कुछ नहीं तो हम अपने मंदिर ही साफ रखें। मिसाल के तौर से वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली में स्थित कालकाजी मंदिर के आसपास की गंदगी पर गहरा एतराज जताते हुए कहा था कि मंदिर में न सिर्फ मन की शुद्धि जरूरी है, बल्कि मंदिर एवं उसके आसपास साफ-सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। उस वक्त अदालत को जानकारी दी गई थी कि मंदिर पर पुजारियों का, इसके दरवाजे पर भिखारियों का और इसके चारों तरफ व्यापारियों का कब्जा हो चुका है। मंदिर जबर्दस्त गंदगी का शिकार है, लेकिन इसे साफ रखने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने मंदिर की व्यवस्था को लेकर ठोस रिपोर्ट तलब की थी। यह कैसी विडंबना है कि साफ-सफाई जैसे आम जनजीवन से जुड़े मुद्दे पर हमारी न्यायपालिका को टिप्पणी करनी पड़ती है। यह हैरानी की बात है कि धर्मस्थलों की ऐसी दुर्दशा देख कर भी देश की धर्मपरायण जनता की आस्था को ठेस नहीं पहुंचती। हिंदू धर्म से जुड़ी छोटी-छोटी बातों पर भड़क उठने वाले धार्मिक नेताओं के लिए भी स्वच्छता खुद में कोई सवाल नहीं है।

एक अन्य मुद्दा लोगों की आदतों में बदलाव नहीं होना भी है। यह बात कुछ तथ्यों और आंकड़ों से और स्पष्ट होती है। मिसाल के तौर पर दो साल पहले गुजरात सरकार ने खुद को 2 अक्टूबर, 2017 में खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था, लेकिन एक साल बाद कैग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस राज्य के 29 फीसद घरों में शौचालय हैं ही नहीं। सवाल उठा कि इन घरों के शौचालय आखिर कहां गए। दावा किया गया कि कुछ घरों में शौचालयों का इस्तेमाल दूसरे कामों में कर लिया गया और कुछ मामलों में शौचालय बनाने के नाम पर पैसों का घालमेल किया गया। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि जरूरत होने और सरकारी पैसे की मदद मिलने पर भी लोग घरों में शौचालय नहीं बनवाते और आदतन खुले में शौच के लिए जाते हैं। ऐसे लोग घर में बने शौचालय का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं।

इसका एक खुलासा तब हुआ, जब यूपी के बरेली में आयोजित टॉयलेट प्रतियोगिता में आयोजकों ने बताया कि लोगों ने घरों में शौचालय तो बना लिए हैं, लेकिन खास तौर पर बुजुर्ग उन्हें (शौचालयों को) अपने घर का हिस्सा नहीं मानते हैं। कुछ ऐसी ही बातें जनवरी, 2019 में सामने आए स्वच्छ भारत के सर्वेक्षण में भी पता चली थीं, जिनके अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लोगों की आदतों में बदलाव नहीं आ पा रहा है और एक चौथाई घरों में शौचालय की मौजूदगी के बावजूद लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं।

खरी-खरी

खरीद रहे या खुद को बेच रहे हैं!

अंशुमाली रस्तोगी

झूठ क्या बोलूं-मैंने अभी तक किसी भी ऑनलाइन ऑफर का 'लाभ' नहीं उठाया है। जबकि हर तरफ 'फेस्टिव-लूटिव सीजन' की सेल लगी हुई है। जिसे देखो वो कुछ न कुछ खरीद ही रहा है। एक मैं हूं, जिसे मोबाइल की टचस्क्रीन आतंकित करती है। उस पर अंगुलियां बार-बार फिसल जाती हैं। टाइप कुछ करता हूं, छपता कुछ और है। ऐसे में ऑनलाइन स्टोर पर जाकर कुछ खरीदना बड़ा ही 'दीदारेजी' का काम है। इसीलिए बीवी मुझे पिछली सदी का पिछड़ा हुआ लेखक कहती है। इस विषय पर उससे अधिक बहस नहीं करता। जो हूं सो हूं। खुद को कितना बदलूं। जब तक बदल पाता हूं, दुनिया चार कदम और आगे बढ़ जाती है।

खैर त्योहार के बहाने सब खरीदने में लगे हैं। आपस में मिलकर भी लोग अब किसी का हाल-चाल नहीं लेते। बस ऑफर्स की ही बातें करते हैं। हर एक की जेब में डेबिट और क्रेडिट कार्ड ऐसे मिलते हैं, जैसे रुमाल। झट से कार्ड निकाला और चीज खरीद डाली। एक मैं हूं, जिसके पास डेबिट कार्ड होते-सोते भी बेकार ही है, क्योंकि अकाउंट में कभी इतने रुपये ही नहीं होते कि कार्ड का इस्तेमाल हो सके। और क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, क्योंकि बाजार की नजर में लेखक की कोई क्रेडिट ही नहीं है?

कभी-कभी सोचता हूं तो चक्कर में पड़ जाता हूं कि लोग कितना खरीदते हैं। जब देखो तब। दुकानें खरीदारों से भरी रहती हैं। सड़क पर कदम रखने की जगह नहीं। ऑनलाइन साइट पर सर्वर क्रैश। हर किसी का हाथ किसी न किसी सामान से भरा हुआ। सब ऑफर्स का लाभ उठाना चाहते हैं। जिन्हें दुकानों पर धक्के खाने की आदत नहीं, वे ऑनलाइन खरीद रहे हैं। अखबार विज्ञापनों से भरे पड़े हैं। उन्हें देख ऐसा लगता ही नहीं कि देश में मंदी भी है। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली दिखाई देती है। सब की जेबों में खूब पैसा है। महंगाई जाने कहां मुंह छुपाए बैठी है। तो क्या मंदी के रोना 'फेक' है?

खरीददारों की इस भीड़ में मैं खुद को 'पिछड़ा' हुआ ही पाता हूं। कभी-कभी मुझे अपने ही आदर्श 'ढकोसले' लगते हैं। दोस्तों की महंगी लाइफ स्टाइल के मुझे अपना सादा जीवन फीका लगता है। समय के साथ जमाना इतना बदल गया है कि ध्यान त्योहार के आनंद का नहीं, सिर्फ खरीदी का रखा जाता है। जो खरीद रहा है, वही मानो त्योहार सेलिब्रेट कर रहा है। अपन पट्टे वाली चड्डी पहनकर घर पर ही बैठे हैं।

ट्वीट-ट्वीट

अगर भारतीय बैंकों की दुर्दशा की पड़ताल करें तो इसके तार बहुत पीछे तक जाएंगे। एक तो 2000 के दशक की शुरुआत में बिना किसी मौद्रिक सख्ती के कर्ज लुटाए गए। फिर 2008 के बाद नीतिगत पंगुता और एनपीए ने मामला बिगाड़ दिया जहां दीवालिया संहिता भी नहीं थी। रही सही कसर लचर राजकोषीय नीति और शैडो बैंकिंग ने पूरी कर दी।

ध्रुव जयशंकर@d_jaishankar

इसमें कुछ बातें और जोड़ लीजिए। एक प्रणब मुखर्जी का विध्वंसक रेट्रो टैक्स। अदालत द्वारा कोयला खदान आवंटन रद करने से भी बैंकों को बड़ा झटका लगा। फिर संप्रग सरकार ने सीएसआर से जुड़े मनमाने कानून लागू कर दिए। सदानंद धूमे@dhume

आरबीआइ में जिस किसी ने भी सभी आंकड़ों को अरब रुपये से बदलकर करोड़ रुपये में कर दिया, उसका बहुत आभार। आदतन भारतीय लोग अरब की तुलना में करोड़ ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं।

दीपक शेनॉय@deepakshenoy

विजय गुप्ता
वरिष्ठ समाचार संपादक, पंजाब

पंजाब डायरी

पराली जलाने की मजबूरी

पंजाब में इन दिनों नेताओं की सांसें अटकी हुई हैं। पराली का प्रदूषण जहां कैप्टन सरकार का दम फुलाने वाला है वहीं उपचुनाव के नतीजों को लेकर सभी दलों में धुकधुकी है। प्रथम पातशाही श्री गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर एक नवंबर से आयोजन शुरू होने जा रहे हैं और इस दौरान दिवाली के एकदम बाद पराली का प्रदूषण भी बढ़ने की पूरी आशंका है। दूसरी ओर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सरकार की साख और उसके प्रदर्शन पर जनता की मुहर साबित होने वाले हैं। मतदान हो चुका है और अब देखना है कि नतीजे किसका धुआं उड़ाते हैं और किसकी दिवाली मनती है।

हर साल उत्तर भारत को इन दिनों में गैस चैंबर बना देने की तोहमत सहते आए पंजाब को इस बार देश-विदेश से आने वाले लोगों को होने वाली असुविधा का संताप भी सहना पड़ सकता है। वजह है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती पर राज्य एवं केंद्र सरकार के कुछ प्रयासों के बावजूद पंजाब में धान के खेतों में पराली जलाई जा रही है। राज्य सरकार पराली को निकालने वाले विभिन्न उपकरणों पर पचास फीसद तक सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। एप के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों और पराली से होने वाले नुकसान की जानकारी दे रही है, लेकिन जमीन पर हकीकत अलग है।

सरकार एवं किसान दोनों मजबूर नजर आते हैं। पराली न जलाने के लिए सरकार के जागरूकता कार्यक्रम एवं सख्ती का किसानों पर होने वाले असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली जलाने की घटनाओं में करीब 45 फीसद तक वृद्धि हो चुकी है। इस साल अब तक 1630 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल से तुलना करें तो दिवाली से पहले इन दिनों तक खेतों में पराली जलाने के 1198 मामले सामने आए थे। आंकड़े सरकार की विफलता बयां कर रहे हैं, वहीं कहीं न कहीं यह संकेत भी दे रहे हैं कि उपचुनाव की वजह से किसानों के प्रति नरमी बरती गई, क्योंकि सरकार किसानों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थी। पिछले साल भी सरकार की यही मजबूरी थी, क्योंकि तब लोकसभा चुनाव थे और किसानों ने कार्रवाई के विरोधस्वरूप डीसी दफ्तरों तक के सामने जाकर पराली जला दी थी।

लगभग एक दशक से सस्ते और ठोस विकल्प उपलब्ध न होने की दलील देकर खुद को मजबूर बताते आ रहे किसान भी वास्तव में पर्यावरण और भविष्य के प्रति कितने सजग एवं संजीदा हैं, इसका आंकलन इन आंकड़ों से किया जा सकता है। किसान अगर मजबूर हैं तो सवाल सरकार की मजबूरी पर भी उठता है। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार को किसानों पर जुर्माना न करने की हिदायत दी थी, लेकिन साथ ही उसका यह भी मानना है कि सब्सिडी, मुफ्त बिजली-पानी जैसी सुविधाएं ले रहे किसानों को गरीब नहीं माना जा सकता। जाहिर है सरकार को और विकल्प देने होंगे, सख्ती तो बरतनी ही होगी। इसमें सियासी नफा या नुकसान नहीं देखना होगा। किसानों को भी पुराना ढर्रा छोड़ना होगा, लेकिन ऐसा फिलहाल इस साल होता नजर नहीं आ रहा। नतीजतन पूरी आशंका है कि आने वाले दिनों में नमी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण बढ़ेगा।

बेशक चुनावी माहौल में सरकार ने कुछ नरमी बरती हो, लेकिन अब उसकी बेचैनी यही है कि दिवाली के एक दम बाद से ही 550वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा तो क्या उनका स्वागत पंजाब में प्रदूषण से होगा? वैसे सरकार ने इस समस्या के हल के लिए आस्था का ही सहारा लिया है। उसने गुरु नानक जी की शिक्षाओं का जिक्र करते हुए पर्यावरण की शुचिता की अपील किसानों से की है। अब यह कितना असर दिखाती है यह दिवाली के बाद ही पता चलेगा।

फिलहाल उससे पहले सियासी माहौल काफी गरमाने वाला है। बेशक केवल चार ही सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इनमें कोई दिग्गज भी मैदान में नहीं है, लेकिन दो-तिहाई बहुमत से एक सीट दूर कैप्टन सरकार के लिए नतीजे ढाई साल के कामकाज पर जनता की मुहर होंगे।

दिलचस्प यह है कि जिन चार सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वे सभी अलग-अलग दलों के पास रही हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री सोम प्रकाश के सांसद चुने जाने से खाली हुई फगवाड़ा सीट पर तीन बार लगातार जीतती आ रही भाजपा के लिए उसे बचाए रखना चुनौती है। जलालाबाद ऐसी ही सीट अकाली दल के लिए है जहां से सुखबीर बादल पिछले तीन विधानसभा चुनाव जीते और गत लोकसभा चुनाव में भी इस हलके ने उन्हें भारी मतांतर से संसद में पहुंचा दिया। यह सीट उनकी प्रतिष्ठा का भी प्रश्न बनी हुई है इसलिए यहां उन्होंने और उनकी पत्नी एवं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने भी पूरा जोर लगाए रखा। एचएस फूल्का की जीत से आप की झोली में गई दाखा सीट हो या फिर कांग्रेस विधायक के निधन से खाली हुई मुकेरियां सीट, कांग्रेस सरकार की परीक्षा तो सभी पर होनी है।

सरकार को कठघरे में खड़ा करने के लिए मौका तलाश रहे शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल कहते रहे हैं कि इन नतीजों के बाद सरकार या तो परफॉर्म करेगी या जाएगी। कैप्टन अमरिंदर इन नतीजों के असर को भांपते हुए ही इस बार उपचुनाव में काफी सक्रिय रहे हैं। बहरहाल एक दिन बाद तय हो जाएगा कि सियासी आतिशबाजी मोती महल में होती है या फिर बादल गांव में।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या सेना की कठोर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान घुसपैठ कराने से बाज आएगा?

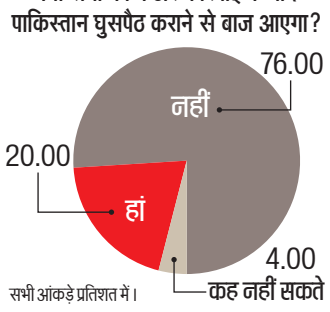

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या पुलिस कर्मियों के कामकाजी घंटे तय होने से पुलिस बल की क्षमता बढ़ेगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर *57272* पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सबकी धड़कन बढ़ गई सुनकर एक्जिट पोल,
कांग्रेस का हो रहा फिर से डब्बा गोल।
फिर से डब्बा गोल न छोड़ोगे लफ्फाजी,
तो कैसे श्रीमान आप जीतोगे बाजी!
बंधु चुकी है चेत देश की जनता कब की,
हैं जितने लफ्फाज बजेगी बारह सबकी!!

– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

भारतीयता युक्त इतिहास दृष्टि

गृह मंत्री अमित शाह इतिहास के जिस भारतीय दृष्टि से युक्त पुनर्लेखन की बात कर रहे, संस्थागत रूप से वर्तमान में उसके लिए कोई संभावनापूर्ण स्थिति नहीं दिखती

पीयूष द्विवेदी
कला-संस्कृति मामलों के जानकार

गत 17 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 'गुप्तवंशक वीर : स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का ऐतिहासिक पुनःस्मरण एवं भारत राष्ट्र का राजनीतिक भविष्य' विषय पर आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास में गड़बड़ियों के लिए अंग्रेजों एवं वामपंथियों को दोष देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वर्तमान में भारतीय दृष्टि से इतिहास का पुनर्लेखन किए जाने की जरूरत है। उन्होंने मौर्य वंश, गुप्त वंश से लेकर शिवाजी तक का उदाहरण देते हुए कहा कि इन महापुरुषों के विषय में आज ढूंढने पर कोई संदर्भ ग्रंथ नहीं मिलता तो यह हमारी कमी है।

अमित शाह के इस वक्तव्य में भारतीय इतिहास का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य मौजूद है। दरअसल आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू पर पश्चिम का गहरा प्रभाव था। समाजवाद को वे देश की समस्याओं का सबसे बेहतर समाधान मानते थे। पश्चिम का यह प्रभाव उनकी इतिहास-दृष्टि पर भी रहा। पश्चिमी विद्वानों द्वारा स्थापित आर्य आक्रमण सिद्धांत, जो इतिहास का एक विवादास्पद विषय रहा है, में उनकी आस्था थी। 'पिता के पत्र पुत्री के नाम' पुस्तक में संकलित एक पत्र में उन्होंने लिखा है, '... हिंदुस्तान के रहने वाले द्रविड़ कहलाते थे। ये वही लोग हैं, जिनकी संतान आजकल दक्षिण हिंदुस्तान में मद्रास के आसपास रहती है। उन पर आर्यों ने उत्तर से आकर हमला किया, उस जमाने में मध्य एशिया में बेशुमार आर्य रहते होंगे। आर्य एक मजबूत लड़ने वाली जाति थी, उसने द्रविड़ों को भगा दिया।'

प्रथम प्रधानमंत्री की इस पश्चिम-प्रभावित दृष्टि का प्रभाव देश के इतिहास लेखन पर भी पड़ा और इतिहासकारों ने पूर्वाग्रहयुक्त अभारतीय दृष्टि के साथ भारतीय इतिहास का लेखन किया, जिसमें विदेशी आक्रांताओं के पराक्रम एवं शासन का वर्णन तो खूब हुआ, परंतु देश के अनेक महापुरुष उचित स्थान नहीं पा सके। यह इतिहास कुछ यूं रहा, जिसमें साम्राज्य-विस्तार की लालसा में खून की नदियां बहाने वाले मुगल शासक अकबर को महान बना दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ जंगल-जंगल भटककर संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप की कोई विशेष चर्चा नहीं की गई। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, मंगल पाण्डेय, तात्या टोपे जैसे अनेक नाम हैं, जिन्हें इतिहास में पर्याप्त स्थान नहीं मिला। कुल मिलाकर अमित शाह ने अपने वक्तव्य में इतिहास में गड़बड़ी की समस्या को तो रेखांकित किया ही, लेकिन उससे कहीं अधिक जोर भारतीय दृष्टि से इतिहास का पुनर्लेखन कर इस समस्या को दूर करने पर दिया।

शाह इतिहास के जिस भारतीय दृष्टि से युक्त पुनर्लेखन की बात कर रहे, संस्थागत रूप से वर्तमान में उसके लिए कोई संभावनापूर्ण स्थिति नहीं दिखती। भारतीय अनुसंधान इतिहास परिषद की वेबसाइट खंगालने पर किसी भी नए ऐतिहासिक शोध या स्थापना से संबंधित किसी किताब की जानकारी नहीं मिलती। ऐसी किसी किताब की कोई चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती।

इससे इतर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर रहे नए लेखकों को देखें तो आज हिंदी का ज्यादातर नया लेखन कथा-कविता पर केंद्रित हो रहा है, शोध-इतिहास की तरफ नए लेखक जाना ही नहीं चाहते। जो भी नया लेखक आ रहा, वह कहानी-संग्रह, कविता-संग्रह या उपन्यास के साथ आ रहा है। कथा-कविता की पुस्तकों की भीड़ में ऐसी पुस्तकें बहुत कम दिखती हैं जो इतिहास में उपेक्षित रहे किसी विषय पर प्रकाश डालती हों या किसी ऐतिहासिक स्थापना को निरस्त कर नई स्थापना करती हों।

हालांकि ऐसा नहीं है कि रचनात्मक साहित्य लिखते हुए ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं लिखे जा सकते। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर दिनकर तक हिंदी साहित्य में कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने रचनात्मक साहित्य के साथ इतिहास पर भी जमकर कलम चलाई और उनका लिखा आज हमारी थाती है, परंतु यह कर्म असीम धैर्य, श्रम और समर्पण के साथ-साथ साहस भी मांगता है, जिसका आज के नए लेखकों की पीढ़ी में खासा अभाव है। विश्वविद्यालयों के इतिहास विभाग में भी शोध के स्तर पर कुछ बेहतर होता नजर नहीं आता। कुल मिलाकर इस बात से अधिकांश लोग सहमत मिलेंगे कि भारतीय इतिहास में सबकुछ ठीक नहीं है, लेकिन कोई इसे ठीक करने की जहमत नहीं उठाना चाहता।

एक प्रश्न यह भी उठता है कि नए सिरे से इतिहास-लेखन की दिशा क्या होनी चाहिए और उसमें किन बिंदुओं पर काम किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ-कुछ दिशा तो गृह मंत्री ने अपने भाषण में ही दे दी कि इतिहास के उपेक्षित महापुरुषों और साम्राज्यों पर संदर्भ ग्रंथ तैयार किए जाएं। इसके अलावा अबतक जो इतिहास लेखन हुआ है, उसका अधिकांश हिस्सा ईसा के बाद का है, जबकि भारतीय सभ्यता की जड़ें बहुत गहरी, बहुत पुरातन हैं। दिक्कत यही है कि हमने भारतीयता युक्त इतिहास दृष्टि से कभी उनको देखने का प्रयत्न ही नहीं किया।

यह अभारतीय दृष्टि ही है, जिसने रामायण और महाभारत जैसे हमारी सभ्यता-संस्कृति के महान ऐतिहासिक ग्रंथों को मिथक बता दिया है, जबकि भारत सहित दुनिया भर में प्राप्त अनेक प्रमाण यह इंगित कर चुके हैं कि यह ग्रंथ इतिहास हैं। राखीगढ़ी में प्राप्त बसावट के अवशेष हों या सिनौली में प्राप्त रथ, मुकुट हों या इंडोनेशिया के समुद्र में मौजूद भगवान विष्णु का पांच हजार साल पुराना मंदिर हो अथवा काफी पहले जर्मनी में प्राप्त हुई नरसिंह भगवान की लगभग चार हजार साल पुरानी प्रतिमा हो, इस तरह के तमाम साक्ष्य हमारी विस्तृत, पुरातन और समृद्ध सभ्यता की कथा कहते हैं। ऐसे ही रामायण और महाभारत से जुड़े सभी साक्ष्यों को संकलित कर इतिहास ग्रंथों के लेखन की दिशा में कार्य किया जा सकता है। निःसंदेह यह कार्य आसान नहीं है और इसके लिए जैसा कि अमित शाह ने कहा हमें हमारी 'मेहनत करने की दिशा को केंद्रित' करने की जरूरत है।

गृह मंत्री के इस वक्तव्य के पश्चात यह उम्मीद कर सकते हैं कि देश के बौद्धिक वर्ग में इसका असर होगा और वे इतिहास की बात आने पर अंग्रेजों और वामपंथियों को कोसने के बजाय नया इतिहास लिखने में ऊर्जा खर्च करना शुरू करेंगे।

60 फीसद लोगों को भारत में हार्ट अटैक के बाद पता चलता है कि उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है। दुनिया में हृदय रोग 55 साल की उम्र में होते हैं, जबकि भारत में यही उम्र 45 साल हो चुकी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 23 अक्टूबर 2019

डाटागीरी

उच्च शिक्षा में पुरुषों से कदम से कदम मिला रहीं महिलाएं

कभी महिलाओं को पढ़ने-लिखने में छूट न देने वाले भारतीय समाज में बड़ा बदलाव आ चुका है। महिलाएं अब केवल शुरुआती शिक्षा तक ही नहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी पुरुषों से बराबरी कर रही हैं। प्रत्येक प्रदेश और जाति व वर्ग में महिलाएं मात्र चंद कदम ही पुरुषों से दूर हैं। हालांकि, कुछ कोर्स में महिलाएं पुरुषों को पछाड़ भी चुकी हैं। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी महिलाएं पुरुषों से आगे हैं।

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। पिछले माह जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (एआइएसएचए) 2018-19 की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में उच्च शिक्षा में कुल अनुमानित छात्र नामांकन 3,73,99,388 हैं, जिनमें से लगभग 51.36 प्रतिशत पुरुष और शेष 48.64 प्रतिशत महिलाएं हैं।

कोर्स के आधार पर अंतर : अधिकांश कोर्स में लिंगानुपात के मामले में पुरुष अधिक हैं, लेकिन इनमें अपवाद भी हैं। जैसे, एम-फिल, स्नातकोत्तर और प्रमाणपत्र स्तरों में महिलाएं अधिक हैं। स्नातक स्तर पर नामांकन में 51 प्रतिशत पुरुष और 49 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि डिप्लोमा के मामले में पुरुष 66.8 प्रतिशत और महिलाएं मात्र 33.2 प्रतिशत हैं। पीएचडी स्तर पर पुरुष नामांकन 56.18 प्रतिशत और महिला नामांकन 43.82 प्रतिशत है। इंटीग्रेटेड स्तर पर 57.50 प्रतिशत पुरुष तो 42.50 प्रतिशत महिलाएं और पीजी डिप्लोमा में 54.09 प्रतिशत पुरुष और 45.91 प्रतिशत महिलाएं हैं।

राज्यों के आधार पर अंतर : उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक देश के वे छह राज्य हैं, जहां सबसे ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा हासिल करते हैं। इन राज्यों से देश के कुल 54.23 प्रतिशत छात्र आते हैं। इन राज्यों में देश की 54.43 प्रतिशत महिला छात्र और 54.05 प्रतिशत पुरुष छात्र शिक्षा हासिल करते हैं।

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा छात्र उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराते हैं। यहां पुरुष छात्रों का नामांकन प्रतिशत 49.30 है। यानी इस राज्य में महिलाएं आगे हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है यहां पुरुष छात्रों का नामांकन प्रतिशत 54.95 और महिला छात्रों का 45.05 प्रतिशत हैं। तमिलनाडु में 50.87 प्रतिशत पुरुष और 49.13 प्रतिशत महिला छात्र, बंगाल में 50.37 प्रतिशत पुरुष तो 49.63 प्रतिशत महिला छात्र हैं। राजस्थान में महिला छात्रों की तुलना में पुरुष छात्र अधिक हैं।

वर्ग के आधार पर नामांकन : देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले कुल नामांकन में 14.89 प्रतिशत नामांकन एससी वर्ग से आते हैं। एसटी वर्ग से 5.53 प्रतिशत छात्र आते हैं। ओबीसी वर्ग से 36.34 प्रतिशत छात्र आते हैं, जिनमें 50.83 प्रतिशत पुरुष होते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि 5.23 प्रशित छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक और 2.32 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं। मुस्लिम में महिलाओं की तुलना में पुरुष छात्र अधिक हैं, जबकि अन्य अल्पसंख्यकों में महिला छात्र पुरुषों से अधिक हैं।

नामांकन के आधार पर छह शीर्ष राज्य

राज्य	पुरुष (प्रतिशत)	महिला (प्रतिशत)
उत्तर प्रदेश	31,89,520 (49.30)	32,76,847 (50.70)
महाराष्ट्र	23,24,424 (54.95)	19,05,902 (45.05)
तमिलनाडु	17,36,870 (50.87)	16,77,326 (49.13)
बंगाल	10,56,511 (50.37)	10,40,899 (49.63)
राजस्थान	10,82,466 (51.93)	10,01,947 (48.07)
कर्नाटक	9,93,417 (49.96)	9,95,077 (50.04)

वर्ग के आधार पर नामांकन

कैटेगरी	छात्र	पुरुष (प्रतिशत)	महिला (प्रतिशत)
एससी	55,67,078	50.94	49.06
एसटी	2,067,748	50.88	49.12
ओबीसी	1,35,91,994	50.83	49.17
मुस्लिम	19,59,004	50.71	49.29
अन्य अल्पसंख्यक	8,68,100	45.75	54.25
दिव्यांग	85,877	56.14	43.86

फरमानों से बेखौफ, गढ़ रहीं नया कश्मीर

बदल रही तस्वीर ▶ 24 को होने हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव, दिख रही बदलाव की बानगी

विकास की राह में रोढ़ा रहे कट्टरपंथ को तोड़ रहीं हैं कश्मीरी महिलाएं

विवेक सिंह, जम्मू

कश्मीर अब बदल रहा है। लंबे समय से विकास की राह में रोढ़ा बने रहे कट्टरपंथ को कोई और नहीं बल्कि खुद कश्मीरी महिलाएं तोड़ रही हैं। 24 अक्टूबर को राज्य में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल (बीडीसी) के चुनाव हैं। बदलाव की बयार चहुंओर बह रही है। ये महिलाएं अलगावाद और आतंकवाद के फरमानों की परवाह न कर बदलाव को धार दे रही हैं। दक्षिण कश्मीर में खौफ का पर्याय रहे जाकिर मूसा और बुरहान वानी जैसे आतंकियों के गढ़ से हुंकार भरने वालीं सकीना अख्तर की बात करें या फिर उड़ी की आसिफा तबस्सुम मीर के हौसले की, एक बड़ा बदलाव स्पष्ट महसूस किया जा सकता है।

नारी सशक्तीकरण

सकीना और आसिफा जैसी निडर महिलाएं कश्मीर में रोल मॉडल बन कर उभरी हैं। कश्मीर में ब्याही गुलाम कश्मीर की आसिफा कुंडीबरजाला पंचायत की सरपंच हैं। कहती हैं, सही मायनों में दुनिया में अगर जम्हूरियत और आजादी है तो वह हिंदुस्तान में है। हमें मिलजुल कर कश्मीर को बदलना है।

कश्मीर में महिलाएं ला रही हैं बदलाव। प्रतीकात्मक चित्र (जागरण आर्काइव)

कुछ समय पहले तक दक्षिण कश्मीर के त्राल के डाडेसर क्षेत्र में दुर्दांत आतंकवादियों का दबदबा था। कश्मीर में दहशत इस कदर थी कि महिलाएं बाहर तक नहीं निकलती थीं। अपने गांव के लोगों को बेहतर भविष्य देने के इरादे से सकीना सामने आईं। उनके खिलाफ फरमान जारी हुए, समाज में बातें होने लगीं, परिवार का भी दबाव बना कि पीछे हट जाएं, लेकिन अपने गांव और कश्मीर के लिए कुछ करने का जुनून था, जिसके बल पर वह डटी रहीं। लोगों का साथ मिला और एक साल पहले सकीना शाहबाद पंचायत से सरपंच चुनी गईं। वह कश्मीर के आतंकग्रस्त क्षेत्रों में देशभक्ति की अलख जगाने के अलावा संबंधित कार्यक्रमों में हमेशा आगे रहती हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में घर-घर जाकर लोगों को अवगत कराना उनका मकसद बन गया है। उनके इस प्रयास के कारण कई लोग योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं। ग्राम विकास के उनके इस जज्बे ने न सिर्फ आतंकवाद को बौना साबित किया, बल्कि बीडीसी चुनाव से पूर्व सकीना निर्विरोध चेयरमैन पद के लिए चुनी गई हैं। कहती हैं कि अगर पांच अगस्त के बाद नया कश्मीर बना है तो लोगों में बदलाव जरूरी है। खौफ को निकालना होगा और सिर्फ विकास की तरफ ही सोचना होगा, तब जाकर हमारा असली मकसद पूरा होगा। बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर ब्वॉय रहे बुरहान वानी के गृह जिले पुलवामा के त्राल क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार ने इस वर्ष संसदीय चुनाव में सबसे अधिक वोट लेकर इतिहास रचा था। अब बुरहान के गांव डाडेसर में सकीना ने कमल को खिलाया है।

उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे जिला बारामुला के उड़ी ब्लॉक की कुंडीबरजाला पंचायत की रहने वाली आसिफा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी कश्मीर में सरपंच बनेगी। पति मंजूर की टेलरिंग की दुकान है। आसिफा ने कहा कि पिछले साल जब पंचायत चुनाव हुए तो हमारा इलाका महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था। सभी ने मेरा नाम तय किया और मैं चुनाव जीत गई। आसिफा अब पक्की हिंदुस्तानी बन चुकी हैं। कहती हैं, जो मेरे शौहर का वतन है वही मेरा वतन है। वतन से मुहब्बत करना एक इबादत है। यहां अच्छी सड़कें, स्कूल और अस्पताल चाहिए। हम लोग यहां बॉर्डर पर रहते हैं, जहां गोलाबारी होती रहती है। इसलिए हम लोगों के लिए बंकर होने चाहिए।

कमान हाथ में लेने को तैयार : जम्मू-कश्मीर में 24 अक्टूबर को बीडीसी के चुनाव हैं और 400 से अधिक पंच, सरपंच इस चुनाव के जरिये गांवों के विकास की कमान को अपने हाथ में लेने को तैयार हैं। इनमें 89 फीसद पंच, सरपंच निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। शोपियां से भाजपा के छह, पुलवामा में चार, बांडीपोरा में दो, अनंतनाग, बडगाम, गांदरबल जिलों में एक-एक उम्मीदवार इन चुनावों के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। पार्टी को उम्मीद है कि 24 अक्टूबर को परिणाम आने के बाद कश्मीर में पार्टी के 60 से अधिक चेयरमैन होंगे। कश्मीर में 130 ब्लॉकों के चेयरमैन चुने जाने हैं। 15 का फैसला चुनाव से पहले ही हो चुका है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

12 लाख क्विंटल फसली अवशेष को जलने से बचाएगी सेंसर पेपर मिल

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव बाखली के प्लाट नंबर पांच में बनी सेंसर पेपर मिल ने बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से इस साल 12 लाख क्विंटल फसली अवशेष को आग लगने से बचाने का लक्ष्य तय किया है। अपने इस तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य करते हुए मिल की ओर से अभी तक 10 लाख क्विंटल फसली अवशेष एकत्रित कर लिए गए हैं। खास बात यह है कि मिल प्रबंधन के इस अभियान से पर्यावरण प्रदूषण से तो बचाव हुआ ही है, साथ ही करीब 2500 लोगों को भी रोजगार मिला है। यह लोग 100 मशीनों के साथ खेतों से फसली अवशेष एकत्रित करने के काम में जुटे हैं। इतना ही नहीं इसको स्टोर करने के लिए मिल की ओर से 90 एकड़ जगह की व्यवस्था की गई है।

मिल के एमडी प्रदीप सैनी ने बताया कि फसली अवशेष एकत्रित करने के लिए कुरुक्षेत्र में 100 मशीनें लगी हुई हैं। इनमें प्रत्येक मशीन के साथ एक ट्रैक्टर और 25 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह मशीनें खेतों से फसली अवशेष कटाई करने के बाद उनकी पैकिंग करती हैं। पैकिंग के बाद किसान इन्हें बेचने के लिए मिल पहुंच रहे हैं। वह इस फसली अवशेष को बिजली बनाने के लिए उपयोग करते हैं। मिल को चलाने के लिए बिजली इसी से तैयार की जाती है।

क्या हैं नुकसान : उन्होंने बताया कि एक टन फसली अवशेष के जलाने पर तीन किलो पार्टिकुलेट मेटर, 14 किलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 60 किलो कार्बन मोनोक्साइड, 190 किलोग्राम राख और दो किलो सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है।

बिहार के सुनील को बांस शिल्प से मिली पहचान, विदेश तक हो रही मांग

शंभूनाथ चौधरी, रोसड़ा (समस्तीपुर)

बांस से न केवल खूबसूरत ईको फ्रेंडली कई सामान बनाए जा सकते हैं, बल्कि यह रोजगार का बेहतर साधन भी बन सकता है। बिहार के रोसड़ प्रखंड के मिर्जापुर गांव निवासी सुनील कुमार राय को इसके जरिये पहचान भी बनाई और आर्थिक विकास भी किया। उनकी बनाई वस्तुओं की मांग दूसरे देशों खासकर इजरायल में भी है।

▶ **बिहार के सुनील 500 से अधिक वस्तुएं बनाते हैं बांस से**

इस तरह हुई शुरुआत : 39 वर्षीय सुनील कुमार बताते हैं कि मैट्रिक की पढ़ाई के दौरान वर्ष 1999 में वह पटना के गांधी मैदान में लगे हैंडीक्राफ्ट मेले में गए थे। वहां असम के स्टॉल पर बांस से बनी नाव देखकर मोहित हो गए। इसके बाद वह इस कला को सीखने असम पहुंच गए। वहां एक महीने 10 दिन तक प्रशिक्षण लिया। घर लौटे और इस काम की शुरुआत की। वह बांस से जहाज, कलम स्टैंड, गुलदस्ता स्टैंड, कुर्सी, मेज, महापुरुषों की मूर्तियां, हैंगिग लैंप, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सहित 500 से अधिक वस्तुएं बनाते हैं।

मेलों में स्टॉल से बढ़ा दायरा : सुनील दिल्ली के प्रगति मैदान और गया के पितृपक्ष मेला सहित अन्य जगहों पर स्टॉल लगाते हैं। दिल्ली और गया में पहुंचने वाले विदेशी बांस से बनीं बुद्ध व गांधी की मूर्तियों के साथ ताजमहल, चूड़ियां, विंड चेन तथा फ्लावर पॉट जरूर खरीदते हैं। नाबार्ड के माध्यम से उन्होंने बांस निर्मित हेड क्लिप, फूड बास्केट, लैंप आदि को विशेष मांग पर इजरायल तक भेजा है।

बांस से तरह-तरह की कलाकृतियां बनाते बिहार के मिर्जापुर गांव निवासी सुनील। जागरण

कई जगह हो चुके सम्मानित : सुनील को वर्ष 2010-11 का बिहार सरकार की ओर से राज्य पुरस्कार दिया गया। सुनील का कहना है कि दैनिक जीवन में बांस से बनी अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग हो तो पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार भी मिलेगा।

पीलीभीत में मिलीं 100 से ज्यादा प्राचीन मूर्तियां

जेएनएन, मेरठ

▶ **सिनौली साइट से कुछ दूर प्राचीन शिव मंदिर में भी सीढ़ियां और खंडित मृणमूर्ति मिलीं**

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के इलावास देवल में नौवीं और दसवीं सदी की सैकड़ों ऐतिहासिक मूर्तियां मिलने के बाद रुहेलखंड विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के विशेषज्ञों ने वहां खोदाई करने का फैसला किया है। इसके लिए विशेषज्ञों ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही उप्र सरकार व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं, बागपत के सिनौली साइट से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में छह सीढ़ियां और खंडित मृणमूर्ति भी मिली है।

रुहेलखंड विवि के प्राचीन इतिहास विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर विजय बहादुर ने कुछ छात्रों के साथ मिलकर पीलीभीत के इलावास स्थित मंदिरों का दौरा किया था। वहां मंदिरों के आसपास सैकड़ों की संख्या में प्राचीन मूर्तियां मिलीं। इन मूर्तियों का अध्ययन किया गया तो मालूम हुआ कि यह नौवीं और दसवीं शताब्दी की हैं। अब विशेषज्ञों को उम्मीद है कि जमीन के नीचे काफी ऐतिहासिक चीजें मिल सकती हैं, जिसका संरक्षण किया जाना। साथ ही इससे उस सदी के बारे में जानने के लिए अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए इलावास और आसपास के इलाकों में खोदाई करने की तैयारी शुरू की है।

दूसरी तरफ बागपत के सिनौली साइट से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में छह सीढ़ियां और खंडित मृणमूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति भी मिली है। यह सीढ़ियां मंदिर के प्रवेश द्वार पर मौजूद हैं। सिनौली गांव के राजकुमार सिंह मान, सौरभ, हरपाल सिंह आदि ने बताया कि गांव के बीच में प्राचीन शिव मंदिर परिसर में पिछले सप्ताह फर्श डालने के लिए खोदाई की गई थी। इस दौरान मंदिर के प्रवेश द्वार से एक के बाद एक कर छह सीढ़ियां मिलीं, जिसकी ऊपर से कम और नीचे से चौड़ाई ज्यादा है। इसी दौरान मिट्टी की एक छोटी खंडित मूर्ति और कुछ मृदभांड भी मिले हैं। सीढ़ियां नीचे से घुमावदार हैं।

एमएम कॉलेज मोदीनगर में एसोसिएट प्रोफेसर व इतिहासकार डॉ. केके शर्मा ने बताया कि प्राचीन काल में मंदिर कुछ ऊंचाई पर बना होगा और जिसमें जाने के लिए श्रद्धालु सीढ़ियों का प्रयोग करते होंगे। उन्होंने दावा किया कि आसपास और भी अवशेष मिल सकते हैं। गौरतलब है कि इस मंदिर परिसर में करीब दो साल पहले भी सीढ़ियां दिखाई दी थीं, लेकिन उस समय लोगों ने इसकी नीचे से खोदाई नहीं की थी। ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग को सूचित किया है।

बागपत के सिनौली गांव में मिली खंडित मृणमूर्ति। जागरण

सिनौली गांव के प्राचीन शिव मंदिर में सीढ़ियां भी निकली हैं। जागरण

फोटो न्यूज

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली : दुनिया में ऐसी बहुत सी कुदरती घटनाएं होती हैं, जो हमें अचंभित और आकर्षित करती हैं। उन्हीं में से एक है 'ब्लू टीयर्स'। यह तस्वीर पूर्वी चीन सागर (ईस्ट चाइना सी) के तट की है, जिसमें पानी में नीली रोशनी इस तरह दिखाई दे रही है, मानों लाखों छोटे-छोटे नीले बल्ब जगमगा रहे हों। दरअसल, यह चमक समुद्र में रहने वाले प्लवक की है। प्लवक वे जीव या वनस्पति को कहते हैं, जो जलतरंगों या जलधारा द्वारा प्रवाहित होते हैं। वैसे ये प्लवक दुनियाभर में पानी में फैले हुए हैं, लेकिन सबमें चमकने की क्षमता नहीं होती है। कुछ विशेष तटीय क्षेत्रों में इन्हें चमकते हुए देखा जाता है। शुरुआत में समुद्र किनारे दिखने वाली यह रोशनी शोधकर्ताओं के लिए भी रहस्य बनी हुई थी, लेकिन अध्ययन के बाद उन्होंने इसके कारण का पता लगाया है।

कैसे चमकते हैं

सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये जीव गुब्बारे जैसे दिखाई देते हैं। जब समुद्र में किसी नाव, तैराक, ज्वार आदि के कारण तरंगें बनती हैं तो पानी की गति के कारण ये जीव चमकने लगते हैं। शोधकर्ताओं ने इस पर विस्तार से अध्ययन किया है। 18 वर्षों में सेटेलाइट की मदद से एकत्र की गई तस्वीरों से पता चला है कि अप्रैल से अगस्त के बीच इनके चमकने की घटनाएं अधिक होती हैं।

पर्यटकों को कर रहे आकर्षित

ये जीव कब और कहां चमकेंगे अभी तक इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। वैज्ञानिकों ने सेटेलाइट से एकत्र तस्वीरों का विश्लेषण किया है, जिसके आधार पर वे काफी हद तक सही अनुमान लगा सकते हैं कि यह अद्भुत प्राकृतिक घटना कब और कहां होगी। इसकी वजह से अब ऐसे स्थानों को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है।

तलैया के बीच विराजमान होंगे कांसे के गुरु गोरक्षनाथ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : एक एकड़ की तलैया होगी और बीच में वज्रासन मुद्रा में विराजमान गुरु गोरक्षनाथ की 12 फीट की कांस्य प्रतिमा होगी। गोरखपुर व संतकबीरनगर सीमा पर कसरवल गांव की कबीर धूनी और गोरख तलैया परिसर का दृश्य अनोखा होगा। इस आध्यात्मिक स्थल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का कार्य जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाले इस कार्य को साल के अंत तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य है। मान्यता है कि करीब 600 वर्ष पहले इस स्थान पर अकाल के दौरान जल संकट दूर करने के लिए गुरु गोरक्षनाथ ने अंगूठे से जमीन को दबाया तो वहां इतना पानी निकला कि तलैया तैयार हो गई। बाद में वह गोरख तलैया के नाम से मशहूर हो गई। समय के साथ तलैया का स्वरूप छोटा होता गया। जब गोरखपुर-लखनऊ फोर लेन का निर्माण हुआ तो तलैया विलुप्तप्राय हो गई। हालांकि पास में ही कबीर धूनी का अस्तित्व बरकरार रहा। योगी ने जब प्रदेश का नेतृत्व संभाला तो अन्य आध्यात्मिक स्थलों के साथ इसको भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनी। चार एकड़ क्षेत्र में पौने पांच करोड़ रुपये की लागत से बीते वर्ष निर्माण कार्य शुरू किया गया।

जानिए क्यों मील के पत्थर की तरह है सिर्फ महिलाओं की स्पेसवॉक

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर ने बीते सप्ताह अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर (आइएसएस) के बाहर चहलकदमी (स्पेसवॉक) कर इतिहास रचा है। उनका मिशन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत करना था। इस स्पेसवॉक को अंतरिक्ष के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब केवल महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे किया हो। साथ ही यह स्पेसवॉक कई तरह की परेशानियों और कई असफल प्रयासों के बाद हो पाई है।

पहली बार क्या हुआ था : गत 18 अक्टूबर को हुई स्पेसवॉक पहले इस वर्ष 29 मार्च को होनी थी। नासा के अनुसार, क्रिस्टीना कोच के साथ एनी मैकक्लेन उस अभियान का हिस्सा थीं। हालांकि, मैकक्लेन के लिए आइएसएस में उपयुक्त स्पेससूट ना होने की वजह से उस समय उसे टाल दिया गया था। मैकक्लेन ने अपनी इससे पहले की स्पेसवॉक के बाद बताया था कि उनके लिए स्पेससूट का ऊपरी हिस्सा मीडियम साइज का होना चाहिए, जबकि आइएसएस में बड़ा साइज मौजूद था। इसलिए वह सूट फिर निकहूज को दे दिया गया था। स्पेसवॉक से पहले स्पेससूट को अंतरिक्षयात्री के शरीर में फिट होना जरूरी होता है। नासा की प्रवक्ता स्टेफनी शियरहोलज इस बारे में बताया था कि एक स्पेससूट को सुरक्षित रूप से स्पेसवॉक के लिए तैयार करने में 12 घंटे का समय लगता है और उसे पहनने में 45 मिनट लगते हैं। 27 मार्च को मैकक्लेन ने ट्वीट किया था कि सिर्फ महिलाओं की स्पेसवॉक को टाल देने का फैसला उनकी सिफारिश पर आधारित था। मिशन और चालक दल की सुरक्षा सबसे पहले है। हमें ऐसे जोखिम को कभी नहीं स्वीकारना चाहिए। हालांकि, मैकक्लेन बाद में दूसरी स्पेसवॉक पर गई थीं।

स्पेससूट की कमी बना था बड़ा मुद्दा : सिर्फ महिलाओं की स्पेसवॉक रद होने के बाद महिलाओं के लिए मीडियम साइज के स्पेससूट की कमी एक बड़ा मुद्दा बन गई थी। चारों तरफ से नासा की आलोचना की गई थी, जबकि नासा को लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील माना जाता है। 2013 के आइएसएस के स्टाफ में 50 फीसद महिलाएं थीं। हालांकि, यह भी सच है कि कई महिलाओं ने नासा में महिलाओं के लिए सही स्पेससूट की कमी महसूस की।

राजनीतिज्ञ भी हुए थे मुखर : जब सिर्फ महिलाओं की पहली स्पेसवॉक रद की गई और स्पेससूट इसकी वजह बना तो राजनीतिज्ञ भी इस मामले में मुखर हुए थे। हिलेरी क्लिंटन ने ट्वीट किया था, 'दूसरे सूट बनाइए', जबकि ब्रिटिश राजनेता एमेलिया वोमैक ने ट्वीट किया था, 'जब दुनिया पुरुषों के आसपास बनी होती है तो महिलाएं कैसे चूक जाती हैं।' ह्यूगो अवॉर्ड से सम्मानित लेखिका मैरी रोबिनेट कोवल ने ट्वीट किया कि 'नासा में छोटे, मध्यम, बड़े और अतिरिक्त बड़े सूट हुआ करते थे। बजट कारणों से छोटे और अतिरिक्त बड़े सूट हटा दिए गए। हालांकि, कई पुरुष अंतरिक्ष यात्री बड़े सूट में फिट नहीं हो सके तो अतिरिक्त बड़े सूट को फिर से लाया गया, लेकिन छोटे सूट कभी नहीं आए।'

गत 18 अक्टूबर को स्पेसवॉक करने वालीं अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर और क्रिस्टीना कोच। फाइल

213 पुरुष और 14 महिलाएं स्पेसवॉक कर चुकी हैं अब तक

15 वीं महिला बनी हैं जेसिका मीर हाल में स्पेसवॉक करने वालीं

421 स्पेसवॉक हो चुकी हैं अब तक कुल

1974 में विकसित किए गए थे वर्तमान में उपयोग किए जा रहे स्पेससूट

किन हिस्सों से मिलकर बनता है स्पेससूट : अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से बाहर काम करने के लिए एक स्पेससूट पहना जाता है। इसे एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट (ईएमयू) भी कहते हैं। स्पेससूट अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। साथ ही यह उन्हें अत्यधिक तापमान, विकिरण और अंतरिक्ष धूल से भी सुरक्षा प्रदान करता है। एक स्पेससूट में ऊपरी धड़, निचला हिस्सा, दस्ताने जैसे अलग-अलग घटक होते हैं जो विभिन्न आकारों के होते हैं और अंतरिक्ष यात्री के हिसाब से उनका संयोजन किया जाता है। इस तरह एक स्पेससूट बनता है। मैकक्लेन के मामले में यह था कि स्पेससूट का ऊपरी हिस्सा फिट नहीं आ रहा था। स्पेससूट महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग नहीं बनाए जाते हैं। वर्तमान में उपयोग किए जा रहे स्पेससूट 1974 में विकसित किए गए थे। ये कई बार उपयोग में लाए जा सकते हैं साथ ही पिछले चार दशकों में इनको कई बार अपग्रेड भी किया जा चुका है।

नासा ने हाल ही विकसित किया है नई तकनीक का सूट : स्पेससूट की फिटिंग को देखते हुए नासा ने हाल में नई तकनीक का सूट विकसित किया है। गत 15 अक्टूबर को नासा की स्पेससूट इंजीनियर क्रिस्टीन डेविस ने एक्सट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट (एक्सईएमयू) सूट को प्रदर्शित किया था। इसके साथ ही एक अन्य सूट 'ओरियन क्रू सर्वाइवल' को भी प्रदर्शित किया था। ओरियन सूट अंतरिक्ष यात्रा के दौरान पहनने के लिए था, जबकि एक्सईएमयू सूट आइएसएस के बाहर स्पेसवॉक और चांद की सतह पर चहलकदमी के लिए है। इन सूट की खासियत यह है कि ये सभी साइज के अंतरिक्षयात्रियों को फिट हो जाते हैं। इन सूट को नासा 2024 में अपने आर्टेमिस मिशन के दौरान उपयोग में लाएगा।

दंगे, दुष्कर्म और हत्या के मामलों में आई कमी

2017 के अपराध के आंकड़ों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 में दंगा पीड़ितों की कुल संख्या में 22 फीसद की वृद्धि के साथ औसतन देश में हर दिन दंगों से जुड़े 161 मामले देखे गए। हलांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2016 की तुलना में 2017 में दंगों की घटनाओं में पांच फीसद की कमी आई। ये आंकड़े सिर्फ सांप्रदायिक दंगों के नहीं हैं। इसमें जमीन-जायदाद, जातीय, राजनीतिक, विभिन्न समूहों और छात्रों के बीच होने वाले दंगे भी शामिल हैं। वहीं दुष्कर्म और हत्या के मामलों में भी कमी देखी गई।

2017 में दंगे

58,880 दंगों के कुल मामले दर्ज
90,394 दंगा पीड़ितों की संख्या

2016 में दंगे

61,974 दंगों के कुल मामले दर्ज
73,744 दंगा पीड़ितों की संख्या

बिहार रहा अव्वल

2017 में बिहार में दंगों के 11,698 मामले दर्ज हुए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में दंगों के 8,990 मामले दर्ज हुए। 7,743 मामलों के साथ महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। 2017 में तमिलनाडु में दंगों के 1935 मामले सामने आए। इन दंगों से पीड़ितों की संख्या 18,749 रही। यहां हर दंगे में औसतन 9 लोग पीड़ित हुए। दंगे की कुल घटनाओं में तमिलनाडु की हिस्सेदारी 3 .28 फीसद रही। लेकिन पीड़ितों के मामले राज्य की हिस्सेदारी 21 फीसद रही। इस मामले में पंजाब सबसे शांत राज्य रहा।

कम हुए सांप्रदायिक दंगे

रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में सांप्रदायिक दंगों के 869 मामले सामने आए थे, जो 2017 में घटकर 723 रह गए। सांप्रदायिक दंगों के मामले में भी बिहार अव्वल रहा। साल 2017 में बिहार में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगों के 163 मामले सामने आए। इसके बाद कर्नाटक और ओडिशा रहे। जहां क्रमश: 92 और 91 मामले सामने आए। वहीं 2016 में हरियाणा में सांप्रदायिक दंगों के 250 मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2017 में सांप्रदायिक दंगों के सिर्फ 25 मामले सामने आए।

2017 में राज्यवार दंगे के मामलों की संख्या

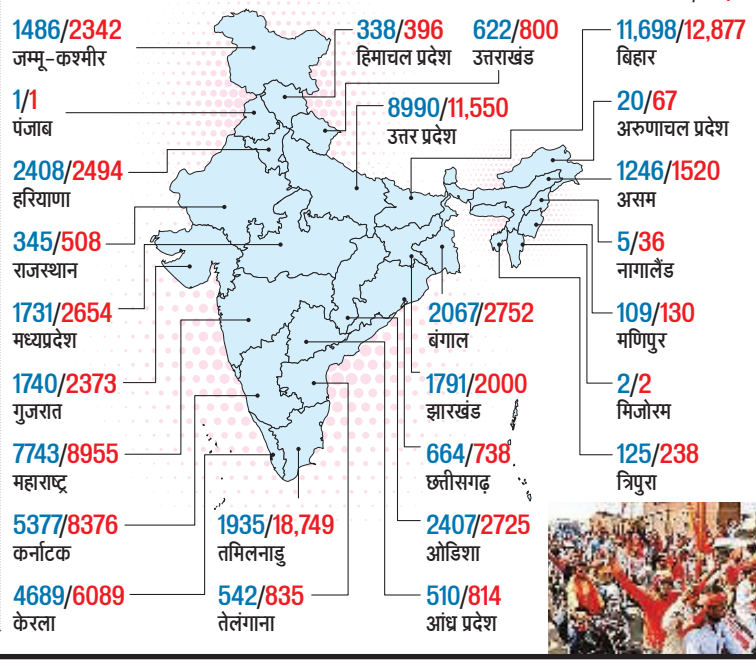

सबसे ज्यादा जमीन जायदाद को लेकर दंगे

2017 में हुए कुल दंगों में 22 फीसद दंगे जमीन जायदाद से जुड़े थे। वहीं दंगा पीड़ित भी 35 फीसद ऐसे थे, जो जमीन जायदाद के विवाद के शिकार हुए थे। जमीन जायदाद के दंगों में भी बिहार अव्वल रहा। बिहार में कुल 7,030 मामले दर्ज हुए। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश रहे। तमिलनाडु में जमीन जायदाद से जुड़े सबसे कम 587 दंगे हुए।

हत्या के मामले घटे

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, 5 .9 फीसद की गिरावट के साथ हत्या के मामलों की संख्या 30,450 से घटकर 28,653 रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक, विवाद और व्यक्तिगत दुश्मनी 2017 में हत्याओं के दो प्रमुख कारण रहे। उत्तर प्रदेश (4,324) और बिहार (2,803) में हत्या के मामलों की संख्या सबसे ज्यादा रही।

दुष्कर्म के मामले घटे

2017 में दुष्कर्म के मामलों की कुल संख्या 32,599 रही। इनमें से 10,221 बालिका / बाल पीड़िता थीं। यह संख्या 2013 के बाद सबसे कम है, जब मामलों और पीड़ितों की संख्या 33,707 और 33,764 थी। दुष्कर्म के मामलों की अधिकतम संख्या मध्य प्रदेश (5,562) में दर्ज की गई। राजस्थान 3,305 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

जातीय दंगों में भी आई कमी: 2016 की तुलना में 2017 में जातीय दंगों में 65 फीसद की कमी आई। जातीय दंगों के मामले में यूपी अव्वल रहा। 2017 में यूपी में जातीय दंगों के 346 मामले सामने आए। 2016 में यह आंकड़ा 899 था।

इस बार लक्ष्मी-गणेश के पांच ग्राम वजन वाले सिक्के भी होंगे उपलब्ध

देश के बड़े हिस्से में आगरा से होती है इन सिक्कों की आपूर्ति। जागरण

संजीव जैन, आगरा

जागरण विशेष

- **10 ग्राम के सिक्के की रहती है अधिक मांग, लेकिन चांदी के बढ़े दामों के कारण इस बार घटा वजन**
- **चांदी कारोबार का गढ़ है आगरा, कुटीर उद्योग के रूप में जुड़े हैं 200 गांवों के पांच लाख लोग**

धनतेरस और दिवाली का बाजार सजने लगा है। पूजा में रखे जाने वाले लक्ष्मी-गणेश के चांदी के सिक्कों की बात करें तो खास यह कि इस बार 10, 20 और 50 ग्राम के अलावा पांच ग्राम वजन के सिक्के भी उपलब्ध होंगे। हालांकि 10 ग्राम के सिक्के की मांग अधिक रहती है, लेकिन चांदी के बढ़े दामों के कारण इस बार वजन घटाया गया है।

चांदी के सिक्कों की ढलाई और आपूर्ति के बड़े केंद्र आगरा में कारोबारियों ने बताया कि इस बार लक्ष्मी-गणेश की छाप वाला पांच ग्राम का चांदी का सिक्का भी बनाया गया है, जिसकी कीमत 250 रुपये तक है। चांदी के बढ़े दामों को देखते हुए ऐसा किया गया है। लक्ष्मी-गणेश के अलावा राम दरबार, क्वीन विक्टोरिया और जार्ज पंचम की छवि वाले सिक्कों की भी ढलाई यहां होती है। हालांकि, कुछ वर्षों से लक्ष्मी-गणेश के सिक्कों की बढ़ती मांग के बीच अन्य छाप वाले सिक्के बाजार से लगभग हट गए। दरअसल, आगरा में चांदी की पायलें बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं। कुटीर उद्योग के रूप में यहां करीब 200 गांवों के पांच लाख लोग इस कारोबार से जुड़े हैं। त्योहारी सीजन में चांदी के सिक्के भी बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। आगरा-मथुरा से प्रतिदिन पांच से सात टन चांदी का कारोबार होता है।

देश के बड़े सराफा कारोबारियों में शुमार स्थानीय कारोबारी आनंद अग्रवाल बताते हैं, पिछले दो महीनों में चांदी के दामों में पांच से सात हजार तक का उछाल आया है। ढाई फीसद ड्यूटी बढ़ी है। इसका असर यह हुआ कि पिछले साल जहां हमारे पास अकेले कॉरपोरेट सेक्टर से करीब 10 करोड़ के ऑर्डर आए थे, वहीं इस बार एक भी नहीं आया। यही हाल अहमदाबाद और मुंबई में भी है, जो सिक्का ढलाई के अन्य बड़े केंद्र हैं। पहले अनेक कंपनियां अपने कर्मचारियों अथवा अन्य लोगों को गिफ्ट में देने के लिए थोक ऑर्डर देती थीं। चांदी के दाम बढ़ने के कारण इस बार इनके ऑर्डर नहीं आए।

चांदी के भावों में हुई वृद्धि से सिक्के कहीं लोगों के बजट से बाहर न हो जाएं, ऐसे में इस बार लक्ष्मी-गणेश के के सिक्कों का वजन घटा दिया है। वैसे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम का सिक्का भी मौजूद हैं।

पिछले दो दशक में आगरा चांदी के कारोबार का बड़ा गढ़ बनकर उभरा है। इसके पीछे यहां रह रहे कारीगरों का हाथ है। आज यह कुटीर उद्योग है। बोदला, मोतीनगर, धाकरान, बलदेव आदि में घर-घर चांदी के आभूषण बनाने का काम होता है। कोई भी आभूषण बनाने के लिए सबसे पहले बंधेल (तार) बनता है। यह काम यहां मुगल काल से चल रहा है। सराफा कारोबारियों व इतिहासविदों के मुताबिक लक्ष्मी के अंकनयुक्त सिक्कों का प्रचलन सैकड़ों वर्ष पुराना है। अब तक मिले सबसे पुराने सिक्के तीसरी सदी ईसा पूर्व के हैं।

डॉलर और मूर्तियां भी : आगरा सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल व श्री सराफा के अध्यक्ष मुरारी लाल फतेहपुरिया बताते हैं कि लक्ष्मी-गणेश के सिक्कों के अलावा आजकल 'चांदी का डॉलर' भी लोकप्रिय हो रहा है, जिसे लोग उपहार में देने के लिए खरीदते हैं। आगरा में बन रहे चांदी के सिक्कों में 91.60 प्रतिशत चांदी होती है, इसलिए इनकी डिमांड रहती है। कारोबारियों ने बताया कि लक्ष्मी-गणेश की चांदी की मूर्तियां भी बनाई गई हैं, जिनकी कीमत एक लाख रुपये तक है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

देवदार के पेड़ों से निकल रहा पोलन दे रहा बीमारी

चिंताजनक ▶ शिमला में दमा के मरीजों की बढ़ने लगी समस्या

स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटक तक गले, नाक व चर्म रोग से हो रहे परेशान

जागरण संवाददाता, शिमला

सितंबर और अक्टूबर में देवदार के पेड़ों से पोलन अधिक गिरता है। प्रतीकात्मक

सुबह-शाम सैर इसलिए की जाती है ताकि सेहत बेहतर हो, लेकिन इन दिनों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सैर करना सेहत को सुधारने की जगह बिगाड़ सकता है। दरअसल, शिमला में देवदार के पेड़ों से निकल रहा पोलन सैर करने वालों को ताजगी की जगह बीमारी दे रहा है। पोलन हवा में घुलकर लोगों के साथ पर्यटकों की परेशानी बढ़ा रहा है। इससे दमा से पीड़ित लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आम शहरी से लेकर पर्यटक भी पोलन के कारण गले, नाक व चर्म रोग से परेशान हैं।

शिमला के जिन स्थानों पर देवदार के पेड़ हैं, वहां यह समस्या अधिक है। पंथाघाटी, विकासनगर, बीसीएस, छोटा शिमला, जाखू, आइजीएमसी, टॉलेंड, कनलोग, ढली, भराड़ी समेत आस-पास के इलाकों में देवदार के पेड़ ज्यादा हैं। इससे यहां पर इसके प्रभावितों की संख्या भी ज्यादा है। पोलन के कारण बीमार होने वाले रोजाना करीब 25 लोग शिमला के रिपन अस्पताल व 15 आइजीएमसी में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं।

बारिश से मिलेगी मुक्ति : विशेषज्ञों का मानना है कि भारी बारिश होने के बाद जब पोलन खत्म होगा तब ही इससे राहत मिल सकेगी।

क्या है पोलन : पोलन देवदार के पेड़ों से गिरने वाला पीला बुरादा होता है। बरसात खत्म होते ही हवा में सूखापन बढ़ गया है। इससे देवदार के पेड़ों से पोलन झड़ना शुरू हो गया है। यह हवा में घुलकर फेफड़ों में चला जाता है। इससे सांस, आंख और त्वचा से संबंधित एलर्जी हो रही है। पोलन सांस से संबंधित बीमारी को बढ़ा रहा है।

विशेषज्ञों की सलाह : आइजीएमसी में चेस्ट एंड टीबी पल्मोनेरी विभागाध्यक्ष डॉ. मलय सरकार ने कहा कि पोलन को गिरने से रोका नहीं जा सकता, पर इससे बचा जा सकता है। सांस से संबंधित मरीजों को अधिक एहतियात बरतने की जरूरत है। दमा के मरीज बिना मास्क पहने घर से बाहर न निकलें। अधिक समस्या होने पर अस्पताल आकर जांच करवाएं। जिन लोगों को स्किन एलर्जी है, वे तेल लगाएं नहीं तो खुजली की समस्या हो सकती है।

कुदरती है पोलन गिरना : पूर्व प्रधान मुख्य अरण्यपाल (पीसीसीएफ) डॉ. ललित मोहन ने कहा कि देवदार के पेड़ों से पोलन गिरना प्राकृतिक है। सितंबर व अक्टूबर में ऐसा ज्यादा होता है। पोलन से ही देवदार का बीज बनता है। इसके बिना देवदार के नए पौधे जंगलों में लगना संभव नहीं है। पोलन हवा के साथ उड़ता है।

बरते एहतियात : ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी इस सीजन में एहतियात बरतने की जरूरत है। पोलन गिरने वाले इलाकों में सैर करने से परहेज करना चाहिए। जिनकी सांस सैर करते समय अधिक फूलती है, वे कुछ दिन सैर से परहेज करें। अगर इस दौरान कोई इन्हेलर का इस्तेमाल करता है तो डॉक्टर से परामर्श लें।

पानी को लेकर हिंसा के मामलों में मध्य प्रदेश सबसे आगे

रवींद्र कैलासिया, भोपाल

एनसीआरबी की रिपोर्ट में आया सामने, 2017 में राज्य में पानी के विवाद में गई 14 जानें

गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से मध्य प्रदेश में जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, उसके कारण हिंसात्मक घटनाएं भी होती हैं। यही वजह है कि 2017 में मध्य प्रदेश में पानी को लेकर हुई हिंसा में 14 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। वहीं, देशभर में पानी को लेकर हुए विवाद के कारण 12 राज्यों में 50 लोगों की जानें गई हैं।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2017 के अपराधों की रिपोर्ट में ऐसे मामलों में 14 लोगों की जान चले जाने संबंधी तथ्य की पुष्टि हुई है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि देशभर में पानी विवाद को लेकर हुई घटनाओं में से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ही 14-14 जानें गई हैं। इनके अलावा गुजरात, पंजाब, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु व तेलंगाना में भी पानी के कारण हुई हिंसा के दौरान कुल 22 लोगों की हत्या हुई। गौरतलब है कि एनसीआरबी की 2018 और 2019 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा हर साल पानी के संकट से जूझता है, जिसके चलते लोग कई किलोमीटर पैदल, साइकिल सा बैलगाड़ी जैसे साधनों से पानी ढोकर लाते हैं। 2019 में ही प्रदेश के 52 में से 35 जिलों में जलसंकट की मार पड़ी थी। तालाब-कुओं से लेकर अन्य जल संरचनाओं में भी पानी नहीं बचा था। 4000 ऐसे गांव थे, जहां जल संकट था। 378 नगरीय क्षेत्रों में से 32 नगरीय निकायों में टैंकरों के जरिये पानी पहुंचाया गया। इसी तरह 96 नगरीय क्षेत्रों में भी एक दिन छोड़कर, 28 में दो दिन छोड़कर और एक नगरीय निकाय ऐसा रहा, जहां तीन दिन में एक बार जलापूर्ति की गई।

गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत के कारण समस्या विकराल हो जाती है। फाइल

हत्या की वारदात में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि

एनसीआरबी की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक मप्र में हत्या की घटनाएं 2016 की तुलना में 6 .7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो बिहार, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद देश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कुल 1908 की हत्या हुई, जिनमें से पानी के विवाद में 14 तो किसी प्रकार के लाभ को हासिल करने के लिए 63 लोगों की जान ली गई। वहीं, मामूली विवाद में 854, जमीन-जायदाद के विवाद में 147, पारिवारिक झगड़े में 193, लेनदेन को लेकर 50, पुरानी रंजिश के कारण 386 लोगों की हत्या हुई।

जखनी मॉडल पर देशभर में तैयार होंगे 1034 जलग्राम

प्रदीप द्विवेदी, बांदा

- **सूखे से जूझने वाला बुंदेलखंड का जखनी गांव जल संरक्षण को लेकर बना मिसाल**
- **नीति आयोग ने जल प्रबंधन प्रणाली-2019 में किया शामिल**

बुंदेलखंड के बांदा जिले के जखनी गांव से निकली जलग्राम की मशाल देशभर में रोशन होगी। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल गांव जखनी को देश का मॉडल घोषित करते हुए हर जिले में 2-2 ऐसे गांव बनाने की तैयारी की है। देशभर में 1034 गांव जखनी मॉडल पर जलग्राम बनेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल पर नीति आयोग ने इसको जल प्रबंधन प्रणाली-2019 में शामिल किया है।

बुंदेलखंड के गांवों में सूखे जैसे हालात किसी से छिपे नहीं हैं। करीब 15 वर्ष पूर्व तक ग्राम जखनी भी इन हालात से गुजर रहा था। तब यहां के उमाकांत पांडेय ने गांव को जल संकट से उबारने की ठानी और ग्रामीणों के सहयोग से 15 साल में परंपरागत जल संरक्षण विधि से जखनी गांव को देश का मॉडल बना दिया। मॉडल को समझने के लिए इजरायल सरकार के जल विशेषज्ञ, वर्ल्ड वाटर रिसोर्स ग्रुप, केंद्रीय भूजल बोर्ड व जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आ चुके हैं।

जल गांव के संयोजक उमाशंकर पांडेय बताते हैं कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में 25 अप्रैल 2005 को आयोजित कार्यशाला में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरित होकर जल संरक्षण का संकल्प लिया था। पिछले माह उन्हें नई दिल्ली में सम्मानित भी किया गया था।

कुछ ऐसा है जखनी मॉडल : गांव के युवाओं व बुजुर्ग किसानों की 30 सदस्यीय टीम ने खेतों की मेड़बंदी कर बारिश के पानी को सहेजना शुरू किया। पानी को तालाबों तक पहुंचाने के लिए नालियां बनाई गईं। घरों से निकलने वाले पानी को भी सहेजा। गांव में 30 कुएं, छह तालाब व दो नाले हैं जो सालभर पानी से लबालब रहते हैं।

यह मिला लाभ : भीषण गर्मी के दौरान जिले का जल स्तर 120 मीटर के आसपास रहता है, जबकि जखनी गांव में यहां के खास मॉडल की वजह से 50 से 60 मीटर पर पानी मिल जाता है। तालाबों से खेतों की सिंचाई होती है। यहां बासमती धान के उत्पादन के साथ बागवानी से किसान समृद्ध हो रहे हैं।

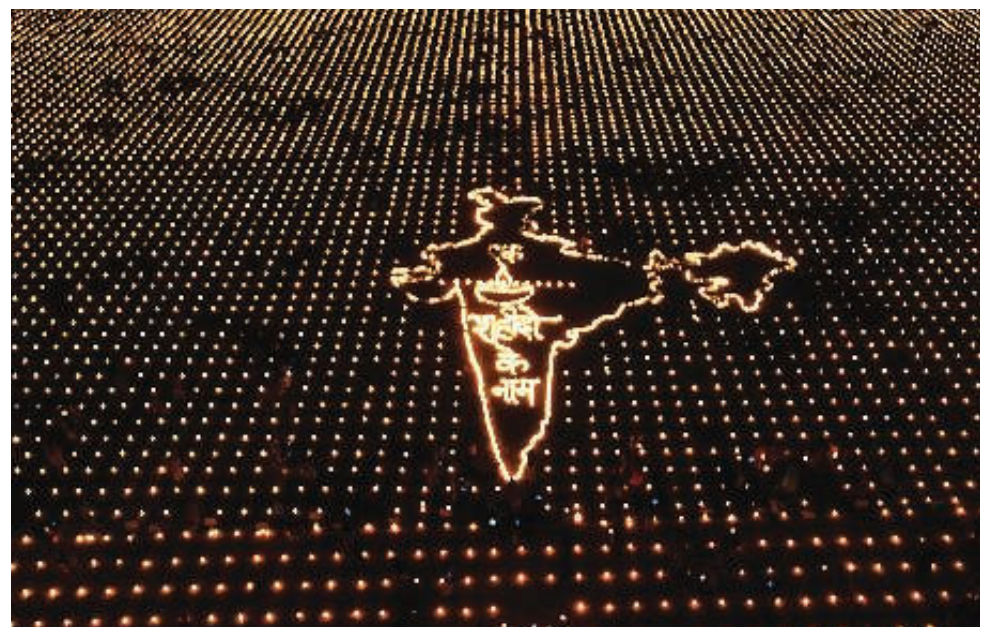

शहीदों को समर्पित किए गए दो लाख एक हजार एक दीये...

देश के अमर शहीदों की याद में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस सोनकपुर स्टेडियम में अविस्मरणीय आयोजन हुआ। इस मौके पर शहीदों की याद में जलाए गए दो लाख एक हजार एक दीयों से पूरा स्टेडियम जगमग हो उठा। मैदान में दीयों के रूप में जगमगाता देश का मानचित्र लोगों में देशभक्ति का अनूठा रंग घोलता नजर आया। यह मौका था दैनिक जागरण की ओर से दीपावली पर शहीदों को याद करने के लिए आयोजित दीपदान का। यह तीसरा बड़ा आयोजन था, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में गणमान्य और आमजन पहुंचे। जनप्रतिनिधियों से लेकर आमजन ने दीप से दीप जलाए। वर्ष 2018 में 1 . 51 लाख दीये जलाए गए थे। उससे पहले 2017 में 1 .21 लाख दीये जलाकर शहीदों के नाम एक अध्याय जोड़ा गया था।

राजू सैनी

अध्ययन

मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में किए गए शोध में आया सामने, शतावरी का एंटीआक्सीडेंट हार्ट के लिए रामबाण

हार्ट अटैक से बचाएगा शतावरी का चूर्ण

संतोष शुक्ल, मेरठ

हार्ट की बीमारी से हर साल लाखों लोग जान गंवा देते हैं, जबकि इससे बचाव की दर्जनों औषधियां रसोई से लेकर बगिया व गमलों में उपलब्ध हैं। आयुर्वेद में अमृत कहलाने वाली शतावरी का एंटी आक्सीडेंट गुणधर्म हार्ट के लिए सुरक्षा कवच बनेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के शोध में शतावरी अंग्रेजी दवाओं की तुलना में हार्ट अटैक रोकने में ज्यादा कारगर साबित हुआ। इस अध्ययन को इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल में भी छापा गया है। कई स्थानों पर क्लीनिकल ट्रायल भी शुरू कर दिया गया।

इस तरह किया शोध : मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. केके सक्सेना ने बताया कि शतावरी के हार्ट पर प्रभाव का पता लगाने के लिए 30 चूहों को छह ग्रुप में बांटकर शोध किया गया। एक ग्रुप में सिर्फ नमक का पानी दिया गया। अन्य ग्रुप में कैंसर की दवा डाक्सोरॉबिसिन दी गई, जिसने चूहों का हार्ट डैमेज कर दिया। इसके बाद 500 मिलीग्राम प्रति किलो व 250 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वजन के अनुपात में चूहों को 21 दिनों तक शतावरी का चूर्ण दिया गया।

फिर शतावरी से हार्ट को किया ठीक : एक ग्रुप के चूहों को हार्ट की रिकवरी के लिए अंग्रेजी दवा दी गई। दोनों दवाओं की तुलना में शतावरी ने तेजी से हार्ट के ब्लाकेज और अटैक का इलाज किया। जुलाई 2019 में जारी शोध-पत्र को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बेसिक एंड क्लीनिकल फार्माकोलॉजी में छापा गया। शोधकर्ताओं डॉ. पिंकी व डॉ. मनीषा चैटर्जी की टीम ने कई वर्कशापों में शतावरी के हार्ट पर प्रभाव संबंधी अध्ययन को प्रस्तुत किया है।

शतावरी हार्ट अटैक रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण औषधि साबित हुई है। इसमें फैट, कैलोरी व कोलेस्ट्राल बेहद कम, जबकि एंटीआक्सीडेंट ज्यादा है। ये कैंसर की दवाओं से हार्ट पर पड़ने वाले विषाक्त प्रभावों को भी खत्म करती है। अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में शोध छपने के बाद कई कंपनियां क्लीनिकल ट्रायल करने जा रही हैं।

- डॉ. केके सक्सेना, विभागाध्यक्ष, फार्माकोलॉजी विभाग, मेडिकल कॉलेज

इन वजहों से बढ़ती है दिल की बीमारियां

खानपान में गड़बड़ी, धूमपान, बीपी व कोलेस्ट्राल बढ़ने और रक्त आपूर्ति बिगड़ने से हार्ट पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इनसे हार्ट डैमेज हो सकता है। ज्यादा नमक सेवन, फास्टफूड, नींद की कमी, शारीरिक श्रम में कमी, एल्कोहल सेवन, प्रदूषित एवं रसायनयुक्त खानपान, सिंथेटिक मिठाइयों के सेवन से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है।

डॉक्टर बता पाएंगे कोमा से कब बाहर आएगा मरीज

ऋषि दीक्षित, कानपुर

- **न्यूरो सर्जन ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर किया अध्ययन**
- **कोमा में गए मरीजों पर रिसर्च कर निर्धारित की ग्रेडिंग**

चिकित्सा विज्ञान में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे यह बताया जा सके कि मरीज कोमा से बाहर कब आएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल (जीएसवीएम) मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉ. राघवेंद्र गुप्ता ने शोध के जरिये इसका अनुमान लगाने में 60 फीसद सफलता हासिल की है।

सड़क हादसे या अन्य कारणों से सिर पर चोट लगने से मरीज कोमा में चले जाते हैं। सीटी स्कैन जांच में चोट की गंभीरता का पता नहीं चलता। ऐसे में डॉ. राघवेंद्र गुप्ता ने भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स, नई दिल्ली) एवं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के विशेषज्ञों के साथ दो साल तक कोमा में गए 200 मरीजों का अध्ययन किया। एमआरआइ कराकर ग्रेडिंग निर्धारित की और अनुमान लगाया गया कि मरीज कोमा से कब बाहर आएगा। 60 फीसद केस में आकलन सही साबित हुआ।

डॉ. गुप्ता ने बताया कि पहले सभी मरीजों की सीटी स्कैन जांच कराई गई। इसमें सब सामान्य दिखा। इसके बाद जब एमआरआइ जांच कराई तो सामने आया कि 40 फीसद मरीजों के ब्रेन में गंभीर चोट है। वहीं, 60 फीसद मरीजों के अंदरूनी हिस्सों में चोट मिली। कई मरीजों के तो सॉफ्ट टिश्यू तक प्रभावित थे। छोटे-छोटे हिस्सों में खून के थक्के जम गए थे।

तीन स्तर पर तय की ग्रेडिंग : गहरे हिस्से में चोट के मरीज को ग्रेड-1 श्रेणी में रखा गया। ग्रेड-दो में वे मरीज शामिल किए गए, जिनके ब्रेन के कॉरपस कैलोशम में खून के थक्के व चोटें थीं। ग्रेड-3 की श्रेणी में नाजुक मरीज रखे, जिनके ब्रेन स्टेम में चोट थी।

ऐसे किया दावा : विशेषज्ञों ने दावा किया है कि ग्रेड-1 के मरीज एक माह में, ग्रेड-2 के तीन माह और ग्रेड-3 के मरीज छह माह में कोमा से बाहर आएंगे। ये भी दावा किया कि ग्रेड-दो के मरीजों में छह माह तक याददाश्त और ग्रेड-3 के मरीजों में एक साल तक चलने-फिरने की समस्या रहेगी।

अध्ययन में 60 फीसद मामलों में सही साबित हुआ अनुमान। प्रतीकात्मक

दो वर्षों तक अध्ययन के दौरान मरीजों के ब्रेन में लगी चोट के हिसाब से ग्रेडिंग की गई। इसी के अनुसार कोमा से बाहर आने का समय निर्धारित किया गया। 60 फीसद मरीजों पर आकलन सटीक रहा।

- डॉ. राघवेंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, न्यूरो सर्जरी, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज

राष्ट्रीय संस्करण
बुधवार 23 अक्टूबर 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

सत्यम घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सेबी

नई दिल्ली, प्रेट्र : बाजार नियामक सेबी ने सिक्युरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सत्यम घोटाले से जुड़े इस मामले में सेबी ने अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के कारण ऑडिट कंपनी प्राइसवाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) पर दो वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया था। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 10 सितंबर के अपने फैसले में पीडब्ल्यूसी को प्रतिबंध से छूट दे दी थी। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि यह मामला सेबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

मैं अगले 10 साल की बात करूं तो उबर के विकास में भारत, अफ्रीका और पश्चिम एशिया की अहम भूमिका रहेगी। इनका योगदान अमेरिका व यूरोप के विकसित देशों से भी ज्यादा रहने की उम्मीद है।

— दारा खोसरोशाही, सीईओ, उबर

सेंसेक्स	38,963.84	▼ 334.54
निफ्टी	11,588.35	▼ 73.50
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 38,810	▲ ₹50
चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 46,690	▲ ₹160
डॉलर	₹ 70.94	▼ ₹0.20
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 59.25	

मुश्किल ▸ दिग्गज आइटी कंपनी के शेयरों में छह साल की सबसे बड़ी गिरावट, मार्केट कैप में आई 53 हजार करोड़ रुपये की कमी

शीर्ष अफसरों पर आरोप से इन्फोसिस के शेयर धड़ाम

कंपनी के सीईओ, सीएफओ पर अनुचित व्यापार नीति का लगा है आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिग्गज आइटी कंपनी इन्फोसिस के शीर्ष अधिकारियों पर अनुचित व्यापार नीति अपनाने के आरोप लगने के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयरों में करीब 17 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के कारण कंपनी के बाजार पूंजीकरण में एक ही दिन में 53,451 करोड़ रुपये की कमी आई। गिरावट के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण घटकर 2,76,300.08 करोड़ रुपये रह गया। अप्रैल, 2013 के बाद इन्फोसिस के शेयरों में यह सबसे बड़ी गिरावट है।

इन्फोसिस के शेयरों में बड़ी गिरावट का असर पूरे शेयर बाजार पर देखने को मिला। इस दौरान बीएसई का सेंसेक्स 334.54 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं एनएसई के निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। खुद को एथिकल एंप्लाई कहने वाले कंपनी के कुछ अज्ञात कर्मचारियों (व्हिसलब्लोअर) ने इसके सीईओ सलिल पारेख और सीएफओ निलंजन रॉय पर व्यापार में मुनाफा दिखाने के लिए अनुचित नीतियां अपनाने का आरोप लगाया था। कंपनी की ओर से कहा गया है कि इस मामले की शिकायत ऑडिट कमेटी को सौंप दी गई है।

दिन के कारोबार में बीएसई में इन्फोसिस के शेयर 16.21 परसेंट की गिरावट के साथ 643.30 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर बंद हुए। एनएसई में कंपनी के शेयर 16.65 परसेंट की गिरावट के साथ 640 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बंद हुए।

डैमेज कंट्रोल में जुटी इन्फोसिस : शेयर बाजार में कंपनी के विरुद्ध बने माहौल को संभालने के लिए इन्फोसिस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कंपनी के चेयरमैन नंदन नीलेकणि ने कहा कि कंपनी की ऑडिट कमेटी स्वतंत्र रूप से आरोपों की जांच करेगी। नीलेकणि ने शेयर बाजारों को बताया कि कमेटी ने कंपनी के स्वतंत्र इंटर्नल ऑडिटर्स से सलाह-मशविरा शुरू कर दिया है। इसके साथ ही स्वतंत्र जांच के लिए शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी लॉ फर्म से संपर्क किया है।

कंपनी की ऑडिट कंपनी स्वतंत्र रूप से कर रही है आरोपों की जांच। प्रतीकात्मक फोटो

पिछले महीने मिले थे पत्र

कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने 30 सितंबर को दो शिकायती पत्र प्राप्त किए थे। इन पत्रों में अनुचित गतिविधियों की शिकायत की गई थी। इन्हें 10 अक्टूबर को कंपनी की ऑडिट कमेटी के सामने पेश किया गया और इसके अगले दिन इस बारे में कंपनी के नॉन एक्जीक्यूटिव सदस्यों को भी अवगत कराया गया। शिकायत पत्र में आरोपितों के ई-मेल और वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद होने की बात कही गई है।

क्या है आरोप?

कंपनी के अधिकारियों पर व्यापार में मुनाफा दिखाने के लिए वीजा लागत को कम करके दिखाने, 353 करोड़ रुपये के रिवर्सल को नजरंदाज करने और कुछ सौदों की जानकारी छिपाने जैसी अनुचित गतिविधियों का आरोप लगा है। बोर्ड की ओर से पत्र का जवाब नहीं मिलने पर इन कर्मचारियों ने तीन अक्टूबर को अमेरिका स्थित ऑफिस ऑफ द व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन प्रोग्राम को भी इस बारे में जानकारी दी थी।

प्रॉफिट बुकिंग से शेयर बाजारों में गिरावट

▸ पिछले छह सत्रों में आई तेजी भुनाते दिखे निवेशक

मुंबई, प्रेट्र : लगातार छह सत्रों में तेजी दर्ज करने के बाद मंगलवार को प्रमुख भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। जानकारों का कहना है कि पिछले सत्रों में आई तेजी को भुनाने के लिए निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की। दिग्गज आइटी फर्म इन्फोसिस के शेयरों में गिरावट का असर पर भी बाजार पर दिखा।

दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 334.54 अंक यानी 0.85 परसेंट की गिरावट के साथ 38,963.84 के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी ओर एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में भी 73.50 अंक यानी 0.63 परसेंट की गिरावट देखी गई। गिरावट के बाद यह 11,588.35 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में इन्फोसिस के अलावा टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 3.51 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं आइसीआइसीआइ बैंक, सन फार्मा, बजाज ऑटो, एचयूएल और एचडीएफसी के शेयरों में 3.06 परसेंट का उछाल देखा गया। आशिका स्टॉक ब्रोकिंग के इक्विटी रिसर्च हैड पारस बोथरा के मुताबिक कुछ चुनिंदा लार्ज कैप में प्रॉफिट बुकिंग और इन्फोसिस संकट से नकारात्मक संदेश फैलने के चलते शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। दूसरी ओर ट्रेड समझौते को लेकर ट्रंप के सकारात्मक बयान के बाद शंघाई, हांगकांग, टोक्यो और सियोल के बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोप के शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में मिला-जुला रुख देखा गया।

प्रतीकात्मक फोटो

योग्य स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक बनाएगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : कॉरपोरेट सेक्टर में गुड गवर्नेंस की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार एक ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के जरिये स्वतंत्र निदेशक बनने के लिए योग्य लोगों का डाटा बैंक बनाएगी। कंपनियां इस डाटा बैंक से अपने लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त कर सकेंगी। डाटा बैंक में योग्य लोगों का नाम, शिक्षा व अन्य जानकारियां रहेंगी।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आइआइसीए) इस टेस्ट का आयोजन कराएगा। इसकी शुरुआत पहली दिसंबर से होगी। मंत्रालय ने कहा है कि कुछ व्यक्तिगत श्रेणियों के मामले में टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। छूट ऐसे निदेशकों को मिलेगी, जिन्होंने निदेशक के तौर पर दस साल तक काम किया है या किसी कंपनी में महत्वपूर्ण प्रबंधकीय पद पर रहे हैं।

अधिसूचना के अनुसार, छूट पाने वाले निदेशकों के अतिरिक्त अन्य सभी को अपना नाम डाटा बैंक में शामिल किए जाने के सालभर के भीतर टेस्ट पास करना होगा। इस अवधि में वह चाहे जितनी बार टेस्ट का सामना कर सकते हैं। टेस्ट पास करके योग्यता साबित करने वालों का नाम डाटा बैंक में बना रहेगा। सालभर में टेस्ट पास नहीं करने वालों का नाम डाटा बैंक से बाहर कर दिया जाएगा।

बजाज फिनसर्व को 1,204 करोड़ का मुनाफा

तिमाही नतीजे

▸ पिछले साल के मुकाबले कंपनी के मुनाफे में 71 फीसद का उछाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : बजाज समूह की फाइनेंशियल सर्विसेज इकाइयों की होल्डिंग कंपनी बजाज फिनसर्व को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1,204 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। पिछले साल के 704 करोड़ रुपये के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 71 फीसद बढ़ा।

समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की आय 47 फीसद बढ़कर 14,224 करोड़ रुपये रही। सालभर पहले इसी अवधि में कंपनी की आय 9,698 करोड़ रुपये रही थी। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में बजाज फिनसर्व की 54.81 फीसद हिस्सेदारी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है।

एक्सिस बैंक को 112 करोड़ का घाटा : एक्सिस बैंक को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 112.08 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी को 789.61 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। बैंक ने बताया कि कॉरपोरेट टैक्स दरों में बदलाव के कारण बीती तिमाही में उसे 2,138 करोड़ रुपये कर के रूप में चुकाने पड़े थे। इसे हटाकर कंपनी को 2,026 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की आय 15,959.37 करोड़ रुपये बढ़कर 19,333.57 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। कंपनी का ग्रॉस एनपीए भी सालभर पहले के 5.96 फीसद से घटकर 5.03 फीसद पर आ गया है।

कोटक महिंद्रा बैंक के मुनाफे में तेज उछाल : बीती तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक का शुद्ध मुनाफा 38 परसेंट उछाल के साथ 2,407.25 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। पिछले वर्ष की इसी अवधि में बैंक का मुनाफा 1,747.37 करोड़ रुपये रहा था। समीक्षाधीन अवधि में बैंक की कुल आय 12,542.99 करोड़ रुपये रही। पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये 10,829.08 करोड़ रुपये रही थी। हालांकि इस अवधि में कंपनी का एनपीए सकल अग्रिम का 2.17 परसेंट रहा, जो पिछले वर्ष 1.91 परसेंट से अधिक है।

वेल्सपन इंडिया का मुनाफा बढ़ा

टेक्सटाइल कंपनी वेल्सपन इंडिया के मुनाफे में 66.5 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि के 121.69 करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार कंपनी ने 202.6 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया। समीक्षाधीन अवधि में कंपनी का कुल राजस्व भी 1,779.94 रुपये से बढ़कर 1,824.92 करोड़ रुपये रहा।

जीएसके फार्मा को 503 करोड़ का मुनाफा

जुलाई–सितंबर की तिमाही के दौरान दवा निर्माता कंपनी जीएसके फार्मा के मुनाफे में आठ परसेंट का इजाफा हुआ। समीक्षाधीन अवधि में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 502.75 करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष की इसी अवधि में कंपनी को 100.83 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी का कुल राजस्व 816.31 करोड़ रुपये से बढ़कर 882.02 करोड़ रुपये रहा।

दिग्गजों के बीच हुई भारत को पांच लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने पर चर्चा

नई दिल्ली में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और चर्चा के लिए दुनियाभर के दिग्गज नीति निर्माता, उद्यमी और विचारक जुटे थे। मौका था जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल काउंसिल के सदस्यों से पीएम की मुलाकात का। इस अंतरराष्ट्रीय काउंसिल में टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस और हेनरी किसिंजर जैसी हस्तियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इन हस्तियों से भारत को 2024 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर चर्चा की और सरकार के प्रयासों से अवगत कराया। एएनआइ

न्यूज गैलरी

टाटा स्टील के वीपी अरुण मिश्रा का इस्तीफा

जमशेदपुर : टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट (रॉ मेटेरियल) अरुण मिश्रा ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 18 नवंबर को पदमुक्त होंगे। कंपनी की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया कि टाटा समूह के बाहर बेहतर अवसर मिलने के कारण अरुण मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन के प्रिंसिपल एक्जीक्यूटिव ऑफिसर (पीईओ) डीबी सुंदर रमण को कंपनी का नया वीपी (रॉ मेटेरियल) बनाया गया है। साथ ही कलिंगनगर (ऑपरेशन) के महाप्रबंधक चैतन्य भानु को एमडी का पीईओ बनाया गया है। (जासं)

रुपया 20 पैसे की मजबूती के साथ दो सप्ताह की ऊंचाई पर

मुंबई : मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में 20 पैसे यानी 0.28 परसेंट का सुधार हुआ। इस दौरान एक डॉलर की कीमत 70.94 रुपये रही। यह पिछले दो सप्ताह का ऊपरी स्तर है। जानकारों के मुताबिक अगले महीने अमेरिका–चीन के बीच आंशिक व्यापार समझौते की उम्मीदों के चलते रुपये को बल मिला। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान के बाद निवेशकों में सकारात्मक संदेश गया। (प्रेट्र)

रूस में तेल, गैस की शिपिंग के प्रमुख केंद्र वेजदा पहुंचे प्रधान

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रूस के सुदूरपूर्व स्थित वेजदा शिपयार्ड का दौरा किया। पीआइबी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रूस व जापान के पांच दिवसीय दौरे के प्रथम चरण में तेल व गैस शिपिंग के प्रमुख रूसी केंद्र वेजदा पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सितंबर के रूस दौरे के बाद प्रधान इन दिनों द्विपक्षीय संबंधों में आई मजबूती को दिशा देने में जुटे हैं। इस क्रम में उन्होंने रूस के सुदूरपूर्व स्थित वेजदा शिपयार्ड का दौरा किया। यह दुनिया के प्रमुख कारोबारी शिपयार्ड में से एक है। रोजनेफ्ट के सीईओ की मौजूदगी में प्रधान ने वहां तेल एवं गैस क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली शिपिंग तकनीक में आ रहे बदलावों की जानकारी ली। वेजदा शिपयार्ड भारत और रूस के मध्य समुद्र मार्ग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दौरे के दौरान प्रधान ने भारत-रूस के संयुक्त तेल उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा भी की। प्रधान ने रूस के जिस सुदूरपूर्वी क्षेत्र से अपने दौरे की शुरुआत की, वह खनिज संपदा एवं तेल व गैस परियोजनाओं के लिए जाना जाता है। भारत न सिर्फ इस क्षेत्र में निवेश कर रहा है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का केंद्र भी बना है।

वॉलमार्ट ने पीएम को लिखा पत्र, कैट ने कहा – दबाव बनाने की तरकीब

नई दिल्ली, प्रेट्र : वॉलमार्ट के सीईओ डॉ मैकमिलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर व्यापार संबंधी सुविधाओं की मांग की है। उधर भारतीय ट्रेड संगठन कैट ने इसे दबाव बनाने की रणनीति करार दिया है और प्रधानमंत्री से वॉलमार्ट को किसी तरह की विशेष सुविधा नहीं दिए जाने का आग्रह किया है।

मैकमिलन ने अपने पत्र में कहा है कि भारत में स्थिर और खुला व्यापारिक माहौल बनाया जाए, जिससे निवेश सुरक्षित हो सके। विश्व के सबसे बड़े रिटेलर वॉलमार्ट के सीईओ ने भारत में स्टोर खोलने के लिए जरूरी मंजूरियों की संख्या घटाकर इसमें लगने वाला समय कम करने की अपील भी की। गौरतलब है कि वॉलमार्ट ने भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में 16 अरब डॉलर का निवेश किया है। सरकार द्वारा एफडीआइ नियमों में परिवर्तन के बाद कंपनी अपने ई-कॉमर्स बिजनेस में कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है।

वॉलमार्ट के जवाब में पीएम को लिखे पत्र में कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि वॉलमार्ट सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश में है। वॉलमार्ट की नजर भारत के 45 लाख करोड़ रुपये के रिटेल मार्केट पर है। उन्होंने कंपनी पर अनुचित तरीकों से भारत में एकाधिकार जमाने और इकोनॉमी को सीधे नियंत्रित करने की कोशिश का आरोप लगाया।

टोल प्लाजा, वे–साइड अमेनिटीज में भी होंगे जल संरक्षण के उपाय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सड़क मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ सभी टोल प्लाजा, रोड साइड अमेनिटीज तथा मंत्रालय से संबंधित सभी पीएसयू और विभागीय दफ्तरों में वाटर हार्वेस्टिंग प्रणालियों के अलावा पानी बचाने वाले नल लगाने को कहा है।

अपने नवीनतम पत्र में मंत्रालय ने अधिकारियों को जल शक्ति मंत्रालय के अनुरोध की याद दिलाते हुए कहा है कि पानी अत्यंत मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है और जल की एक-एक बूंद कीमती है। मंत्रालय ने अपने सभी विभागों तथा पीएसयू को टॉयलेट के नलों में 'एयरेटर' लगाने की सलाह भी दी है। यह बाजार में आसानी से उपलब्ध एक डिवाइस है जिसे नलों में लगाकर पानी की खपत में 80 फीसद तक की कमी की जा सकती है। इसके अलावा मंत्रालय ने सभी परिसरों में साधारण कुओं के अलावा बोरवेल तथा रिचार्ज ट्रेंचेज जैसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं निर्मित करने की सलाह भी दी है।

नीति आयोग के मुताबिक देश में 60 करोड़ लोग किसी न किसी स्तर पर पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। हर साल तकरीबन दो लाख लोगों की मौत पानी की कमी या असुरक्षित पानी के कारण हो जाती है। 2030 तक देश में पानी की मांग दो गुना हो जाने के आसार हैं। चूंकि सड़कें वर्षा जल के संग्रहण का सबसे बढ़िया माध्यम हैं, लिहाजा सरकार ने 2013 से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के साथ वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं के निर्माण को अनिवार्य कर दिया है। अनुमान है कि इन संरचनाओं के माध्यम से भूमिगत जल स्तर में सालाना 500 अरब घन मीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है।

प्रतीकात्मक फोटो

▸ सड़क मंत्रालय ने अपने दफ्तरों में भी पानी बचाने वाले नल लगाने को कहा

▸ सड़कों पर वाटर हार्वेस्टिंग से भूजल स्तर में 500 अरब घनमीटर की वृद्धि संभव

सरकार जल्द बदलेगी एमएसएमई की परिभाषा

▸ सेक्टर को एक ही नाम से परिभाषित करने पर होगा विचार, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस परिदृश्य में होगा सुधार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जल्द ही माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सेक्टर अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ रोजगार पैदा करेगा। इससे पहले अगस्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार एमएसएमई में सुधार करके इसे एक ही नाम से परिभाषित करने पर विचार करेगी।

एमएसएमई की परिभाषा में सुधार के जरिये इस सेक्टर में टैक्स और निवेश जैसे मुद्दों को साधने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एमएसएमई एक्ट में सुधार की जरूरत पड़ेगी। इस कवायद से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस परिदृश्य में और सुधार होगा। पिछले वर्ष फरवरी में इस एक्ट में सुधार किया गया था। गडकरी ने कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था का ह्रदय है। यह देश के जीडीपी में 29 परसेंट का योगदान करता है। इसके साथ ही इस सेक्टर ने अब तक 11 करोड़ रोजगार पैदा किए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही 'सोलर वस्त्र स्कीम' के तहत 13 कलस्टर को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है। इसमें से प्रत्येक क्लस्टर तीन हजार से अधिक नौकरियां सृजित करने की क्षमता रखता है। सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है, क्योंकि यह रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संभाल रहे गडकरी ने बताया कि नई दिल्ली से मुंबई के बीच 12 लेन के कंक्रीट एक्सप्रेस हाइवे पर भी काम शुरू हो चुका है। उन्होंने हाइवे पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाने की बात भी कही। यह संग्रहालय भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की मार्केटिंग में और पर्यटन को प्रोत्साहित करने में मददगार होगा। गडकरी ने बताया कि सरकार 400 रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ का प्रयोग अनिवार्य कर रही है। हवाई अड्डों पर भी इस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी है। सिंगल यूज प्लास्टिक के निपटने में यह कारगर पहल होगी।

अभियान

कृषि क्षेत्र में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग की सख्त जरूरत

कृषि मंत्री ने जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाने पर दिया जोर, मिट्टी में सूक्ष्म तत्वों की कमी, संतुलन बनाए रखना जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कृषि क्षेत्र में उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से जमीन की उर्वर क्षमता को बनाए रखने और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर देना होगा। तोमर मंगलवार को यहां उर्वरकों के उचित प्रयोग पर जागरूकता अभियान में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 50 फीसद से घटकर 14 फीसद पर आ गई है। यह अच्छी बात नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में खेती की हिस्सेदारी फिर से 50 फीसद तक होनी चाहिए। कृषि मंत्री तोमर के साथ अभियान की शुरुआत करने वालों में केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी थे। तोमर ने कहा कि खरीफ सीजन की फसलें तैयार हैं और रबी की बोआई होनी है, जिसमें उर्वरकों का संतुलित व उचित प्रयोग होना जरूरी है। इसी के भरोसे फसलों की उत्पादकता और पैदावार बढ़ सकती है। खाद के संतुलित प्रयोग से ही जमीन की गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सकता है और किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

2014 में केंद्र में पहली बार सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता सूची में किसानों की खुशहाली सबसे ऊपर रही। उसके बाद से खेती को लाभ का कारोबार बनाने पर सरकार का पूरा जोर है। इसके साथ ही सरकार का ध्यान जमीन की सेहत को संरक्षित करने पर ज्यादा था, जिसके चलते देश के आठ करोड़ से अधिक किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड बांट दिया गया है। जीडीपी में कृषि क्षेत्र की 14 फीसद की हिस्सेदारी पर चिंता जताते हुए तोमर ने कहा यह नाकाफी है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने किसानों से सवाल करते हुए कहा, 'क्या हम इसे बढ़ाकर 50 फीसद कर सकते हैं?'

कृषि मंत्री ने किसानों से कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से खेतों की उर्वरा क्षमता बिगड़ेगी। तोमर ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर डेढ़ गुना करने और पीएम-किसान जैसी योजना में हर किसान को छह हजार रुपये सालाना वित्तीय मदद जैसे कदमों का भी जिक्र किया। इस मौके पर केंद्रीय उर्वरक व रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि इस समय मिट्टी की सेहत को जांचने और उसे संरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने विभिन्न उर्वरकों पर दी जा रही सब्सिडी का जिक्र किया। उर्वरक सचिव छबिलेंद्र राउल ने कहा कि सरकार सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों को देने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड सेरेमनी के दौरान आयोजित प्रदर्शनी का भी मुआयना भी किया।

नई दिल्ली में प्रदर्शनी का मुआयना करते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। एएनआइ

खेत की सेहत के लिए भी घातक है पराली जलाना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पराली जलाने से केवल मानव स्वास्थ्य पर ही बुरा असर नहीं पड़ता बल्कि खेत की सेहत के लिए भी यह घातक है। कृषि मंत्रालय के एक समारोह में देशभर से आए किसानों से उन्होंने पराली न जलाने की अपील की। तोमर ने कहा कि पराली के धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ जाता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली जलाने से बचने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनका लाभ उठाकर किसान फायदा कमा सकते हैं। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में धान की पराली जलाने से इस मौसम में धुएं का बादल छा जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। पर्यावरण मंत्रालय के साथ कृषि मंत्रालय ने व्यापक रूप से कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनसे किसान पराली जलाने से बच सकते हैं। खेतों की मिट्टी में केंचुआ समेत कई तरह के जीव रहते हैं, जो मिट्टी की उर्वर क्षमता और गुणवत्ता को लगातार बढ़ाते हैं। पराली जलाने के कारण बनी गरमी से ऐसे जीव मर मर जाते हैं।

ह्वाइट हाउस में गुरुवार को दिवाली मनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को ह्वाइट हाउस में दिवाली का जश्न मनाएंगे। वर्ष 2016 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ट्रंप तीसरी बार इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, वह दीया जलाकर जश्न की शुरुआत करेंगे। ह्वाइट हाउस में दिवाली मनाने की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2009 में की थी।

वर्ष 2017 में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के प्रमुख लोगों और सरकार में शामिल अधिकारियों के साथ दिवाली मनाई थी। पिछले साल के आयोजन में ट्रंप ने तत्कालीन भारतीय राजदूत नवतेज सिंह सरना को भी आमंत्रित किया था। इस आयोजन के दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती, भारत-अमेरिका के मजबूत संबंधों और अमेरिका के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान पर भी चर्चा की थी।

ह्वाइट हाउस के बाहर भी दिख रहा उत्साह : दिवाली को लेकर सिर्फ ह्वाइट हाउस ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में गजब का उत्साह दिख रहा है। कई नेताओं और संगठनों की ओर से दिवाली पार्टी आयोजित की जा रही है। टेक्सास के गर्वनर ग्रेग एबॉट ने बीते शनिवार को भारतीय-अमेरिकी समुदाय के साथ दिवाली मनाई। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, 'हमने बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश की जीत का जश्न मनाया। राजभवन में चारों तरफ जगमग दीप जलाए और पीएम मोदी की टेक्सास यात्रा पर चर्चा भी की।'

राष्ट्रपति बनने के बाद से तीसरी बार करेंगे उत्सव का आयोजन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रायटर

पंजाबियों के दम पर ही ट्रूडो फिर बनेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री

जेएनएन, नई दिल्ली

कनाडा के आम चुनाव में जीते 18 पंजाबी, इनमें से 13 ट्रूडो की पार्टी से

ट्रूडो को नहीं मिला बहुमत, जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी से समर्थन की उम्मीद

कनाडा के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने जीत दर्ज की है। वह एक बार फिर पंजाबियों के दम पर सरकार बना पाएंगे। कनाडा के आम चुनाव में जीते 18 पंजाबियों में से ट्रूडो की पार्टी से सबसे ज्यादा 13 पंजाबियों ने जीत दर्ज की। वहीं, कंजरवेटिव पार्टी से चार और एनडीपी से एक पंजाबी इस बार सांसद चुना गया। ट्रूडो की पार्टी इस चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। ट्रूडो को दोबारा सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। 2015 के आम चुनाव में लिबरल पार्टी ने 184 सीटों पर जीत दज की थी, लेकिन इस बार वह 157 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है।

कनाडा के चुनाव आयोग के अनुसार 338 सदस्यीय संसद के लिए हुए चुनाव में लिबरल पार्टी अब तक 156 सीटें जीत चुकी है या बढ़त बनाए हुए है। जबकि ट्रूडो के मुख्य प्रतिद्वंद्वी एंड्रयू शीर की कंजरवेटिव पार्टी के खाते में 122 सीटें आई हैं। ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी 170 के आंकड़े को पाने के लिए ट्रूडो को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) का सहारा लेना पड़ सकता है। ट्रूडो ने मंगलवार सुबह मांट्रियल में अपने समर्थकों से कहा, 'मेरे दोस्तो आपने कर दिखाया। बधाई।'

एनडीपी कर सकती है समर्थन : एनडीपी को इस बार 24 सीटें मिली हैं। पूर्व वित्त मंत्री जॉन मेनली ने कहा, 'मेरे विचार से एनडीपी लिबरल सरकार का समर्थन कर सकती है।'

मांट्रियल में मंगलवार को आम चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत के बाद समर्थकों का अभिवादन करते पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तथा उनकी पत्नी सोफी। एपी

जीतने वाले पंजाबी उम्मीदवार

लिबरल पार्टी
- अंजू ढिल्लों, डोरवाल लाचेन लासेल सीट
- गगन सिकंद, मिसिसॉगा स्ट्रीट्सविले सीट
- हरजीत सिंह सज्जन, वैंकूवर दक्षिण सीट
- कमल खैहरा, ब्रैम्पटन पश्चिम सीट
- नवदीप बैंस, मिसिसॉगा माल्टन सीट
- राज सैनी, किचनरे केंद्रीय सीट
- रामेश्वर सिंह संघा, ब्रैम्पटन केंद्रीय सीट
- रणदीप सराय, सरी केंद्रीय सीट
- रूबी सहोता, ब्रैम्पटन उत्तर सीट
- मनिंदर सिद्धू, ब्रैम्पटन पूर्व सीट
- सोनिया सिद्धू, ब्रैम्पटन दक्षिण सीट
- सुख धालीवाल, सरी न्यूटन सीट
- बरदीश चग्घर, वाटरलू ओन्टारियो सीट

कंजरवेटिव पार्टी
- बॉब सरोया, मार्खम-यूनियनविले सीट
- जगदीप साहो, कैलगरी स्काईव्यू सीट
- जसराज सिंह, कैलगरी फारेस्ट लॉन सीट
- टिम उप्पल, एडमोंटन मिलवुड्स सीट

एनडीपी पार्टी
- जगमीत सिंह, बरनबी दक्षिण सीट

जगमीत सिंह की होगी अहम भूमिका

एनडीपी के नेता जगमीत सिंह। एएफपी

एनडीपी के नेता जगमीत सिंह हैं। वह कनाडा की किसी संघीय पार्टी के नेता बनने वाले पहले गैर श्वेत हैं। इस चुनाव में वह किंगमेकर बनकर उभरे हैं। माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन में उनकी पार्टी की भूमिका अहम हो सकती है। 40 वर्षीय जगमीत पेशे से वकील हैं। वह 2017 में एनडीपी के नेता चुने गए थे। उनके माता-पिता पंजाब से आकर कनाडा में बस गए थे।

न्यूज गैलरी

थाइलैंड के राजा ने बॉडीगार्ड से वापस लीं सभी उपाधियां

बैंकॉक : थाइलैंड के राजा महा वजिरालोंगकोर्न ने अपनी बॉडीगार्ड सिनीनात से सभी सम्मान और उपाधियां वापस ले ली हैं। शाही राजमहल ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि 34 वर्षीय सिनीनात महारानी सुथिदा से बराबरी की कोशिश कर रही थीं। सिनीनात को इस साल राजा के 67वें जन्मदिन पर विशेष शाही उपाधि देकर सम्मानित किया गया था। ताजा शाही आदेश में कहा गया है कि सिनीनात ना तो शाही परंपरा समझती थी और ना ही राजा को सम्मान देती थीं। वह थाई महारानी सुथिदा की जगह लेने की फिराक में थी। महारानी सुथिदा भी शाही अंगरक्षकों की उप प्रमुख रह चुकी हैं। इसी साल मई में वह राजा की चौथी पत्नी बनी थीं। (रायटर)

श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी

कोलंबो : श्रीलंका में 16 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रवाद प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। इस साल 21 अप्रैल को हुए आत्मघाती आतंकी हमलों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी चुनाव प्रचार में हावी है। इन दोनों मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस चुनाव में भले ही रिकॉर्ड 35 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला श्रीलंका पोदुजना पेरामुना (एसएलपीपी) के उम्मीदवार व पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के भाई गोतबाया राजपक्षे और यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के उपाध्यक्ष सजित प्रेमदासा के बीच होने की उम्मीद है। प्रेमदासा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (एनडीएफ) के उम्मीदवार हैं। राष्ट्रपति मैत्रिपाल सिरिसेन ने कहा है कि वह किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन उनकी पार्टी गोतबाया राजपक्षे के पक्ष में खड़ी है। श्रीलंकाई तमिलों की प्रमुख पार्टी तमिल नेशनल अलायंस (टीएनए) ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। (आइएएनएस)

धर्म के आधार पर लड़ाई से खतरनाक कुछ भी नहीं : राइस

नई दिल्ली : अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री कोंडोलिजा राइस ने कहा कि धर्म के आधार पर लड़ाई से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता। लोकतंत्र में सरकारों को धार्मिक भावना से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। यहां अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच को संबोधित करते हुए राइस ने दुनिया भर में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दुनियाभर में इनकी सुरक्षा एक समस्या बनती जा रही है। अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो कुछ खास धर्म को मानने वाले लोगों के खिलाफ घृणा अपराध बढ़ने से चिंतित हैं। राइस ने एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। (प्रेट

कोर्ट लखपत जेल से अपना आतंकी संगठन चला रहा है हाफिज सईद

सामने आया सच ▶ आतंकी ने अपने समर्थक और पुलिस के बीच विवाद में की मध्यस्थता

17 जुलाई से लाहौर की जेल में है मुंबई हमलों का मास्टर माइंड

लाहौर, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र से घोषित आतंकी और मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद लाहौर की कोट लखपत जेल से ही अपने प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा का संचालन कर रहा है। हाल ही में प्रतिबंधित आतंकी ने पुलिस और संदिग्ध एटीएम चोर के परिवार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। एटीएम चोर की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। मानसिक रूप से बीमार सलाहुद्दीन अयूबी की पिछले महीने पुलिस हिरासत में मौत हो गई। एटीएम से पैसे की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रताड़ना ने उसकी मौत हुई। उसकी मौत के बाद पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया।

आतंकवाद को आर्थिक मदद के आरोप में 17 जुलाई को गिरफ्तार सईद अत्यंत सुरक्षित समझी जा रही जेल में बंद है। पिछले सप्ताह उसने सलाहुद्दीन के परिवारवालों से मुलाकात की और अल्लाह के नाम पर हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों को माफ करने के लिए समझाया।

हाफिज सईद। फाइल

लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक को अधिकारियों ने गुजरांवाला में पीड़ित परिवार के गांव की जर्जर सड़क की मरम्मत कराने और गैस आपूर्ति सुनिश्चित कराने का वादा किया है। विवाद खत्म करने के लिए होने वाले इस काम पर 80 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। परिवार के कुछ लोग सईद के समर्थक हैं इसलिए पुलिस ने जेल में उनकी मुलाकात की व्यवस्था की। सईद ने परिवार के सामने तीन विकल्प रखे। आरोपितों से खून की कीमत लेने या अल्लाह के नाम पर उन्हें माफ करने या उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करने का विकल्प सुझाया। परिवार ने माफी का रास्ता चुना। सलाहुद्दीन के पिता ने इस बात की पुष्टि की।

मुजफ्फराबाद में आजादी समर्थकों पर लाठीचार्ज, दो लोगों की मौत

मुजफ्फराबाद, एएनआइ : गुलाम कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में मंगलवार को शांतिपूर्ण ढंग से रैली कर रहे आजादी समर्थकों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। इसमें दो नागरिकों की जहां मौत हो गई वहीं 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पिछले साल 22 अक्टूबर को ही मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली, गिलगित, रावलपिंडी और अन्य क्षेत्रों में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे।

दरअसल, 22 अक्टूबर 1947 को ही पाकिस्तान के सैनिकों ने जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण करके इसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भारत इसे गुलाम कश्मीर कहता है। इस हिस्से के लोग इस दिन को काला दिवस के तौर पर मनाते हैं और पाकिस्तान से मुक्ति के लिए आवाज उठाते हैं। मंगलवार को पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा किए गए आक्रमण की 72वीं वर्षगांठ पर ऑल इंडिपेंडेंट पार्टीज अलायंस (एआइपीए) के बैनर तले कई राजनीतिक दलों ने मुजफ्फराबाद में आजादी समर्थक रैली का आह्वान किया था। अपना विरोध दर्ज कराने के लिए लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे।

पुलिस ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के बजाय भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आसूं गैस के गोले का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन से पहले एक व्यक्ति ने कहा कि हमने काला दिवस के मौके पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है।

सेना प्रमुख के खिलाफ बोलने पर शरीफ के दामाद गिरफ्तार

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन (रिटायर्ड) मुहम्मद सफदर को सेना प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ बोलना भारी पड़ गया है। उन्हें सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनके तहत उन्हें उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

लाहौर पुलिस के अनुसार, सफदर को शहर के रावी टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने गत 13 अक्टूबर को अदालत में पेशी के दौरान सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि इमरान सरकार सिर्फ कार्यकाल बढ़ाने और प्रमोशन सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। सेना और न्याय व्यवस्था के खिलाफ भड़काने वाले बयान को लेकर उनके खिलाफ लाहौर के सदर रोड थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। इमरान सरकार ने गत अगस्त में बाजवा का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया था। विपक्षी दल यह आरोप लगाते रहे हैं कि सेना के समर्थन से ही इमरान सरकार बनी।

पीएमएल-एन ने की निंदा : सफदर की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा, 'इमरान खान की फासीवादी सरकार शरीफ परिवार से बदला ले रही है। घृणास्पद बयान के लिए अगर किसी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो वह व्यक्ति इमरान खान हैं।'

मुहम्मद सफदर ने पाक सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भी की थी टिप्पणी

मुहम्मद सफदर। फाइल

पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत बिगड़ी

भ्रष्टाचार से जुड़े अल-अजीजिया स्टील मिल मामले में सात साल की सजा काट रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें सोमवार देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। 69 वर्षीय शरीफ के निजी चिकित्सक डॉ अदनान खान ने ट्वीट के जरिये बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री के प्लेटलेट्स भी घट गए हैं।

शरीफ की बेटी भी हिरासत में : सफदर की पत्नी और नवाज शरीफ की बेटी मरयम भी इस समय हिरासत में हैं। वह मनी लांड्रिंग मामले में पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में हैं।

फिर सरकार बनाने में विफल रहे नेतन्याहू अब विपक्षी नेता गेंट्स को मिलेगा मौका

यरुशलम, प्रेट्र : इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी नई सरकार बनाने में विफल हो गए हैं। इससे विपक्षी नेता बेनी गेंट्स के लिए देश का अगला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुल गया है। राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन ने कहा है कि वह अब पूर्व सेना प्रमुख और ब्लू एंड ह्वाइट पार्टी के नेता गेंट्ज को सरकार बनाने का मौका देंगे।

गत 17 सितंबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को सरकार बनाने का मौका दिया था। इसके लिए उन्हें 28 दिनों की मोहलत मिली थी। नेतन्याहू ने साझा सरकार बनाने के लिए गेंट्स को प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन बात नहीं बनी। साझा सरकार के लिए खुद राष्ट्रपति ने भी प्रयास किए थे।

उन्होंने नेतन्याहू और गेंट्स की अपने दफ्तर में बैठक करवाई थी। नेतन्याहू ने 28 दिन की अवधि समाप्त होने से दो दिन पहले सोमवार को एक वीडियो संदेश में कहा, 'मैंने साझा सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन गेंट्स को वार्ता टेबल पर लाने और दोबारा चुनाव को टालने की मेरी कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि ब्लू एंड ह्वाइट पार्टी के नेता ने इन्कार कर दिया।'

इसके जवाब में 60 वर्षीय गेंट्स ने ट्विटर पर एलान किया, 'यह ब्लू एंड ह्वाइट पार्टी का वक्त है।' अब गेंट्स को भी गठबंधन सरकार बनाने के प्रयास करने के लिए 28 दिन मिलेंगे। अगर वह भी इस अवधि में सरकार बनाने में विफल हुए तो इजरायल में एक साल में तीसरी बार चुनाव कराने की नौबत आ सकती है।

गेंट्स को गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास करने के लिए मिलेंगे 28 दिन

17 सितंबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी दल को नहीं मिला था बहुमत

ब्लू एंड ह्वाइट पार्टी के नेता बेनी गेंट्ज। एएफपी

पांच महीने में दूसरी बार हुए चुनाव

इजरायल में गत 17 सितंबर को पांच माह में दूसरी बार संसदीय चुनाव हुए थे। लेकिन 120 सदस्यीय संसद में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 32 और ब्लू एंड ह्वाइट पार्टी को 33 सीटें मिली थीं। बाकी सीटों पर छोटी पार्टियों ने जीत दर्ज की थी। इजरायल में गत अप्रैल में भी संसदीय चुनाव हुए थे। उस समय भी किसी दल को बहुमत नहीं मिला था।

समय पर ब्रेक्जिट डील मंजूर न हुई तो कराएंगे चुनाव : जॉनसन

लंदन, एएफपी : ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को सांसदों को धमकी दी कि अगर उन्होंने समय-सारणी के मुताबिक ब्रेक्जिट डील को पारित नहीं किया तो वह विधेयक पूरी तरह वापस ले लेंगे और चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। जॉनसन 31 अक्टूबर की समयसीमा के भीतर समझौते के साथ यूरोपीय यूनियन (ईयू) से अलग होने की डील पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं।

सोमवार रात ईयू विदड्राल एग्रीमेंट बिल प्रकाशित होने के बाद मंगलवार को जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमंस में बहस की शुरुआत की। उनकी योजना सप्ताह के अंत तक इस पर मतदान कराने की है। हालांकि विपक्षी सांसदों ने उन पर 110 पेज के इस विधेयक को बिना उचित स्क्रूटनी के पारित कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

इस पर जॉनसन ने धमकी दी कि अगर विधेयक पारित करने की उनकी समय-सारणी को खारिज किया गया तो वह विधेयक को पूरी तरह वापस ले लेंगे और आम चुनाव कराने की मांग करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं इसके लिए किसी भी कीमत पर और महीनों की मोहलत नहीं दूंगा। अगर संसद ब्रेक्जिट की अनुमति

बोरिस जॉनसन। फाइल

विपक्ष ने लगाया बिना उचित स्क्रूटनी पारित कराने की कोशिश का आरोप

बिल पर इस सप्ताह के अंत तक मतदान कराना चाहते हैं प्रधानमंत्री

नहीं देती है और हर चीज को जनवरी या और अधिक समय तक विलंबित करने का फैसला करती है तो किसी भी सूरत में सरकार इसके साथ नहीं बनी रह सकती। और बेहद खेद के साथ मैं कहूंगा कि विधेयक वापस लेना होगा और हमें आम चुनावों की ओर बढ़ना होगा और मैं उन चुनावों की वकालत करूंगा। इसलिए ब्रेक्जिट को सफल बनाएं।'

कुर्दों ने सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर फेंके सड़े फल

दमिश्क, आइएएनएस : सीरिया से लौट रहे अमेरिकी सैनिकों को स्थानीय कुर्द नागरिकों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। सीरिया के उत्तरी शहर कामिशली से सोमवार को पड़ोसी मुल्क इराक की ओर रवाना हुए पांच सौ अमेरिकी सैनिकों के काफिले पर स्थानीय कुर्दों ने सड़े-गले फल फेंके। यह इलाका सीरिया, तुर्की और इराक की सीमा से सटा है।

अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने हाल में कहा था कि सीरिया में तैनात एक हजार अमेरिकी सैनिकों को इराक भेजा जाएगा, जहां वे आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा की थी। सीरिया में आइएस आतंकियों के खिलाफ निर्णायक जंग में कुर्द लड़ाकों ने अमेरिकी सेना की मदद की थी। सीरिया से अपने सैनिक हटाने के अमेरिका के एलान के तुरंत बाद पड़ोसी मुल्क तुर्की ने कुर्दों के नियंत्रण वाले इलाके में सैन्य अभियान शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ दिन पहले हुए समझौते के बाद तुर्की ने अभियान बंद कर दिया था।

करतूत

आइफोन व एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को हैक करने लिए बनाई हैकर्स की टीम, गूगल के शोधकर्ताओं ने उइगरों पर हो रहे साइबर हमले को किया उजागर

विदेश में भी उइगर मुस्लिमों को चीन बना रहा निशाना

न्यूयॉर्क टाइम्स से

सैन फ्रांसिस्को : चीन के उत्तर-पूर्वी शिनजियांग प्रांत में रह रहे अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिमों पर सख्ती के लिए वहां की कम्युनिस्ट सरकार हमेशा ही तरह-तरह के हथकंडे अपनाती रहती है। अब विदेश में रहे उइगरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ और खुफिया अधिकारियों का कहना है कि उइगरों की कड़ी निगरानी के लिए सरकार हैकर्स की मदद ले रही है। इसके लिए भारी मात्रा में धन व संसाधन खर्च किए गए हैं।

पिछले तीन साल में सरकार समर्थित हैकर्स की टीम के काम के तरीके में भी काफी बदलाव आया है। उन्होंने नई तकनीक विकसित की हैं, जिसके जरिये वह आइफोन और एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को भी हैक कर रहे हैं। गूगल से जुड़े शोधकर्ता ने आइफोन पर हुए हमले का पता लगाया है। उनके मुताबिक हमले का मुख्य निशाना चीन के साथ-साथ अन्य देशों में रह रहे उइगर मुसलमान ही बन रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हैकिंग के लिए आइफोन की जिस खामी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी कीमत काले बाजार में कई करोड़ में होगी। वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज से जुड़ी पूर्व अधिकारी जेम्स लुईस ने कहा, 'चीन पहले अपने देश के नागरिकों के खिलाफ सारी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वह उनसे ही डरा हुआ है। अब वह विदेशियों की निगरानी के लिए हथकंडे अपना रहा है।' बता दें कि शिनजियांग प्रांत में हजारों उइगरों को हिरासत केंद्रों में रखा गया है। कई रिपोर्ट में उनके मानवाधिकार उल्लंघन की बात भी सामने आ चुकी है। हालांकि, चीन इससे इन्कार करता है। उसके अनुसार, वह हिरासती केंद्र नहीं, बल्कि प्रशिक्षण कैंप हैं, जो कट्टरपंथ पर काबू पाने के लिए जरूरी हैं।

चीन में उइगर मुसलमानों के हालात बदतर हैं। चीन उन्हें हमेशा निगरानी में रखता है। फाइल

रूसी इंस्टाग्राम अकाउंट ने अमेरिकी मतदाताओं को निशाना बनाया

लंदन, रायटर : रूस से संचालित इंस्टाग्राम अकाउंट ने राजनीतिक संदेशों के साथ अमेरिकियों को निशाना बनाया है। यह काम अगले साल अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव से पहले किया गया है। ऐसा करते हुए वर्जीनिया और फ्लोरिडा सहित अमेरिकी प्रांतों के स्थानीय लोगों की तरह दर्शाया है। यह दावा फेसबुक ने किया है।

फेसबुक ने कहा है कि उसने सोमवार को ईरान से ऑपरेट होने वाले तीन अलग-अलग नेटवर्क के साथ ही अकाउंट निलंबित कर दिए। रूसी नेटवर्क ने रूस की इंटरनेट रिसर्च एजेंसी (आइआरए) के कुछ लिंक प्रदर्शित किए हैं।

फेसबुक साइबर सुरक्षा नीति के प्रमुख नाथनिएल ग्लेचेर ने कहा, 'हमने पाया है कि इस ऑपरेशन में मुख्य रूप से अमेरिकी बहस को निशाना बनाया गया है।' उन्होंने कहा कि वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि उनका उद्देश्य क्या है। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस, ईरान और अन्य देश अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।

जापान के सम्राट नारुहितो का हुआ राज्याभिषेक

टोक्यो, रायटर : जापान के सम्राट नारुहितो का मंगलवार को वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार राज्याभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स समेत 180 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राज्याभिषेक के बाद नारुहितो (59) ने राजप्रमुख के तौर पर अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने की शपथ ली। वह द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पैदा हुए देश के पहले सम्राट हैं।

बीते एक मई को ही एक कार्यक्रम में नारुहितो को सम्राट और उनकी पत्नी मासाको को साम्राज्ञी बनाए जाने की घोषणा कर दी गई थी। पूर्व सम्राट व अपने पिता अकिहितो के पद त्यागने के बाद वह देश के 126 वें सम्राट बने। मंगलवार को हुए भव्य कार्यक्रम 'सोक्यु नो रेइ' के जरिये नारुहितो को आधिकारिक तौर पर पूरे विश्व के सामने जापान का राजप्रमुख घोषित किया गया। कार्यक्रम में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबी भी मौजूद थे और उन्होंने नए सम्राट

राज्याभिषेक के दौरान सम्राट नारुहितो के समक्ष निष्ठा व्यक्त करते प्रधानमंत्री शिंजो एबी। एपी

को बधाई दी। राज्याभिषेक के मौके पर सरकार ने ट्रैफिक उल्लंघन जैसे मामूली अपराधों में शामिल पांच लाख लोगों की सजा माफ कर दी। बता दें कि जापान में हाल ही में हगिबिस तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। इसके चलते पब्लिक परेड को अगले हफ्ते तक के लिए टाल दिया गया है। कई लोगों ने राज्याभिषेक के दौरान किए जा रहे तामझाम पर विरोध भी जताया।

सफाया

ये भी जानिए

22 अगस्त 2018 को ट्रेंट ब्रिज में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के पांचवें दिन एक विकेट की दरकार थी। इसके लिए उसने 17 गेंद ली जबकि रांची में चौथे दिन दो विकेट के लिए भारत ने मात्र 12 गेंद ली।

कोहली-शास्त्री ने नए रोल में मदद की : रोहित

रांची : दक्षिण अफ्रीका के साथ खत्म हुई टेस्ट सीरीज में पहली बार खेल के लंबे प्रारूप में सलामी बल्लेबाजी करने वाले रोहित ने कहा कि इस नए रोल में टीम के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने उनकी काफी मदद की।

मैन ऑफ द सीरीज चुने गए रोहित ने कहा कि जिस तरह की सीरीज यह रही उससे मैं काफी सकारात्मक चीजें सीख सकता हूं, खासकर नई गेंद को कैसे खेलना है। विश्व भर में कहीं भी नई गेंद को खेलना परेशानी भरा होता है। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए अच्छी शुरुआत रही इसलिए मैं इसे जाने नहीं देना चाहता। मुझे पता चला की पारी की शुरुआत में आपको अनुशासन में खेलना होता है। एक बार आप जब जम जाते हो तो आप अपना खेल खेल सकते हो, मैंने यही किया। मैंने कुछ निश्चित चीजों का पालन किया जिससे मुझे सफलताएं मिलीं।

भारत- दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई टेस्ट मैच सीरीज भारत ने 3-0 से जीत ली। रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट में मंगलवार को जीत हासिल करने के बाद विजेता भारतीय टीम के सदस्य ट्रॉफी के साथ • जागरण

भारत में हमारी गेंदबाजी सफल नहीं : फाफ

रांची : भारत के हाथों तीन मैचों की टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने कहा है कि रणनीति की कमी के कारण उनकी टीम को इस तरह की हार का सामना करना पड़ा है। कप्तान ने यह भी माना है कि उनकी टीम की बल्लेबाजी इस सीरीज में मानसिक तौर पर भी कमजोर रही।

उन्होंने कहा कि भारत के तेज गेंदबाजों ने हमें बताया है कि गेंदबाजी किस तरह से की जाती है। जिस तेजी से उन्होंने गेंदबाजी की, हमारे तेज गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से नकार दिया। इसने हमें बताया है कि जब हम उपमहाद्वीप में खेलते हैं तो हमारी गेंदबाजी की शैली सफल नहीं है। इस दौरे ने दक्षिण अफ्रीका टीम की रणनीति की कमी को भी उजागर कर दिया कि देश के बोर्ड ने हाशिम अमला और एबी डिविलियर्स के बाद बल्लेबाजी के भविष्य के बारे में नहीं सोचा।

यहां के हम सिकंदर

- तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को पारी और 202 रन से दी शिकस्त
- गेंदबाजों और रोहित शर्मा की बदौलत तीन मैचों की सीरीज में मेहमानों का किया सफाया

संजीव रंजन • रांची

अगर कोई यह पूछे कि 2015 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद टीम में क्या बदलाव आया है जो यह दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम बन गई तो, इसका एक ही जवाब मिलता है कि हमारे तेज गेंदबाज अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं तेज गेंदबाजों का बैकअप इतना मजबूत है कि जसप्रीत बुमराह के नहीं होने के बावजूद भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को छह की छह पारियों में ऑलआउट किया। यही कारण है कि भारतीय टीम को घर में कोई विदेशी टीम चुनौती तक नहीं दे पाती और विदेशों में भी यह टीम झंडे गाड़कर आ रही है। झुके हुए कंधों के साथ फाफ डुप्लेसिस की कप्तानी में टेस्ट सीरीज खेलने उतरी दक्षिण अफ्रीका की 0-3 की हार की किसी ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन यह मुमकिन हो पाया तेज गेंदबाजों की वजह से। घरेलू पिचों पर भारतीय बल्लेबाज हमेशा विरोधियों के खिलाफ पहाड़ की तरह खड़े होते थे लेकिन अब स्पिनर ही नहीं तेज गेंदबाज भी विपक्ष की रीढ़ तोड़ रहे हैं।

इस मैच में भारत की ओर से रोहित शर्मा ने ऐतिहासिक दोहरा शतक जड़ा तो बतौर कप्तान आठवीं बार फॉलॉओन देते हुए कोहली के गेंदबाजों ने भी दक्षिण अफ्रीका को दो बार ऑलआउट कर अपने दम-खम को साबित किया। भारत ने तीसरे दिन सोमवार का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में आठ विकेट 132 रनों पर ही चटका दिए थे। भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट के नुकसान पर 497 रन पर घोषित की थी। इसके बाद तीसरे ही दिन साउथ अफ्रीका को पहली पारी में 162 रनों पर ढेर कर उसे फॉलोऑन दिया। दूसरी पारी में भी दक्षिण अफ्रीका की स्थिति बदल नहीं सकी और टीम लगातार विकेट खोती रही। 2001-02 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉलोऑन खेलने के बाद ऐसा दूसरी बार था, जब दक्षिण अफ्रीकी टीम लगातार दूसरी बार एक ही सीरीज में फॉलोऑन खेली। आखिरी पारी में भारत की ओर से मुहम्मद शमी ने 10 रन देकर तीन विकेट जबकि उमेश यादव व शाहबाज नदीम ने दो-दो विकेट चटकाए। जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को एक-एक विकेट मिला। तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत ने स्वदेश में छठी बार क्लीनस्वीप किया है।

रांची के राजा : जेएससीए स्टेडियम में भी परिणाम पुणे जैसा ही रहा। तीसरे दिन जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी भारतीय टीम ने मैच के चौथे दिन मेहमानों के दो विकेट निकालने में ज्यादा माथापच्ची नहीं की। भारत ने यह मुकाबला एक पारी व 202 रनों से अपने नाम किया। यह भारत की दक्षिण अफ्रीका पर पारी और रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत भी है।

तेज गेंदबाज बने हथियार : अगर आप इस सीरीज के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो रविचंद्रन अश्विन भले ही सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं लेकिन स्पिन पिचों पर भारत के तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अश्विन ने 15 विकेट लिए जबकि शमी ने इतने ही मैचों में 13 विकेट ले लिए। रवींद्र जडेजा ने भी 13 विकेट लिए। उमेश यादव ने 39 ओवर फेंकते हुए 11 विकेट निकाले।

नदीम ने झटके दोनों विकेट : मैच के चौथे दिन सिर्फ 12 गेंदों का खेल हुआ। अपना पहला टेस्ट खेल रहे नदीम ने चौथे दिन अपने पहले ओवर की अंतिम दो गेंदों पर दो विकेट झटकते हुए दक्षिण अफ्रीका की पारी को 133 रनों पर समेट दिया। दक्षिण अफ्रीका को नौवां झटका थेउनिस डी ब्रूएन के रूप में लगा जो 30 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी विकेट लुंगी नगिदी के रूप में लगा जो बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार हुए।

नोर्टजे के हेलमेट से लगी गेंद और आउट हुए नगिदी : मैच का अंतिम विकेट नदीम को नाटकीय अंदाज में मिला। नदीम के ओवर की आखिरी गेंद पर नगिदी ने जोरदार बल्ला घुमाया, गेंद गेंदबाजी छोर पर खड़े बल्लेबाज एनरिक नोर्टजे के हेलमेट से जा टकराई और सीधा नदीम की तरफ छिटकी, जिसे गेंदबाज ने कैच कर लिया।

जीत की हकदार टीम इंडिया

रांची : डीन एल्गर, मार्करैम, फाफ और डिकॉक उस अफ्रीकी टीम का हिस्सा थे जिन्होंने पिछले वर्ष अपने घर में भारत को हराया था लेकिन यहां पर भारत के गेंदबाजों, खासकर तेज गेंदबाजों ने उनके हौसले तोड़ दिए। भारत ने तो जोहानिसबर्ग टेस्ट में 63 रनों से एकमात्र टेस्ट जीत हासिल की थी लेकिन यहां पर अफ्रीकी टीम वह भी नहीं कर पाई।

सुधरा तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन

नई दिल्ली : एक जनवरी 2015 से अगर देखा जाए तो भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने घर में काबिल-ए-तारीफ प्रदर्शन किया है। घरेलू पिच स्पिनरों के मुफीद होने से पहले और दूसरे नंबर पर जरूर अश्विन और जडेजा काबिज हैं, जिन्होंने 26 टेस्ट में 154 और 26 टेस्ट में 130 विकेट लिए हैं। लेकिन उमेश यादव, मुहम्मद शमी और इशांत शर्मा ने अनुकूल पिच नहीं होने और कम मैच खेलने के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया। उमेश यादव ने इस दौरान 21 मैचों में 66, शमी ने 12 मैचों में 42 विकेट, इशांत ने 13 मैचों में 24 और भुवनेश्वर कुमार ने पांच मैचों में 18 विकेट लिए हैं। यानि कुल मिलाकर तेज गेंदबाजों ने एक जनवरी 2015 से अब तक घरेलू जमीन पर 51 मैचों में 150 विकेट अपने नाम किए हैं। बुमराह ने अभी तक घरेलू जमीन पर कोई टेस्ट नहीं खेला है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका

टीम	मैच	जीत	हार	ड्रॉ	अंक
भारत	5	5	0	0	240
न्यूजीलैंड	2	1	1	0	60
श्रीलंका	2	1	1	0	60
ऑस्ट्रेलिया	5	2	2	1	56
इंग्लैंड	5	2	2	1	56
वेस्टइंडीज	2	0	2	0	00
द. अफ्रीका	3	0	3	0	00

टेस्ट सीरीज में शीर्ष पांच गेंदबाज

गेंदबाज	मैच	ओवर	विकेट	औसत	सर्वश्रेष्ठ	5विकेट
अश्विन	3	138	15	25.26	7/145	1
शमी	3	74.5	13	14.76	5/35	1
जडेजा	3	149.2	13	30.69	4/87	0
उमेश	2	39	11	12.18	3/22	0
रबादा	3	90	07	40.71	3/85	0

टेस्ट सीरीज में शीर्ष पांच बल्लेबाज

बल्लेबाज	मैच	रन	औसत	100	सर्वश्रेष्ठ
रोहित शर्मा	3	529	132.25	3	212
मयंक अग्रवाल	3	340	85.00	2	215
विराट कोहली	3	317	158.50	1	254*
डीन एल्गर	3	232	46.40	1	160
अजिंक्य रहाणे	3	216	72.00	1	115

65 छक्के कुल तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में लगे

04 लगातार सीरीज दक्षिण अफ्रीका से अपने घर में जीता है भारत

05 टेस्ट लगातार अपनी कप्तानी में एशिया में हारे हैं फाफ डुप्लेसिस। इस दौरान वह एक बार भी टॉस नहीं जीते

भारत- दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई टेस्ट मैच सीरीज भारत ने 3-0 से जीत ली। रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट में मंगलवार को जीत हासिल करने के बाद ट्रॉफी के साथ शाहबाज नदीम। जागरण

संक्षिप्त स्कोर बोर्ड

टॉस : भारत (बल्लेबाजी), **परिणाम :** भारत पारी और 202 रनों से जीता, **मैन ऑफ द मैच/ सीरीज :** रोहित शर्मा, **भारत (पहली पारी) :** 497/9 (पारी घोषित, 116.3 ओवर), **दक्षिण अफ्रीका (पहली पारी) :** 162 (56.2 ओवर), **(दूसरी पारी) :** 133 (फॉलोऑन, 48 ओवर), (आठ विकेट पर 132 रन से आगे), थेउनिस डि ब्रूएन का. साहा बो. नदीम 30, एनरिक नोर्टजे नाबाद 05, लुंगी नगिदी का. एवं बो. नदीम 00, **अतिरिक्त :** 6 (बा-5, लेबा-1), **कुल :** 48 ओवर में 133 रनों पर सभी आउट, **विकेट पतन :** 9-133 (थेउनिस, 47.5), **गेंदबाजी :** शमी 10-6-10-3, उमेश यादव 9-1-35-2, जडेजा 13-5-36-1, नदीम 6-1-18-2, आर अश्विन 10-3-28-1

35 विकेटों का बड़ा अंतर रहा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज में। दक्षिण अफ्रीका भारत के मात्र 25 विकेट हासिल कर सका जबकि भारत ने मेहमानों के 60 विकेट हासिल किए, यानी छह के छह बार ऑलआउट किया

52.60 का बड़ा औसत अंतर रहा दोनों ही टीमों के गेंदबाजों के विकेट लेने का इस सीरीज में। भारतीय गेंदबाजों ने 22.84 के औसत से विकेट लिए, जबकि मेहमान टीम के गेंदबाजों ने 75.44 के औसत से विकेट लिए। भारतीय गेंदबाजों ने पांच बार पांच विकेट लिए, जबकि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज एक बार भी ऐसा नहीं कर सके

52.70 का बड़ा अंतर रहा दोनों टीम के तेज गेंदबाजों के विकेट औसत में। भारतीय तेज गेंदबाजों ने जहां 17.50 के औसत से 26 विकेट लिए वहीं मेहमान टीम के तेज गेंदबाज 70.20 के औसत से मात्र 10 विकेट ही ले सके

20 शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने जहां 15.60 की औसत से 20 विकेट लिए, वहीं दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज 43.40 के औसत से पांच ही विकेट ले सके

भाड़ में गई पिच, अपने को 20 विकेट चाहिए : शास्त्री

जागरण संवाददाता, रांची : क्लीन स्वीप के बाद रवि शास्त्री ने कहा कि हमारी कोशिश पिच के समीकरण को हटाना चाहते थे। भाड़ में गई पिच। हमारी रणनीति 20 विकेट लेने की होती है, पिच चाहे जैसी हो।

भारतीय कोच ने कहा कि हमारी बल्लेबाजी काफी अच्छी है। हमारे पास कोहली, रोहित, चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल जैसे बल्लेबाज हैं। और अगर ये चल जाएं और हम 20 विकेट ले लें तो फिर हमें रोक पाना आसान नहीं। हमारी पूरी कोशिश 20 विकेट लेने की होती है। उप कप्तान अजिंक्य रहाणे के बारे में उन्होंने कहा कि रहाणे कहीं नहीं जा रहे थे, उन्हें बस खुद को खोजना था। रोहित के प्रदर्शन से गदगद शास्त्री ने कहा कि उसने इस सीरीज में एक दोहरे शतक समेत कुल तीन शतक लगाए। सीरीज में 529 रन बनाने वाले रोहित ने कई अटकलों को शांत किया। पारी की शुरुआत के लिए आपको अलग मानसिकता की जरूरत होती है। आप पहली 10 गेंदों पर भी आउट हो सकते हैं। रोहित ने पहले दो घंटे तक टिके रहकर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। एक बार सेट होने के बाद उन्होंने परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाया। अगर बतौर ओपनिंग बल्लेबाज आप शुरुआती वक्त निकाल लेते हैं तो फिर आप दादा होते हैं।

सोते हुए शास्त्री की फोटो ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यहां खेले गए तीसरे टेस्ट के दौरान जिस बात ने सबका ध्यान खिंचा वो भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री की सोती हुए फोटो ने। मैच के दौरान शास्त्री ड्रेसिंग रूम में सोते हुए कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनको लेकर चुटकुले बने। शास्त्री की उस फोटो को शेयर करते हुए एक प्रशंसक ने ट्विटर पर लिखा कि सोता हुआ कोच।

शमी बोले, टीम को अपनी धुन पर नचाना अच्छा लगता है : मुहम्मद शमी ने कहा है कि हमारा तेज गेंदबाजी आक्रमण स्पिन के मुफीद अपने घर की पिचों पर भी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाने में सक्षम है। भारत की परिस्थितियां अभी तक स्पिन गेंदबाजों के लिए जानी जाती थीं, लेकिन अब हमारे पास ताकत है, हमारे तेज गेंदबाज बल्लेबाजों को नचा सकते हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट कप्तानों का प्रदर्शन

कप्तान	मैच	जीते	हारे	ड्रॉ	जीत %
अजहर	4	0	1	3	00.00
सचिन	8	2	5	1	25.00
गांगुली	4	1	1	2	25.00
द्रविड़	3	1	2	0	33.33
कुंबले	2	0	1	1	00.00
धौनी	8	3	3	2	37.50
कोहली	10	7	2	1	70.00

भारत की घर में लगातार 11 सीरीज जीत

बनाम	सत्र	जीत का अंतर
ऑस्ट्रेलिया	2012-13	4-0 (4)
वेस्टइंडीज	2013-14	2-0 (2)
द. अफ्रीका	2015-16	3-0 (4)
न्यूजीलैंड	2016-17	3-0 (3)
इंग्लैंड	2016-17	4-0 (4)
बांग्लादेश	2016-17	1-0 (1)
ऑस्ट्रेलिया	2016-17	2-1 (4)
श्रीलंका	2017-18	1-0 (3)
अफगानिस्तान	2018	1-0 (1)
वेस्टइंडीज	2018-19	2-0 (2)
द. अफ्रीका	2019-20	3-0 (3)

तेज गेंदबाजों ने अच्छा काम किया

वीवीएस लक्ष्मण

वेरी-वेरी स्पेशल

दिल से कहूं तो भारत की एक पारी से जीत टीम के सामूहिक प्रदर्शन से मिली है, लेकिन रोहित शर्मा सबसे आगे थे। अनुभव और परिपक्वता के साथ बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने एक सही फैसला लिया था। जब कैगिसो रबादा को इस पिच से मदद मिल रही थी और गेंद स्विंग हो रही थी तब रोहित बार-बार गेंद को छोड़ रहे थे और जब उन्हें जरूरत लगी तो उन्होंने अपने शॉट खेले। वह अधिक रन बनाने के लिए बैकफुट पर खेलने में अधिक विश्वास करते हैं।

वह इस सीरीज में अपनी खेल योजना के साथ आए थे और इसके साथ ही उन्होंने अनुशासन भी दिखाया। उन्होंने पहला दोहरा शतक लगाकर सबूत दे दिया था कि वह आसानी से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। मैच में भारत की पकड़ को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपने जोड़ीदार अजिंक्य रहाणे के साथ चौथे विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी की। रहाणे ने भी अच्छी शतकीय पारी खेली थी। वह हमेशा टीम की पारी को संभाल लेते हैं। वह अपना खेल खेलते हैं जो भारत की पारी के दौरान भी देखने को मिला जब टीम के 39 रन पर ही तीन विकेट गिर गए थे।

पहली पारी में 500 के करीब स्कोर पहुंचाने के बाद स्पिन के मुकाबले तेज गेंदबाजों ने मेजबान टीम के लिए अच्छा काम किया। शमी और उमेश को विकेट लेते हुए देखना अच्छा लगता है। 'मैच की गेंद' वहीं थी जब उमेश ने पहली पारी में क्विंटन डिकॉक का विकेट निकाला था। डिकॉक शॉर्ट गेंदों को अच्छी तरह से खेलते हैं, लेकिन उमेश की गेंद का उनके पास कोई जवाब नहीं था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कई वर्षों तक खेलने के बाद मुझे इस बात की खुशी थी कि नदीम ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। यह एक ऐसा बोनस था जिसमें वह अपने घरेलू मैदान पर पदार्पण कर रहे थे।

भारत में सिर्फ पांच टेस्ट स्थल होने चाहिए : कोहली

जागरण न्यूज नेटवर्क, रांची : भारतीय कप्तान विराट कोहली का मानना है कि अब समय आ गया है कि भविष्य में होने वाली घरेलू सीरीज के लिए बीसीसीआइ को पांच टेस्ट स्थलों का चयन करना चाहिए जैसा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शीर्ष टीमों के दौरे पर होता है। बड़ी टीमों के दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ब्रिसबेन और एडिलेड पांच टेस्ट स्थल हैं। इसी तरह बड़ी टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में लॉर्ड्स, ओवल, ट्रेंट ब्रिज, ओल्ड ट्रैफर्ड, एजबेस्टन, साउथैंप्टन और हेडिंग्ले मुख्य टेस्ट स्थल हैं।

रांची में टेस्ट के दौरान मैदान में दर्शकों की कमी के बारे में पूछे जाने पर भारतीय कप्तान ने कहा कि यह अच्छा सवाल है। हम काफी समय से इस बारे में चर्चा कर रहे है। मेरा मानना है कि टेस्ट मैचों के पांच स्थल होने चाहिए। कोहली ने कहा कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट को जीवंत और रोचक बनाए रखना चाहते है तो मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से सहमत हूं कि अधिक से अधिक पांच टेस्ट स्थल होने चाहिए। यह इतने अधिक जगह पर नहीं होना चाहिए जहां कम लोग मैच देखने पहुंचते है या नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से भारत दौरे पर आने वाली टीमों को भी फायदा होगा जिन्हें पता होगा कि उन्हें इन्हीं पांच जगहों में से कहीं टेस्ट खेलना होगा। कोहली ने यह नहीं बताया कि वह कौन से पांच टेस्ट स्थल होने चाहिए लेकिन माना जा रहा है कि वह चाहते हैं कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु पांच मुख्य टेस्ट स्थल रहें।

सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए बहुआयामी होना पड़ता है : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली बार टेस्ट में क्लीन स्वीप करने के बाद कोहली ने कहा कि किसी भी समय चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुआयामी होना महत्वपूर्ण है। एक टीम के रूप में हमने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वह गर्व की बात है। आप लोगों ने इस बारे में काफी बात की है। एक टीम के तौर पर हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। मुझे अपनी पूरी टीम पर गर्व है। विदेशी दौरों पर भी हमने हर मैच में कड़ा मुकाबला किया है। टीम की मानसिक दृढ़ता देखना लाजवाब है।

सबसे ज्यादा टेस्ट आयोजित करने वाले भारत के स्टेडियम

स्टेडियम	शहर	टेस्ट	जीत %
ईडन	कोलकाता	41	29
कोटला	दिल्ली	34	38
चिदंबरम	चेन्नई	32	44
वानखेड़े	मुंबई	25	44
चिन्नास्वामी	बेंगलुरु	23	35
ग्रीन पार्क	कानपुर	22	32
बिंद्रा	मोहाली	13	54
वीसीए	नागपुर	6	67
राजीव गांधी	हैदराबाद	5	80

गांगुली से धौनी पर बात नहीं

रांची : कोहली ने कहा कि महेंद्र सिंह धौनी के भविष्य को लेकर उनकी सौरव गांगुली से कोई बात नहीं हुई है और जब जरूरत होगी तब बीसीसीआइ के भावी अध्यक्ष बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक लेने वाले धौनी के बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज में खेलने की संभावना नहीं है। जब पत्रकारों ने धौनी के आने पर सवाल पूछा तो कोहली ने कहा कि वह ड्रेसिंग रूम में आए और मैंने उन्हें 'हेलो' बोला।

भारतीय बोर्ड के 39वें अध्यक्ष बनेंगे सौरव, गांगुली ने तीनों वर्तमान पदाधिकारियों को भी दिया निमंत्रण

बीसीसीआइ से आज खत्म होगा सीओए का शासन

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली बुधवार को मुंबई में होने वाली सालाना आम बैठक (एजीएम) में बीसीसीआइ के 39वें अध्यक्ष बनेंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) का 33 महीने से चला आ रहा शासन खत्म हो जाएगा।

बीसीसीआइ अध्यक्ष पद के लिए गांगुली का नामांकन सर्वसम्मति से हुआ है जबकि जय शाह सचिव होंगे। उत्तराखंड के माहिम वर्मा नए उपाध्यक्ष होंगे। बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण सिंह धूमल कोषाध्यक्ष होंगे जबकि केरल के जयेश जॉर्ज संयुक्त सचिव होंगे। गांगुली का कार्यकाल नौ महीने का ही होगा और सुप्रीम कोर्ट या सरकार के स्तर पर कुछ बड़ा नहीं होता है तो उन्हें जुलाई में पद छोड़ना होगा क्योंकि नए संविधान के प्रावधानों के तहत छह साल के कार्यकाल के बाद तीन साल का 'कूलिंग ऑफ' अनिवार्य है। गांगुली ने कुछ लक्ष्य तय कर रखे हैं जिनमें प्रशासन को ढर्रे पर लाना और प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों के वेतन में बढ़ोतरी शामिल है। गांगुली ने पद संभालने के लिए वर्तमान तीनों पदाधिकारियों कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को भी आमंत्रण दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) ने इन तीनों को आमंत्रित नहीं किया था। मालूम हो कि अब इन तीनों पदाधिकारियों के जरिये ही गांगुली और उनकी टीम चार्ज लेगी।

राय से मतभेदों पर इडुल्जी ने कहा, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं : सीओए सदस्य डायना इडुल्जी ने कहा कि विनोद राय की अगुआई वाले पैनल के भीतर गंभीर मतभेद थे जैसे कि एक लोकतांत्रिक संगठन में हो सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था। भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान इडुल्जी ने मुंबई में हुई सीओए की अंतिम बैठक के बाद कहा, 'यह अच्छा अनुभव था और लंबी यात्रा रही। मैंने नहीं सोचा था कि यह यात्रा इतनी लंबी होगी, लेकिन मैं चुनाव और पदाधिकारियों की वापसी से खुश हूं और अब वे बीसीसीआइ का संचालन करेंगे।' इडुल्जी और राय के बीच अक्सर कई मसलों पर मतभेद रहे। उन्होंने कहा, 'हमारे बीच मतभेद रहे और हमने इन्हें खुलकर जाहिर भी किया। पिछले नौ महीने से सीओए का हिस्सा रहे लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) रवि थोडगे ने कहा, 'क्रिकेट प्रशासन से जुड़ने से काफी कुछ सीखने को मिला।'

बोर्ड के पदाधिकारी

अध्यक्ष	सौरव गांगुली
सचिव	जय शाह
कोषाध्यक्ष	अरुण सिंह धूमल
उपाध्यक्ष	माहिम वर्मा
संयुक्त सचिव	जयेश जॉर्ज
आइपीएल चेयरमैन	बृजेश पटेल

गांगुली के सामने चुनौतियां

- 'हितों के टकराव' के नियमों के बीच क्रिकेट सलाहकार समिति और राष्ट्रीय चयन समिति में अच्छे क्रिकेटरों को लाने की चुनौती
- एन. श्रीनिवासन और निरंजन शाह जैसे बीसीसीआइ के पुराने धुरंधरों को साथ लेकर बीसीसीआइ का संचालन
- क्रिकेट नीतियों के अलावा महेंद्र सिंह धौनी के भविष्य, दिन रात के टेस्ट क्रिकेट और स्थायी टेस्ट केंद्रों पर भी उनका रुख देखना होगा
- शशांक मनोहर वाली आइसीसी के आक्रमणों को झेलना और एक बार फिर बीसीसीआइ की धमक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना

पूरी प्रक्रिया का पालन होगा : राय

नई दिल्ली : सीओए के प्रमुख विनोद राय ने कहा, 'एजीएम के दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। पहले पिछले तीन साल के खातों को मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद निर्वाचन अधिकारी चुनाव के नतीजे की घोषणा करेंगे क्योंकि सभी निर्विरोध चुने गए हैं। हम सौरव से बात करके बुधवार का कार्यक्रम तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, मैं उससे खुश हूं। हमने निर्देश मांगे थे क्योंकि हम इस्तीफा नहीं दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें नियुक्त किया था। हमें अपने कर्तव्यों से मुक्त होना पड़ रहा है जो कोर्ट का आदेश है। हर फैसले को कोर्ट ने अनिवार्य किया था। हमने संविधान नहीं बदला है। हमें जो भी दिया गया था, हमने उसमें ही काम किया है।'

राय और इडुल्जी को 3.5-3.5 करोड़

नई दिल्ली : सीओए के सभी सदस्यों को 2017 के लिए प्रतिमाह 10 लाख रुपये, 2018 के लिए 11 लाख रुपये और 2019 के लिए 12 लाख रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा। बीसीसीआइ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'न्यायमित्र पीएस नरसिम्हा से चर्चा के बाद इस राशि को अंतिम रूप दिया गया।' इस तरह से इडुल्जी और राय दोनों में से प्रत्येक को 3.5 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि विक्रम लिमये, रामचंद्र गुहा और रवि थोडगे को उनके कार्यकाल के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

अधिकारियों के पदभार संभालने के बाद सीओए को हटना होगा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि बीसीसीआइ के निर्वाचित पदाधिकारियों के पदभार संभालने के बाद पूर्व सीएजी विनोद राय की अध्यक्षता वाली प्रशासकों की समिति (सीओए) को हटना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीओए और उसके पदाधिकारियों द्वारा क्रिकेट संगठन में किए गए किसी भी कार्य के लिए उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। सीओए और उसके अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। दो जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एसए बोबडे ने कहा कि बीसीसीआइ के हित में कोई भी फैसला लेने के क्रम में सीओए के खिलाफ कोई सिविल या फिर आपराधिक मामला नहीं बनता।

ड्रेसिंग रूम में धौनी

कोच रवि शास्त्री के साथ धौनी • ट्विटर

जागरण संवाददाता, रांची : टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ने मंगलवार को जेएससीए स्टेडियम पहुंचकर भारतीय खिलाड़ियों से भेंट की और जीत की शुभकामना दी। तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन से ही धौनी के स्टेडियम में आने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन धौनी तीन दिन तक रांची में रहते हुए स्टेडियम नहीं पहुंचे और रांची के सड़कों पर सेना का जीप जोंगा चलाते नजर आए। तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को पराजित करने के बाद टीम जब जीत का जश्न मना रही थी तभी वहां धौनी पहुंचे और सभी को जीत की बधाई दी।

टी-20 में भारत को बांग्लादेश से कड़ी टक्कर मिलेगी : लक्ष्मण

रांची, आइएएनएस : पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण का मानना है कि भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज में मेहमान टीम से कड़ी टक्कर मिलेगी। भारत ने मंगलवार को तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को पारी और 202 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। हालांकि लक्ष्मण का कहना है कि बांग्लादेश के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज में भारतीय टीम को सावधान रहना होगा।

श्रीसंत के टीम से बाहर जाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। इस पर बात करना ही मूर्खता होगी।
– दिनेश कार्तिक, भारतीय बल्लेबाज

मेसी को रोनाल्डो और वान से मिलेगी चुनौती

फुटबॉल डायरी ▶ बैलन डि ओर पुरस्कार के लिए 30 खिलाड़ियों की सूची की घोषणा

नेमार और पिछले बार के विजेता मॉड्रिक को नहीं मिली सूची में जगह

पेरिस, एपी : स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी को 2019 के बैलन डि ओर पुरस्कार के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विर्गिल वान डिज्क से चुनौती मिलेगी लेकिन नेमार को इस सूची में जगह नहीं मिल पाई है। दुनिया भर के पत्रकारों की वोटिंग के बाद सोमवार को जब 30 नामित दावेदारों की घोषणा की गई तो उसमें नेमार का नाम नहीं था। इसकी घोषणा नेमार के मौजूदा फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) के शहर पेरिस में की गई। नेमार दो बार बैलन डि ओर पुरस्कारों में तीसरे स्थान पर रहे हैं। अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी मेसी ने पिछले महीने लिवरपूल के डिफेंडर वान डिज्क और रोनाल्डो को पछाड़कर छठी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हासिल किया था।

फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका द्वारा दिए जाने वाले इन पुरस्कारों में मेसी और जुवेंटस के स्टार रोनाल्डो के 10 साल के वर्चस्व को पिछले साल लुका मॉड्रिक ने तोड़ा था। रीयल मैड्रिड और अपने देश क्रोएशिया की ओर से 2018 में शानदार प्रदर्शन की बदौलत मॉड्रिक को पिछली बार बैलन डि ओर और फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था लेकिन इस साल भी इस सूची में जगह नहीं मिली है।

30 नामित पुरुष खिलाड़ी

सर्जियो अग्यूरो (मैनचेस्टर सिटी), ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड (लिवरपूल), पियरे एमरिक आउबामेयांग (आर्सेनल), एलिसन बेकर (लिवरपूल), करीम बेंजमा (रीयल मैड्रिड), केविन डि ब्रूने (मैनचेस्टर सिटी), फ्रैंकी डि जोंग (बार्सिलोना), मैथिस डि लिट (जुवेंटस), जोआओ फेलिक्स (एटलेटिको मैड्रिड), रॉबर्टो फर्मिनो (लिवरपूल), एंटोनी ग्रीजमैन (बार्सिलोना), ईडन हैजार्ड (रीयल मैड्रिड), कालिडोउ कौलिबेली (नापोली), रॉबर्टो लेवांदोवोस्की (बायर्न म्यूनिख), हुगो लॉरिस (टॉटनहम), रियाद महारेज (मैनचेस्टर सिटी), सादियो माने (लिवरपूल), मार्किन्होस (पीएसजी), कायलियन एमबापे (पीएसजी), लियोन मेसी (बार्सिलोना), क्रिस्टियानो रोनाल्डो (जुवेंटस), मुहम्मद सलाह (लिवरपूल), बेनार्डो सिल्वा (मैनचेस्टर सिटी), सोन ह्यूंग मिन (टॉटनहम), रहीम स्टर्लिंग (मैनचेस्टर सिटी), दुसान टाडिक (अजाक्स), मार्क आंद्रे टेर स्टेगन (बार्सिलोना), डॉनी वान डि बिक (अजाक्स), विर्गिल वान डिज्क (लिवरपूल), जॉर्जिनियो विज्नाल्डम (लिवरपूल)

टॉटनहम के लिए खेलने वाले दक्षिण कोरिया के सोन ह्यूंग मिन इस सूची में शामिल इकलौते एशियाई खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में मेगान रेपिनो बैलन डि ओर खिताब जीतने की प्रबल दावेदार हैं।

ट्रेनिंग सेशन के दौरान लियोन मेसी। रायटर

लगातार छठे जीत की तलाश में उतरेगा बार्सिलोना

प्राग : यूएफा चैंपियंस लीग के ग्रुप-एफ में जब स्पेनिश क्लब बार्सिलोना बुधवार को स्लाविया प्राग के खिलाफ उतरेगा तो उसकी नजर लगातार छठी जीत दर्ज करने पर होगी। यह पहला मौका होगा जब प्राग में बार्सिलोना की टीम खेलने उतरेगी। बार्सिलोना की टीम ने लियोन मेसी, लुइस सुआरेज और एंटोनी ग्रीजमैन द्वारा किए गए गोल की मदद से ईबर को ला लीगा में 3-0 से हराकर लगातार पांचवीं जीत दर्ज की थी। उससे पहले उसने चैंपियंस लीग में इंटर मिलान को 2-1 से हराया था। वहीं स्लाविया ने अपने पिछले मुकाबले में इंटर मिलान को 1-1 की बराबरी पर रोका था। इसी ग्रुप में इंटर की टीम जर्मन क्लब बोरुसिया डोर्टमंड से भिड़ेगी। यह मुकाबला दोनों टीम के लिए अहम है।

समाता पर होंगी निगाहें : ग्रुप-ई में बुधवार को मौजूदा चैंपियन लिवरपूल को अपने स्टार स्ट्राइकर मुहम्मद सलाह और सादियो माने से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें हैं लेकिन उसके विरोधी रेसिंग जेंक के एक अफ्रीकी सुपर स्टार एंबवाना एली समाता पर खास निगाहें होंगी। समाता ने पिछले सत्र में 23 लीग गोल किए थे और अब वह लिवरपूल के खिलाफ अपनी चमक बिखेरने की तैयारी में हैं। 23 वर्षीय समाता चैंपियंस लीग में खेलने वाले तंजानिया के पहले खिलाड़ी हैं।

चेल्सी की होगी परीक्षा : ग्रुप-एच में चेल्सी की युवा टीम को बुधवार को नीदरलैंड्स के क्लब अजाक्स से कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। मैनेजर फ्रैंक लैंपार्ड की चेल्सी की टीम सभी प्रतियोगिताओं में पिछले पांच मुकाबलों से जीतते आ रही है लेकिन पिछले बार सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली अजाक्स की टीम से उसे कड़ी टक्कर मिलेगी।

अभी संन्यास नहीं लेंगे रोनाल्डो

तुरिन, एएफपी : पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने इटालियन क्लब जुवेंटस के प्रशंसकों को आश्वस्त किया है कि अभी संन्यास नहीं लेंगे। रोनाल्डो ने कहा कि उम्र बस एक संख्या है। 34, 35, 36 की उम्र होने का मतलब ये नहीं है कि आपका करियर खत्म होने वाला है। मैं अपने खेल से यह साबित कर सकता हूं कि मैं कितना अच्छा और तेज हूं। हाल ही में रोनाल्डो ने अपने करियर में 700 गोल का आंकड़ा पार किया है।

हड़ताल के बाद बांग्लादेश क्रिकेट पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप

ढाका, एएफपी : खिलाड़ियों की वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के पूर्व अध्यक्ष ने देश में क्रिकेट में बड़े पैमाने पर फिक्सिंग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

बीसीबी के पूर्व अध्यक्ष साबीर हुसैन चौधरी ने कहा कि बोर्ड की संचालन परिषद भी भ्रष्टाचार में शामिल है। चौधरी संसद सदस्य भी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, 'बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दुनिया की एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय खेल इकाई है जो संस्थागत तरीके से मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। यह अविश्वसनीय है। मैंने खुद कई बार इस मुद्दे को उठाया है।' राष्ट्रीय टीम के कप्तान शाकिब अल हसन ने भी घरेलू क्रिकेट में भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर करते हुए क्रिकेटरों के वेतन को बढ़ाने की मांग के साथ देश के पेशेवर खिलाड़ियों के साथ हड़ताल शुरू की है। खिलाड़ियों के इस हड़ताल के कारण बांग्लादेश का आगामी भारतीय दौरा अधर में लटक सकता है। मैच फिक्सिंग के कथित आरोपों के कारण 2014 के बांग्लादेश प्रीमियर लीग टी-20 टूर्नामेंट को रद कर दिया गया था।

बांग्लादेश में भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही मामला 2017 मे सामने आया जब दूसरे श्रेणी के एक मुकाबले में गेंदबाज ने लगातार वाइड और नो बाल फेंक कर पहले ओवर में ही 92 रन लुटाए और टीम मैच हार गई। टीम ने हालांकि कहा था कि यह अंपायर के पक्षपाती रवैये के कारण किया गया था। इस मुकाबले में लालमाटिया की टीम 14 ओवर में 88 रन पर आउट हो गई थी जबकि एक्जिओम ने महज चार गेंदों में बिना विकेट गंवाए 92 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस दौरान गेंदबाज ने 13 वाइड और तीन नोबॉल फेंकी और ये सभी गेंद सीमा रेखा के पार गयी जिससे 80 अतिरिक्त रन बने।

क्रिकेटरों की हड़ताल साजिश : बीसीबी के अध्यक्ष नजमुल हसन ने कहा है कि यह खिलाड़ियों की साजिश है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीबी ने मीरपुर में बैठक की है, लेकिन आगे बोर्ड क्या कदम उठाने वाला है इस बारे में हसन ने कुछ भी नहीं बताया।

बीसीबी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि बोर्ड की संचालन परिषद भ्रष्टाचार में शामिल है

इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं सीडब्ल्यूएबी प्रमुख

इस बीच क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (सीडब्ल्यूएबी) के अध्यक्ष नइमुर रहमान ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। रहमान ने कहा, 'मैंने सीडब्ल्यूएबी में अपनी जेब से भी राशि दी है और काफी समय से इसके साथ हूं। यह स्वाभाविक है कि कोई नया आएगा और मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी दबाव में नहीं। सीडब्ल्यूएबी में चुनाव होंगे। अगर कोई चुना जाता है तो वह अध्यक्ष बनेगा। इस संगठन का एक संविधान है और हमें उसका पालन करना चाहिए।'

विजय हजारे ट्रॉफी में रिजर्व डे न होने से युवराज व हरभजन निराश

चंडीगढ़, आइएएनएस : भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह और ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने मंगलवार को भारतीय किकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) से विजय हजारे ट्रॉफी में रिजर्व डे न होने पर सवाल किया है। रिजर्व डे न होने के कारण पंजाब की टीम सेमीफाइनल में नहीं जा सकी।

क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु द्वारा रखे गए 175 रनों के जवाब में पंजाब ने 13 ओवरों में दो विकेट खोकर 52 रन बना लिए थे, लेकिन तभी बारिश आ गई और मैच रद कर दिया गया। लीग चरण में ज्यादा मैच जीतने के कारण तमिलनाडु को सेमीफाइनल में जगह मिली।

युवराज ने ट्वीट में लिखा कि पंजाब के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ एक और दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम। एक बार फिर मैच खराब मौसम के कारण रद्द हो गया और अंकों के आधार पर हम सेमीफाइनल में नहीं जा सकते। क्यों हमारे पास रिजर्व डे नहीं है। या फिर यह वो घरेलू टूर्नामेंट है जो बीसीसीआइ के लिए मायने नहीं रखता। पंजाब के क्रिकेटर मनदीप सिंह ने भी ट्विटर पर इस बात पर नाराजगी जताई थी।

उन्होंने लिखा था, च्च्लीग चरण में बेहतरीन क्रिकेट खेलना क्वालीफाई करना मुश्किल है। अब हम बारिश के कारण टूर्नामेंट से बाहर हैं वो भी बिना क्वार्टर फाइनल खेले। यह बेहद निराशाजनक है। मनदीप को हरभजन का साथ मिला। हरभजन ने उनके ट्वीट का जवाब में लिखा, च्च्खराब नियम, इन टूर्नामेंट में रिजर्व डे नहीं है। बीसीसीआइ को इसे देखना चाहिए और इसे बदलना चाहिए।

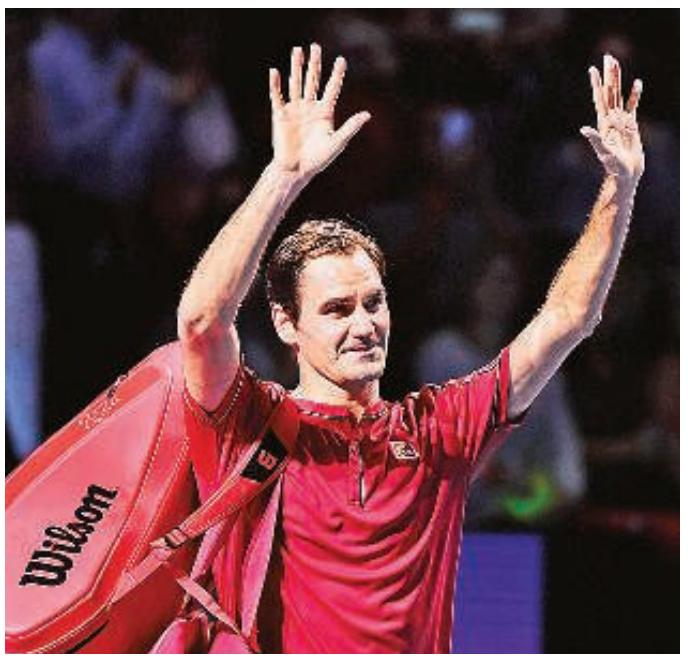

करियर के 1500वें मैच में जीत हासिल करने के बाद दर्शकों का अभिवादन करते रोजर फेडरर। एएफपी

करियर के 1500वें मैच में जीते फेडरर

बासेल, एएफपी : स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अपने घरेलू कोर्ट पर बासेल में करियर के 1500वें मुकाबले में सोमवार को शानदार जीत दर्ज की। बासेल में अपने 10वें खिताब की चुनौती पेश करने उतरे 38 वर्षीय फेडरर ने जर्मनी के क्वालीफायर पीटर गोजोविक को 6-2, 6-1 से हराकर इस स्विस इंडोर टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बनाई।

20 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन फेडरर ने जर्मनी के खिलाड़ी को इससे पहले दो बार हराया था। फेडरर पहली बार इस टूर्नामेंट में बॉल ब्वॉय के रूप में उतरे थे। इस टूर्नामेंट में उनकी यह लगातार 21वीं जीत है जबकि यहां अब तक फेडरर ने कुल 72 मुकाबले जीते हैं और केवल नौ गंवाए हैं। इस साल फेडरर ने दुबई, मियामी और हाले में एटीपी खिताब जीते थे। उधर ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डि मिनॉर ने बोलीविया के हुगो डेलीन को 6-1, 7-5 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। साथ ही हेनरी लाकसोनेन ने फ्रांस के आठवें वरीय बेनोइट पियरे को 6-3, 7-5 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया।

टेनिस डायरी

ऑस्ट्रेलियाई टीम में किर्गियोस

सिडनी : निक किर्गियोस को डेविस कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान लेटिन हेविट ने कहा कि वह एटीपी टूर के दौरान किर्गियोस के हालिया हरकतों को नजरअंदाज करके उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह दे रहे हैं क्योंकि वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। अगस्त में सिनसिनाटी ओपन में अपने बयान की वजह से किर्गियोस एटीपी टूर से छह महीने के लिए निलंबित हैं। हालांकि यह निलंबन सिर्फ एटीपी टूर पर लागू है और वह डेविस कप में खेल सकते हैं।

फेडरर ने की मरे की तारीफ : स्विस स्टार रोजर फेडरर ने कूल्हे की सर्जरी के 10 महीने बाद एंटवर्प में खिताब जीतने पर एंडी मरे की तारीफ की है। फेडरर ने कहा कि एंडी की उपलब्धि बहुत बड़ी थी। मुझे थोड़ी तकलीफ हुई क्योंकि उन्होंने फाइनल में मेरे हमवतन स्टेन (वावरिंका) को हराया लेकिन उनके लिए यह बेहतरीन वापसी है। वह अपने पुराने स्तर तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऑस्ट्रेलिया ओपन के लॉकर रूम की घटना याद है। तब हमारे और उनके लिए बहुत दुविधा की स्थिति थी। अब मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। मालूम हो कि साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन में चोट और दर्द के साथ खेल रहे मरे पहले दौर में हारकर बाहर होने के बाद काफी भावुक थे। तीन बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन मरे खिताबी जीत के बाद ताजा एटीपी रैंकिंग में 116 पायदान की लंबी छलांग लगाकर 127वें स्थान पर पहुंच गए। उन्हें ब्रिटेन की डेविस कप टीम में भी शामिल किया गया है।

विविध

कार्बेट के नरभक्षी बाघ ने उड़ाई नींद

केदार दत्त, देहरादून

देश में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाले कार्बेट टाइगर रिजर्व के जंगलों में बेहतर वासस्थल और भरपूर भोजन की उपलब्धता के बावजूद बाघ के बढ़ते हमलों ने नींद उड़ा दी है। सालभर के वक्फे में बाघ अब तक चार वनकर्मियों की जान ले चुके हैं, जबकि इससे पहले 18 साल में ऐसी छह घटनाएं हुई थीं। ऐसे में कई प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहा कि अब अचानक जंगल में बाघ के व्यवहार में ऐसा बदलाव क्यों नजर आ रहा। कहीं जंगल अथवा सिस्टम की कार्यशैली में कोई खोट तो नहीं। इस उलझन से पार पाने को भारतीय वन्यजीव संस्थान को गहन अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है।

ढाई सौ से अधिक बाघों की संख्या वाला कार्बेट टाइगर रिजर्व इन दिनों वनकर्मियों पर बाघ के हमलों के कारण चर्चा में है। गत वर्ष नवंबर में रिजर्व की ढिकाला रेंज में बाघ ने एक वनकर्मी पर हमला किया। इसके बाद जुलाई में खनसूर, अगस्त में ढिकाला और अब चौखम क्षेत्र में बाघ ने गश्त के दौरान एक-एक वनकर्मी की जान ली है। ढिकाला रेंज और खनसूर-चौखम की सीमाएं आपस में मिलती हैं। इन घटनाओं ने महकमे की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। महकमा पशोपेस में है कि जंगल में भोजन की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद बाघ के हमले क्यों बढ़ रहे हैं। अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं

कार्बेट में वनकर्मियों पर बाघ के हमले की घटनाएं असामान्य और चिंताजनक हैं। खासकर सालभर के भीतर दो स्थानों पर चार हमले। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय वन्यजीव संस्थान से गहन अध्ययन कराने की तैयारी है। इसके बाद ही वस्तुस्थिति सामने आ पाएगी।
– राजीव भरतरी, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखंड

हो पाया कि हमले करने वाला एक ही बाघ है या अलग-अलग। जानकारों की मानें तो यदि एक ही बाघ है तो वह अशक्तता की स्थिति में हमले कर सकता है। यदि अलग-अलग हैं तो यह चौंकाने वाली बात है। ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है कि कहीं जंगल में खाद्य शृंखला में कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही, जिससे बाघ के स्वभाव में परिवर्तन दिख रहा है। यह सवाल भी फिजां में तैर रहा है कि गश्त की रणनीति में कहीं कोई खोट तो नहीं है। गश्त के दौरान वनकर्मियों को मोबाइल एप पर लोकेशन देनी होती है। टाइगर रिजर्व के कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां कनेक्टिविटी नहीं है। ये बात भी उठ रही कि एप में लोकेशन व रिकार्ड दर्ज करने के दरम्यान तो ऐसी घटनाएं नहीं हो रहीं। ऐसे तमाम सवाल हर किसी को कचोट रहे हैं।

मनोबल पर भी असर : बाघ के हमलों में वनकर्मियों की जान जाने के बावजूद इसके समाधान को अभी तक कदम नहीं उठाए गए हैं। इससे वनकर्मियों के मनोबल पर भी असर पड़ रहा है।

हिमाचल के आयुर्वेद घोटाले में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी आएंगे जांच के दायरे में

राज्य ब्यूरो, शिमला

आयुर्वेद घोटाले की अब हिमाचल प्रदेश सरकार विजिलेंस जांच कराएगी। इस संबंध में आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) आयुर्वेद भी जांच के दायरे में आएंगे। सरकार ने आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ सहायक राजेश कुमार कौशल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लिखे पत्र का कड़ा संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने इसकी पुष्टि की है।

उन्होंने कहा कि एसीएस की भूमिका की भी जांच होगी। अगर वह दोषी पाए गए तो सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। घोटाले में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों को सरकार नहीं बख्शेगी चाहे कोई किसी भी अहम ओहदे पर क्यों न बैठा हो। हालांकि एसीएस ने आयुर्वेद विभाग के निदेशक से जवाब-तलब किया था। इसमें कहा गया कि उन्होंने अभी तक राजेश को चार्जशीट क्यों नहीं किया है? इस कर्मचारी ने पत्र के जरिये दो आला आइएएस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे।

सरकार ने इससे पहले आयुर्वेद घोटाले में विभाग के पूर्व निदेशक संजीव भटनागर को चार्जशीट किया था। दैनिक जागरण ने आयुर्वेद विभाग में घोटाला उजागर किया था। इसके बाद सरकार ने तकनीकी कमेटी को निलंबित कर दिया था। इस कमेटी में डॉ. तेजस्वी विजय आजाद, डॉ. केडी शर्मा व डॉ. शैली बंसल शामिल हैं। सरकार ने संजीव भटनागर को आयुर्वेद विभाग से तुरंत हटाया था। इससे पूर्व जैम पोर्टल संचालित करने वाले वरिष्ठ सहायक राजेश कुमार कौशल को एक दिन के लिए निलंबित किया गया था।

क्या है मामला : इस वर्ष के शुरू में आयुर्वेद विभाग में 11 चिकित्सा उपकरणों की खरीद हुई थी। यह खरीद लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। उस समय 2.25 करोड़ रुपये का हेड बदल कर चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम का रेट कांट्रैक्ट बनाया गया, मगर चिकित्सा उपकरणों की खरीद जैम पोर्टल से की गई। दैनिक जागरण ने आयुर्वेद विभाग में व्याप्त गड़बड़झाले का मामला प्रमुखता से उठाया था। इस साल 23 जून से सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित किए गए। इसके बाद सरकार ने हरकत में आते हुए एक के बाद एक कार्रवाई की थी।

दो नौकरशाहों पर दर्ज हो एफआइआर : कर्मचारी महासंघ

राज्य ब्यूरो, शिमला : अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने आयुर्वेद घोटाले में दो बड़े नौकरशाहों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की है। संगठन इस मामले में गवाह के पक्ष में उतरा है। महासंघ के विनोद गुट के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि आयुर्वेद विभाग में हुए घोटाले के अहम गवाह को जान का खतरा बना हुआ है। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया।

उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है कि इस प्रकरण की जांच में छोटे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि नौकरशाहों के कारनामों का खामियाजा उन्हें न भुगतना पड़े। यह वित्तीय अपराध से जुड़ा मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार के दो बड़े नौकरशाहों की सीधी भूमिका है। उन्होंने कहा कि अब अपने बचाव में इस घोटाले के साक्ष्यों को कमजोर करने के लिए विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है जिसे महासंघ बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में संलिप्त बड़े लोग पकड़ में आ सकें, इसके लिए गवाह के लिखित बयान में पर्याप्त साक्ष्य हैं।

पर्दे की जिंदगी को हकीकत बनाकर 'आइकन' बने हेम

भानु जोशी, हल्द्वानी

मुफलिसी और परेशानियों से भरी जिंदगी के बावजूद कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचा जाता है, यह फिल्मी पर्दे पर साकार होते तो देखा है। लेकिन, असल जिंदगी में इक्का-दुक्का नाम ही ऐसे होते हैं, जो ऐसा हकीकत में कर दिखाते हैं। ऐसा ही एक नाम हेम चंद्र का भी है। उन्होंने गरीबी की तंग गलियों से निकलकर 'मोटिवेशन आइकन ऑफ इंडिया' तक का सफर तय किया। अब वह यू-ट्यूब चैनल के जरिये लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। खेल व पढ़ाई के क्षेत्र में भी उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए हैं।

उत्तराखंड के हल्द्वानी के पनियाली निवासी हेम चंद्र का जीवन विषम परिस्थितियों के बीच बीता। पढ़ाई-लिखाई के साथ ही डांस और बॉडी बिल्डिंग में भी उनकी दिलचस्पी थी, जो बड़े होते-होते शौक में बदल गई। मिस्टर पंतनगर व मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीतने के बाद वर्ष 2018 में उन्हें 'मोटिवेशनल आइकन ऑफ इंडिया' चुना गया। इस बीच कई विभागों में उन्होंने सरकारी नौकरी भी की, लेकिन आगे बढ़ने की ललक उनके जुनून को और बढ़ाती चली गई। वर्तमान में ऊधमसिंहनगर जिले में रेशम विभाग में सहायक निदेशक हेम की इन्हीं उपलब्धियों और जज्बे को देखते हुए 'जोश टॉक्स' नाम के यू-ट्यूब चैनल ने उन्हें आमंत्रित किया।

डेढ़ साल में पिता को खोया : गरीबी एवं अभावों के कारण अक्सर युवा सोचते हैं कि वे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए हेम ने मिसाल पेश की है। बकौल हेम, जब मैं महज डेढ़ साल का था, पिता खीम राम आर्य का साया सिर से उठ गया। निरक्षर मां ने मृतक आश्रित पद पर नौकरी करते हुए कठिन संघर्षों के बीच तीन बच्चों की परवरिश की।

ऊधमसिंहनगर जिले में रेशम विभाग में सहायक निदेशक हैं हेम

हेम चंद फाइल

हेम के नाम दर्ज उपलब्धियां

- वॉडी बिल्डिंग में मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर कुमाऊं, मिस्टर नैनीताल, मिस्टर हल्द्वानी, मिस्टर पंतनगर विश्वविद्यालय का खिताब
- पावर लिफ्टिंग व वेट लिफ्टिंग में तीन साल तक विवि चैंपियन
- विश्वविद्यालय की वॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग व इंडोर टीम के कप्तान रहे

बिहार के मोतिहारी के बालिका गृह से फरार दो किशोरियों को पुलिस ने खोज निकाला

संस, मोतिहारी

बिहार के मोतिहारी के बरियारपुर स्थित बालिका गृह से सोमवार की शाम चार किशोरी साड़ी के सहारे प्रथम तल से कूदकर फरार हो गईं। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो को खोज निकाला। अन्य दो की तलाश चल रही है। एक बालिका को बरियारपुर के चर्च के पास से व दूसरी को चंद्रहिया से खोज निकाला गया है। फरार दो अन्य की तलाश के लिए पुलिस टीम को बेतिया व बगहा भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा ने मंगलवार को बालिका गृह पहुंचकर मामले की जांच की व सुरक्षा व्यवस्था पर भी चिंता जताई। एसपी के साथ प्रशिक्षु डीएसपी विनिता कुमारी के अलावा थानाध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे, अनुसंधानकर्ता कंचन भास्कर भी मौजूद थे। बालिका गृह की अधीक्षक मधु कुमारी ने थाना में आवेदन देकर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रशिक्षु डीएसपी ने लड़कियों से पूछताछ की। ड्यूटी पर तैनात सिपाही से भी पूछताछ की गई। फरार दो किशोरी बेतिया व बगहा की रहने वाली हैं। जिन किशोरियों को पुलिस ने खोजा है उनमें एक आदापुर की व दूसरी मेहसी की रहने वाली हैं।

- एसपी ने की मामले की जांच चार से मांगा गया स्पष्टीकरण
- दो किशोरियों की तलाश में बेतिया व बगहा में छापेमारी

बगहा की किशोरी ने भागने के लिए किया था प्रेरित

पकड़ी गईं दो किशोरियों ने कहा कि बगहा की किशोरी ने यहां से भागने के लिए सबको प्रेरित किया था। दो दिन पूर्व सभी एक राय होकर यहां से फरार हो गईं। बालिका गृह के अधीक्षक ने भी दो कर्मी व दो सुरक्षाकर्मी से स्पष्टीकरण मांगा है। भागने की सूचना पर मंगलवार को डीपीओ प्रतिभा कुमारी गिरी व बालगृह के अधीक्षक राकेश कुमार के अलावा मेजर रमेश कुमार साह भी पहुंचकर पूछताछ की। बताया गया कि बगहा की किशोरी 14 अक्टूबर व बेतिया की किशोरी 15 अक्टूबर को बालिका गृह में आई थी।

छत्तीसगढ़ ने बिहार और कानपुर की बिजली कंपनियों को पछाड़ा

संजीत कुमार, रायपुर

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों की बिजली कंपनियों के उत्पादन, गुणवत्ता और संसाधनों पर उनकी रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) ने बिहार और कानपुर (उत्तर प्रदेश) की बिजली कंपनियों को पछाड़ कर सूची में 31 से 20वें स्थान पर जगह बना ली है। जबकि टॉप पर गुजरात की तीन बिजली वितरण कंपनियों का दबदबा बना हुआ है। उत्तराखंड की बिजली वितरण कंपनी तीन पायदान खिसक कर सातवें स्थान पर पहुंच गई है।

रैंकिंग में पहले से तीसरे नंबर पर गुजरात की तीन कंपनियां हैं। चौथे नंबर पर कर्नाटक की कंपनी है, जबकि पिछली बार उत्तरखंड की कंपनी चौथे नंबर पर थी जो इस बार सातवें स्थान पर फिसल गई है। पांचवें नंबर पर फिर गुजरात की एक कंपनी का कब्जा है।

2018 की रैंकिंग में बिहार की नार्थ बिहार और उत्तर प्रदेश की कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी छत्तीसगढ़ के ऊपर थीं। इस बार नार्थ बिहार 22 और कानपुर 24वें स्थान पर है। कानपुर पिछली बार भी 24वें स्थान पर थी, जबकि नार्थ बिहार 17वें स्थान पर थी। बिहार की दूसरी वितरण कंपनी 25वें स्थान पर है। वहीं, यूपी की बाकी तीन कंपनियां क्रमशः 31, 35 और 36वें स्थान पर हैं।

छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) ने राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। कंपनी ने तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान (एटी एंड सी लॉस) को भी कम किया है।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में सुबह ठंडी और दिन सहज रहेगा। पंजाब व राजस्थान में मुख्यतः साफ आसमान के साथ सुबह में धुंध रहेगी तथा हरियाणा व दिल्ली में आंशिक बादल छाए रहेंगे। दिन आरामदायक बना रहेगा। दोपहर में हल्की हवाओं के साथ मौसम सहज बना रहेगा।

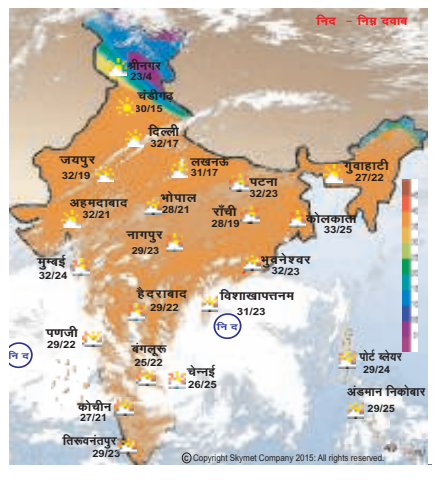

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	32/24/व	अहमदाबाद	32/17/व
कोलकाता	33/25/आंबा बड़ोदा		30/22/व
चेन्नई	27/23/व	नागपुर	29/22/व
हैदराबाद	27/22/व	इन्दौर	26/19/सा
बंगलूरू	26/22/आंबा	रांची	27/23/आंबा
त्रिवेन्द्रम	30/23/व	पटना	32/22/सा
गुवाहाटी	29/21/व	जमशेदपुर	30/23/व
गंगटोक	14/00/व	पुणे	29/21/व

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

बुधवार 23 अक्टूबर 2019

16

www.jagran.com

पहली बार युद्ध में लड़ाकू विमान का इस्तेमाल हुआ

1911 में आज ही तुर्की-इटली युद्ध के दौरान लीबिया से इटली के एक पायलट ने तुर्की का सैनिक सर्वेक्षण करने के लिए लड़ाकू विमान से उड़ान भरी थी। इसके बाद उसी साल एक नवंबर को इसी तरह के लड़ाकू विमान से तुर्की की सेना पर पहली बमबारी की गई थी।

हंगेरी में क्रांति की शुरुआत हुई

1956 में आज ही हंगरी में सोवियत संघ के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे और इसी के साथ हंगरी में क्रांति की शुरुआत हुई थी। हालांकि इस विद्रोह को सोवियत संघ ने कामयाब नहीं होने दिया था और 10 नवंबर, 1956 को इसको समाप्त कर दिया गया था।

हिंदी सिनेमा के बेहतरीन हास्य कलाकार थे देवेन वर्मा

फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों को गुदगुदाने वाले हास्य अभिनेता देवेन वर्मा का जन्म 1937 में आज ही के दिन पुणे में हुआ था। 1961 में आई फिल्म धर्मपुत्र से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। उन्होंने अंगूर, हलचल, गोलमाल, खट्टा मीठा, कोरा कागज, कभी कभी जैसी फिल्मों में काम किया। वर्ष 1966 देवेन के लिए बेहद खास रहा। इस वर्ष उनकी कलाकारी के विविध रूप देखने को मिले। उन्होंने दाना पानी, बेशर्म, बड़ा कबूतर और नादान जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया। उन्हें तीन बार फिल्मफेयर बेस्ट कॉमेडियन अवॉर्ड मिला। दो दिसंबर, 2014 को उनका निधन हो गया।

इधर-उधर की

बांग्लादेश में आठ हमशक्लों से दिलवाई परीक्षा

ढाका,एजेंसी : बांग्लादेश में नकल का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है।

यहां सत्तारूढ़ दल की सांसद तमन्ना नुसरत ने विश्वविद्यालय में परीक्षा देने के लिए हमशक्लों का इस्तेमाल किया। विश्वविद्यालय को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो तत्काल कार्रवाई करते हुए तमन्ना को बर्खास्त कर दिया। तमन्ना ने अपनी जगह परीक्षा दिलाने के लिए 8 हमशक्लों का प्रयोग किया और इसके लिए उन्होंने मोटी रकम खर्च की। परीक्षा में होने वाले इस नकल का खुलासा बांग्लादेश के ही एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल ने किया। चैनल के मुताबिक, विश्वविद्यालय के कई अधिकारियों को नकल के बारे में पहली से ही पता था, लेकिन सच्चाई जानते हुए भी वो चुप रहे। सांसद तमन्ना नुसरत काफी रसूखदार परिवार से हैं। परीक्षा हॉल के बाहर तमन्ना के बाउंसर्स तैनात रहते थे, जो हमशक्लों को सुरक्षा देते थे।

नासा ने दी खुशखबरी, ओजोन छिद्र में इस साल रिकॉर्ड गिरावट

- छिद्र के आकार में आई कमी की वजह पर अंतरिक्ष एजेंसी ने जताई चिंता
- स्ट्रेटोस्फेयर में सामान्य से अधिक तापमान होने के चलते सिकुड़ा ओजोन परत का छेद

1982 के बाद पहली बार इतना सिकुड़ा है छेद का आकार। फाइल

वाशिंगटन, प्रेट्र : अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन गैस की परत के छिद्र में इस साल रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के अनुसार, 1982 के बाद से पहली बार ओजोन परत का छिद्र इतना सिकुड़ा है। आठ सितंबर को इसका आकार 1.64 करोड़ वर्ग किलोमीटर के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वहीं, अक्टूबर में यह घटकर एक करोड़ वर्ग किलोमीटर हो गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खबर अच्छी तो है, लेकिन इसके सिकुड़ने की वजह चिंतित करने वाली है।

नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में अर्थ साइंसेज विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक पॉल न्यूमैन ने कहा, 'छिद्र सिकुड़ा है, लेकिन यह इस बात का संकेत नहीं है कि ओजोन परत की स्थिति दुरुस्त हो गई है। वायुमंडल की दूसरी सबसे बड़ी परत स्ट्रेटोस्फेयर में सामान्य से अधिक तापमान बढ़ने के चलते ऐसा हुआ है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।' ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनी ओजोन गैस एक अत्यधिक क्रियाशील अणु है। इस गैस की परत पृथ्वी की सतह के ऊपर 11 से 40 किलोमीटर के बीच फैली हुई है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, जो कई तरह के रोगों का कारण बन सकती है।

2002 में भी हुई थी ऐसी घटना : नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार, बीते चालीस वर्षों में तीसरी बार तापमान बढ़ने के चलते ओजोन परत में बन रहे छिद्र का आकार घटा है। इससे पहले 1988 और 2002 में भी ऐसा देखने को मिला था। लेकिन इन दोनों के बीच संबंध का अभी पता नहीं लग पाया है। नासा के साथ काम करने वाले यूनिवर्सिटी स्पेस रिसर्च एसोसिएशन के वैज्ञानिक, सुसान स्ट्रहान ने कहा, 'यह एक दुर्लभ घटना है, जिसे हम अब भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वार्मिंग नहीं हुई होती तो संभवतः हम एक विशिष्ट ओजोन छेद देख रहे होते।'

ब्रोमीन से होता है नुकसान : अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छेद सर्दियों के दौरान प्रभावित होता है क्योंकि इस दौरान सूर्य की किरणें ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में क्लोरीन और ब्रोमीन के यौगिक सक्रिय रूप शामिल रहते हैं।

1913 में हुए थी खोज : ओजोन की परत की खोज वर्ष 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फैबरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। इनसे पहले भी वैज्ञानिकों ने जब सूर्य से आने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा तो उन्होंने पाया था कि उसमें कुछ काले रंग के क्षेत्र थे और 310 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्ध्य का कोई भी रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी तक नहीं आ रहा था। वैज्ञानिकों ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई तत्व पराबैगनी किरणों को सोख रहा है, जिससे कि स्पेक्ट्रम में काला क्षेत्र बन रहा है तथा पराबैंगनी हिस्से में कोई भी विकिरण दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम का जो हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था वह ओजोन नाम के तत्व से पूरी तरह मैच कर गया, जिसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन ही वह तत्व है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा है।

'डोबसन' से मापी जाती है इकाई : ओजोन के गुणों का विस्तार से अध्ययन ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी जी एम बी डोबसन ने किया था। उन्होंने एक सरल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था, जो ओजोन को भूतल से माप सकता था। इसकी मात्रा मापने की इकाई का नाम डोबसन के सम्मान में 'डोबसन इकाई' रखा गया है।

रिकॉर्ड ऊन देने वाले ऑस्ट्रेलियाई नर भेड़ की हुई मौत

मेरिनो नस्ल का क्रिस। रायटर

सिडनी, रायटर : मेरिनो नस्ल के चर्चित ऑस्ट्रेलियाई नर भेड़ क्रिस की मंगलवार को मौत हो गई। क्रिस ने वर्ष 2015 में तब सुर्खियां बटोरी थीं जब उसके शरीर से एक बार में 40 किलोग्राम से ज्यादा ऊन उतारी गई थी। यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। बेहतरीन किस्म की इतनी ऊन की कीमत वर्तमान में 413.6 डॉलर (करीब 29,300 रुपये) है।

क्रिस को पहली बार 2015 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के पास देखा गया था। उसके बाल तब तक किसी ने नहीं काटे थे। इसके बाद उसे कैनबरा स्थित लिटिल ओक अभयारण्य में पहुंचा दिया गया था। क्रिस की मौत पर दुख जताते हुए लिटिल ओक अभयारण्य के सह संस्थापक व उपाध्यक्ष केट ल्यूक ने बताया कि क्रिस की मौत उम्र पूरी हो जाने की वजह से हुई। वह करीब दस साल का हो चला था। आमतौर पर भेड़ का जीवनकाल 10 साल होता है।

अंतरिक्ष से खींची जाएंगी हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें

तकनीक ▶ इजरायल में भारतीय वैज्ञानिक ने तैयार किया नया इमेजिंग सिस्टम

कम लागत में मिलेंगे अच्छी गुणवत्ता वाले चित्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : अंतरिक्ष में तस्वीरें लेने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया इमेजिंग सिस्टम तैयार किया है, जो नैनोसेटेलाइट से भी छोटा है और हाई-रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें खींच सकता है। इजरायल में एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा तैयार की गई इस दूरबीन प्रणाली (टेलिस्कोप सिस्टम) की खासियत यह है कि यह कम खर्च में अच्छी तस्वीरें खींच सकती है। नई प्रणाली के जरिये न सिर्फ अंतरिक्ष से प्रभावी और स्पष्ट चित्र लिए जा सकते हैं बल्कि पृथ्वी पर लगे दूरबीनों की गुणवत्ता को भी काफी हद तक सुधारा जा सकता है।

बेन-गुरियन यूनिवर्सिटी (बीजीयू) की शोधकर्ता अंगिका बुलबुल ने कहा, 'नई तकनीक अंतरिक्ष-आधारित कैमरों और पृथ्वी पर लगाई गई दूरबीनों से उपलब्ध होने वाले चित्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है और यह आर्थिक रूप से भी फायदेमंद साबित हो सकती है।'

बिहार के भागलपुर निवासी बुलबुल ने कहा, 'यह एक ऐसा आविष्कार है जो अंतरिक्ष अन्वेषण, खगोल विज्ञान, एरियल फोटोग्राफी की लागत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा।'

यह अध्ययन ऑप्टिका नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। फाइल

उन्होंने कहा कि हमारी प्रणाली मौजूदा दूरबीन प्रणाली के कुल क्षेत्र का केवल 0.5 फीसद है। ऑप्टिका नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि नैनोसैटेलाइट्स सरीखी नई प्रणाली ऐसे चित्रों को खींचने में सक्षम है, जो टेलीस्कोपों में इस्तेमाल होने वाले फुल-फ्रेम-लेंस आधारित कैमरों द्वारा खींची गई तस्वीरों से मेल खाते हैं।

बीजीयू के इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जोसेफ रोसेन की देखरेख में काम करने वाली बुलबुल ने कहा, 'लंबी दूरी की फोटोग्राफी के बारे में पहले भी कई तरह के अनुमान लगाए जाते रहे हैं पर अब सभी गलत साबित हो चुके हैं।'

राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (एनआइटी) कालीकट और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की पूर्व छात्रा रहीं बुलबुल ने कहा, 'अध्ययन के दौरान हमने पाया कि अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरों को प्राप्त करने के लिए आपको केवल टेलीस्कोप लेंस के एक छोटे से हिस्से की आवश्यकता होती है। इसके लिए लेंस के एपर्चर का 0.43 फीसद से कम करने की जरूरत होती है, लेकिन हम नई इमेजिंग प्रणाली से भी हाई रिजोल्यूशन वाले चित्रों को खींचने में कामयाब रहे हैं। बुलबुल ने कहा कि टेलीस्कोपिक सिस्टम को और प्रभावी बनाने से पहले हमें इस सिस्टम की दक्षता में सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि टेलीस्कोप खगोलीय पिंडों से बहुत कम रोशनी प्राप्त करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें सिग्नल भी कम मिल पाते हैं और इसका काम प्रभावित होता है, इसलिए पहले इनकी ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने की जरूरत है।

सबसे बड़ी टेलीस्कोप के लिए विकसित किया सॉफ्टवेयर

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : कनैरी आइलैंड में स्थापित हो रही थर्टी मीटर टेलीस्कोप (टीएमटी) दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप (दूरबीन) है। इस अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर अमेरिका, कनाडा, चीन, जापान और भारत के संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं। इस परियोजना में भारत का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में योगदान लगभग 70 फीसद है। भारतीय संस्थाएं सॉफ्टवेयर के साथ-साथ दूरबीन नियंत्रण प्रणाली भी विकसित करने में लगी हुई हैं। इस टेलीस्कोप का एक मुख्य सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। बीते दिनों वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण भी किया। टेलीस्कोप कॉमन सॉफ्टवेयर (सीएसडब्ल्यू) नामक यह सॉफ्टवेयर दो वर्षों से तैयार किया जा रहा था। इसकी मदद से टेलीस्कोप का बाहरी डिजाइन और भीतरी आधारभूत संरचना

प्रतीकात्मक

तैयार की जानी है। इस सॉफ्टवेयर को पुणे के एक तकनीकी संस्थान की टीम ने विकसित किया है।

भारत को जल्द मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमेटेड फेशियल रेकॉग्निशन सिस्टम

नई दिल्ली, प्रेट्र: अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज से लगभग 19 दिन बाद भारत को विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमेटेड फेशियल रेकॉग्निशन सिस्टम (स्वचालित चेहरा पहचान प्रणाली-एएफआरएस) मिल जाएगा। दरअसल, गृह मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने इसके लिए बोलियां मंगाने का काम आठ जुलाई को शुरू किया था। निविदा जमा करने की अंतिम तारीख आठ नवंबर है। बोली किसके हक में गई इसकी घोषणा भी उसी दिन कर दी जाएगी।

वर्तमान में अमेजन रेकॉग्निशन, लैंब्डा लैब्स, माइक्रोसाफ्ट फेस एपीआइ, गूगल क्लाउड विजन और आइबीएम विजुअल रेकॉग्निशन सहित अन्य एएफआरएस मौजूद हैं। पिछले साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने फेशियल रेकॉग्निशन के माध्यम से चार दिनों में लगभग 3,000 लापता बच्चों को खोज निकाला था।

शोध अनुसंधान

नींद में मस्तिष्क की मरम्मत करती हैं प्रतिरक्षी कोशिकाएं

लंबे समय तक चले शोध के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि माइक्रोग्लिया नामक प्रतिरक्षी कोशिकाएं उस वक्त भी सक्रिय रहती हैं, जब हम सोते हैं। संक्रमण से लड़ने में मदद और शरीर में आई क्षति को दुरुस्त करने के साथ यह तंत्रिका कोशिकाओं के संपर्क को पुनर्स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ रोशेस्टर ने चूहों पर किए अध्ययन के बाद बताया कि यह मस्तिष्क के पहले उत्तरदाता के रूप में काम करती हैं। सोते वक्त माइक्रोग्लिया मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डियों में गश्त करती हैं और मृत कोशिकाओं को हटाने के साथ ही शरीर की किसी भी तरह के संक्रमण से रक्षा करती हैं। ताजा शोध को नेचर न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। शोध से जुड़े प्रोफेसर एनिया मजेवेस्का ने कहा, 'हमारे अध्ययन से स्पष्ट है कि मस्तिष्क में सोने और जागने का सिग्नल ही प्रतिरक्षी कोशिकाओं के सिस्टम को सक्रिय या बंद करने वाले स्विच की तरह भी काम करता है।' (आइएएनएस)

कई बीमारियों से बचाता है अखरोट का सेवन

रोजाना कुछ अखरोट खाने से व्यक्ति की सेहत पर काफी सकारात्मक असर पड़ता है। वह कई सारी खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रह सकता है। 11 देशों में किए गए 55 यूनिवर्सिटी के विभिन्न अध्ययनों और परीक्षणों में सामने आया है कि प्रतिदिन चार अखरोट खाने से व्यक्ति मोटापे, डायबिटीज के साथ ही कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से भी बच सकता है। उनकी मानसिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। कैलिफोर्निया वालनट कमीशन (सीडब्ल्यूसी) के हेल्थ रिसर्च डायरेक्टर कैरोल बर्ग ने कहा, 'अखरोट को पोषक तत्वों का पावर हाउस कहा जा सकता है। इनमें प्रोटीन, मैगनीशियम और फाइबर के साथ ओमेगा-3 अल्फा-लिनोलेनिक एसिड की भी प्रचुरता होती है। यह स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जो केवल कुछ सूखे मेवों में ही पाया जाता है।' शोधकर्ताओं ने बताया कि शाकाहारियों के पास ओमेगा-3 प्राप्त करने के बहुत ही सीमित विकल्प होते हैं। ऐसे में अखरोट फायदेमंद हो सकता है। (प्रेट्र)

सिंगापुर के मरीना बे पर फ्लाइंग टैक्सी का परीक्षण

सिंगापुर ने मंगलवार को 26वें इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्ल्ड कांग्रेस में फ्लाइंग टैक्सी की पहली झलक देखी। यहां के मरीना बे पर जर्मन एविएशन फर्म वोलोकॉप्टर की ड्रोन जैसी फ्लाइंग टैक्सी का फ्लाइट टेस्ट हुआ। 18 प्रोपलर वाली इस टैक्सी ने करीब दो मिनट 30 सेकंड तक उड़ान भरी। यह टैक्सी स्वायत्त रूप से उड़ान भरने में सक्षम है। हालांकि परीक्षण के दौरान सुरक्षा कारणों से इसमें पायलट भी सवार था। जर्मन फर्म को उम्मीद है कि उसकी यह टैक्सी जाम से जूझते एशियाई शहरों के लिए यातायात में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। वोलोकॉप्टर जर्मनी, दुबई और फिनलैंड में इसका सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुकी है। एएफपी

यूरोपीय संसद के बाहर किसानों का प्रदर्शन

फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में मंगलवार को यूरोपीय संसद के बाहर यूरोपीय देशों से जुटे किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों, अनुचित प्रतिस्पर्धा और गैर-लाभकारी नीतियों के विरोध में आवाज बुलंद की। किसानों ने आरोप लगाया कि यूरोपीय संघ की नीतियों से हमारी आमदनी घट रही है। इससे हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। एपी

स्क्रीन शॉट

परिणीति और प्रियंका का रिश्ता है अनोखा

फिल्म इंडस्ट्री की बहनों में प्रियंका और परिणीति चोपड़ा का नाम सबसे ऊपर आता है। यूं तो परिणीति प्रियंका की चचेरी बहन हैं, लेकिन दोनों के बीच बहुत मजबूत और अनोखा रिश्ता है। दोनों बहनें एक-दूसरे की तारीफ का मौका नहीं छोड़ती हैं। मंगलवार को परिणीति के जन्मदिन पर भी प्रियंका ने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर उन्हें विश किया। परिणीति बड़ी बहन प्रियंका को अपना मार्गदर्शक मानती हैं। दोनों ने भले ही एक साथ किसी फिल्म में काम न किया हो, लेकिन अब हॉलीवुड की फिल्म इन्हें साथ लेकर आ रही है। हॉलीवुड की एनीमेशन फिल्म 'फ्रोजेन 2' के हिंदी संस्करण के लिए दोनों बहनें डबिंग करेंगी। 'फ्रोजेन 2' की कहानी भी दो बहनों एल्सा और एना की है। प्रियंका एल्सा का किरदार, जबकि परिणीति एना के किरदार के लिए अपनी अवाज दे रही हैं। पहली बार दीदी के साथ काम कर रहीं परिणीति को लगता है कि एल्सा और एना के बीच का रिश्ता ठीक उनके रिश्ते की तरह हैं। परिणीति बताती हैं कि मिमी दीदी (प्रियंका) के साथ उनका अनोखा रिश्ता है। उन्हें जब प्रियंका के साथ काम करने का मौका मिला तो उन्होंने झट से हां कर ही। परिणीति ने 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' की शूटिंग पूरी कर ली है और फिलहाल साइना नेहवाल की बॉयोपिक की तैयारियों में व्यस्त हैं।

दूसरों को देखकर सीखते हैं राजकुमार राव!

इन दिनों हिंदी सिनेमा के व्यस्त कलाकारों में राजकुमार राव का नाम भी शामिल हैं। अलग तरह की कहानियों का हिस्सा बन रहे राजकुमार की आगामी फिल्म 'मेड इन चाइना' होगी। प्रयोग करते रहने में यकीन करने वाले राजकुमार का मानना है कि अच्छा कलाकार वही होता है, जो हमेशा सीखता रहता है। अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए राजकुमार राव दूसरे कलाकारों का काम देखना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि पर्दा चाहे बड़ा हो या छोटा या मोबाइल पर चलने वाली वेबसीरीज ही क्यों न हो, वह अच्छे काम को देखकर हमेशा उससे कुछ न कुछ सीखते हैं। राजकुमार किसी दूसरे कलाकार से प्रतिस्पर्धा करने में यकीन नहीं रखते हैं। कई मल्टीस्टारर फिल्में कर चुके राजकुमार कहते हैं कि फिल्म में अपने सह कलाकारों से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय उनसे सीखते हैं। राजकुमार ने बताया कि 'मेड इन चाइना' फिल्म में बमन ईरानी, परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकारों से ऑन और ऑफ स्क्रीन काफी कुछ सीखने का मौका मिला है। सेट पर परेश रावल और बमन ईरानी ने अपने अलग-अलग किरदारों के बारे में उन्हें कई बातें भी बताई थीं। राजकुमार का कहना है कि उनकी करीबी पत्रलेखा भी बहुत अच्छी अदाकारा हैं।

'पति पत्नी और वो' में अभिनेत्रियों का रोल पुरानी फिल्म से मजबूत : अनन्या

अनन्या पांडे जल्द ही कार्तिक आर्यन और भूमि पेडणेकर के साथ फिल्म 'पति पत्नी और वो' में नजर आएंगी। फिल्म 1977 में इसी नाम की संजीव कुमार, विद्या सिन्हा और रंजीता की फिल्म पर बेस्ड है। फिल्म के डायरेक्टर और स्टार्स का मानना है कि फिल्म पहली वाली फिल्म से बिल्कुल अलग है। अनन्या पांडे कहती हैं, 'इस एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर कॉमेडी को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए मेरे और भूमि के रोल को फिल्म में ज्यादा महत्व दिया गया है। 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' स्टार कहती हैं, 'आज इस रिलेशनशिप को पहले की तुलना में अलग तरह से देखा जाता है, इसलिए 70 के दशक की फिल्म को आज के समय में दिखाने पर सवाल उठाना बिल्कुल सही है। लेकिन यह लव ट्रायंगल हमेशा से ही प्रासंगिक रहा है। पहले की पीढ़ी इसे उनके दृष्टिकोण से देखती थी और आज की हमारे परिप्रेक्ष्य से देखती है।' अनन्या कहती हैं, 'मेकर्स ने पुरानी फिल्म के सार को वैसा ही रखा है, लेकिन महिला किरदारों को ज्यादा महत्व दिया है। इस फिल्म में भूमि और मेरा किरदार मजबूत है। हमारे किरदार मूल फिल्म के किरदारों से ज्यादा प्रभावी हैं। सशक्त महिलाओं को दिखाना प्रेरणादायक भी होगा।' फिल्म का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है।

शुरू हुआ दिवाली का जश्न

सितारों के बीच दिवाली पार्टी करने को लेकर अभी से होड़ शुरू हो गई है। तभी तो डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिवाली की पार्टी एक हफ्ते पहले यानी सोमवार को ही रख दी। मनीष जाने-माने फैशन डिजाइनर हैं, ऐसे में उनकी पार्टी सितारों से सजी। मनीष की पार्टी में शामिल शिल्पा शेट्टी ने एक बेहद ही प्यारी तस्वीर साझा की है। तस्वीर में मनीष मल्होत्रा के साथ शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, नुसरत भरूचा, पूजा हेगड़े, ताहिरा कश्यप और सलमान खान की बहन अर्पिता नजर आ रही हैं। शिल्पा ने इस तस्वीर के साथ लिखा, 'दिवाली नाइट्स'।

अध्ययन

अमेरिका की हवाई यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का दावा है कि जलवायु संकट अल नीनो के लिए भी जिम्मेदार है

बदलती जलवायु है मौसमी आपदाओं का कारण

लास एंजिलिस, प्रेट्र : बाढ़, सूखा, तूफान, भूस्खलन जैसी आपदाओं के लिए लगातार बदलती जलवायु जिम्मेदार है। यह जलवायु संकट अब अल नीनो का कारण भी बन रहा है और ये साल-दर-साल और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। एक नए अध्ययन में अमेरिकी शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है।

पीएनएएस नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि अल नीनो के कारण मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह का पानी सामान्य से काफी गर्म हो जाता है, जिसके कारण पश्चिमी प्रशांत से अमेरिका की ओर गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही यह वैश्विक मौसम को भी प्रभावित कर रहा है। इस अध्ययन के शोधकर्ताओं में अमेरिका की हवाई यूनिवर्सिटी के शोधार्थी भी शामिल थे। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा, 'यदि जलवायु परिवर्तन की बढ़ती दर पर काबू नहीं पाया गया तो भविष्य में पश्चिमी प्रशांत महासागर में और चरम मौसमी आपदाएं देखने को मिल सकती हैं।'

1901 से 2017 के बीच की आपदाओं का किया अध्ययन : इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं की टीम ने वर्ष 1901 से लेकर 2017 तक 33 अल नीनो की घटनाओं के विवरणों की जांच की। इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि लगातार बढ़ती गर्मी के कारण पश्चिमी प्रशांत महासागर में सतह का तापमान बढ़ रहा है। साथ ही, मध्य प्रशांत में तेज हवाओं के चलने से चरम अल नीनो की आवृत्ति में और वृद्धि हुई है।

प्रतीकात्मक

पांच बार आ चुकी है मौसमी आपदा: शोधकर्ताओं ने पाया कि पूर्वी प्रशांत में होने वाली सभी अल नीनो घटनाएं 1970 के दशक से पहले हुई थीं, जबकि पश्चिमी-मध्य प्रशांत में एक दशक के बाद ऐसी घटना देखी गई थी। उन्होंने यह भी पाया कि 1970 के बाद के इतिहास में पांच बार चरम अल नीनो घटनाएं हुई हैं।

बढ़ेंगी समस्याएं

हवाई यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और इस अध्ययन के सह-लेखक बिन वांग ने कहा, 'कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चलता है कि यदि भविष्य में भी जलवायु परिवर्तन इसी प्रकार जारी रहा तो चरम अल नीनो की आवृत्ति तो बढ़ेगी ही, साथ ही कई तरह की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी।'

पहले पड़ चुका है अकाल

अध्ययन के मुताबिक, कई वर्षों पहले चरम अल नीनो के कारण पश्चिमी प्रशांत द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया में गंभीर सूखे पड़ गया था, जिससे अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं, दूसरी और अत्यधिक बारिश ने दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तटों को काफी नुकसान पहुंचाया था। इससे समुद्र में मछलियों के साथ-साथ प्रवाल भित्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। शोधकर्ताओं का दावा है कि इस अध्ययन के परिणामों से वैश्विक स्तर पर मौसम का बेहतर पूर्वानुमान लगाने में मदद मिल सकती है।